



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 5, 2016/माघ 16, 1937

No. 48]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 5, 2016/MAGHA 16, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2016

(अंतिम जांच परिणाम)

विषय: चीन जनवादी गणराज्य और इजरायल मूल के अथवा वहां से निर्यातित सिंक्रोनस डिजिटल हेयरार्ची ट्रांसमिशन उपस्कर के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने संबंधी निर्णायक समीक्षा जांच।

फा. सं. 15/20/2014-डीजीएडी.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियम भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए ;

क. मामले की पृष्ठभूमि

2. यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने चीन जनवादी गणराज्य और इजरायल (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) मूल के अथवा वहां से निर्यातित सिंक्रोनस डिजिटल हेयरार्ची ट्रांसमिशन उपस्कर {जिसे आगे एसडीएच उपस्कर अथवा संबद्ध वस्तुएं अथवा विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) भी कहा गया है} के आयातों में संबंधित पाटन-रोधी शुल्क संबंधी जांच शुरू करने के लिए दिनांक 21 अप्रैल, 2009 को एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी की थी। प्राधिकारी ने अधिनियम और नियमावली को ध्यान में रखते हुए इस मामले की जांच की थी और तब दिनांक 7 सितंबर, 2009 की अधिसूचना द्वारा संबद्ध देशों मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर आयतों पर अनंतिम रूप से पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी तथा वित्त मंत्रालय ने दिनांक 8 दिसंबर, 2009 की अधिसूचना संख्या 132/2009-सीमा शुल्क के द्वारा अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए थे।

3. और यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 19 अक्टूबर, 2010 को अंतिम निर्णय संख्या 14/2/2009-डीजीएडी जारी किया था जिसमें उन्होंने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क लगाने की

सिफारिश की थी तथा वित्त मंत्रालय ने दिनांक 16 दिसंबर, 2010 की अधिसूचना संख्या 125/2010-सीमा शुल्क के द्वारा निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क लगाए थे।

4 और यतः कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने माननीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण (सीईएसटीएटी), मुख्य पीठ, नई दिल्ली के समक्ष दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 के अंतिम निर्णय तथा 16 दिसंबर, 2010 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 125/2010 अपीले दायर की थीं। माननीय सीईएसटीएटी ने हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग की व्यापक सुनवाई के बाद, निर्णय पश्चात अपील कर्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई करने और ऐसे निर्णय पश्चात सुनवाई किए जाने के परिणाम स्वरूप यदि अंतिम निर्णय में कोई कोई संशोधन करने आवश्यक समझे जाएं तो ऐसे संशोधन करने के लिए इस मामले को वापस प्राधिकारी को भेज दिया था। प्राधिकारी ने 19 अक्टूबर, 2010 की अधिसूचना संख्या 14/2/2009-डीजीएडी द्वारा पहले अधिसूचित किए गए अंतिम निर्णय की सुपुष्टि करते हुए दिनांक 10 फरवरी, 2012 को अपना अंतिम निर्णय पश्चात निर्णय संख्या 14/2/2009-डीजीएडी जारी किया था।

5. और यतः नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग के प्रतिनिधि, मेसर्स तेजा नेटवर्कस लिमिटेड (जिसे आगे याचिकादाता अथवा आवेदक कहा गया है) ने विधिवत् वास्तविक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि केन्द्रीय सरकार की 16 दिसंबर, 2010 की अधिसूचना संख्या 125/2010 द्वारा लगाए गए पाटन-रोधी शुल्कों को जारी रखा जाए। उसका यह अनुरोध इस आधार पर है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्कों के लागू होने के बावजूद भी निरंतर संबद्ध वस्तुओं का पाटन हो रहा है तथा घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से ऐसे आयात होते रहने के कारण निरंतर क्षति हो रही है, क्योंकि लगाया गया पाटन-रोधी शुल्क का रूप और उसकी मात्रा अपर्याप्त है। याचिकादाता ने आगे यह भी अनुरोध किया है कि संबद्ध देशों के खिलाफ लगाए गए उपायों के समाप्त होने पर पाटन के निरंतर अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने तथा घरेलू उद्योग को उनसे क्षति होने की संभावना है। याचिकादाता का यह भी दावा है कि पाटन-रोधी उपायों को रद्द किए जाने के परिणामस्वरूप पाटन गहन हो जाएगा और उसके परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग को और क्षति होगी तथा इसलिए ऐसे शुल्कों को आगे और पांच वर्षों तक लगाए रहने की आवश्यकता है।

6. और प्राधिकारी ने याचिकादाता द्वारा दिए गए प्रथम दृष्टया प्रमाणों के आधार पर पाटन-रोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 - क (5) के अनुसार दिनांक 6 दिसंबर, 2014 की अधिसूचना संख्या 15/20/2014-डीजीएडी द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच (एसएसआर) शुरू की थी ताकि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में लागू शुल्कों को निरंतर लागू रखे जाने की आवश्यकता की पुनरीक्षा की जा सके तथा इसकी जांच की जा सके कि क्या ऐसे शुल्क को समाप्त करने के फलस्वरूप पाटन के निरंतर अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने तथा घरेलू उद्योग को उनसे क्षति होने की संभावना है। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 5 जनवरी, 2015 की अपनी अधिसूचना सं. 1/2015 द्वारा पाटनरोधी शुल्क को, जोकि सीमाशुल्क की दिनांक 16 दिसंबर, 2010 की अधिसूचना सं. 125/2010-सी.शु. द्वारा लगाया गया था, बढ़ाकर 7 दिसंबर, 2015 तक कर दिया था।

ख. क्रिया-विधि

7. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच करने के संबंध में निम्नोक्त वर्णित क्रिया-विधि को प्रयोग किया गया है :

- (i) प्राधिकारी ने नियमावली के अनुसार जांच की कार्यवाई शुरू करने से पहले आवेदन पत्र प्राप्त होने के संबंध में भारत में संबद्ध दूतावासों को अधिसूचित अधिसूचित किया है।
- (ii) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के बारे में दिनांक 6 दिसंबर, 2014 को एक सार्वजनिक सूचना संख्या 15/20/2014-डीजीएडी जी की थी, जो कि भारत सरकार के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।
- (iii) प्राधिकारी ने उपलब्ध सूचना के अनुसार 6 दिसंबर, 2014 की जांच की शुरुआत करने संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध देशों के दूतावास, संबद्ध देशों के ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उत्पादकों को प्रेषित की थी। ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करें तथा इस संबंध में निर्धारित समय-सीमा के अंतर अपने लिखित विचारों से प्राधिकारी को अवगत कराएं। निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रतियां ज्ञात निर्यातकों/आयातकों की सूची के साथ संबद्ध देशों के दूतावासों और भी इस अनुरोध के साथ भेजी गई थीं कि वे संबद्ध देशों के निर्यातकों/आयातकों को यह परामर्श दें कि वे इस संबंध में निर्धारित समय-सीमा के अंतर अपने उत्तर प्राधिकारी को भेज दें।
- (iv) नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार आवेदक की और से प्रस्तुत किए गए आवेदन के अगोपनीय वृत्तान्त की एक प्रति ज्ञात निर्यातकों, अन्य घरेलू उत्पादकों और संबद्ध देशों के दूतावासों को उपलब्ध कराई गई थी।

(v) प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के बारे में जारी की गई सार्वजनिक सूचना की एक प्रति संबंधित देशों के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों/संगठनों के प्रतिनिधियों को भेजी थी और उन्हें यह अवसर प्रदान किया था कि वे नियमावली के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने लिखित विचार प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दें :-

- (क) हुआवाई टेकनलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन
- (ख) बुहान फाईबरहोम इंटरनेशनल, चीन
- (ग) जेड टी ई कापॉरेशन लिमिटेड, चीन
- (घ) हेंगझाऊ ईसीआई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, चीन
- (ङ) हाई सिलिकोन टेकनलॉजी लिमिटेड, चीन
- (च) ईसीआई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, इजरायल
- (छ) एल्काटेल ल्यूसेंट शंघाई बैल कंपनी लिमिटेड, चीन
- (ज) यूएस स्टारकोम लिमिटेड, चीन, हांगकांग
- (झ) यूएस स्टारकोम लिमिटेड, हांगकांग, चीन
- (ञ) सियाना कापॉरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका
- (ट) सेरागोन नेटवर्क्स लिमिटेड, इजरायल
- (ठ) आरएडी डीएटीए, कम्युनिकेशन, इजरायल
- (ड) चीन चेम्बर ऑफ कामर्स फोर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आफ मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, चीन

(vi) संबंधित जांच शुरू करने के उत्तर में संबंधित देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित प्रपत्र में प्रश्नावली के उत्तर दिए हैं :-

- (क) जेड टी ई कापॉरेशन लिमिटेड, चीन
- (ख) हुआवाई टेकनलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य
- (ग) हुआवाई इंटरनेशनल पीटीई, सिंगापुर
- (घ) हुआवाई टेक. इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, हांगकांग
- (ङ) हेंगझाऊ ईसीआई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य
- (च) ईसीआई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, इजरायल
- (छ) एल्काटेल ल्यूसेंट शंघाई बैल कंपनी लिमिटेड

(vii) बाजार अर्थव्यवस्था प्रतिपादन (एमईटी) की प्रश्नावली चीन जनवादी गणराज्य के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास को इस अनुरोध के साथ भेजी थी कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी को संबंधित सूचना प्रस्तुत कर दें। संबंधित देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने बाजार अर्थव्यवस्था प्रतिपादन (एमईटी) की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं :-

- (क) हुआवाई टेकनलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य
- (ख) हेंगझाऊ ईसीआई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य
- (ग) एल्काटेल ल्यूसेंट शंघाई बैल कंपनी लिमिटेड

(viii) नियमावली के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के प्रयोजन से भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं/ एसोसिएशनों को भी प्रश्नावलियां भेजी गई थीं :-

- (क) एयरसेल लिमिटेड
- (ख) पृथ्वी इंफोरमेशन सिस्टम
- (ग) डिशनेट वायरलैस लिमिटेड
- (घ) पंजाब कम्युनिकेशन लिमिटेड
- (ङ) भारती एयरटेल लिमिटेड
- (च) एचटीएल जीएसटी
- (छ) भारत संचार निगम लिमिटेड
- (ज) हुआवाई टेक (इंडिया) कंपनी प्रा0 लिमिटेड (हुआवाई इंडिया)
- (झ) टाटा टेलीसर्विसिज लिमिटेड
- (ण) जेडटीई इंडिया
- (ट) आईडिया सेल्युलर लिमिटेड
- (ठ) एल्काटेल ल्युसेंट
- (ड) वोडाफोन ईसार लिमिटेड
- (ढ) नोकिया सीमेन्स लिमिटेड
- (रा) रेटेल कापॉरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
- (त) एरिकसन
- (थ) टाटा कम्युनिकेशन
- (द) हिमाचल फ्युरिस्टिक कम्युनिकेशन
- (ध) रिलायन्स कम्युनिकेशन लिमिटेड
- (न) आईसीओएमएम
- (प) श्याम टेलिलिंक्स
- (फ) बुप्पालामृथा मेग्नेटिक कंपोनेंट्स लिमिटेड, हैदराबाद

(ix) उपरोक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं :-

- (क) हुआवाई टेलिकम्युनिकेशन (इंडिया) कंपनी प्रा0 लिमिटेड
- (ख) मेसर्ज एल्काटेल - ल्युसेंट इंडिया
- (ग) ईसीआई टेलिकोम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
- (x) इसके अतिरिक्त हुआवाई टेकनलॉजी कंपनी लिमिटेड, हुआवाई टेलिकम्युनिकेशन (इंडिया), हुआवाई टेक. इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड और हुआवाई इंटरनेशनल पीटीई लिमिटेड ने भी जांच शुरू किए जाने संबंधी अधिसूचना के संयुक्त कानूनी निवेदन प्रस्तुत किए हैं।
- (xi) एसोसिएशन ऑफ यूनिफाईड टेलिकोम सर्विसिज प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया, सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली ने और टेलीकॉम एक्जूपमेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी जांच शुरू किए जाने संबंधी अधिसूचना के कानूनी निवेदन किए हैं।
- (xii) मौजूदा जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि अप्रैल, 2013 से जून 2014 तक की है। तथापि, क्षति की जांच अवधि में अप्रैल, 2010 – मार्च, 2011, अप्रैल, 2011, मार्च, 2012, अप्रैल, 2012 - मार्च, 2013 और जांच की अवधि (पीओआई) भी शामिल है।

- (xiii) जांच अवधि सहित विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारोबार-वार आंकड़े प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी को उक्त सूचना प्राप्त हो गई है। प्राधिकारी ने जांच शुरू करने के लिए आयातों की मात्रा और मूल्य का आकलन करने के लिए डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रदत्त आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- (xiv) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और गैर-क्षति कीमत का आकलन करने के लिए अनुबंध -3 में निर्धारित दिशा निर्देशों के आधार पर घरेलू उत्पाद द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जितना संभव हो सका है, उतनी जांच की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यदि पाटन मार्जिन से कम पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाता है तो क्या वह घरेलू उद्योग को हो रही क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- (xv) पाटन-रोधी शुल्क नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 18 सितंबर, 2015 को हुई मौखिक सुनवाई के दौरान अपनी विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया था। निम्न पक्षकारों जिन्होंने एक मौखिक सुनवाई में अपने विचार व्यक्त किए थे, उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें :-
- (क) हुआवाई ग्रुप कंपनीज
 - (ख) एल्काटेल-ल्यूसेंट शंघाई बैल ग्रुप कंपनीज
 - (ग) ईसीआई ग्रुप कंपनीज
 - (घ) आईडिया सेल्युलर लिमिटेड
 - (ङ) फिबकोम इंडिया लिमिटेड
 - (च) एसोसिएशन ऑफ यूनिफाईड टेलिकोम सर्विसिज प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया और सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
 - (छ) टेलीकॉम एक्ज्यूपमेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
 - (ज) जेड टी ई कार्पोरेशन लिमिटेड
 - (झ) तेजा नेटवर्क्स लिमिटेड
- (xvi) जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों ने भी निवेदन किए थे जिनकी जांच की गई है और प्राधिकारी द्वारा जहां कहीं भी प्रासंगिक हुआ है, उनका निदान इस जांच में किया गया है।
- (xvii) घरेलू उद्योग तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और आंकड़ों की जांच, जितनी आवश्यक समझी गई है, उतनी की गई है।
- (xviii) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीय के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय वृत्तान्त भी प्रस्तुत करें।
- (xix) जब कभी भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने मौजूदा जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना का अभिगमन करने अथवा उसे अन्यथा प्रदान नहीं करने से मनाही की है अथवा जांच में विशेष रूप से अडचन पैदा की है, प्राधिकारी ने ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर उसे इस अंतिम निर्णय में उसको रिकार्ड किया है।
- (xx) इस जांच के अनिवार्य तथ्यों युक्त एक प्रकटन विवरण, जो इस अंतिम जांच-परिणाम का आधार होगा, दिनांक 18.01.2016 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया। घरेलू उद्योग एवं विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरणों पर इस अंतिम जांच परिणाम में आवश्यक समझी गई सीमा तक विचार किया गया है।
- (xxi) प्राधिकारी के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार ने जांच को पूरा करने के लिए तथा अंतिम निर्णय को अधिसूचित करने के लिए समयावधि को 05.03.2016 तक बढ़ा दिया है।

(xxii) इस अंतिम निर्णय में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा ***सूचना को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार किया गया है।

(xxiii) प्राधिकारी द्वारा इस जांच के लिए अपनाई गई औसत विनिमय दर, 1 अमरीकी डालर = 60.77 रूपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु का कार्य क्षेत्र

8. विचाराधीन उत्पाद, जिसे दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 की मूल अंतिम निर्णय की अधिसूचना संख्या 14/2/2009 में शुल्क की तालिका के नीचे दिया गया है, जिसे दिनांक 22 अक्टूबर, 2010 के शुद्धि पत्र संख्या 14/2/2009 के साथ पढ़ा जाए और उसे आगे दिनांक 10 फरवरी, 2012 के अंतिम निर्णय संबंधी अधिसूचना संख्या 14/2/2009 के साथ पढ़ा जाए, निम्नानुसार था :-

***** टिप्पणी 1 :** विचाराधीन उत्पादों में सिंक्रोनुअस डिजीटल हेयरार्ची ट्रांसमिशन उपस्कर नामतः एसटीएम-1, एसटीएम-4, एसटीएम-16, एसटीएम-64, एसटीएम-256 संग्रहीत रूप में, सीकेडी, एसकेडी रूप में, उसके संग्रह और उप-संग्रह के रूप में अथवा अंततः ब्रोड बैंड सेल्युलर उपस्कर में प्रयुक्त किए गए उपस्कर शामिल होंगे। विचाराधीन उत्पादों में सभी एड ड्राप मल्टीप्लेक्सरज (एडीएम) (केवल एसडीएच अनुप्रयोग के लिए), मल्टीपल एड ड्राप मल्टीप्लेक्सरज (एमएडीएम) (केवल एसडीएच अनुप्रयोग के लिए) और डिजीटल क्रोस कनेक्ट (डीएक्ससी) (केवल एसडीएच अनुप्रयोग के लिए), पापुलेटिड सर्किट बोर्ड्स (केवल एसडीएच अनुप्रयोग के लिए) तथा उपस्करों के एक अंश के रूप में कलपुर्जे/संघटक, जब तक कि वे उपस्कारों के साथ अथवा उसके संग्रह/उप-संग्रह के रूप में आयातित किए जाते हैं, भी शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त विचाराधीन उत्पादों में एसडीएच के निमित्त सॉफ्टवेयर भी शामिल होंगे जो कि इन उपस्करों का ही एक संगठित भाग है जिसे उपस्कर के रूप में अथवा पृथक रूप से खरीदा जा सकता है। तथापि, एकल आधार पर आयातित संघटक/कल-पुर्जे, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं।

***** टिप्पणी 2 :** एसडीएच उपस्कर अनिवार्य रूप से ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से संकेतों को संप्रेषित करते हैं। ऐसे एसडीएच उपस्कर होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक कोप्पर के माध्यम से अथवा माइक्रोवेव रेडियो के माध्यम से ट्रांसमिशन के निमित्त होते हैं। केवल ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से संकेतों को संप्रेषित करने वाले एसडीएच उपस्कर पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने के अध्वधीन होंगे।

***** टिप्पणी 3 :** जब एसडीएच का आयात अन्त्य ब्रोडबैंड/सेल्युलर उपस्कर के एक अंश के रूप में किया जाता है तो पाटन-रोधी शुल्क का भुगतान आयातों के केवल एसडीएच के भाग पर ही देय होगा। इसी प्रकार जब अन्त्य ब्रोडबैंड/सेल्युलर उपस्कर का आयात एसडीएच उपस्कर के रूप में किया जाता है तो पाटन-रोधी शुल्क का भुगतान आयातों के केवल एसडीएच के भाग पर ही देय होगा।

***** टिप्पणी 4 :** पीडीएच, सीडब्ल्यूडीएम, डीडब्ल्यूडीएम, माइक्रोवेव प्रणालियों, जीपीओएन, डीएसएलएम, एमएसएएन, बीआईटीएस, राउटर्स, पीडीएसएन, एसजीएसएन, एमजीडब्ल्यू, बीटीएस, बीएससी, एमएससी, ओएनटी, एलएलआर, एचएसएस और एमआरपी के किसी भी रूप में गैर-एसडीएच होने के कारण ये विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं और इसलिए ये पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने के अध्वधीन नहीं हैं।

***** टिप्पणी 5 :** माइक्रोवेव रेडियो टर्मिनल जो कि एसडीएस ट्रांसमिशन उपस्कर का एक एसटीएम-1 इंटरफेस हो सकते हैं और जो रेडियो और एसडीएच उपस्कर के बीच संपर्क स्थापित कर सकने में वास्तविक साधन होते हैं, ये पाटन-रोधी शुल्क का भुगतान करने के अधिकार-क्षेत्र से बाहर हैं।

ग. 1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

9. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- मौजूदा याचिका में विचाराधीन उत्पाद, "सिंक्रोनुअस डिजीटल हेयरार्ची ट्रांसमिशन उपस्कर, उसके सहायक उपकरण, सहयोजित सॉफ्टवेयर और उसके अत्यावश्यक कल-पुर्जे और संघटक, उसके संग्रह और उप-संग्रह के रूप में अथवा अंततः ब्रोड बैंड सेल्युलर उपस्कर में प्रयुक्त किए गए उपस्कर" हैं।
- एसडीएच ट्रांसमिशन उपस्करों को ड्राप मल्टीप्लेक्सरज (एडीएम) (केवल एसडीएच अनुप्रयोग के लिए), मल्टीपल एड ड्राप मल्टीप्लेक्सरज (एमएडीएम) (केवल एसडीएच अनुप्रयोग के लिए) और डिजीटल क्रोस कनेक्ट्स के रूप में भी जाना जाता है। पापुलेटिड सर्किट बोर्ड्स, पावर सप्लाय, लेसर्ज, चेसीज और सॉफ्ट वेयर एसडीएच उपस्कर आदि के निमित्त होते हैं, जिनमें एसडीएच ट्रांसमिशन उपस्करों के अत्यावश्यक कल-पुर्जे शामिल होते हैं और ये विचाराधीन उत्पाद के अधिकार-क्षेत्र के भीतर आते हैं बशर्ते कि ऐसे संघटक केवल एसडीएच ट्रांसमिशन उपस्कर के अनुप्रयोग के लिए ही हों।

- iii. एसडीएच ट्रांसमिशन उपस्करों को ट्रांसमिशन उपस्करों के रूप में अथवा ब्रोडबैंड और/अथवा सेल्युलर (जीएसएम और सीडीएमए दोनों प्रकार के) उपस्कर जैसे अन्य उपस्कर के बनने वाले भाग के रूप में खरीदा जा सकता है। ब्रोडबैंड और/अथवा सेल्युलर उपस्कर जैसे अन्य उपस्कर के बनने वाले भाग के रूप में एसडीएच ट्रांसमिशन उपस्कर भी विचाराधीन उत्पाद के अधिकार-क्षेत्र के भीतर आते हैं।
- iv. विचाराधीन उत्पाद अनेक इलेक्ट्रॉनिक संघटकों और/अथवा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्डों का एक संग्रह होते हैं, जिनको दूरी (कम अथवा अधिक) में ऑप्टिकल फाईबर के माध्यम से ट्रांसमिशन करने के लिए विशेष रूप से संयुक्त निम्न गति के सिग्नलों को उच्च-गतिके सिग्नलों में संयोजित करने के लिए मल्टीफ्लेक्सिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चूंकि अन्य अनुप्रयोगों के साथ इन्हें बेस ट्रांसमिशन स्टेशनों, स्विच एक्सचेंजों और उनकी अवस्थिति के अन्य स्थल पर स्थापित किया जाता है, इसलिए विभिन्न स्थलों पर स्थापित एसडीएच उपस्करों में सहयोजित परिसम्पतियों के रूप में अंतर हो सकता है।
- v. विभिन्न एसडीएच उपस्कर, वास्तविक और ऑप्टिकल, उत्पादन प्रौद्योगिकी, विनिर्माण प्रक्रिया, अनुसंधान व विकास, सॉफ्टवेयर की क्षमताओं, कार्यों और प्रयोगों आदि की दृष्टि से तुलनीय होते हैं। इसलिए मौजूदा जांच के प्रयोजन के लिए एसडीएच उपस्कर एक जैसे ही उत्पाद होते हैं।
- vi. विचाराधीन उत्पाद को पूरे उपस्कर के रूप में अथवा सीकेडी, एस्केडी अथवा समान संघटक के रूप में आयात किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नेटवर्क में एसडीएच ट्रांसमिशन उपस्कर को जोड़ने/स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार के सहायक उपकरणों (ई1 केबिल्स, पीसीएम केबिल्स, पावर केबिल्स, रैक्स, वर्कस्टेशनों आदि) की आवश्यकता होती है। सॉफ्टवेयर इन उपस्करों को अंतरंग भाग होता है जिसे उपस्कर के एक भाग के रूप में अथवा पृथक् रूप से खरीदा जा सकता है। ये सभी उपकरण भी विचाराधीन उत्पाद के अधिकार-क्षेत्र के भीतर आते हैं।
- vii. विचाराधीन वस्तुओं के उत्पादन में निहित मुख्य प्रयास, प्रौद्योगिकी का विकास करना होता है। विश्व भर में उत्पादकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं का डिजाइन तैयार करने और विकास करने के लिए पर्याप्त अनुसंधान और विकास प्रयास किए जाते हैं जिसका आकलन इस तथ्य से किया जा सकता है कि लगभग 60 प्रतिशत जन शक्ति विचाराधीन उत्पाद का डिजाइन तैयार करने और विकास करने में लगी हुई है।
- viii. उत्पादन का मुख्य कार्य उत्पाद की प्रौद्योगिकी, तकनीकी जानकारी, डिजाइन तैयार करना और विकास करना होता है। वास्तव में इसके विनिर्माण की प्रक्रिया, विचाराधीन वस्तुओं के उत्पादन और आपूर्ति में लगी कुल सक्रियता का बहुत छोटा भाग होती है और इसमें पीसीबी (पापुलेटिड पीसीबी) के अनेक संघटकों का जटिल संग्रहण करना और उसके बाद उन्हें तैयार उत्पाद के रूप में उनका संग्रहण और परीक्षण करना शामिल होता है।
- ix. मौजूदा उत्पाद में उत्पादन एक ऐसा क्रियाकलाप होता है जिसमें जटिल सॉफ्टवेयर, जडित सॉफ्टवेयर और नेटवर्क प्रबंधन सॉफ्टवेयर के साथ-साथ तैयार उत्पाद का अंतिम संग्रहण और परीक्षण करना शामिल है। याचिकादाता, संबद्ध देशों के उत्पादक और विश्व के अन्य निर्माता सभी ऐसे मिश्रित क्रिया कलापों को करते हैं।
- x. इसके उत्पादन की प्रक्रिया को मूल अंतिम निर्णय में उल्लिखित मानदंड के पन्द्रह कार्यों में विभाजित किया जा सकता है।
- xi. उत्पाद का कोई भी उपभोक्ता किसी भी पक्षकार को आर्डर देने से पहले उपरोक्त मिश्रित कार्यों पर बल देता है। इसके अतिरिक्त भारत में कुछेक उपभोक्ता विक्रियों और सहायता पर भी बल देते हैं जो कि भारत में कुछेक को दी जा रही हैं। इसलिए संबद्ध देशों के उत्पादकों ने अपने निजी/संबंधित उद्यमों को भारत में भी स्थापित किया हुआ है ताकि विक्री और सहायिक सेवा सेवाएं प्रदान की जा सकें।
- xii. संबद्ध वस्तुओं के डिजाइन और विकास में अनुसंधान और विकास के काफी संसाधनों को प्रयुक्त किया जाता है। याचिकादाता ने इसमें अनेक वर्षों से काफी बौद्धिक सम्पदा विकसित की है। इसी प्रकार से विदेशी उत्पादकों ने भी इस क्षेत्र में अनेक वर्षों से काफी बौद्धिक सम्पदा विकसित की है।
- xiii. इस उद्योग में याचिकादाता और विश्व भर के व्यवसायिक, संघटकों के विनिर्माण के काफी बड़े भाग को बाह्य स्रोत विशेषीकृत उत्पादकों (इलेक्ट्रॉनिक संविदा विनिर्माताओं) से प्राप्त करते हैं। ऐसी कंपनियां जो कि संघटक विनिर्माण के काफी भाग के क्रियाकलाप करती हैं, चाहे वे कार्यों की संसाधक ही क्यों नहीं हों, उनको उत्पाद में निहित प्रौद्योगिकी और डिजाइन तथा विकास के बारे में ज्ञान नहीं होता है। ऐसे कार्यों की संसाधक कंपनियों में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक बौद्धिक सम्पदा के ज्ञान की कमी होती है।

- xiv. पाटन-रोधी भारतीय नियम और विश्व व्यापार संगठन के करार में विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र के बारे में किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान निर्धारित नहीं है, और न ही उसमें ऐसा कोई प्राचल निर्धारित है, जिसके आधार पर विचाराधीन उत्पाद का परिभाषित/विनिश्चित करने पर विचार किया जा सके।
- xv. याचिकादाता ने विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र के अपने दावे के समर्थन में भारत, यूरोपीय कमीशन और संयुक्त राज्य अमरीका में जांच किए गए अनेक मामलों का अनुसंधान किया है। ऐसे निर्णीत मामलों में शामिल हैं: चीन जनवादी गणराज्य से सर्टेन टो-विहाइन्ड लॉन गरूमर्स और उसके पार्टस् के मामलों में यूएस आईटीसी, चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया से डायमंड साब्लेड्स और उसके पार्टस सर्टेन टो-विहाइन्ड लॉन गरूमर्स और उसके पार्टस्, जापान से ग्रे पोर्टलैंड सीमेंट और सीमेंट क्लिंकर, चीन जनवादी गणराज्य से हैंड ट्रक और उनके कुछ पार्टस्, जापान से बड़े समाचार पत्र के प्रिंटिंग प्रेस और उसके संघटक, चाहे वे संग्रहीत हों अथवा गैर-संग्रहीत तथा जापान से मेकेनिकल ट्रांसफर प्रेस। इनके अतिरिक्त याचिकादाता ने आयरनिंग बोर्डों, स्टील ठूब और पाईप फिटिंग्स, कम्पेट डिस्क प्लेयर (सीडीपी) के मामलों में यूरोपीय कमीशन के निर्णयों का हवाला भी दिया है।
- xvi. “एसडीएच उपस्करों” में ऐसे उत्पाद भी शामिल हैं, जिनके विभिन्न रूप हैं, विभिन्न नाम हैं और जिनकी आपूर्ति विभिन्न रूपों में की गई है। ड्राप मल्टीप्लेक्सर्स, एड ड्राप मल्टीप्लेक्सर्स (एमएडीएम), मल्टीपल एड ड्राप मल्टीप्लेक्सर्स (एमएडीएम), डिजिटल क्रोस कनेक्ट्स एक ही उत्पाद के विभिन्न नाम हैं। पापुलेटिड सर्किट बोर्ड्स, पावर स्प्लाय, लेसर्स, चेसीज और सोफ्ट वेयर, एसडीएच ट्रांसमिशन उपस्कर आदि के निमित्त होते हैं और ये उत्पाद के विभिन्न सब-लेट होते हैं।
- xvii. उत्पाद की आपूर्ति संग्रहीत रूप में अथवा उत्पाद के इनके विभिन्न सब-लेट में टुकड़ों के रूप में की जा सकती है। निर्यातक उपस्कर में प्रयुक्त करने के लिए तैयार उत्पाद के रूप में अथवा उप-संग्रहीत, काडों, सीकेडी/एसकेडी दशाओं में भी इनका निर्यात कर सकता है और उनके बाकी के प्रचालन कार्य (जिनमें नगण्य मूल्य संवर्धन शामिल है) भारत में कर सकता है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पाद को विभिन्न आकारों में निर्मित भी किया जा सकता है और उसकी आपूर्ति भी की जा सकती है।
- xviii. जिस तरीके से एसडीएच उपस्कर का निर्माण और प्रयोग किया जाता है तथा विभिन्न जांच प्राधिकारियों द्वारा जांच किए गए विभिन्न मामलों में निर्णय दिया जाता है, उससे यह सिद्ध हो जाता है कि विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र मौजूदा मामले में व्यापक नहीं है। इसके अतिरिक्त विचाराधीन उत्पाद से संबंधित उत्पादन क्रिया कलापों को ध्यान में रखते हुए कल पुर्जों/संघटकों को शामिल करना पूर्णतया यथोचित है।
- xix. याचिकादाता ने एसडीएच अनुप्रयोग के लिए केवल कलपुर्जों/संघटकों पर ही पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने की मांग की है।
- xx. याचिकादाता ने फास्टनर्स के मामले में यूरोपीय कमीशन के निर्णय का हवाला दिया है और यह तर्क दिया है कि उत्पाद के कुछ विशेष प्रकार के संघटक/कलपुर्जे, किसी कंपनी को उत्पाद के उत्पादन के संरक्षण की मांग करने के लिए अयोग्य नहीं बना देते हैं। घरेलू उद्योग को उत्पाद का उत्पादन करना चाहिए और उसे बाजार में उत्पाद के कलपुर्जों की पेशकश करने की आवश्यकता नहीं है।
- xxi. याचिकादाता ने कलपुर्जों और संघटकों को शामिल किए जाने की मांग की है, क्योंकि (क) इनके डिजाइन एसडीएच उपस्करों के उत्पादन के लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं, (ख) इनका कोई अनुप्रयोग नहीं है सिवाए उत्पाद का उत्पाद करने के लिए और (ग) ऐसे उत्पाद के उत्पादन के चरण में कलपुर्जों/संघटकों/संग्रहण/उप-संग्रहण के लिए केवल स्कू चलन की प्रोद्योगिकी ही प्रयुक्त होती है और इसलिए इनको विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा जाने का स्पष्ट अभिप्राय पाटित कीमतों के आयातों को अनुमति देना जैसा होगा, जिसके परिणामस्वरूप पाटन-रोधी शुल्कों के लगे रहने के बावजूद भी इनका निरंतर पाटन होगा और क्षति होगी। घरेलू उद्योग ने यह भी प्रश्न उठाया है कि यदि विचाराधीन उत्पाद पर पाटन-रोधी शुल्क यथोचित हैं, तो ऐसे आयातों की अनुमति क्यों दी जाए और ऐसे आयात घरेलू उद्योग को क्षति क्यों नहीं पहुंचाएंगे। घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि प्राधिकारी यह विनिश्चित कर सकते हैं कि कलपुर्जों, संघटकों, उप-संग्रहणों पर ऐसे शुल्कों को घोषणा के आधार पर लागू किया जा सकता है और उन्हें सीमा शुल्क की संबद्ध अधिसूचना में विनिश्चित किया जा सकता है।
- xxii. डीडब्ल्यूडीएम मल्टीप्लेक्सर्स और पीडीएच मल्टीप्लेक्सर्स भिन्न उत्पाद हैं। प्राधिकारी विशेष रूप से इनको स्पष्ट कर सकते हैं ताकि कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनावश्यक रूप से पैदा किए गए संदेहों को दूर किया जा सके। इसके अतिरिक्त

प्राधिकारी उपयुक्त विनिर्देशनों के बारे में प्रतिवादी पक्षकारों के ऐसे अन्य तर्कों पर भी विचार कर सकते हैं और अपने अंतिम निर्णय में उनको स्पष्ट कर सकते हैं ताकि शुल्कों को लगाए जाने के समय स्पष्टता सुनिश्चित की जा सके।

- xxiii. ऐसा दावा किया गया है कि यह सुस्थापित विधि है कि उत्पाद के विनिर्देशन बने रहते हैं और सीमा शुल्क विभाग के स्पष्टीकरण केवल सुविधा के लिए ही दिए जाते हैं। यह मात्र कहने से कि उत्पाद के आयात, पाटन-रोधी शुल्क संबंधी अधिसूचना में विनिश्चित किसी वर्गीकरण के अंतर निर्दिष्ट किए गए हैं, ऐसा स्पष्ट नहीं हो जाता है कि उन पर पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाएगा।
- xxiv. हितवद्ध पक्षकारों के इन दावों के संबंध में कि कुछ उत्पादों को विशिष्ट रूप से बाहर रखा जाए, घरेलू उद्योग ने जो दावे किए हैं, वे निम्नानुसार हैं :-
- (1) *एसटीएम -1, 4 और 16* - इन किस्मों को शामिल किए जाने पर कोई विवाद नहीं है।
 - (2) *एसटीएम - 64* - घरेलू उद्योग ने इसको निर्मित किया और इसकी आपूर्ति की है। यह दावा निराधार है। कंपनी एसटीएम - 64 का उत्पादन करती है जो कि डीएक्ससी है। यह तथ्य मात्र कि मेसर्ज तेजा ने विशिष्ट ग्राहक के लिए विशिष्ट प्रकार के लिए विशिष्ट निविदा में बोली प्रस्तुत नहीं की है, का अभिप्राय यह नहीं है कि कंपनी विशिष्ट उत्पाद का उत्पादन नहीं करती है। किसी विशिष्ट निविदा में भाग नहीं लेने से यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि कंपनी ऐसे विशेष उत्पाद का उत्पादन नहीं करती है।
 - (3) *एसटीएम - 256* - भारत में अभी तक एसटीएम - 256 की कोई आवश्यकता नहीं है। एसटीएम - 256, एसडीएच उपस्कर के सिवाए और कुछ नहीं है। किसी भी उपभोक्ता ने एसटीएम - 256 को प्रयुक्त नहीं किया है और साथ ही एसटीएम - 256 प्रणाली के लिए कोई अनुमोदित विनिर्देशन (टीईसी जीआर) नहीं है। किसी उत्पादको तभी निर्मित किया जा सकता है जब उसकी मांग/आवश्यकता विद्यमान हो। ऐसा समझा जाता है कि भारत में कोई भी टेलीकोम ओपरेटर ने किसी एसटीएम - 256 प्रणाली को स्थापित किया है और यहां तक कि विश्वभर में बहुत कम टेलीकोम ओपरेटरों ने ही अपने नेट वर्क में एसटीएम - 256 प्रणाली को स्थापित किया है। मेसर्ज तेजा ने पहले से ही एसटीएम - 256 प्रणाली प्रोद्योगिकी के अनुसंधान और विकास करने के लिए बहुताधिक निवेश किया हुआ है और वह जब कभी भी आवश्यक होगा अपनी प्रणालियों में एसटीएम - 256 की क्षमताएं प्रदान कर सकती है।
 - (4) *मल्टीफ्लेक्सर्ज* - मल्टीफ्लेक्सर्ज एक व्यापक शब्दावली है। एसडीएच उपस्करों में भी मल्टीफ्लेक्सर्ज होते हैं। घरेलू उद्योग ने इनको निर्मित किया है और इनकी आपूर्ति की है। भारत में इनका आयात किया जाता है। तथापि, प्राधिकारी यह स्पष्ट कर सकते हैं कि केवल एसडीएच मल्टीफ्लेक्सर्ज की विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र के भीतर आते हैं।
 - (5) *डीडब्ल्यूडीएम* - ये एसडीएच उपस्कर नहीं हैं और विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर हैं। हितवद्ध पक्षकारों ने इसे बाहर रखने की मांग, महज भ्रम पैदा करने के लिए ही की है।
 - (6) *एसडीएच उपस्कर के कल पुर्जे और संघटक* - इन्हें बाहर नहीं रखा जा सकता है।
- xxv. अन्त्य उपभोक्ता घरेलू और विदेशी उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं का उपयोग, पारस्परिक रूप से परिवर्तनीय वस्तुओं के रूप में करते हैं। भारत में सभी प्रमुख टेलीकोम सेवा प्रदायक जैसे कि बीएसएनएल, भारती और एयरसेल हुआवाई के उत्पादों और मेसर्ज तेजा के उत्पादों का प्रयोग करते हैं और वह भी समान नेटवर्क, समान अनुप्रयोग के लिए ही और विनिर्देशनों के विरुद्ध।
- xxvi. डीडब्ल्यूडीएम प्रोद्योगिकी पर प्रयुक्त होने वाले मल्टीफ्लेक्सर्ज अथवा अन्य उपस्कर, विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। याचिकादाता एसडीएच मल्टीफ्लेक्सर्ज अथवा डीएक्ससी की आपूर्ति करता है।
- xxvii. मेसर्ज तेजा एसडीएच उत्पाद और कैरियर ईथरनेट उत्पादों दोनों का विनिर्माण करती है। मेसर्ज तेजा लागू होने वाले शुल्क का भुगतान करेगी यदि वह एसडीएच के प्रयोग के लिए मूल दोहरे प्रयुक्त होने वाले संघटक हैं और यदि ये विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र के भीतर आते हैं। याचिका केवल एक वस्तु के संबंध में ही है, जो कि वास्तव में विभिन्न रूपों में उपलब्ध है। नियमों में किसी भी जगह ऐसा उल्लेख नहीं है कि किसी वस्तु के विभिन्न रूपों को विचाराधीन उत्पाद के

कार्य—क्षेत्र के भीतर उसके विभिन्न रूपों में शामिल करने से रोका जाए। अभी तक मुश्किल से ऐसी कोई जांच होगी जिसमें विचाराधीन उत्पाद के भीतर उसके विभिन्न रूप शामिल नहीं किए गए हों।

- xxviii. एसडीएच उपस्कर, उसके उपकरण, सहयोजित सॉफ्टवेयर, कल-पुर्जे और संघटक, पापुलेटिड सर्किट पीसीबी, पावर सप्लाय, लेसर्ज, चेसीज, ई 1 केबिल्स, पीसीएम केबिल्स, पावर केबिल्स, रैक्स संग्रहीत रूप से एक एसडीएच उपस्कर के रूप में बनते हैं (जिसमें वर्क स्टेशन शामिल नहीं है)। पृथक् रूप से इसमें से किसी भी एक अंश का कोई अंत प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण के लिए एक ठूब लाईट में एक ठूब, एक चोक, एक स्टार्टर और एक बेस की जरूरत होती है यह नहीं कहा जा सकता है कि इन चारों मदों में से प्रत्येक मद विभिन्न मद है, महज इसलिए क्योंकि उनकी अपनी निजी विशेषता है।
- xxix. विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले उत्पाद को नियम 5 में उल्लिखित प्रावधान को संतोषजनक ढंग से पूरा करना होता है और न कि विचाराधीन उत्पाद के पृथक् रूप में। विचाराधीन उत्पाद एसडीएच ट्रांसमिशन उपस्कर है। जब “एसडीएच-1 इंटरफेस” के साथ “विभिन्न प्रोद्योगिकी की उपस्कर” का आयात किया जाता है, तो “विभिन्न प्रोद्योगिकी की उपस्कर” के समस्त मूल्य पर शुल्क नहीं लागू होंगे, लेकिन एसडीएच-1 प्रोद्योगिकी से संबंधित कलपुर्जों पर ही ये लागू होंगे।

ग. 2. निर्यातकों/आयातकों/प्रयोक्ताओं/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

10. विचाराधीन उत्पाद और उसके कार्य-क्षेत्र के संबंध में निर्यातकों/आयातकों/प्रयोक्ताओं/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-
- (1) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित उत्पाद के कार्य-क्षेत्र और जिसके आधार पर मौजूदा जांच शुरू की गई है, उसके उत्पाद के कार्य क्षेत्र के बीच असमानता है और इसलिए “उपयुक्त वास्तविक अनुरोध” पर स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। निर्णायक समीक्षा जांच में उत्पाद का कार्य-क्षेत्र समान होना चाहिए जैसा कि मूल जांच में है। घरेलू उद्योग ने उत्पाद के कार्य क्षेत्र के बारे में निर्णायक समीक्षा जांच करने का अनुरोध किया है, जो कि विचाराधीन उत्पाद जिस पर इस समय शुल्क लागू होता है, से काफी व्यापक है। तथापि, ऐसी जांच की शुरुआत उपरोक्त याचिका के आधार पर ही स्वतः शुरू की गई है तो मौजूदा जांच की शुरुआत पाटन-रोधी नियमावली की अपेक्षाओं का उल्लंघन करना है विशेषकर क्योंकि मौजूदा याचिका विभिन्न प्रकार के उत्पाद के लिए है और इसलिए “उपयुक्त वास्तविक अनुरोध” पर स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि मूल जांच में उत्पाद के कार्य-क्षेत्र की तुलना में विभिन्न उत्पाद के कार्य-क्षेत्र के लिए शुल्कों को किसी भी प्रकार से जारी नहीं रखा जा सकता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी, एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी होने के नाते अपने पहले निर्णयों से विचलित नहीं हो सकते हैं और वे सामंजस्य और भविष्यवाणी को बनाए रखने के लिए अपने निर्णयों का अनुसरण करने के लिए बाध्य हैं। प्रचलित पद्धति के अनुसार विगत में भी प्राधिकारी ने यह माना है कि उक्त उत्पाद के कार्य-क्षेत्र को पुनरीक्षाओं में बढ़ाया नहीं जा सकता है।
 - (2) निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया नहीं जा सकता है और उसके कार्य-क्षेत्र के भीतर किसी अन्य उत्पाद को शामिल नहीं किया जा सकता है। आरोपित घरेलू उद्योग ने प्रिंटेड सर्किट बोर्डों जिन्हें बेयर बोर्ड भी कहा जाता है, को शामिल करने के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद में विस्तार करने की मांग की है। मूल अंतिम निर्णयों के अनुसार आरोपित घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देश (चीन) में प्रिंटेड सर्किट बोर्डों का उत्पादन किया जा रहा है।
 - (3) आवेदक को अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं के विनिर्देशन और निर्यात की मात्रा सहित कारोबार-वार सूचना प्रकट करनी चाहिए ताकि अन्य हितबद्ध पक्षकार को भी यह देखने का अवसर मिले कि क्या आवेदक द्वारा किए गए आयात विचाराधीन उत्पाद हैं अथवा नहीं। ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्राधिकारी को आवेदक के अपुष्ट दावों को स्वीकार नहीं करना चाहिए।
 - (4) आवेदक न तो एसटीएम - 64 और एसटीएम - 256 का निर्माण करता है और न ही इन उत्पादों को बेचता है। इसलिए आवेदक द्वारा यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि इन उत्पादों के आयातों के कारण उसकी क्षति हो रही है। डीजीएडी को उत्पादों को ऐसे गलत और गैर-कानूनी ढंग से विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र के भीतर शामिल नहीं करना चाहिए।
 - (5) आरोपित घरेलू उद्योग ने मूल जांच में यह दावा किया था कि उसने बीएसएनएल को एसटीएम - 64 की वाणिज्यिक मात्राओं में आपूर्ति की थी। घरेलू उद्योग ने अब तक एसटीएम - 64 की किसी भी निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है। इसकी संपुष्टि बीएसएनएल द्वारा दिनांक 17.10.2009 के पत्र द्वारा कर दी गई थी। तदनुसार आरोपित घरेलू उद्योग द्वारा बीएसएनएल को एसटीएम - 64 की वाणिज्यिक आपूर्ति करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। डीजीएडी ने अंतिम निर्णय में अपने रवैये में परिवर्तन कर दिया है और यह दावा किया है कि मौके पर जांच करने पर उसने यह पाया था कि ऐसे उत्पाद की वाणिज्यिक आपूर्तियां क्विकटेल (और न कि बीएसएनएल) को की गई थीं। बीएसएनएल से क्विकटेल

- नामक किसी भी कंपनी ने कोई आर्डर प्राप्त नहीं किए थे। इसलिए यह निवेदन किया जाता है कि इस संबंध में आरोपित घरेलू उद्योग का दावा पूर्णतया झूठा और दुर्भावपूर्ण है।
- (6) आरोपित घरेलू उद्योग ने एसटीएम - 64 के लिए कभी भी भारतीय घरेलू बाजार में प्रवेश नहीं किया है और एसटीएम - 256 का भारत में कभी भी आयात नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त भारत में अभी भी एसटीएम - 256 प्रयुक्त किए जाने के लिए तकनीकी अनुमोदन नहीं किया जाता है/अनुमति नहीं दी जाती है। जब इस मूल शर्त को ही पूरा नहीं किया जाता है, तो एसटीएम - 256 को विचाराधीन उत्पाद में शामिल करने और उस पर पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।
- (7) इसके अतिरिक्त याचिका में आवेदक ने यह स्वयं स्वीकार किया है कि एसटीएम -1, 4, 14, 64 और 256 आदि पर्याप्त रूप से भिन्न वस्तुएं हैं। इसलिए इन उत्पादों को आवेदक द्वारा अपनी याचिका में विचाराधीन उत्पाद की व्यापक श्रेणी में एक साथ शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। एसटीएम - 256 का न ही भारत में कभी भी आयात हुआ है और न ही उसे प्रयुक्त किया गया है। इसलिए एसटीएम - 256 को विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र के भीतर शामिल करना उचित नहीं होगा।
- (8) एसटीएम - इंटरफेस अन्य दूरसंचार उपस्करों में भी हो सकते हैं और यह जरूरी नहीं है कि ऐसे एसटीएम - इंटरफेस केवल एसटीएम - 1 इंटरफेस ही हों। इसलिए एसडीएच से भिन्न अन्य किसी भी प्रकार के उत्पाद को, जो कि एसडीएम ट्रांसमिशन उपस्कर में प्रयुक्त एसटीएम - इंटरफेस हो सकता है और वह रेडियो और एसडीएच उपस्कर के बीच कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए वास्तविक मीडिया के रूप में काम कर सकता है, विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।
- (9) आवेदक द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद की वही वास्तविक और तकनीकी विशेषताएं नहीं हैं। आवेदक द्वारा प्रयुक्त प्रोद्योगिकी पुरानी है तथा यह कम एंड के एसडीएच उपस्कर की आपूर्ति करता है जबकि भारत से बाहर के निर्यातक सभी श्रेणियों के उपस्कर विनिर्मित करते हैं जो कि एकल नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली (एनएमएस) अथवा प्रचालन सहायता प्रणाली (ओएसएस) में संचालित हो सकते हैं।
- (10) अंतिम निर्णय के प्रकाशन के बाद आवेदक द्वारा विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा के भीतर कुछ उत्पादों को, हमें सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना गलती से शामिल कर लिया गया है। जैसा कि याचिका में भी उल्लेख किया गया है, एसडीएच मानक आईटीयू-टी मानक संख्या जी 707 पर आधारित है। इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि विशेष रूप से ओटीएन को विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा जाए क्योंकि न तो यह एसडीएच उत्पाद है और न ही यह आईटीयू-टी मानक संख्या जी 707 पर आधारित है, जो कि एसडीएच के निमित्त है लेकिन विचाराधीन उत्पाद से उसे विशेष रूप से बाहर कर दिए जाने के कारण यह सीमा शुल्क के प्राधिकारियों में भ्रम पैदा कर रहा है।
- (11) पीटीएन को मूलतः दिनांक 16.10.2010 के अंतिम निर्णयों की टिप्पणी संख्या 4 के अनुसार सूची से बाहर रखा गया था, लेकिन संशोधन द्वारा इसे बाहर की गई मदों की सूची से निकाल दिया गया था जिसके कारण भ्रम पैदा हुआ था। यह निवेदन किया जाता है कि ऐसा सुनवाई किए जाने का अवसर प्रदान किए बिना मनमाने ढंग से किया गया था। पीटीएन न तो मूल जांच का कोई भाग था और न ही इसे विकसित पीसीएन में शामिल किया गया है। पीटीएन, एसडीएच उपस्कर नहीं है और इसलिए इसे विचाराधीन उत्पाद में भी शामिल नहीं किया गया है/था और इसलिए यह उचित होगा कि प्राधिकारी इस संबंध में यथा शीघ्र स्थिति को स्पष्ट कर दें ताकि इस संबंध में व्याप्त भ्रम दूर हों और अनावश्यक मुकदमेबाजी न हो और हमारे उत्पादों को क्लियर करने में कोई विलंब नही हो।
- (12) इसके अतिरिक्त विचाराधीन उत्पादों के कार्य-क्षेत्र में प्रिंटेड सर्किट बोर्डों (पीसीबी) को इस आधार पर शामिल करने के लिए कि पीसीबीए के विनिर्माण के लिए पीसीबी का बड़ी मात्रा में आयात किया जा रहा है और पाटनरोधी शुल्क का भुगतान करने से बचा जा रहा है, का मौजूदा अनुरोध अनुचित है। यह निवेदन किया जाता है कि मूल जांच के अंतिम निर्णय के प्रारंभिक निर्णयों में आवेदक द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया है कि आवेदक ने स्वयं चीन से पीसीबी के आयात किए हैं और आवेदक ने अब इसी मुद्दे को डीजीएडी पर दबाव डालने के लिए उठाया है, ताकि उसका ध्यान ऐसे पीसीबीए (पापुलेटिड सर्किट बोर्ड असेम्बलीज) से हटा दिया जाए जिसे आवेदक द्वारा विनिर्मित नहीं किया जा रहा है और उसे विचाराधीन उत्पाद के भीतर ही बना रहने दिया जाए।
- (13) इसके अतिरिक्त सीमा शुल्क की दिनांक 16.12.2010 की अधिसूचना संख्या 125/2010 के बावजूद जिसमें पापुलेटिड सर्किट बोर्ड असेम्बलीज के संबंध में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जब उनका आयात उपस्कर के साथ अथवा उसकी असेम्बली और सब-असेम्बली के साथ किया जाता है, तो इन्हें केवल एसडीएच अनुप्रयोग के लिए ही प्रयुक्त किया जाएगा,

सीमा शुल्क ने आगे की कार्रवाई की है और ऐसे पीसीए पर शुल्क की मांग की है, जबकि उनका आयात एसडीएच उपस्करों के साथ नहीं किया जा रहा है।

- (14) पीसीएन का वर्गीकरण, संबंधित उत्पाद की विशेषताओं को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है। पीसीएन, विचाराधीन उत्पाद को अनेक उप-श्रेणियों में वर्गीकृत करके पाटन-रोधी जांच में उचित तुलना किए जाने के प्रयोजन को पूरा करता है जो कि प्रत्येक विनिश्चित पीसीएन के बीच लागत और कीमत के अंतर को अनिवार्य रूप से प्रतिबिंबित करने के लिए आवश्यक है। तथापि, कंपनी की लेखाकरण प्रणाली, क्रियाकलापों की विक्री, लागत ढांचा और प्रबंधन की स्थापना पीसीएन के आधार पर नहीं की जाती है क्योंकि जो कंपनी विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने में लगी होती है, वह उचित प्रचालन करने के लिए संबंधित उपस्कर की स्थापना की प्रगति के साथ-साथ समग्र लाभ अर्जित करने में इच्छुक होती है।
- (15) संघटकों को शामिल किए जाने के संबंध में मौजूदा जांच में स्पष्टता की कमी है। प्राधिकारी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि मौजूदा कार्य-क्षेत्र में केवल संपूर्ण एसडीएच उत्पाद ही शामिल हैं और उसके संघटक नहीं। यदि आवश्यक हो तो संघटकों को भी शामिल किया जा सकता है। तब प्राधिकारी को यह स्पष्ट करना होगा कि विशेष रूप से एसडीएच के लिए ही प्रयुक्त किए जाने वाले संघटक ही उत्पाद के कार्य-क्षेत्र का भाग हैं।
- (16) विचाराधीन उत्पाद में डीएक्ससी को इस आधार पर गलती से शामिल किया गया है कि यह एक एसडीएच ट्रांसमिशन उपस्कर है। डीएक्ससी एक एसडीएच ट्रांसमिशन उपस्कर नहीं है। एसडीएच ट्रांसमिशन उपस्कर की तुलना में इसके कार्य भिन्न हैं। जबकि किसी एसडीएच ट्रांसमिशन उपस्कर का प्रयोग, मल्टीफ्लेक्सिंग और परिवहन अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, डीएक्ससी का प्रयोग परियात की देखभाल करने और स्विचिंग कार्यों के लिए किया जाता है। घरेलू उद्योग ने एसडीएच ट्रांसमिशन उपस्कर से संरक्षण की मांग की है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद में उसको एक स्विचिंग उपस्कर के रूप में गलती से शामिल किया गया है। जबकि प्रत्येक एसटीएम उपस्कर के कुछ डिजिटल क्रॉस कनेक्ट करने के कार्य होते हैं, डीएक्ससी एक विशिष्ट उपकरण होता है जिसे केवल क्रॉस कनेक्ट कार्य करने के लिए ही बनाया जाता है। तदनुसार यह निवेदन किया जाता है कि डीएक्ससी एक एसडीएच ट्रांसमिशन उपस्कर नहीं है। जबकि एसडीएच ट्रांसमिशन उपस्कर का उपयोग मल्टीफ्लेक्सिंग और परिवहन अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, डीएक्ससी का प्रयोग परियात की देखभाल करने और स्विचिंग कार्यों के लिए किया जाता है। उपरोक्त तथ्य के प्रति किसी प्रकार का पक्षपात किए बिना यह निवेदन किया जाता है कि आरोपित घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग ने एसडीएच ट्रांसमिशन उपस्कर से संरक्षण की मांग की है। तथापि विचाराधीन उत्पाद में इसे एक स्विचिंग उपस्कर के रूप में गलती से शामिल किया गया है। इसके साथ ही यह भी निवेदन किया जाता है कि जबकि प्रत्येक एसटीएम उपस्कर के कुछ डिजिटल क्रॉस कनेक्ट करने के कार्य होते हैं, डीएक्ससी एक विशिष्ट उपकरण होता है जिसे केवल क्रॉस कनेक्ट कार्य करने के लिए ही बनाया जाता है। तदनुसार यह निवेदन किया जाता है कि डीएक्ससी एक एसडीएच ट्रांसमिशन उपस्कर नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह निवेदन किया जाता है कि एसडीएच ट्रांसमिशन उपस्कर और पाटन-रोधी शुल्क को केवल एसडीएच तक ही सीमित रखा जाए।
- (17) विचाराधीन उत्पाद का विवरण सीमाशुल्क के प्रयोजनार्थ कोई स्पष्ट स्थिति प्रदान नहीं करता है। इसलिए डीजीएडी से यह अनुरोध है कि विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र को तकनीकी विनिर्देशनों की यथार्थ स्थिति के साथ स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि सीमा शुल्क के प्राधिकारियों द्वारा विचाराधीन उत्पाद का विवेचन करने में कोई भ्रान्ति नहीं हो। कृपया यह निर्धारित किया जाए कि न तो ओटीएन और न ही डीडब्ल्यूडीएम के उपस्कर को जो कि एसडीएच से भिन्न होते हैं, न ही कार्ड, उनमें प्रयुक्त होने वाले पीसीबी जिनके फलस्वरूप गैर-एसडीएच आउटपुट होती है, को विचाराधीन उत्पाद माना जाए।
- (18) याचिकादाता का यह दावा कि विभिन्न भागों में संघटक के रूप में भारत में आयातित एसडीएच उपस्कर को विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जाए, गुण-दोष रहित है। ऐसे संघटकों और कलपुर्जों को जिन्हें कि उपस्करों/उसके संग्रहणों/उप-संग्रहणों के साथ आयातित नहीं किया जाता है अथवा जिन्हें अकेले आधार पर आयातित किया जाता है, जांच के अधिकार-क्षेत्र से बाहर रखा जाता है। इसलिए यह अनुरोध है कि उत्पाद के कार्य-क्षेत्रको स्पष्ट किया जाए।
- (19) सीमा शुल्क विभाग ऐसे संघटकों/कलपुर्जों जिन्हें अकेले आधार पर आयातित किया जाता है और ऐसे अन्य उत्पादों जिन्हें विचाराधीन उत्पाद से अधिकार-क्षेत्र से बाहर है, पर भी पाटन-रोधी शुल्क वसूल कर रहा है। इसलिए अनुरोध है कि यदि प्राधिकारी इस समय लागू शुल्कों को बढ़ाने का निर्णय लेते हैं तो कृपया उत्पाद के कार्य-क्षेत्र को स्पष्ट किया जाए ताकि हितवद्ध पक्षकारों को इस जांच के अधिकार-क्षेत्र से बाहर के उत्पादों पर पाटन-रोधी शुल्कों का भुगतान करने के रूप में अनुचित कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े।

- (20) इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन है कि घरेलू उद्योग द्वारा क्रोस कनेक्ट के लिए स्वीकार की गई उनके एसडीएच की क्षमता, एसटीएम-64 के लिए अधिकतम 320 जी है। आरोपित घरेलू उद्योग के संबद्ध उत्पादों (टीजे 1400, टीजे 1600, टीजे 1400 पीटीएन, टीजे 1600 पीटीएन, टीजे 1100, टीजे 1270, टीजे 1100 एमई, टीजे 1500, टीजे 1600, टीजे 2031, टीजे 2051, टीजे 5500) जो कि उनकी बेवसाईट पर उपलब्ध हैं, को देखने से ऐसा पता चला है कि उसने 1000जी तक की उच्चतर प्रोद्योगिकी को विकसित नहीं किया, जैसा कि उसने व्यक्तिगत सुनवाई में दावा किया था। यदि घरेलू उद्योग ने ऐसी तकनीकी उच्चतर स्थिति को प्राप्त कर लिया है तो इसका उल्लेख उसे अपनी बेवसाईट पर भी करना चाहिए था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमताओं से संबद्ध ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं/सूचना प्रस्तुत नहीं की है, सिवाए इसके कि उसने इनका दावा व्यक्तिगत सुनवाई में ही किया है और इसके बारे में कोई भी सूचना उसकी बेवसाईट सहित किसी भी सार्वजनिक स्थल पर उपलब्ध नहीं कराई गई है, उपभोक्ता की आपूर्ति के प्रमाण की तुलना में इस संबंध में आरोपित घरेलू उद्योग के दावे की जांच डीजीएडी द्वारा की जाए।
- (21) इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि एसडीएच के अनुप्रयोग के लिए भी जहां आवश्यकता 320 जी से अधिक की क्षमता वाले किसी भी उपस्कर सहित 1.2 टीबी है, प्रत्यक्षतः घरेलू उद्योग ऐसे उपस्कर की आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं है और इस कारणवश ऐसे उपस्कर को स्वतः ही किसी भी प्रकार के पाटन-रोधी शुल्क को लगाए जाने से क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाना होगा। इस प्रकार दिए गए उदाहरण में एसडीएच विनिर्देशन का उपस्कर होने पर भी उस पर पाटन-रोधी शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। इसी प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा एसटीएम-1, एसटीएम-4 और एसटीएम-16 के लिए उपलब्ध कराई गई अधिकतम क्रोस कनेक्ट क्षमता को ध्यान में रखते हुए केवल ऐसे क्रोस कनेक्ट क्षमताओं पर ही पाटन-रोधी शुल्क प्रतिबंधित होने चाहिए और आरोपित घरेलू उद्योग के ऐसा निराधार दावे की बजाए वास्तविक स्थिति पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए कि घरेलू उद्योग को उच्चतर गति के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ऐसा उसने उपभोक्ताओं के बीच भी स्वीकार किया है।
- (22) यह निवेदन किया जाता है कि ऐसी कोई भी आयातित मद जो कि केवल एसडीएच अनुप्रयोग के लिए नहीं है, दिनांक 16.12.2010 की अधिसूचना संख्या 125/2010-सीमा शुल्क के अंतर्गत पाटन-रोधी शुल्क के अध्याधीन नहीं हो सकती है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद की अस्पष्ट परिभाषा के कारण यह देखा गया है कि सीमा शुल्क प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा का विवेचन करने से कहीं ऊपर चले गए हैं और उन्होंने ऐसा मान लिया है कि ओटीएन और डीडब्ल्यूडीएम श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र के ही भीतर आती हैं। उदाहरण के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने ओएसएन 9500 काडों के संबंध में जिनका उपयोग डीडब्ल्यूडीएम की आउटपुट के लिए किया जाता है, हितबद्ध पक्षकारों को इस आशय कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि उनके द्वारा पाटन-रोधी शुल्क का भुगतान क्यों नहीं किया जाए।
- (23) कुछ ऐसे आयातों पर भी शुल्कों की मांग की गई है, जिनमें जी. 707 पर आधारित एसटीएम-64 से भिन्न सपोर्ट लाईनों दूरों को समर्थित करने वाले रंगीन ओटीएन लाईन काडर्स शामिल हैं। इस प्रकार यदि आयातित उपस्कर का डिजाइन जी. 709 और जी. 694 प पर आधारित ओटीएन लाईनों की दूरों और जी. 694 पर आधारित रंगीन इंटरफेज को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है, जो कि एसडीएच नहीं है और साफ तौर पर पाटन-रोधी शुल्कों के कवरेज से बाहर है, उन पर भी सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने शुल्क लगाने का प्रयास किया है।
- (24) जैसा कि अंति निर्णय के लागू होने वाले भाग की टिप्पणी संख्या 5 में पहले से ही माना गया है कि माईक्रोवेव रेडियो टर्मिनल जो कि एसडीएस ट्रांसमिशन उपस्कर का एक एसटीएम-1 इंटरफेस हो सकते हैं और जो रेडियो और एसडीएच उपस्कर के बीच संपर्क स्थापित कर सकने में वास्तविक साधन होते हैं, ये पाटन-रोधी शुल्क का भुगतान करने के अधिकार-क्षेत्र से बाहर हैं, इसी प्रकार का स्पष्टीकरण इन कार्रवाईयों के दौरान भी किया जाना चाहिए कि ऐसे इंटरफेस जो कि एसडीएच उपस्कर विशिष्ट नहीं हैं, उन्हें विचाराधीन उत्पाद उत्पाद के भाग के रूप में नहीं माना जाना चाहिए जैसे कि राउटर्स, ओटीएन, डीडब्ल्यूडीएम, सीडब्ल्यूडीएम, एमएस-ओटीएन, पीटीएन, स्विचिजस्विचिज, एमपीएलएस, एमपीएलएस-टीपी, जीपीओएन, डीएसएलएम, एमएसएएन, बीआईटीएस, डीएलसी, बीएससी, एमएससी, एसजीएसएन, पीडीएसएन, एलएलआर, एचएसएस, एमआरपी, एमजीडब्ल्यू, और माइक्रावेव आदि अथवा किसी भी प्रकार के एसटीएम इंटरफेस जैसे कि एसटीएम-1, 4, 64 और 256 वाले एसडीएच से भिन्न अन्य प्रकार के दूरसंचार के उपस्कर जो कि उपरोक्त उत्पादों और एसडीएच उपस्कर के बीच कनेक्टिविटी समर्थ बनाने के लिए वास्तविक माध्यम के रूप में कार्य करते हैं, पाटन-रोधी शुल्क के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, क्योंकि विगत में ऐसा उपयुक्त वर्गीकरण नहीं होने के फलस्वरूप मुकद्देबाजी हुई है।

- (25) हितबद्ध पक्षकारों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में ऐसा भी दृढ़ विश्वास किया गया है कि कार्डों को स्वतः ही एसडीएच उपस्कर के रूप में माना जाता है, जो कि मूलतः गलत है।
- (26) इसके अतिरिक्त दिनांक 16.12.2010 की अधिसूचना संख्या 125/2010-सीमा शुल्क के बावजूद भी जिसके अंतर्गत पापुलेटिड सर्किट बोर्ड असेम्बलीज के बारे में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यदि उनका आयात उपस्करों अथवा उसके संग्रहण अथवा उप-संग्रहण के साथ किया जाता है तो वे केवल एसडीएच अनुप्रयोग के निमित्त ही हैं, सीमा शुल्क प्राधिकारी इससे भी आगे चले गए और उन्होंने ऐसे पीसीबीए पर शुल्क की मांग की है, भले ही उनका आयात एसडीएच ट्रांसमिशन उपस्कर के साथ नहीं किया जाता है।
- (27) कृपया यह समझा जाए कि एसडीएच ट्रांसमिशन उपस्कर पर पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने से संबंधित मौजूदा अधिसूचना के परिणामस्वरूप वास्तव में पाटन-रोधी शुल्क एसडीएच उत्पाद की बजाय एसडीएच प्रौद्योगिकी पर लगाया गया है। इसलिए यह अत्यावश्यक है कि विचाराधीन उत्पाद की सभी संदिग्धताओं को दूर करने के लिए इन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए ताकि इसमें क्षण मात्र भी संदेह बचा नहीं रहे। सीमा शुल्क के अंतर्गत कर निर्धारण की स्कीम, उत्पादों के वर्गीकरण पर आधारित है न कि प्रौद्योगिकी पर। इसलिए उत्पाद को ठीक तरह से परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है और न कि प्रौद्योगिकी द्वारा।
- (28) जब कभी भी एसडीएच उपस्कर के आयात पावर केबल्स, चेसीज, पैच कार्ड्स, कनेक्टर्स, रैक आदि जैसी मदों के रूप में किए जाते हैं, तो ऐसी मदों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इन्हें उपकरण माना जाता है। इसके परिणामस्वरूप यदि डीडब्ल्यूडीएम/ओटीएन आदि प्रौद्योगिकी के उपस्कर का आयात किया जाता है तो सीमा शुल्क विभाग की ओर से पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने का कोई भी प्रयास ऐसा कारण बताते हुए कि कुछ इंटरफेस की उनमें एसडीएच प्रौद्योगिकी निहित है को प्राधिकारी द्वारा इन कारणों से कृपया कठोरता पूर्वक असंगत और निंदनीय घोषित किया जाना चाहिए कि आयातित मदें पूर्णतया भिन्न प्रौद्योगिकी की हैं और इसका कोई भी अंश इन कारणों से पाटन-रोधी शुल्क के अध्वधीन नहीं हो सकता है कि ऐसे उपस्कर शीर्ष 851762 के अंतर्गत नहीं आते हैं जिनमें एसडीएच उपस्कर को शामिल किया जाता है और साथ ही इस कारण से कि इन उपस्करों में इंटरफेस कभी भी केवल एसडीएच अनुप्रयोग के लिए नहीं कहे जा सकते हैं जो कि पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने का मुख्य मानदंड है। सीटीए के सामान्य रूप से प्रतिपादित नियमों के अनुसार भी समग्र डीडब्ल्यूडीएम/ओटीएन उपस्कर के साथ उसके संघटकों की अत्यावश्यक विशेषता उनके केवल डीडब्ल्यूडीएम/ओटीएन के निमित्त होना है और इस कारणवश भी डीडब्ल्यूडीएम/ओटीएन उपस्कर के किसी भी भाग को, एसडीएच प्रौद्योगिकी के परिचायक के रूप में पाटन-रोधी शुल्क के अध्वधीन नहीं माना जा सकता है।

ग. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

11. अनेक हितबद्ध पक्षकारों ने अनेक आधार पर विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र का प्रतिवाद किया है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि चूंकि मौजूदा जांच पहले से ही लगाए गए पाटन-रोधी शुल्क निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र सामान्यतया वही बने रहने दिया जाना चाहिए जो कि मूल जांच में है। तथापि, कुछेक हितबद्ध पक्षकारों ने “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “संबद्ध वस्तुओं” की श्रेणी में कुछ किस्मों के उत्पादों को शामिल किए जाने का दृढ़ता से प्रतिवाद किया है और उत्पाद के कार्य-क्षेत्र पर और साथ ही कुछ प्रकार के उत्पाद को बाहर किए जाने पर कुछ स्पष्टीकरण देने की मांग की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिकतर ऐसे निवेदन दोहराए गए हैं क्योंकि ऐसे ही निवेदन पहले भी मूल जांच के दौरान दिए गए हैं और प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी को उनमें ठोस प्रमाण के रूप में कुछ भी नया प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि मौजूदा निर्णायक जांच समीक्षा में उत्पाद के कार्य-क्षेत्र भी कोई परिवर्तन किया जा सके। प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दे जिनका हालांकि पहले से निदान कर दिया गया है, निम्नानुसार हैं:-

- (क) *एसटीएम – 64* : याचिकादाता मेसर्स तेजा नेटवर्क ने एसटीएम – 64 का निर्मित किया है और उसे भारतीय और विदेशी बाजारों में बेचा है जिसकी प्राधिकारी द्वारा जांच कर ली गई थी, इसलिए इसे उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर नहीं किया जाएगा और यह विचाराधीन उत्पाद का ही भाग बना रहेगा।
- (ख) *एसटीएम – 256* : यह स्वीकार्य है कि निर्णायक जांच समीक्षा की अवधि के दौरान एसटीएम – 256 का न ही आयात किया गया है और न ही उसकी आपूर्ति घरेलू उद्योग द्वारा की गई है। वास्तव में हितबद्ध पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि देश में एसटीएम-256 को प्रयुक्त किए जाने का अभी तक तकनीकी अनुमोदन नहीं किया गया है/अनुमति नहीं दी गई है। तथापि, प्राधिकारी यह पाते हैं कि विशेष प्रकार के उत्पाद को बाहर करने के दावे पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता है जब तक कि संबद्ध अवधि के दौरान उसे भारत में निर्यात नहीं किया गया हो। तथ्य तो यह है कि घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु की गैर-आपूर्ति को तब तक सिद्ध नहीं किया जा सकता है जब तक कि इस प्रकार की वस्तु का निर्यात भारत में नहीं कर दिया जाता है। इसलिए प्राधिकारी की

यह धारणा है कि मौजूदा निर्णायक जांच समीक्षा में उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से एसटीएम- 256 को बाहर किए जाने का कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- (ग) पीटीएन : प्रतिवादी हितवद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में कि एसडीएच और पीटीएन पूर्ण रूप से अलग-अलग प्रौद्योगिकियां हैं जो कि अलग-अलग जरूरतों की पूर्ति करती हैं और इस प्रकार से इन्हें निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह मामला पहले से ही पूर्व अन्तिम जांच परिणाम में निपटा लिया गया है और वर्तमान जांच चूंकि निर्णायक समीक्षा जांच है, प्राधिकारी ड्यूटी टेबल में नोट 4 को बनाए रखेंगे, क्योंकि इसका दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 की अन्तिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/2/2009-डीजीएडी, जिसे दिनांक 22 अक्टूबर, 2010 के शुद्धि पत्र संख्या 14/2/2009 के साथ पढ़ा जाए और उसे आगे दिनांक 10 फरवरी, 2012 के अन्तिम निर्णय संबंधी अधिसूचना संख्या 14/2/2009 के साथ पढ़ा जाए, में उल्लेख था।
- (घ) डिजिटल क्रॉस कनेक्ट्स (डीएक्ससी) : हितवद्ध पक्षकारों द्वारा डिजिटल क्रॉस कनेक्ट्स को बाहर निकलने का तर्क दिया गया है। विगत निर्णयों में यह बताया गया है कि जांच से ऐसा पता चला है कि डिजिटल क्रॉस कनेक्ट्स वास्तव में ऐसा उपस्कर है जिसका दूरसंचार नेटवर्क में उपयोग करने से निम्न स्तर के सिग्नलों को पुनः व्यवस्थित किया जाता है और उन्हें उच्चतर-स्तर के सिग्नलों के साथ पारस्परिक रूप से जोड़ा जाता है। डिजिटल क्रॉस कनेक्ट्स को एसडीएच प्रौद्योगिकी अथवा अन्य प्रौद्योगिकियों में निर्मित किया जा सकता है। एसडीएच प्रौद्योगिकी के डिजिटल क्रॉस कनेक्ट्स स्पष्ट रूप से एसडीएच उपस्कर होते हैं। जांच अवधि के दौरान एसडीएच प्रौद्योगिकी के डिजिटल क्रॉस कनेक्ट्स को निर्मित किया गया है और उनकी आपूर्ति की गई है। क्षति और क्षति मार्जिन का मूल्यांकन करने संबंधी सूचना में शामिल लागत और कीमत संबंधी सूचना में एसडीएच प्रौद्योगिकी के डिजिटल क्रॉस कनेक्ट्स के उत्पादन और बिक्री की सूचना निहित है। इसलिए प्राधिकारी की यह धारणा है कि एसडीएच प्रौद्योगिकी के डिजिटल क्रॉस कनेक्ट्स सही रूप से विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र के भीतर आते हैं। तथापि, क्योंकि डिजिटल क्रॉस कनेक्ट्स को अन्य प्रौद्योगिकियों में भी निर्मित किया जाता है, इसलिए यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अन्य प्रौद्योगिकियों के डिजिटल क्रॉस कनेक्ट्स विचाराधीन उत्पाद और मौजूदा निर्णायक जांच समीक्षा के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं।
- (ङ) कलपुर्जे और संघटक : याचिकादाता ने कलपुर्जे और संघटकों को शामिल किए जाने कि पुनः मांग की है, क्योंकि (क) इनके डिजाइन एसडीएच उपस्करों के उत्पादन के लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं, (ख) इनका कोई अनुप्रयोग नहीं है सिवाए उत्पाद का उत्पाद करने के लिए और (ग) ऐसे उत्पाद के उत्पादन के चरण में कलपुर्जे/संघटकों/संग्रहण/उप-संग्रहण के लिए केवल स्क्रू चलन की प्रौद्योगिकी ही प्रयुक्त होती है और इसलिए इनको विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा जाने का स्पष्ट अभिप्राय पाटित कीमतों के आयातों को अनुमति देना जैसा होगा, जिसके परिणामस्वरूप पाटन-रोधी शुल्कों के लगे रहने के बावजूद भी इनका निरंतर पाटन होगा और क्षति होगी। घरेलू उद्योग ने यह भी प्रश्न उठाया है कि यदि विचाराधीन उत्पाद पर पाटन-रोधी शुल्क यथोचित हैं, तो ऐसे आयातों की अनुमति क्यों दी जाए और ऐसे आयात घरेलू उद्योग को क्षति क्यों नहीं पहुंचाएंगे। इस संबंध में प्राधिकारी की यह धारणा है कि विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र में अकेले कल-पुर्जे और संघटकों के आयातों को नहीं शामिल किए जाने के मुद्दे का समाधान पहले से ही मूल जांच में कर लिया गया है और घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र में अकेले कल-पुर्जे और संघटकों के आयातों को शामिल किए जाने को यथोचित ठहराने के लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए प्राधिकारी मौजूदा निर्णायक जांच समीक्षा में अपने मत को पुनः दोहराते हैं कि अकेले आधार पर आयातित कल-पुर्जे और संघटक विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर हैं।
- (च) घरेलू उद्योग ने प्रिंटीड सर्किट बोर्डों को जिन्हें बेयर बोर्ड भी कहा जाता है, शामिल करते हुए विचाराधीन उत्पाद का विस्तार करने की भी मांग की है। ये प्रिंटीड सर्किट बोर्ड केवल कल-पुर्जे और संघटकों की श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त मूल अन्तिम निर्णय में ऐसा सिद्ध हो गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा स्वतः ही प्रिंटीड सर्किट बोर्ड का संबद्ध देश अर्थात् चीन जनवादी गणराज्य से आयात किया गया है। यदि घरेलू उद्योग ने मौजूदा निर्णायक जांच समीक्षा की जांच अवधि के दौरान प्रिंटीड सर्किट बोर्ड का आयात नहीं किया होता तो वह उसे बदल नहीं सकता है और न ही ऐसा दावा कर सकता है कि अब उनकी प्रकृति में परिवर्तन हो गया है और इस प्रकार इन्हें विचाराधीन उत्पाद में शामिल कर लिया जाए। इसलिए प्राधिकारी अपने निर्णय को पुनः दोहराते हैं कि अकेले आधार पर आयातित प्रिंटीड सर्किट बोर्ड विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर हैं।

- (छ) उत्पाद के कार्य-क्षेत्र को स्पष्ट किए जाने के संबंध में प्राधिकारी ने विगत निर्णयों में उत्पाद के कार्य-क्षेत्र में शामिल करने और बाहर निकालने से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान कर दिया है और प्राधिकारी नोट करते हैं कि जैसा कि दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 की मूल अंतिम निर्णय की अधिसूचना संख्या 14/2/2009 में शुल्क की तालिका के नीचे दिया गया है, जिसे दिनांक 22 अक्टूबर, 2010 के शुद्धि पत्र संख्या 14/2/2009 के साथ पढ़ा जाए और उसे आगे दिनांक 10 फरवरी, 2012 के अंतिम निर्णय संबंधी अधिसूचना संख्या 14/2/2009 के साथ पढ़ा जाए, अपने सभी रूपों में विचाराधीन उत्पाद, मौजूदा जांच के अधीन है।
- (ज) विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क के टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 85 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसे आगे भारतीय व्यापार वर्गीकरण के अनुसार सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची के शीर्ष 851762 और 851770 के अंतर्गत भी वर्गीकृत किया गया है। तथापि, ऐसा वर्गीकरण निर्देशात्मक है और यह मौजूदा जांच पर किसी भी तरीके से बाध्यकारी नहीं है।

12. समान वस्तु के संबंध में नियम 2 (घ) में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है :-

“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

13. याचिकादाता ने यह दावा किया है कि आवेदक द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं की भौतिक और दृष्टव्य, उत्पादन प्रौद्योगिकी, विनिर्माण प्रक्रिया, अनुसंधान और विकास, सॉफ्टवेयर क्षमताओं, कार्यों और उपयोगों आदि जैसे प्राचलों के रूप में तुलनीय विशेषताएं हैं।

14. मौजूदा आवेदन पत्र लागू किए गए पाटन-रोधी शुल्क की पुनरीक्षा करने, उसको जारी रखने और उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए प्रस्तुत किया गया है और समान वस्तु के मुद्दे का समाधान विगत जांच में पहले से ही कर दिया गया है। पूर्व जांच में प्राधिकारी ने पहले से ही यह निर्णय दे दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं के समान ही हैं तथा इस जांच में प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई ऐसा नया प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह पता चलता हो कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं के समान नहीं हैं।

15. *उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) प्रणाली :* विचाराधीन उत्पाद, अनेक प्रकार से और विभिन्न किस्मों में निर्मित और बेचा जाता है। विशिष्ट ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे अनेक प्रकार से और विभिन्न किस्मों में निर्मित किया जाता है। सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना सुनिश्चित करने के प्रयोजन से प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद को, ट्रांसमिशन क्षमता, क्रोस कनेक्ट क्षमता, ई 1 इंटरफेस, इलेक्ट्रिकल इंटरफेसिज, ऑप्टिकल इंटरफेसिज, ऑप्टिकल किस्मों आदि आदि जैसे प्राचलों के आधार पर विभिन्न किस्मों में वर्गीकृत किया है। इस संबंध में प्राधिकारी ने 15 अंकों की एक उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) प्रणाली बनाई है। मूल जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे निर्देश दिए गए थे कि वे प्रत्येक पीसीएन के लिए लागत और कीमत की सूचना पृथक से दें। हालांकि पीएन मानदंड बना कर प्राचलों का मानकीकरण करने के कुछ प्रयास किए गए हैं, फिर भी कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो कि अपनी विशिष्ट प्रकृति के कारण मानकीकरण के अधीन नहीं हैं, क्योंकि वे पूर्णतया गैर-मानकीकृत हैं, प्रत्येक नेटवर्क की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए गए हैं, विभिन्न फ्रीक्वेंसी पर कार्य करते हैं, उनमें विभिन्न माड्युलस निहित हैं, उनमें संवर्धन अथवा विलोपन करने के परिणामस्वरूप उनकी लागतों में व्यापक अंतर हो सकता है और लागत प्रयुक्त प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इंटरफेस पर निर्भर करती है आदि। चूंकि मौजूदा जांच निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इस जांच में भी पीसीएन यथावत् बना रहेगा।

16. घरेलू उद्योग और प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के संबद्ध निवेदनों और दावों की जांच करने के बाद प्राधिकारी का निष्कर्ष यह है कि विचाराधीन उत्पाद वही बने रहेंगे जैसा कि दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 की मूल अंतिम निर्णय की अधिसूचना संख्या 14/2/2009 में शुल्क की तालिका के नीचे दिया गया है, जिसे दिनांक 22 अक्टूबर, 2010 के शुद्धि पत्र संख्या 14/2/2009 के साथ पढ़ा जाए और उसे आगे दिनांक 10 फरवरी, 2012 के अंतिम निर्णय संबंधी अधिसूचना संख्या 14/2/2009 के साथ पढ़ा जाए। विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार हैं :-

**** टिप्पणी 1 : विचाराधीन उत्पादों में सिंक्रोनुअस डिजिटल हेयराची ट्रांसमिशन उपस्कर नामत : एसटीएम-1, एसटीएम-4, एसटीएम-16, एसटीएम-64, एसटीएम-256 संग्रहीत रूप में, सीकेडी, एसकेडी रूप में, उसके संग्रह और उप-संग्रह के रूप में अथवा अंततः ब्रोड बैंड सेल्युलर उपस्कर में प्रयुक्त किए गए उपस्कर शामिल होंगे। विचाराधीन उत्पादों में सभी एड ड्राप मल्टीप्लेक्सरज*

(एडीएम) (केवल एसडीएच अनुप्रयोग के लिए), मल्टीपल एंड ड्राप मल्टीप्लेक्सर्स (एमएडीएम) (केवल एसडीएच अनुप्रयोग के लिए) और डिजीटल क्रॉस कनेक्ट (डीएक्ससी) (केवल एसडीएच अनुप्रयोग के लिए), पापुलेटिड सर्किट बोर्ड्स (केवल एसडीएच अनुप्रयोग के लिए) तथा उपस्करों के एक अंश के रूप में कलपुर्जे/संघटक, जब तक कि वे उपस्कारों के साथ अथवा उसके संग्रह/उप-संग्रह के रूप में आयातित किए जाते हैं, भी शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त विचाराधीन उत्पादों में एसडीएच के निमित्त सॉफ्टवेयर भी शामिल होंगे जो कि इन उपस्करों का ही एक संगठित भाग है जिसे उपस्कर के रूप में अथवा पृथक् रूप से खरीदा जा सकता है। तथापि, एकल आधार पर आयातित संघटक/कल-पुर्जे, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं।

*** टिप्पणी 2 : एसडीएच उपस्कर अनिवार्य रूप से ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से संकेतों को संप्रेषित करते हैं। ऐसे एसडीएच उपस्कर होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक कोप्पर के माध्यम से अथवा माइक्रोवेव रेडियो के माध्यम से ट्रांसमिशन के निमित्त होते हैं। केवल ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से संकेतों को संप्रेषित करने वाले एसडीएच उपस्कर पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने के अध्वधीन होंगे।

*** टिप्पणी 3 : जब एसडीएच का आयात अन्त्य ब्रोडबैंड/सेल्युलर उपस्कर के एक अंश के रूप में किया जाता है तो पाटन-रोधी शुल्क का भुगतान आयातों के केवल एसडीएच के भाग पर ही देय होगा। इसी प्रकार जब अन्त्य ब्रोडबैंड/सेल्युलर उपस्कर का आयात एसडीएच उपस्कर के रूप में किया जाता है तो पाटन-रोधी शुल्क का भुगतान आयातों के केवल एसडीएच के भाग पर ही देय होगा।

*** टिप्पणी 4 : पीडीएच, सीडब्ल्यूडीएम, डीडब्ल्यूडीएम, माइक्रोवेव प्रणालियों, जीपीओएन, डीएसएलएम, एमएसएएन, बीआईटीएस, राउटर्स, पीडीएसएन, एसजीएसएन, एमजीडब्ल्यू, बीटीएस, बीएससी, एमएससी, ओएनटी, एलएलआर, एचएसएस और एमआरपी के किसी भी रूप में गैर-एसडीएच होने के कारण ये विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं और इसलिए ये पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने के अध्वधीन नहीं हैं।

*** टिप्पणी 5 : माइक्रोवेव रेडियो टर्मिनल जो कि एसडीएस ट्रांसमिशन उपस्कर का एक एसटीएम-1 इंटरफेस हो सकते हैं और जो रेडियो और एसडीएच उपस्कर के बीच संपर्क स्थापित कर सकने में वास्तविक साधन होते हैं, ये पाटन-रोधी शुल्क का भुगतान करने के अधिकार-क्षेत्र से बाहर हैं।

घ. घरेलू उद्योग का कार्य-क्षेत्र और उसका दर्जा

घ.1. निर्यातकों/आयातकों/प्रयोक्ताओं/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

17. घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र और अवस्थिति के संबंध में निर्यातकों/आयातकों/प्रयोक्ताओं/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- i. हुआवेई टेलीकम्युनिकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (हुआवेई इंडिया) ने यह दावा किया है कि वह भारत में एसटीएम-1, एसटीएम-4, एसटीएम-16, एसटीएम-64, एसडीएच अनुप्रयोग के लिए एंड ड्राप मल्टीप्लेक्सर्स, एसडीएच अनुप्रयोग के लिए मल्टीपल एंड ड्राप मल्टीप्लेक्सर्स, एसडीएच अनुप्रयोग के लिए डिजीटल क्रॉस कनेक्ट और एसडीएच अनुप्रयोग के लिए पापुलेटिड सर्किट बोर्ड्स का विनिर्माण करने के कार्यों में लगी हुई है। कंपनी के पास विचाराधीन उत्पाद सहित दूरसंचार उपस्करों का विनिर्माण करने के लिए डीटीए फैक्टरी विनिर्माण लाइसेंस है और उसे एक केन्द्रीय उत्पाद पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है। कंपनी ने भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत शामिल किए गए एसडीएच उपस्कर की आपूर्ति, आईडिया सेल्युलर लिमिटेड, सिफ़ी टेक्नोलॉजी लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, एलसन टी एंड डी (इंडिया) लिमिटेड, डिशनेट वायरलैस लिमिटेड, एयरसेल लिमिटेड, वोडाफोन सेल्युलर लिमिटेड सहित अन्य ग्राहकों को की है।
- ii. प्राधिकारी ने मूल जांच में दिनांक 19.10.2010 के अपने अंतिम निर्णय में यह निष्कर्ष दिया था कि विचाराधीन उत्पाद के "उत्पादन" की प्रक्रिया में 15 कार्य निहित हैं। इसके अतिरिक्त जब कि कंपनी को ऐसा प्रत्येक करने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी ऐसा संभव होता है कि इनमें से कुछ कार्यों में एक अथवा अधिक उप-प्रक्रियाएं निहित हो सकती हैं, जिन्हें स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है अथवा ऐसी कुछ प्रक्रियाएं कुछ कंपनियों द्वारा एकीकृत की जा सकती हैं। हुआवेई इंडिया ने यह भी बताया है कि कंपनी विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन चेन्नई में स्थित अपने संयंत्र में करती है जहां संघटकों को संग्रहीत किया जाता है और पीसीबीए का निर्माण करने के लिए पर्याप्त रूपान्तरण किया जाता है।

- iii. सॉफ्टवेयर का विकास, आवेदक, मेसर्स तेजा नेटवर्क्स को सॉफ्टवेयर का उत्पादक बनाता है और न कि एसडीएच उपस्कर के उत्पादक को जो कि विभिन्न संघटकों, जिनमें सॉफ्टवेयर भी एक इनपुट है, का प्रयोग करके निर्मित किया जाता है। इन क्रियाकलापों को बेहतर ढंग से एसडीएच उपस्कर का विनिर्माण करने से संबंधित क्रियाकलापों के रूप में माना जा सकता है और न कि एसडीएच उपस्कर का स्वतः विनिर्माण।
- iv. आवेदक मेसर्स तेजा नेटवर्क को अपने अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) के ब्यौरे प्रस्तुत करने चाहिए जैसे कि क्या ये विचाराधीन उत्पाद अथवा अन्य उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए हैं, लागत क्या है, आवेदक की वास्तविक विनिर्माण लागत क्या है, कौन सा अकेला मानदंड है आदि, क्योंकि वह यह दावा कर रहा है कि उसकी 60 प्रतिशत जनशक्ति अनुसंधान और विकास कार्यों में लगी हुई है और वह इसका भी दावा करता है कि एसडीएच उत्पाद जो कि विचाराधीन उत्पाद का ही भाग है, अब अप्रचलित प्रौद्योगिकी हो गई है।
- v. आवेदक मेसर्स तेजा नेटवर्क पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के दर्जे के मानदंड को पूरा नहीं करता है। यदि आवेदक घरेलू उत्पादन में मुख्य अंशदान भी करता है, तो भी वह नियम 2 (ख) के अंतर्गत के मानदंड को पूरा नहीं करता है क्योंकि वह स्वयं एक आयातक है।
- vi. मेसर्स हुआवेई इंडिया ने विगत 4 से 5 वर्ष की अवधि में भारत में पर्याप्त निवेश किया है और वह सूचीबद्ध उत्पादन के 15 मानदंडों को पूरा करता है क्योंकि उसके सभी क्रियाकलाप स्वतः भारत में उसके सुविधा केन्द्र पर ही किए जा रहे हैं। साथ ही उसने मौजूदा निर्णायक समीक्षा जांच की जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत ने वाले बहुत कम मर्दों का ही आयात किया है। उसने अपना ध्यान मुख्यतया घरेलू उत्पादन पर ही संकेन्द्रित किया हुआ है और वह भारत में सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है तथा इसे दूरसंचार विभाग द्वारा भी माना गया है। वास्तव में मेसर्स हुआवेई इंडिया में उसी बाजार में लाभ अर्जित कर रहा है जिसमें पाटन-रोधी शुल्कों के रूप में अत्यधिक संरक्षण प्राप्त होने पर भी आवेदक ऐसा दावा कर रहा है कि उसे घाटे हो रहे हैं। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह कृपया घरेलू उद्योग की स्थिति की पुनः जांच करें और सभी हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष यह यह स्पष्ट करें कि वास्तव में कौन घरेलू उद्योग है।
- vii. प्राधिकारी को स्वतंत्र रूप से अन्य उत्पादकों से उनकी क्षमता और उत्पादन के ब्यौरे प्राप्त करने चाहिए। सभी हितबद्ध पक्षकारों को भी ऐसे आंकड़े प्रदान करने चाहिए ताकि वे उनकी जांच और उन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकें। यह नोट किया जाए कि उल्लिखित किसी भी उत्पादक ने याचिका का समर्थन नहीं किया है।
- viii. न तो विश्व व्यापार संगठन का और न ही पाटन-रोधी नियमावली का ऐसा प्रयोजन है कि “घरेलू उद्योग” को परिभाषित करते समय सीधे ऐसे आवरण युक्त सूत्र को ही अपनाया जाए जो कि आवेदक की आवश्यकताओं और उसके द्वारा किए गए कानून के विवेचन के अनुकूल हो तथा इस प्रकार आवेदक की मांग के अनुसार अन्य सभी घरेलू उत्पादकों को एक अथवा अन्य आधार पर “घरेलू उद्योग” के दर्जा देने से अपात्र माना जाए।
- ix. मूल जांच में अंतिम निर्णय के बाद, मेसर्स हुआवेई इंडिया अब भारत में तैयार वस्तुओं को विनिर्मित कर रहा है और वह एक घरेलू उद्योग है तथा इसलिए उसे विचाराधीन उत्पाद के आयातक के रूप में नहीं माना जाए। घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद के एक निर्यातक के रूप में माने जाने के लिए आवेदक द्वारा अपनाया गया मानदंड, पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार गलत और विपरीत है।
- x. प्राधिकारी को मेसर्स हुआवेई इंडिया को एक घरेलू उद्योग के रूप में माना जाना चाहिए और घरेलू उद्योग के रूप में आवेदक को सुने जाने के अधिकार की जांच करनी चाहिए तथा उसको गैर-क्षति कीमत प्राप्त करने के समय मेसर्स हुआवेई इंडिया द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर विचार करना चाहिए।
- xi. घरेलू उद्योग के गलत विवेचन पर आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण करने वाले भारतीय उत्पादकों को, आयातित संघटकों को विचाराधीन उत्पाद के रूप में परिवर्तित करके आयातकों के रूप में वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। यहां तक कि अंतिम उत्पाद प्राप्त करने के लिए आयातित संघटकों को संग्रहीत करने के कार्य को भी जो कि संग्रहीत संघटकों से भिन्न प्रकृति का है, विनिर्माण ही माना जाएगा और इसे प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय के पैरा 30 (2) में स्वीकार किया गया है।
- xii. आवेदक मेसर्स तेजा नेटवर्क ने विशेषीकृत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवा (ईएमएस) प्रदायकों के लिए पीसीवीए के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त किए गए विशेष कलपुर्जे को बाह्य स्रोत से प्राप्त किया है। ऐसा कार्य आवेदक को घरेलू उद्योग माने जाने से वर्जित किया जाना चाहिए। इस आशय के तथ्य को आवेदक ने अपनी याचिका में, वर्ष 2007-08 की अपनी वार्षिक

रिपोर्ट में भी, अंतिम निर्णय में और आवेदक द्वारा वर्ष 2009 में प्रस्तुत किए गए अपने विभिन्न विवरणों में भी स्वीकार किया है।

- xiii. आवेदक मेसर्स तेजा नेटवर्क पीसीबीए का विनिर्माण करने के कार्य में नहीं लगा है, क्योंकि आवेदक द्वारा पीसीबीए की पापुलेटिंग करने का क्रियाकलाप नहीं किया जा रहा है और विशेषीकृत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवा (ईएमएस) के लिए यह क्रियाकलाप बाह्य स्रोत से करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पीसीबीए में ईएमएस के माध्यम से सॉफ्टवेयर जडित किया जाता है। इस प्रकार पीसीबीए का निर्माण ईएमएस द्वारा किया जाता है और न कि आवेदक द्वारा तथा इसलिए वह अंतिम निर्णय के पैरा 30 (2) के साथ पठित नियम 2 (ख) की आवश्यकता को पूरा नहीं कर रहा है।
- xiv. “घरेलू उद्योग” के दर्जे का निर्धारण करने के लिए आवेदक द्वारा प्रयुक्त किया गया अनुसंधान और विकास का मानदंड वृत्तिपूर्ण है और उसने ऐसे कानूनी भारतीय उत्पादकों को गलती से बाहर रखा है, जो कि संघटकों को खरीदते हैं और जिन्होंने संबंधित उत्पाद को बेचने के लिए स्वयं संग्रहीत किया है। अनुसंधान और विकास का कार्य, निर्धारित उत्पाद के उत्पादन की एकीकृत पूर्ण लागत को आवधिक रूप से निर्धारित किए जाने का ही एक भाग है। कुछ परिस्थितियों में अनुसंधान और विकास की लागत को तब तक पूंजी में परिणत नहीं किया जाता है जब तक कि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उत्पाद को विकसित नहीं कर लिया जाता है और उसके बाद उसका परिशोधन शुरू हो जाता है।
- xv. प्राधिकारी ने “घरेलू उद्योग” के दर्जे का निर्धारण करने के लिए प्राचल के रूप में अनुसंधान और विकास के क्रियाकलाप की व्यवस्था करके स्वयं का खंडन किया है जबकि दूसरी ओर सीआईईएनए के मामले में मूल देश का निर्धारण करने के लिए आईपीआर के तर्क को खारिज किया गया है।
- xvi. पाटन-रोधी नियमावली मूल्य संवर्धन और विनिर्माण के क्रियाकलाप का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ अनुसंधान और विकास, आईपीआर और तकनीकी जानकारी पर किए जाने वाले व्यय को नहीं मान्यता नहीं देती है। इस संबंध में कृपया नियम 25 का संदर्भ ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए मूल अंतिम निर्णय के पश्चात पाटन-रोधी नियमावली ने भी अपने परिवेश में से विशेष रूप से आईपीआर, तकनीकी जानकारी आदि के मानदंड को बाहर कर दिया है और इस प्रकार पाटन-रोधी नियमावली को अन्य कानूनों के साथ सम्मिलित कर दिया गया है जैसे कि विनिर्माण की प्रक्रिया का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ सीमा शुल्क के नियम, जिसके लिए जांच, इनपुट को आउटपुट के रूप में पर्याप्त रूप से दृष्टव्य परिवर्तन होने का निर्धारण करना होता है। ऐसा पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अनुरूप किया जाता है जिसमें यह अधिदेश दिया गया है कि घरेलू उद्योग को विनिर्माण और उससे संबंधित अन्य क्रियाकलापों में लगा होना चाहिए। यहां अनुसंधान और विकास, आईपीआर आदि जैसे कुछ अन्य क्रियाकलापों के आवरण में विनिर्माण की आवश्यकता से किसी भी प्रकार का विचलन नहीं हो सकता है।
- xvii. प्रिंटीड सर्किट बोर्ड को स्थापित करने का क्रियाकलाप, सीसीई, मद्रास बनाम कोरोमंडल इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले के अनुसार जिसे 1997 (90) ईएलटी 443 के अनुसार सूचित किया गया है, विनिर्माण कार्य ही है। इसलिए ईएमएस को ही ऐसे पीसीबी के विनिर्माता के रूप में माना जाना चाहिए, जिनका प्रयोग आवेदक द्वारा अंतिम उत्पाद नामतः एसडीएच को संग्रहीत करने के लिए किया जाता है।
- xviii. आवेदक ने चतुराई से स्वयं को और कुछ अन्य को घरेलू उत्पादक के रूप में माना है तथा भारत में अन्य सभी उत्पादकों को आयातक के रूप में माना है।
- xix. पाटन-रोधी नियमावली के अंतर्गत 15 बिन्दुओं के मानदंड को पूरा करने के संबंध में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है जिसे भारत में उत्पादन शुरू करने वाली कंपनी को पूरा करना हो। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि ऐसे 15 बिन्दुओं के मानदंड में अनुसंधान और विकास अत्यंत महत्वपूर्ण संघटक है, फिर भी यदि घरेलू उद्योग के इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसी अनेक विदेशी कंपनियां, जिन्होंने भारत में बिलियन डालर निवेश किए हैं, घरेलू उत्पादकों के रूप में योग्य बनने में विफल हो जाएंगी।
- xx. भारत में अधिकतर आधुनिक विनिर्माण करने के लिए “प्रयोग करने का अधिकार” के मॉडल अथवा “प्रौद्योगिकी अंतरण करारों” के अंतर्गत प्रौद्योगिकी को प्रयुक्त किया जा रहा है। ऐसे कारण मात्र से कि कंपनी भारत में अनुसंधान और विकास का क्रियाकलाप नहीं कर रही है अथवा उसके पास भारत में आईपीआर नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ऐसी कंपनी भारत में उत्पादक नहीं है।
- xxi. मौजूदा समीक्षा में मूल जांच के समय विद्यमान तथ्यों में पूर्णतया बदलाव आ गया है। अन्य उत्पादक अब भारत में पर्याप्त रूप से उत्पादन के क्रियाकलाप शुरू कर रहे हैं और प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वे इसकी जांच करें।

- हुआवेई इंडिया ने निवेदन किया है कि भारत में ऐसा कौन सा उत्पादक है जिसे मौजूदा समीक्षा से बाहर रखा जाए, इसका अनुमान लगाने के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाया गया 15 बिन्दु का मानदंड कोई कानूनी आधार नहीं है।
- xxii. आवेदक मेसर्स तेजा नेटवर्क ने याचिका के पृष्ठ 81 पर दिए गए दिनांक 5 सितंबर, 2014 के अपने पत्र में यह बताया है कि उसने संबद्ध उत्पाद का आयात नहीं किया है। तथापि, इस याचिका के पृष्ठ 82-क पर आवेदक के आयातों की सूचना दी गई है। यथाशीघ्र यह स्पष्ट किया जाए कि आवेदक ने किसका आयात किया है। यदि आवेदक ने संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है, तो मौजूदा समीक्षा में वह घरेलू उद्योग के योग्य नहीं बनता है। इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी से आग्रह किया जाता है कि वह आवेदक को निर्देश दें कि संबद्ध उत्पाद के आयातों के आंकड़े हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट करें। उद्योग के स्रोत से और सीओआईएसोसिएशन के दिनांक 19 फरवरी, 2015 के पत्र से ऐसा समझा जाता है कि याचिकादाता संबद्ध उत्पाद का एक आयातक है। इसलिए प्राधिकारी को मौजूदा जांच को समाप्त कर देना चाहिए।
- xxiii. यह स्पष्ट नहीं है कि क्या हुआवेई इंडिया, घरेलू उद्योग का भाग है अथवा नहीं। क्षति का विश्लेषण, घरेलू उद्योग के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। यदि हुआवेई इंडिया को घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाता है, तो भी इस मुद्दे पर स्थिति तुरंत स्पष्ट कर दी जानी चाहिए और प्राधिकारी द्वारा इसका यथाशीघ्र स्पष्ट निर्धारण कर दिया जाना चाहिए।
- xxiv. हुआवेई इंडिया व्यापारिक कंपनी मात्र नहीं है, बल्कि इसने आवेदक की तुलना में बड़े पैमाने पर अनुसंधान और विकास के क्रियाकलाप शुरू किए हैं तथा यह पर्याप्त स्तर पर विनिर्माण क्रियाकलाप भी कर रही है। यह लगभग 5700 भारतीय कर्मचारियों को रोजगार प्रदान कर रही है और भारत में इसका निवेश भारतीय रूप्यों में 1700 करोड़ से भी अधिक है तथा यह वर्ष 2000 से भारत में प्रचालन कार्य कर रही है।
- xxv. ईएमएस (जॉब्स कार्यकर्ताओं) के लिए सूचीबद्ध 15 क्रियाकलापों में से “सोलडरिंग और ईएमएस क्रियाकलाप”, “एकीकरण”, “टेस्ट जिग्स तैयार करना”, “असेम्बली”, “परीक्षण” (जैसे सभी क्रियाकलाप वास्तविक विनिर्माण से संबंधित हैं) के कार्यों को आरोपित घरेलू उद्योग द्वारा बाह्य स्रोतों से करवाया जा रहा है तथा अनुसंधान और विकास, उत्पाद ब्लू प्रिंट और विकास के क्रियाकलापों को घरेलू उद्योग द्वारा स्वयं शुरू किया गया है। सीआईईएनए के मामले में प्राधिकारी ने पाटन-रोधी शुल्क लगाया है जिसका एक मात्र आधार यह है कि ऐसे उत्पाद चीन मूल के हैं, जबकि उसके अधिकतर 15 क्रियाकलाप जिनमें विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पूरा अनुसंधान और विकास कार्य शामिल है, सीआईईएनए द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका में शुरू किए गए हैं। सीआईईएनए के मामले में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए मापदंड को लागू करते हुए आरोपित घरेलू उद्योग को, जो कि चीन और/अथवा अन्य देशों से पीसीबीए का आयात करता है, इस तथ्य की ओर ध्यान दिए बिना कि उसने अनुसंधान और विकास के कार्य भारत में शुरू किए हैं, घरेलू उद्योग की परिभाषा से बाहर कर दिया जाना चाहिए।
- xxvi. याचिकादाता मुख्यतया विनिर्माण से जुड़े अनुषंगिक क्रियाकलाप करने में लगा हुआ है जैसे कि उत्पाद डिजाइन का अनुसंधान और विकास और वह विचाराधीन उत्पाद का वास्तव में विनिर्माण नहीं कर रहा है। विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्डों को, उनमें केपासिटर्स, ट्रांसिस्टर्स, रेसिस्टर्स और अन्य घटक को लगा कर ही पीसीबीए के रूप में निर्मित किया जाता है। इस सिद्धांत की संपुष्टि सीसीई, मद्रास बनाम कोरोमंडल इलेक्ट्रॉनिक्स {1997 (90) ईएलटी 443}, सीसी, गोवा बनाम डी-लिंक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड {2014 (306) ईएलटी 479 (ट्रि-मुंबई) के मामलों में की गई है।
- xxvii. इस विधान का अभिप्राय गैर-क्षति कीमत का निर्धारण करते समय आरोपित घरेलू उद्योग द्वारा जॉब कार्य पर किए गए व्यय को भी बाहर रखना है। ऐसे प्रावधान आगे इस तथ्य को भी निर्दिष्ट करते हैं कि जिस उत्पादक को घरेलू उद्योग के रूप में माना जाता है, उस उत्पादक के लिए यह अनिवार्य है कि वह स्वयं भी संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माण कार्य में लगा हुआ हो।
- xxviii. चूंकि आरोपित घरेलू उद्योग का घरेलू उत्पादन में अंशदान नगण्य है, जो कि कुल उत्पादन के 25 % से भी कम बनता है और इसलिए वह क्षति का दावा नहीं कर सकता है।
- xxix. आरोपित घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि उसके द्वारा विनिर्मित किए गए पीसीबीए अनोखे हैं और यह आरोपित घरेलू उद्योग की ही योग्यता है। उसने यह भी दावा किया है कि उसने ऐसे पीसीबीए (जॉब कार्य से विनिर्मित) के आयात थाईलैंड और सिंगापुर से किए हैं। इस संबंध में यह अनुरोध है कि थाईलैंड और सिंगापुर से पीसीबीए के आयातों के लिए प्रवेश बिलों में उनके मूल देश का पता चलता है, जिसकी जांच की जानी चाहिए।

- xxx. आरोपित घरेलू उद्योग ने स्वयं स्वीकार किया है कि विनिर्माण की वास्तविक प्रक्रिया उनके समग्र क्रियाकलाप का बहुत छोटा भाग है और आरोपित घरेलू उद्योग मुख्यतया संबद्ध उत्पाद के डिजायन और विकास के कार्यों में ध्यान संकेन्द्रित कर रहा है। यह उसकी आत्म-स्वीकृति है कि उसकी लगभग 60 प्रतिशत जनशक्ति विचाराधीन उत्पाद के डिजायन और विकास के कार्यों में लगी हुई है। आरोपित घरेलू उद्योग द्वारा शुरू किए गए डिजायन और विकास के कार्यों का लक्ष्य/प्रयोजन स्पष्ट नहीं है क्योंकि एसटीएम-26 को अनेक वर्षों से विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विकसित किया जा रहा है जबकि आरोपित घरेलू उद्योग को एसटीएम-1, 4 और 16 से ऊपर किसी भी उत्पाद की कोई जानकारी नहीं है।
- xxx.i. आवेदक मेसर्स तेजा नेटवर्क द्वारा शुरू किए गए अनुसंधान और विकास के क्रियाकलापों की प्रकृति की स्थिति स्पष्ट नहीं है। दिनांक 18.09.2015 को हुई मौखिक सुनवाई में आरोपित घरेलू उद्योग ने यह स्वीकार किया था कि एसडीएच ट्रांसमिशन उपस्कर के संबंध में अनुसंधान और विकास के कार्य-क्षेत्र में अब कुछ पर्याप्त बचा हुआ नहीं है। यदि आरोपित घरेलू उद्योग के एसडीएच ट्रांसमिशन उपस्कर के संबंध में अनुसंधान और विकास के क्रियाकलापों को शुरू नहीं किए जाते हैं, बल्कि कुछ अन्य उत्पाद शुरू किए जाते हैं तो ऐसे अनुसंधान और विकास पर हुए व्यय को, मौजूदा समीक्षा/जांच के लिए अप्रासंगिक माना जाएगा और इस प्रकार उन्हें मौजूदा मामले में आरोपित पाटन के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए किए जाने वाले परिकलन से बाहर रखा जाएगा।
- xxx.ii. इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन किया जाता है कि मौखिक सुनवाई के समय व्यक्त किए गए इस तथ्य के बावजूद कि फिबकोम द्वारा अनुसंधान और विकास के क्रियाकलाप भारत से बाहर किए जा रहे हैं, आरोपित घरेलू उद्योग ने फिबकोम के इस निवेदन का समर्थन किया है कि उसने विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण कार्य भारत में शुरू किया है और इसलिए उसे "घरेलू उद्योग" की श्रेणी में ही शामिल किया जाए। इस संबंध में यह निवेदन किया जाता है कि इसी प्रकार से हुआवेई इंडिया (जो कि सीओआई का एक सदस्य है) को भी इसी सिद्धांत पर "घरेलू उद्योग"/घरेलू उत्पादक माना जाना चाहिए। इसके साथ ही यह भी निवेदन किया जाता है कि हुआवेई इंडिया ने वर्ष 2010 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी और भारत में पर्याप्त रूप से निवेश करने के बाद वर्ष 2011 से विचाराधीन उत्पाद का घरेलू उत्पादन करना शुरू कर दिया था और स्वयं को मात्र वस्तुओं का व्यापारी नहीं बनाया था। तदनुसार हुआवेई इंडिया को भी "घरेलू उद्योग" में शामिल अन्य पक्षकारों की ही तरह एक पक्षकार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। आरोपित घरेलू उद्योग बाजार में एकाधिकार प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है और उपभोक्ता उद्योग को जिनके हित अत्यधिक व्यापक हैं और जो सीधे जन हित से जुड़े हैं, विवश कर रहा है कि वह आरोपित घरेलू उद्योग के अप्रचलित और गैर-प्रतिस्पर्द्धी उत्पादों को खरीदे।
- xxx.iii. आरोपित घरेलू उद्योग का यह विचार है कि प्राधिकारी की यह अवधारणा है कि यदि कोई कंपनी भारत में उपरोक्त 15 क्रियाकलापों को करती है तो उसे भारत में संबद्ध उत्पाद का उत्पादक माना जाएगा। तथापि, यह निवेदन किया जाता है कि ऐसे अंतिम निर्णय में प्राधिकारी के ऐसे किसी भी प्रेक्षण का कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है। घरेलू उद्योग मूल जांच के अंतिम निर्णय का गलत ढंग से प्रतिपादन कर रहा है।
- xxx.iv. इसके अतिरिक्त पाटन-रोधी नियमावली में ऐसी कोई कानूनी अपेक्षा नहीं है कि किसी कंपनी को भारत में उत्पादक का पात्र बनने के लिए उपरोक्त 15 क्रियाकलाप करने अपेक्षित होंगे। इसके अतिरिक्त विधि में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि यदि कोई कंपनी भारत में अनुसंधान और विकास के क्रियाकलाप करती है और उसकी भारत में आईपीआर हैं, तो उसे भारत में एक उत्पादक के रूप में माना जाएगा। इसलिए घरेलू उद्योग के तर्कों को खारिज कर दिया जाना चाहिए।
- xxx.v. इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने दर्जे का निर्धारण करने के लिए ओवम रिपोर्टों पर विश्वास किया है। यह निवेदन किया जाता है कि ओवम रिपोर्टें कंपनियों के नाम और बाजार सूचना के आधार पर मूल्य के रूप में बाजार में उनके अंशदान की सूचना मात्र ही प्रदान करती हैं। ओवम रिपोर्टें इस आशय की सूचना प्रदान नहीं करती हैं कि क्या कंपनियां घरेलू रूप से संबद्ध उत्पाद का उत्पादन कर रही हैं अथवा उनका आयात कर रही हैं। इसलिए इस मामले में दर्जे का निर्धारण करने के लिए ओवम रिपोर्टों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

घ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

18. घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र और उसके दर्जे के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- i. याचिकादाता द्वारा प्रदत्त सूचना पर्याप्त और सही है तथा यह इसकी स्पष्ट रूप से संपुष्टि करती है कि याचिकादाता का उत्पादन भारतीय उत्पादन का प्रमुख अंश है।
- ii. हुआवेई इंडिया को नियामावली के अनुसार घरेलू उत्पादक नहीं माना जा सकता है।

- iii. भारतीय उत्पादक ऐसी कंपनियां हैं जो कि भारत में उत्पादन के क्रियाकलाप कर रही हैं और जिनको संबद्ध देशों सहित विभिन्न विदेशी स्रोतों से कलपुर्जों/संघटकों का आयात करने की आवश्यकता होती है जैसे कि किसी भी घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल का आयात किया जाता है जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई अनेक जांचों में पाया गया है। इसलिए जब तक ये आयात इनपुट के आयात बने रहते हैं तब तक याचिकादाता को ऐसे आयातों के बारे में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है।
- iv. तृतीय देश के उत्पादक सिना जैसी कंपनियां हैं। इन कंपनियों को संबद्ध देशों सहित विश्व के स्रोतों से संघटक खरीदने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त ऐसी कंपनियां चीन में अवस्थित ईएमएस सेवाओं को उपयोग करती हैं।
- v. चीन और इजरायल की ऐसी कंपनियों को जो कि एसडीएच उपस्कर का विनिर्माण कर रहीं हैं, शुल्कों का भुगतान करना चाहिए, भले ही वे तैयार उपस्कर अथवा एसकेडी/सीकेडी के रूप में अथवा संघटक के रूप में ही आपूर्ति करती हों। यदि ये कंपनियां संघटक के रूप में एसडीएच उपस्कर का निर्यात करती हैं तो उत्पादन की प्रक्रिया के लिए अपेक्षित बची इन-पुट तकनीकी जानकारी (जो कि चीन की है) और सोल्डरिंग सेवाएं (जो कि स्कू संचालित प्रोद्योगिकी है) होती हैं। इसलिए ये कंपनियां सीमा शुल्क की क्लियरेंस प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए संघटकों के रूप में एसडीएच उपस्कर का सुगमता से आयात कर सकती हैं, जबकि सीमा शुल्क के क्लियरेंस के बिना ही देश में तकनीकी जानकारी लाई जा सकती है।
- vi. *एसडीएच उपस्कर के आपूर्तिकर्ता* - ये ऐसी पार्टियां हैं जो कि भारत में किसी भी रूप में उत्पाद को एक निर्यात के रूप में स्वीकार करते हुए एसडीएच का निर्यात कर रही हैं, जिनके बारे में स्पष्ट उल्लेख अंतिम निर्णय में किया गया है कि ऐसे निर्यात विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र के भीतर आते हैं और उनके लिए उपयुक्त पाटन-रोधी शुल्क का भुगतान किया जाता है।
- vii. याचिकादाता ने पहले यह सिद्ध किया था कि कंपनी द्वारा किए जा रहे क्रियाकलाप उत्पादन करने के हैं तथा पृथ्वी, हुआवेई और वीएमसीएल जैसी अन्य कंपनियों द्वारा किए जा रहे क्रियाकलाप उत्पादन के क्रियाकलाप नहीं बनते थे। याचिकादाता ने इस संबंध में अनेक तर्क दिए थे जिन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्णयों में उल्लिखित किया गया है और जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। याचिकादाता ने मूल जांच के दौरान द्वारा किए गए अपने निवेदनों को पुनः व्यक्त किया है तथा मूल जांच में अंतिम निर्णयों का हवाला दिया है:-

(क) सभी उत्पादों के लिए उत्पादन का अर्थ समान नहीं हो सकता है। मौजूदा जांच के प्रयोजनार्थ उत्पादन का स्पष्ट तात्पर्य उत्पादन के ऐसे क्रियाकलाप से है जिसके फलस्वरूप “विचाराधीन उत्पाद” का “उत्पादन होता” है। इसके अतिरिक्त उत्पाद को उसके अनेक प्राचलों से अभिज्ञात किया जाता है, जैसे कि उत्पाद की विशेषताएं, उत्पादन प्रोद्योगिकी, उत्पादन प्रक्रिया, कार्य और उपयोग, कीमत निर्धारण तथा सीमा शुल्क का वर्गीकरण। एसडीएच उपस्कर के उत्पादन में अनेक कार्य/चरण निहित होते हैं जिनमें संकल्पन, विस्तृत रेखा-चित्र और डिजाइन तैयार करना (ब्लू प्रिंट) शामिल हैं।

(ख) प्रचालनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर मेसर्ज तेजा अपेक्षित विशिष्ट संघटकों को अभिज्ञात करता है और विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर तत्व विकसित करता है, जिनसे बांछित प्रचालन के लिए क्रियात्मक हार्डवेयर निर्मित होते हैं। हार्डवेयर और विकसित सॉफ्टवेयर के लिए ब्लू प्रिंट के आधार पर ही एक पूर्णतया क्रियात्मक “प्रोटोटाईप” निर्मित किया जाता है। ऐसे “प्रोटोटाईप” में हार्डवेयर और जड़ित सॉफ्टवेयर दोनों ही शामिल होते हैं, जो कि उपस्कर को चलाने और नेटवर्क में अन्य उपस्करों के साथ उसकी सुसंगति के लिए आवश्यक होते हैं, जैसा कि नेटवर्क की प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से देखा जाता है। मेसर्ज तेजा द्वारा विकसित किया गया “प्रोटोटाईप” का परीक्षण, जांच विनिर्देशन और परीक्षण सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके किया जाता है। पूर्णरूपेण क्रियात्मक “प्रोटोटाईप” में चेसीज, रैक्स, पीसीबी, केबिल्स, सॉफ्टवेयर आदि सम्मिलित होते हैं। एसडीएच प्रोटोटाईप के परीक्षण के बाद मेसर्ज तेजा की आवश्यकता के अनुसार पीसीबी पर संघटकों की सोल्डरिंग करने के लिए ईएमएस को अनुदेश दिए जाते हैं। मुख्यतया सोल्डरिंग क्रियाकलापों के लिए कुछ असेम्बली लाईन प्रचालन करने के लिए कैरियर मीडिया पर ईएमएस को विभिन्न सॉफ्टवेयर भी प्रदान किए जाते हैं। मेसर्ज तेजा को जिसकी भारत में विनिर्माण सुविधा केन्द्र स्थापित है, ईएमएस द्वारा सोल्डर किए हुए गैर-क्रियात्मक पीसीबी की आपूर्ति की जाती है। मेसर्ज तेजा के ग्राहकीकृत चेसीज, रैक्स, पीसीबी,

केविल्स, सॉफ्टवेयर तत्व आदि जैसे संघटकों के साथ एसडीएच उपस्कर को एकीकृत किया जाता है और उनका परीक्षण किया जाता है। एकीकरण क्रियाकलाप के बाद कठोर परीक्षण, डिबगिंग और गुणवत्ता नियंत्रण की प्रक्रिया की जाती है। परीक्षण, डिबगिंग और रिवर्किंग क्रियाकलाप में विशेष टेस्ट जिम्स, टेस्ट विनिर्देशन और परीक्षण सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं जो कि एसडीएच उपस्कर की विनिर्माण प्रक्रिया का जटिल कार्य है।

- (ग) पाटन-रोधी विधि में यह परिभाषित नहीं है कि “उत्पादन” अथवा “विनिर्माण” में क्या सम्मिलित है। “घरेलू उत्पादक” के शब्दांश के कार्य-क्षेत्र का अनुमान, अधिनियम की धारा 9 क और नियमावली के प्रावधान, जिसका उल्लेख नीचे किया गया है, के प्रयोजनार्थ और उद्देश्य के संदर्भ में लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त नियमावली, घरेलू उद्योग और घरेलू विनिर्माता को विशेष रूप से पृथक् करती है। सभी घरेलू उत्पादक, घरेलू उद्योग नहीं होते हैं।
- (घ) अन्य विधान के अंतर्गत “विनिर्माता” की परिभाषा को, पाटन विधि के अंतर्गत घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र को समझने के प्रयोजनार्थ थोपा नहीं जा सकता है। इस सिद्धांत को, काजी नुरुल एचएचएच पेट्रोल पम्प बनाम उप निदेशक, ईएसआई कॉर्पोरेशन के मामले में जिसे 2009 (240) ईएलटी 481 (एससी) में सूचित किए गए माननीय उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय में अच्छी तरह से निर्दिष्ट किया गया है।
- (ङ) ऐसे अनेक विधान हैं जिनमें “विनिर्माण”, “विनिर्माण प्रक्रिया” अथवा “विनिर्माता” को परिभाषित किया गया है। इनमें कैक्टरी अधिनियम, 1948, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986, बीडी और सिगार कामगार अधिनियम, 1966, भार और मापन मानक अधिनियम, 1976 तथा विदेशी व्यापार नीति शामिल हैं। इन विधान के अंतर्गत उत्पादन की परिभाषा विशेष रूप से भिन्न हैं जो कि यह सिद्ध करती हैं कि इस कारण मात्र से ही कि किसी कंपनी द्वारा उत्पाद शुल्क का भुगतान किया जाता है तथा इसलिए उसे सीमा शुल्क विधि के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, ऐसी कंपनी को मौजूदा विधि के प्रयोजनार्थ एक घरेलू उत्पादक माना जाना चाहिए।
- (च) पाटन-रोधी विधि के अंतर्गत उत्पादक का निर्धारण करने के लिए संबद्ध तर्क ऐसे तथ्य हैं जैसे कि भारत में निवेश का स्तर, किए जा रहे क्रियाकलापों में निहित तकनीकी सुविज्ञता, भारत में मूल्य संवर्धन की सीमा, रोजगार का स्तर, अन्य लागत तथा भारत में किए जा रहे क्रियाकलाप जिनके फलस्वरूप वस्तु का उत्पादन होता है।
- (छ) उत्पाद के मूल्य का अत्यधिक विशिष्ट भाग का श्रेय भारत में विकसित सॉफ्टवेयर को जाता है जिसे आंशिक रूप से ईएमएस द्वारा असेम्बली के चरण में लगाया जाता है, जिसका आंशिक रूप से उपयोग भारत में जांच, डिबगिंग और पुनः कार्यचालन के लिए किया जाता है और साथ ही इसे एसडीएच नेटवर्क के कार्यचालन के लिए प्रयोक्ताओं को भी दिया जाता है। सॉफ्टवेयर के विकास में वस्तुओं का उत्पादन करना भी शामिल है।
- (ज) उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने इस बात पर विचार किया कि क्या सॉफ्टवेयर को “वस्तु” शब्द की परिभाषा में शामिल किया जाएगा और इसलिए क्या सॉफ्टवेयर के विकास को वस्तुओं के उत्पादन के रूप में माना जाएगा।
- (झ) तेजस भारत में सॉफ्टवेयर का विकास करता है, जिसके एक भाग को संवहन मीडिया पर ईएमएस को उपलब्ध कराया जाता है और तेजस द्वारा ऐसी गतिविधि “वस्तुओं” के उत्पादन के रूप में मानी जाती है।
- (ञ) ईएमएस से वस्तुओं के वापस आने के पश्चात् तेजस ठोस गतिविधियाँ भी करता है। इस अवस्था में उत्पाद एसडीएच के रूप में कार्यात्मक नहीं होता है और यह उत्पादन की मध्यस्थ अवस्था में होता है। “इन हाऊस” विकसित सॉफ्टवेयर, परीक्षण विशेषताओं और परीक्षण प्रक्रियाओं का उपयोग कर तेजस द्वारा असेंबलिंग और परीक्षण गतिविधियाँ की जाती हैं। तेजस अन्य सॉफ्टवेयर कारकों जैसे “नेटवर्क प्रबंधन सॉफ्टवेयर, कारक

प्रबंधन साफ्टवेयर, अनुप्रयोग साफ्टवेयर आदि" का भी विकास करता है, जो कि एसडीएच नेटवर्क को कार्यात्मक बनाने के लिए आवश्यक है।

- (ट) इस तहरीर पर विचार करते हुए कि कामगार भी विनिर्माता है, तेजस ने तर्क दिया कि जबकि संपूर्ण प्रक्रिया कामगारों द्वारा की जाती है अतः वह विनिर्माता की हैसियत हासिल कर सकते हैं। तथापि जहाँ उत्पादन गतिविधि के एक भाग का ही आऊटसोर्स होता है और ज्यादातर गतिविधियाँ विनिर्माता द्वारा की जाती हैं, ऐसे मामले में यह नहीं कहा जा सकता कि कुछ प्रक्रियाओं के आऊटसोर्स होने के कारण निर्मित वस्तु के विनिर्माता के रूप में उसकी पहचान समाप्त हो जाती है।
- (ठ) 2001 (129) ईएलटी 278 (एससी) में सूचित श्री रामविनयाल और केमिकल उद्योग बनाम सीसी, मुंबई के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि असेंबल करने वाले को अभिव्यक्त विनिर्माता के बराबर नहीं माना जा सकता है। 2009 (241) ईएलटी 380(टी) में सूचित यूनाइटेड टेलिकॉम लिमिटेड बनाम सीसी, बंगलौर के मामले में यह कहा गया कि मोबाइल फोन तब तक वैसे नहीं बनते हैं जब तक कि विनिर्माता द्वारा सॉफ्टवेयर लोड नहीं किया जाता है। इसलिए मात्र असेंबल करने वाला विनिर्माता बन जाएगा, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। मात्र एसडीएच उपकरणों के उत्पादन में शामिल एक या दो प्रक्रियाओं को आऊटसोर्स किए जाने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि तेजस एसडीएच उपकरणों का विनिर्माता नहीं है।
- (ड) विनिर्माण की सामान्य परिभाषा के तहत, वीएमसीएल और पृथ्वी द्वारा की गई गतिविधियों को विनिर्माण नहीं माना जा सकता, लेकिन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के डीमिंग प्रावधानों के तहत इसे विनिर्माण माना जा सकता है। डीमिंग प्रावधान का सही-सही अर्थ लगाया जाना चाहिए और केवल उस अधिनियम के प्रयोजन से लगाया जाए जिसमें वह अधिनियमित किया गया है।
- (ढ) याचिकाकर्ता ने तेजस और आयातकों द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों का एक तुलनात्मक अध्ययन उपलब्ध कराया है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वर्तमान उत्पाद के प्रयोजन के लिए उत्पादन का तात्पर्य, किए गए अनुसंधान एवं विकास पर आधारित विशिष्टता विकास और हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग, आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिलकर सहभागी घटक विकास गतिविधियाँ, प्रोटो टाइप उत्पाद विकास, भारत में नेटवर्क प्रबंधन सॉफ्टवेयर का विकास, एलिमेंट प्रबंधन सॉफ्टवेयर का विकास, परीक्षण प्रक्रियाओं का विकास, भारत में परीक्षण विशेषताएँ और परीक्षण सॉफ्टवेयर का विकास, भारत में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के विशिष्टताओं और गुणवत्ता के संदर्भ में उत्पाद सत्यापन, संपूर्ण एसडीएच प्रोटो टाइप (हार्डवेयर + सॉफ्टवेयर संयुक्त) की विशिष्टताओं और गुणवत्ता के संदर्भ सहित पूर्ण सत्यापन, बोर्डों का विनिर्माण, एसडीएच हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर का संस्थापन, संपूर्ण एसडीएच बॉक्स (हार्डवेयर + सॉफ्टवेयर) की अंतिम असेम्बलिंग और परीक्षण, बिक्री बाद (पोस्च सेल्स) बग फिक्स" करना, बिक्री बाद "उत्पाद विशिष्टता को बढ़ाना (इनहेन्समेंट) / उन्नयन (अपग्रेडेशन)", बिक्री बाद- पुर्जों की आपूर्ति/ प्रौद्योगिकी सहायता (सपोर्ट) जैसी गतिविधियों से है और दावा किया कि तेजस इन सभी प्रचालनों का निष्पादन करता है, अतः उसे उत्पादक के रूप में माना जाना आवश्यक है, जबकि पृथ्वी, वीएमसीएल मात्र भारत में असेंबल करने का कार्य करते हैं।
- (ण) तेजस ने भारत में ग्राहक सहायता और सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिए भारी निवेश किया है। तेजस भारत में अपने उत्पादों के लिए "संस्थापन सेवाओं, संवर्द्धन, बग फिक्स" करने में सक्षम है।
- (त) तेजस ने भारत के भीतर या बाहर विभिन्न घटकों और उनकी खरीद और विकास की पहचान की है तथा तर्क दिया है कि ईएमएस की मदद लेना इसकी डिजाइन और विकास में मदद लेने से काफी अलग है। वीएमसीएल और पृथ्वी के मामले में, यह वास्तविकता है कि हुआवेई, जो संबंधित उत्पाद का विनिर्माता है, ने असेंबलिंग प्रचालन (यदि कोई हो) कार्य को वीएमसीएल और पृथ्वी पर छोड़ा है। तेजस, जो उत्पादक है, के मामले में, कंपनी ने सोलडरिंग कार्य ईएमएस ठेकेदारों पर छोड़ा है।
- (थ) ईएमएस की गतिविधियों के संबंध में, याचिकाकर्ता ने दलील दी कि यह विश्व स्तर पर स्वीकार किया जाता है कि ईएमएस कंपनियाँ मात्र अनुबंध विनिर्माता हैं, जिनके पास उत्पाद अधिकार, आईपीआर या तकनीकी जानकारी का कोई स्वामित्व नहीं है, वे मात्र काम करने वाले श्रमिक हैं, जो विभिन्न उद्योगों से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए सोलडरिंग / परीक्षण सेवाएं प्रदान करते हैं।

- (द) याचिकाकर्ता ने कंपनी के संबंध में संबंधित उत्पाद का उत्पादक होने अथवा नहीं होने का निर्धारण करने के लिए यूएसआईटीसी द्वारा छह कारकों के विचार पर भी भरोसा किया गया है। ये कारक हैं-
- फर्मों के पूंजी निवेश की विस्तार और स्रोत;
 - अमेरिका की उत्पादन गतिविधि में शामिल तकनीकी विशेषज्ञता;
 - संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पाद मूल्य संवर्द्धन;
 - रोजगार स्तर;
 - संयुक्त राज्य अमेरिका में भेजी गई (सोर्सड) पूर्जों की मात्रा और प्रकार; और
 - उत्पादन निर्णय लिए जाने वाले स्थान सहित समान उत्पाद के उत्पादन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई अन्य लागत और गतिविधियाँ।
- (ध) याचिकाकर्ता ने विभिन्न पुस्तकों जैसे मैसर्स स्ट्रेनबूक और हूपर की डंपिंग एंड सब्सिडिज, मैसर्स क्लाइव स्ट्रेनबूक और फिलिप बेन्टली की द लॉ एंड प्रोसिजर्स गवर्निंग द इम्पोजिशन ऑफ एंटी डंपिंग एंड काउंटरवैलिंग झूटिज इन यूरोपियन कम्युनिटी, जूडिथ कजाको, जोहान ह्यूमन और जॉर्ज मिरांडा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की ए हेंडबुक ऑन एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन्स, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग की एंटी डंपिंग एंड काउंटरवैलिंग झूटी हेंडबुक में उभरते न्यायशास्त्र का भी संदर्भ दिया है। याचिकाकर्ता ने इसी, भारत और अमेरिका के अधिकारियों के भी कई निर्णयों का संदर्भ दिया है।

viii) डीआरआई ने आयातकों के खिलाफ जांच की है और बोडाफोन, एयरटेल, आइडिया आदि सहित 6 टेलीकॉम कंपनियों द्वारा एसडीएच उपकरण आयात के दौरान कथित तौर पर एंटी-डंपिंग झूटी चोरी के लिए 427 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान करने की मांग की है। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क से बचने के लिए या तो गैर एसडीएच अथवा अन्य उपकरणों के हिस्से के रूप एसडीएच की गलत व्याख्या करने संबंधी दूरसंचार कंपनियों के बारे में विशिष्ट जानकारी अधिकारियों के पास उपलब्ध थी। विचाराधीन उत्पाद को स्पष्ट करना प्राधिकरण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ताकि आयातकों द्वारा अपनाए गए इस तरह के व्यवहार को रोका जा सके और एंटी डंपिंग झूटी अपना उद्देश्य पूरा कर सके।

(IX) निम्नलिखित कारणों से हुआवेई भारत विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माता नहीं है-

(क) तेजस के विपरीत, "हुआवेई भारत" ने एसडीएच से संबंधित किसी सॉफ्टवेयर जैसे "एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, परीक्षण सॉफ्टवेयर या प्रबंधन सॉफ्टवेयर" का विकास नहीं किया है, जो कि एसडीएच बक्से के निर्माण के लिए आवश्यक है।

(ख) हुआवेई भारत ईएमएस चरण से पहले एसडीएच उत्पाद अवधारणा, अनुसंधान एवं डिजाइन और पूरी तरह कार्यात्मक एसडीएच प्रोटोटाइप के विकास में शामिल नहीं है। यहां तक कि उनके चीनी प्रौद्योगिकी भागीदार हुआवेई चीन द्वारा प्रदान की गई विशिष्टताओं और सॉफ्टवेयर तत्वों का उपयोग कर ईएमएस चरण के बाद असेंबल और परीक्षण कार्य किया जाता है। हुआवेई भारत की क्षमताएँ केवल हुआवेई द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने तक सीमित है।

(ग) हुआवेई भारत, भारत में केवल असेंबल करने का कार्य करता है और "घरेलू विनिर्माता" होने का इसका दावा निराधार है। उत्पादन से संबंधित अधिकतर कार्य हुआवेई चीन द्वारा भारत से बाहर किया जाता और इसलिए हुआवेई भारत एक घरेलू विनिर्माता नहीं हो सकता। दरअसल, पृथ्वी और वीएमपीएल जैसी कंपनियों ने वर्तमान जांच में भाग भी नहीं लिया है।

(घ) भारत में, हुआवेई भारत द्वारा प्रमुख अनुसंधान और विकास गतिविधियां नहीं की जाती है। कंपनी अपनी मूल कंपनी की प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है और इसके सॉफ्टवेयर भी अपने नहीं हैं।

(ङ) उत्पाद विनिर्माण (माल की लागत और उससे ऊपर) से संबंधित विभिन्न "मूल्य वर्धित गतिविधियों" में खर्च की गई राशि का एक बड़ा हिस्सा अनुसंधान एवं विकास पर खर्च होता है। इस प्रकार अनुसंधान एवं विकास कार्य, उत्पाद सृजन में महत्वपूर्ण गतिविधि है। अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी विकास, जो कि एक महत्वपूर्ण गतिविधि है, के अतिरिक्त तेजस भारत में तेजस की 'उत्पाद डिजाइन टीम द्वारा भारत में विकसित 'परीक्षण प्रक्रियाओं और विशिष्टताओं' के आधार पर "समान उत्पादों" की ठोस असेंबलिंग और परीक्षण भी करता है। इसके विपरीत, हुआवेई भारत उपर्युक्त उत्पादों के लिए कोई भी प्रौद्योगिकी विकास या अनुसंधान कार्य नहीं करता है और यहां तक कि आयातित उत्पादों की अंतिम असेंबली और परीक्षण भी संबंधित देशों में स्थित उनके विदेशी प्रौद्योगिकी प्रदाताओं / विनिर्माता द्वारा दिए गए विनिर्देशों के अनुसार करता है।

(च) हुआवेई भारत के पास भारत के भीतर "संवर्द्धन बग फिक्स" करने के लिए प्रौद्योगिकी का बुनियादी ढांचा नहीं है और वे "संवर्द्धन और बग फिक्स" उपलब्ध करने के लिए अपने विदेशी प्रौद्योगिकी प्रदाताओं / विनिर्माताओं पर निर्भर हैं। यह सत्य है कि एसडीएच विनिर्माता होने का दावा करने के बावजूद, उनके पास अपने स्वयं का "उत्पाद दस्तावेज़" भी नहीं है (वे परीक्षण प्रयोजनों के लिए हुआवेई चीन को उत्पाद उपलब्ध करा रहे हैं), इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे केवल आयातक और व्यापारी हैं, न कि एसडीएच के घरेलू विनिर्माता।

(छ) इसके अतिरिक्त, हुआवेई भारत एसडीएच उपकरण मॉडलों का विनिर्माता होने का दावा करते हैं जिसका विकास पहले ही उनकी मूल कंपनी द्वारा किया गया था। हुआवेई भारत ने इस तरह के मॉडलों के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधि करने हेतु पूंजी निवेश नहीं किया है अथवा न ही विकास किया है, इसे पहले से ही हुआवेई चीन द्वारा विकसित किया गया है और स्थापित किया गया है।

(ज) हुआवेई भारत निविदा दाखिल करता है और अपने पिछले आपूर्ति इतिहास को दिखाने के लिए हुआवेई चीन द्वारा की गई आपूर्ति का उल्लेख करता है। इसके अतिरिक्त हुआवेई नीदरलैंड की ओर से दायर प्रश्नावली प्रतिक्रिया भी यह दर्शाती है कि उसने हुआवेई भारत को हुआवेई चीन द्वारा निर्मित उत्पादों को बेचा है। इसलिए, यह पता चलता है कि हुआवेई भारत के पास भारत में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की अपनी स्वयं की क्षमता नहीं है और निविदाओं की खरीद के लिए अपनी मूल कंपनी पर निर्भर रहता पड़ता है। याचिकाकर्ता को यह समझने में असफल रहा है कि यदि दोनों कंपनियों की अपनी अलग कानूनी पहचान हैं, तो कैसे हुआवेई भारत निविदा दस्तावेजों में परीक्षण प्रयोजनों के लिए हुआवेई चीन के उत्पाद उपलब्ध करा सकती है।

(झ) हुआवेई भारत मात्र पीसीबी और एसएमटी डिवाइस आयात करता है। इनका आयात करने के पश्चात, मात्र (क) पीसीबी का पॉपुलेटिंग और (ख) कार्ड को असेंबल करने हेतु छोड़े गए कार्य को भारत में किया जाता है। विशेष संस्थाओं द्वारा पीसीबी को पॉपुलेटिंग करने का कार्य किया जाता है और कार्ड को असेंबल करने का कार्य एक स्कू-ड्राइवर प्रौद्योगिकी है। इस प्रकार हुआवेई भारत किसी अन्य कंपनी द्वारा तैयार पीसीबी को प्राप्त कर और मात्र भारत में कार्डों की असेंबल करने का कार्य कर अपने को विनिर्माता होने का दावा कर रहा है।

(ञ) उत्पादन सुविधाओं के आधार पर हुआवेई भारत द्वारा दावा किए गए उत्पादन की मात्रा कुछ भी नहीं है।

(ट) ट्राई ने भारतीय उत्पाद और भारतीय विनिर्मित उत्पादों के बीच भेद किया है। हुआवेई भारत द्वारा विनिर्मित किए जाने का दावा किए गए उत्पाद भारतीय उत्पाद नहीं है, और इसलिए, कंपनी को भारत में उत्पाद के विनिर्माता के रूप में नहीं माना जा सकता।

(ठ) इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवा (ईएमएस) के ठेकेदार, डिजाइन और विकास में मदद लेने वालों से काफी अलग है। हुआवेई भारत के मामले में, यह वास्तविकता है कि हुआवेई चीन, जो संबंधित उत्पाद का विनिर्माता है, ने असेंबली प्रचालन (यदि कोई हो) कार्यों को हुआवेई भारत पर छोड़ा है। तेजस, जो उत्पादक है, के मामले में, कंपनी ने सोलडरिंग कार्य ईएमएस ठेकेदारों पर छोड़ा है।

(ड) यह विश्व स्तर पर स्वीकार किया जाता है कि ईएमएस कंपनियां मात्र अनुबंध निर्माता हैं, जिनके पास उत्पाद अधिकार, आईपीआर या तकनीकी जानकारी का कोई स्वामित्व नहीं है, वे मात्र काम करने वाले श्रमिक हैं, जो विभिन्न उद्योगों के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए सोलडरिंग / परीक्षण सेवाएं प्रदान करते हैं। दरअसल हुआवेई भारत भी ईएमएस कंपनियों की सेवाएं ले रहा है।

(ढ) भले ही यह माना जाता है कि हुआवेई भारत एक भारतीय विनिर्माता है, वही विचाराधीन उत्पाद के निर्यातक से संबंधित है और उसने उत्पाद का आयात किया है। कंपनी ने आयातक प्रश्नावली प्रतिक्रिया भी प्रस्तुत की है जबकि हुआवेई चीन कंपनी ने निर्यातक प्रश्नावली प्रतिक्रिया भरा है। इसलिए, कंपनी किसी भी मामले में अयोग्य घरेलू उद्योग है और कंपनी के उत्पादन का मानक निश्चरण करने पर विचार नहीं किया जा सकता है।

(x) याचिकाकर्ता को वर्तमान याचिका दायर करने के लिए पात्र घरेलू विनिर्माता के रूप में माना जाना चाहिए, चूंकि उनके द्वारा घटकों या उप असेंबलियों के अनुपूरक का आयात किया गया है।

(xi) भारत में एक उद्योग संघ, टीईएमए (दूरसंचार उपकरण विनिर्माता संघ), ने पुष्टि की कि तेजस एसडीएच के अधिकांश हिस्से का व्यापारी है और हमारे रुख की पुष्टि करता है कि कौन उत्पादक है और कौन आयातक / व्यापारी है।

(xii) अन्य घरेलू उत्पादकों जैसे फिब्रॉम इंडिया लिमिटेड (फिब्रॉम) और कोरल टेलीकॉम स्पष्ट रूप से तेजस के पक्ष का समर्थन करते हैं और आयातकों/असेंबल करने वालों जैसे हुआवेई भारत, जो मात्र विदेशी प्रौद्योगिकी के उत्पादों का आयात करते हैं, को घरेलू एसडीएच विनिर्माता के रूप में नहीं मानते हैं।

(xiii) मूल निष्कर्ष में प्राधिकरण का मानना है कि (क) याचिकाकर्ता का उत्पादन का भारतीय उत्पादन में बड़ा हिस्सा है, (ख) संबद्ध देशों से याचिकाकर्ता द्वारा किया गया आयात विचाराधीन उत्पाद के आयात की पुष्टि नहीं करता है चूंकि ये बहु-उपयोग घटक हैं और एकल घटक नहीं हैं, (ग) नियम 2(ख) के अर्थों के भीतर घरेलू उद्योग के रूप में मानने से याचिका कर्ता को अयोग्य घोषित करने हेतु संबद्ध देश से याचिका कर्ता द्वारा किया गया आयात किसी भी मामले में नगण्य है, (घ) इस तथ्य से बिना पक्षपात किए कि पक्षों जैसे हुआवेई द्वारा की गई गतिविधि उन्हें एक उत्पादक समझे जाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, उनके द्वारा बहुत अधिक आयात किए जाने के कारण वे, किसी भी मामले में, पात्र उत्पादक नहीं हैं।

(xiv) याचिकाकर्ता की पात्रता के संबंध में, याचिकाकर्ता द्वारा गैर संबद्ध देशों और संबद्ध देशों से कुछ एकल उपयोग घटकों का आयात किया जा रहा है, इससे संबंधित विवरण याचिका में शामिल है, इससे जुड़ा विवरण प्राधिकरण को हमारे दिनांक 7 नवंबर, 2014 के पत्र के माध्यम से उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अलावा भी, विवरण अभी अथवा आगे जाँच के दौरान उपलब्ध करा दिया जाएगा, यदि प्राधिकरण द्वारा मांगा जाता है। एकल उपयोग घटक विचाराधीन उत्पाद के आयात की स्थापना नहीं करते हैं चूंकि प्राधिकरण ने विशेष रूप से अंतिम निष्कर्ष में विचाराधीन उत्पाद के दायरे से पूर्ण / घटकों के आयात को बाहर रखा है।

(xv) याचिकाकर्ता का ध्यान मूल जांच के समय प्राधिकरण द्वारा पहचान कराई गई पूर्ण उत्पादन प्रक्रिया को शुरू करने में निहित है। प्राधिकरण को यह मानने के लिए कि कोई कंपनी उत्पादक है, उसके द्वार संगत पाई गई सभी गतिविधियाँ मूल जाँच के समय की जा रही थी और वर्तमान में याचिका कर्ता द्वारा की जा रही है। इसके अतिरिक्त, याचिका कर्ता विचाराधीन उत्पाद, जैसाकि उपर बताया गया है, के उत्पादन और बिक्री में शामिल अनिवार्य उत्पादन गतिविधि करता आ रहा है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि यह निराधार है कि याचिकाकर्ता की गतिविधियाँ केवल अनुसंधान एवं विकास तक ही सीमित है। दरअसल, यह उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने वर्तमान क्षति अवधि में 1000 करोड़ रुपये से अधिक के उपकरण बेचे हैं और याचिकाकर्ता विगत 14 सालों से कायम हैं।

(xvi) वर्तमान में याचिकाकर्ता द्वारा की जा रही गतिविधियाँ वही हैं जैसा कि मूल जांच के समय याचिकाकर्ता द्वारा निष्पादित की जा रही थीं। यहां तक कि मूल जांच के समय, याचिकाकर्ता चीन से कुछ पूर्ण / घटकों का आयात कर रहा था। वर्तमान अवधि में भी याचिकाकर्ता ने चीन से कुछ पूर्ण / घटकों का आयात किया है। इस प्रकार, किसी भी मामले में चीन से याचिकाकर्ता द्वारा आयात किए गए पूर्ण / घटकों के कारण घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने संबंधी याचिकाकर्ता के हक से याचिकाकर्ता को वंचित करना नहीं चाहिए।

(xvii) इस प्रकार के उपकरणों के लिए याचिकाकर्ता द्वारा किया गया आयात - (i) पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध देश से उल्लिखित वस्तु के कुल आयात (ii) कुल भारतीय उत्पादन (iii) घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और (iv) भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए कुल मांग के संबंध में बहुत ही गौण प्रतिशत है।

(xviii) जहाँ तक तर्क का संबंध है कि हुआवेई भारत, भारत में सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है और दूरसंचार विभाग द्वारा भी इसे स्वीकार किया गया है तथा कंपनी मुनाफा कमा रही है, यह कहा जाता है कि इसे साबित करने के लिए न ही हुआवेई भारत या किसी अन्य इच्छुक पार्टी द्वारा कुछ भी उपलब्ध कराया गया है।

(xix) पार्टियों द्वारा सूचीबद्ध दावा किए गए अन्य उत्पादकों के नाम विचाराधीन उत्पाद के घरेलू विनिर्माता के रूप में उन्हें स्थापित नहीं करते हैं। इसके अलावा, इन कंपनियों ने भी याचिका का विरोध नहीं किया है। इसके अलावा टीईएमए (दूरसंचार उपकरण विनिर्माता एसोसिएशन), जो भारत में एक उद्योग संघ है, ने पुष्टि की है कि तेजस एसडीएच के बड़े-भाग का व्यापारी है और हमारे रुख की पुष्टि करता है कि कौन उत्पादक है और कौन आयातक / व्यापारी है। अन्य घरेलू उत्पादकों जैसे फिब्रॉम इंडिया लिमिटेड (फिब्रॉम) और कोरल टेलीकॉम स्पष्ट रूप से तेजस के पक्ष का समर्थन करते हैं।

(xx) अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ उत्पादन प्रक्रिया की न केवल अभिन्न भाग है अपितु सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। डिजाइन और विकास के बिना, संबंधित उत्पाद का उत्पादन करना संभव नहीं है। तथ्य यह है कि आईपीआर को भारत में बनाया गया है, इसका स्वामित्व भारतीय कंपनी के पास है जो कि भारतीय प्रबंधन के तहत है और यह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ईएमएस गतिविधि एक वृद्धिशील मूल्य वृद्धित गतिविधि है। तेजस पहले भारत में पूर्ण उत्पाद प्रोटोटाइप विकसित करता है और तब पीसीवीए के बड़े पैमाने पर सोलडरिंग के लिए ईएमएस के साथ उत्पादों की आवश्यक विशेषताओं को साझा करता है। ईएमएस रोजगार कार्य के आधार पर कार्य करता है और वे मात्र पीसीवी के सोलडरिंग कार्य के लिए तेजस के 'निर्देशों' का पालन करते हैं। ईएमएस बाद की गतिविधियाँ जैसे असेंबलिंग, एकीकरण और परीक्षण गतिविधियाँ भारत में की जाती हैं। तेजस भारत के साथ-साथ विदेश में भी, रोजगार कार्य के आधार पर, जब भी आवश्यकता हो, ईएमएस कंपनियों का उपयोग करता है।

(xxi) इसके अलावा, विरोध करने वाली इच्छुक पार्टियों ने यह नहीं बताया कि कैसे 15 सूत्री मापदंड बदल दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने अपने लिखित बयान में विचाराधीन उत्पाद के भारतीय विनिर्माता के रूप में हुआवेई भारत नहीं माने जा सकने के संबंध में विस्तार से बताया है। किसी अन्य कंपनी ने विचाराधीन उत्पाद के एक विनिर्माता होने का दावा नहीं किया है।

(xxii) हुआवेई भारत द्वारा भारत में अनुसंधान और विकास कार्य करना हुआवेई भारत को विचाराधीन उत्पाद का एक विनिर्माता नहीं बनाता है। विचाराधीन उत्पाद का अनुसंधान और विकास कार्य किए जाने की आवश्यकता होती है और विशेष रूप से हुआवेई भारत के उत्पाद के लिए न कि अन्य समूह कंपनियों के उत्पाद के लिए। हुआवेई भारत के संयंत्र का दौरा करने और उनके परिसर में की जा रही सभी गतिविधियों को देखने हेतु प्राधिकरण से अनुरोध किया जात है।

(xxiii) जहाँ तक हुआवेई भारत के दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण के लिए डीटीए विनिर्माण लाइसेंस का संबंध है, इसका यह मतलब नहीं है कि कंपनी वास्तव में संबद्ध उत्पाद का विनिर्माण कर रही है।

(xxiv) जहाँ तक हुआवेई भारत के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण प्रमाणपत्र का संबंध है, याचिकाकर्ता अंतिम निष्कर्ष को संदर्भित करता है और भरोसा करता है जिसमें प्राधिकरण ने उल्लेख किया है कि मात्र आबकारी पंजीकरण या उत्पाद शुल्क के भुगतान का अर्थ यह नहीं है कि कंपनी उत्पाद का उत्पादक है। याचिकाकर्ता, प्राधिकरण से इसी दृष्टिकोण का पालन करने का अनुरोध करता है।

(xxv) मूल जांच में विस्तार से विश्लेषण करने के बाद प्राधिकरण ने निर्धारित किया था कि किन सभी गतिविधियों को संबंधित उत्पाद का विनिर्माण कहा जाएगा और उस आधार पर घरेलू उद्योग को परिभाषित किया जा सकेगा। एक कंपनी जिसके पास उत्पाद की आईपीआर नहीं है और मात्र विदेशी उत्पाद के लिए असेंबल कार्य करता है, को पाटनरोधी जांच में विचाराधीन उत्पाद के एक घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना जा सकता।

(xxvi) हुआवेई भारत स्वयं इस बात से सहमत है कि वे मात्र घटकों को असेंबल करते हैं और प्राधिकरण ने अपने निष्कर्ष में स्पष्टतः उल्लेख किया है कि मात्र असेंबल कार्य को विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण के रूप में नहीं माना जा सकता है। प्राधिकरण ने यह कहीं नहीं उल्लेख किया है कि जबकि एक कंपनी को इन प्रत्येक गतिविधि को करने की आवश्यकता नहीं है, यह संभव है कि इन कदमों में से कुछ में एक अथवा एक से अधिक उप-प्रक्रियाएँ शामिल हो सकती हैं, जो स्वतंत्र रूप से की जा सकती हैं अथवा इन प्रक्रियाओं में से कुछ को कुछ कंपनियों द्वारा एकीकृत किया जा सकता है। पूर्ण और घटकों, असेंबल और उप-असेंबल करने के कार्य को शामिल किए जाने के संबंध में प्राधिकरण ने मूल अंतिम निष्कर्ष में विस्तृत तर्क प्रस्तुत किया है, जिसे संदर्भित किया जाता है तथा इस पर भरोसा किया जाता है।

(xxvii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में विनिर्माता की परिभाषा को पाटनरोधी शुल्क जांच के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।

(xxviii) हुआवेई के बाजार में हिस्सेदारी के संबंध में, यह उल्लेख किया गया है कि हुआवेई चीन और हुआवेई भारत दोनों ने अपनी अन्य संबंधित कंपनियों के साथ मिलकर उत्तर प्रश्नावली प्रस्तुत की है और उनके आकड़ों के आधार पर डंपिंग और क्षति मार्जिन स्थापित किया जाएगा।

(घ.3) प्राधिकरण द्वारा जाँच

19. विभिन्न हितवद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों में तेजा नेटवर्क लि. के पात्र घरेलू उद्योग होने पर प्रश्न उठाया है जिसका कुल भारतीय उत्पादन में मुख्य भाग है। इसके अतिरिक्त हुआवाई इंडिया ने भी यह दावा किया है कि वस्तुतः हुआवाई इंडिया संबद्ध उत्पाद का मुख्य विनिर्माता है जबकि तेजा नेटवर्क लि. नहीं है और इस प्रकार उसे ही घरेलू उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए और न कि तेजा नेटवर्क को। तथापि, तेजा नेटवर्क ने यह तर्क दिया है कि वह एक पात्र घरेलू उद्योग है जिसका कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख अंश है और हुआवाई इंडिया जिसने कि विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माता होने का दावा किया है, वास्तव में ऐसे उत्पाद का आयातक है और वह विनिर्माता नहीं है और इस प्रकार उसे पात्र घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना जा सकता है।

20. प्राधिकरण यह उल्लेख करता है कि नियम 2 (ख) निम्नानुसार व्यवस्था है :-

“(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ‘घरेलू उद्योग’ पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

21. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत यह प्रमुख आवश्यकता है कि ऐसे उत्पादक, जो घरेलू उत्पादक होने का दावा करते हैं, वे आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों से संबंधित नहीं हैं अथवा वे स्वयं वहाँ से आयातक हैं। इस संबंध में प्राधिकारी ने उल्लेख किया है कि हुआवाई टेलीकम्यूनिकेशन (इंडिया) कंपनी प्रा. लि. (हुआवेई) अपने स्वयं के कथन के अनुसार हुआवाई टेलीकम्यूनिकेशन कंपनी लि. (हुआवेई चीन) से संबंधित पक्ष है। हुआवेई भारत ने वर्तमान अंतिम समीक्षा जाँच और दायर आयातक प्रश्नावली-जवाब के जांच अवधि में विचाराधीन उत्पाद का भी आयात किया है। चूंकि आवाई इंडिया, हुआवाई चीन की एक पूर्ण स्वामित्वाधीन सामूहिक कंपनी है और उसने मौजूदा निर्णायक समीक्षा जांच की जांच अवधि में विचाराधीन उत्पाद का आयात भी किया है और उसने आयातकों की प्रश्नावली के उत्तर भी दायर किए हैं। इसलिए हुआवाई इंडिया को, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) की परिभाषा के भीतर मौजूदा निर्णायक समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ एक घरेलू उद्योग नहीं माना जाएगा।

22. भारत में संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों की ओर से मैसर्स तेजस नेटवर्क लिमिटेड द्वारा आवेदन दायर किया गया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने जांच नहीं किए जाने वाले देशों से कुछ पृथक घटकों का आयात किया है और कुछ पृथक घटकों का आयात चीन जन.गण. से किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह तथ्य नियम 2 (ख) के तहत याचिकाकर्ता को एक घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने के संबंध में अयोग्य घोषित नहीं करता है। इसके अलावा, किसी भी मामले में याचिकाकर्ता द्वारा किए गए पृथक पूर्यों या घटकों के आयात को विचाराधीन उत्पाद के आयात के रूप में प्रतिष्ठित नहीं करता है।

23. क्या तेजस नेटवर्क भारत में संबंधित उत्पाद को "घरेलू उद्योग" के रूप में प्रतिष्ठित करता है, इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार तेजस नेटवर्क लिमिटेड के संबद्ध वस्तु का प्रमुख उत्पादक है और इसका उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का प्रमुख अनुपात है जैसा कि नीचे तालिका में देखा जा सकता है -

		2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि (अप्रैल, 13 - जून, 2014)	जांच अवधि (वार्षिकीकृत)
तेजस नेटवर्क	संख्या	***	***	***	***	**
अन्य	संख्या	***	***	***	***	**
कुल		28,178	9,769	9,669	14,716	11,773
तेजस नेटवर्क	%	74	67	80	85	85
कुल	%	26	33	20	15	15

24. विस्तृत जांच के बाद प्राधिकारी यह मानते हैं कि तेजस नेटवर्क लिमिटेड के पास जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात है और नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग का अधिकारी है तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के मामले में निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है।

25. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि अनेक हितबद्ध पक्षकारों ने प्रतिवाद किया है कि एस डी एच उपस्करों के उत्पादन में किन वस्तुओं को शामिल किया गया है, क्या उनमें असेम्बली ऑपरेशन को भी उत्पादन के रूप में माना जाना चाहिए, क्या 15 सूत्री मानदंड को पूरा करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत कोई कानूनी अपेक्षा है जिससे इस बात की संतुष्टि हो कि कंपनी भारत में उत्पादन कर रही है आदि। प्राधिकारी ने इन तर्कों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और वह नोट करते हैं कि यह मुद्दा इसलिए उठा है क्योंकि उत्पाद की अनेक विशिष्टताएं हैं, जिसके लिए उत्पादन प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, कंपनियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों की प्रकृति विशिष्ट है जोकि भारत और संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण अथवा असेम्बलिंग करने के कार्य में लगी हुई है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जांच के दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 के अंतिम निर्णय में प्राधिकारी ने पहले से ही निम्नलिखित को शामिल किया है : (1) यह उपयुक्त होगा कि अलग-अलग मामले के आधार पर उत्पादन की समान भाषा के रूप में उत्पादन के अभिप्राय को समझा जाना उपयुक्त नहीं होगा, (2) वास्तव में विभिन्न विधियों और विनियमों द्वारा उत्पादन की विभिन्न भाषा वर्णित की गई है/मानी गई है जैसाकि विभिन्न विधियों के अंतर्गत उत्पादन के विभिन्न अभिप्राय/विवेचन से पता चलता है, (3) उत्पादन की परिभाषा को विशिष्ट विधि और विनियमन के संबंध में विचार किए जाने की आवश्यकता है, उसमें दी गई विशिष्ट परिभाषाएं और विवेचन तथा उनके उद्देश्य और लक्ष्य जिसके लिए विधि बनायी गई है, (4) उदाहरण के लिए मौजूदा मामले में पाटनरोधी शुल्कों के प्रयोजनार्थ यह अत्यधिक अनुपयुक्त होगा कि कंपनी को इसलिए घरेलू उद्योग माना जाए क्योंकि वह कुछ संवर्धनात्मक उत्पादन क्रियाकलाप कर रही है तथा (5) पाटनरोधी विधि के प्रयोजनार्थ उन्हीं वस्तुओं पर विचार किया जाना चाहिए जिनका उत्पादन आउटपुट में एक पर्याप्त परिवर्तन लाने के लिए उसकी इनपुट का प्रयोग किया गया है। इसलिए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मूल जांच के अंतिम निर्णय में इस मुद्दे का समाधान पहले से ही कर लिया गया है और इस पुनरीक्षा जांच में ऐसा कोई नया तथ्य सामने नहीं आया है जिसके लिए प्राधिकारी को इस मामले में भिन्न विचार प्रकट करने की आवश्यकता हो।

(इ) विविध मुद्दे

इ 1. निर्यातकों / आयातकों / उपयोगकर्ताओं / अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध

26. निर्यातकों / आयातकों / उपयोगकर्ताओं / अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा की गई निम्नलिखित अनुरोध किए गए :-

- i. अनिवार्य प्रारंभिक जांच पाटनरोधी नियमों के नियम 23 (1 बी) और पाटनरोधी समझौते के अनुच्छेद 11.3 की बिल्कुल गलत व्याख्या है। याचिकाकर्ता अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए अन्य मामलों के कानूनों की गलत व्याख्या पर भरोसा करता रहता है।
- ii. याचिकाकर्ता का उत्तर अपूर्ण है और इसने केवल घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गोपनीयता की कोई वारंटी दिए बिना जानकारी या औचित्य उपलब्ध कराने का मात्र दावा किया है। ओवम रिपोर्ट का सार, पाटन कीमत, क्षति मार्जिन और कीमत में कटौती जैसी सूचना, हाथ से निकल गए आदेशों / प्रस्तावों के लिए तेजस द्वारा पेश की गई कीमत पर आधारित है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गयी संबंधी सूचना के लिए उन्होंने क्षमता उपयोग के संबंध में कोई भी आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया है। कोई भी सूचकांक आंकड़ा या सार उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- iii. याचिका में जांच की अवधि के विपरीत एक अलग अवधि की जानकारी दी गई है। यह तो अनुबंध-। को पढ़ने मात्र से स्पष्ट हो जाता है कि नियम 10 के तहत निर्धारित पाटन और अनुबंध को बिना किसी अपवाद के जांच की अवधि से सम्बन्धित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इसका यह भी मतलब है कि पाटन (और तत्संबंधी गणना), नियम में जहाँ भी आता है, को नियम 5 सहित जांच की अवधि से अवश्य संबंधित होना चाहिए। इसलिए पदनामित प्राधिकरण आवेदन में सबूत की सटीकता और पर्याप्तता का आकलन करने के अपने दायित्व को पूरा करने में नाकाम रहा है।
- iv. वर्तमान याचिका में अधूरी जानकारी है, जो कि वर्तमान पहल के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त है। प्राधिकारी ने याचिका के साथ प्रस्तुत साक्ष्य की पर्याप्तता की जांच नहीं कर के विश्व व्यापार संगठन एडीए के अनुच्छेद 5.3 का उल्लंघन किया है।
- v. याचिकाकर्ता ने या तो पूरी मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है अथवा याचिका में उपलब्ध कराई गई जानकारी का आधार या समर्थन करने वाला सबूत उपलब्ध नहीं करवाया है। याचिकाकर्ता ने गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई जानकारी का कोई सार्थक सारांश उपलब्ध कराने से परहेज किया है। याचिकाकर्ता कारणों का विवरण उपलब्ध कराने में विफल रहा है कि क्यों गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना संक्षिप्तीकरण के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है।
- vi. अपनी ओर से अधिकारी सभी सूचना को मात्र इसलिए गोपनीय नहीं मान सकते क्योंकि सूचना जानकारी उपलब्ध कराने वाले पक्ष ने गोपनीयता का अनुरोध किया है।
- vii. याचिका में याचिकाकर्ता को धारा VI- लागत सूचना में नियोजित पूंजी पर निवेश का दावा करने के लिए एक औचित्य देना होता था। हालांकि, आवश्यकता के बावजूद, याचिकाकर्ता ने गोपनीय सूचना का दावा किया है और उत्तर देना निश्चित किया है तथा और एक स्पष्टीकरण दिया है।
- viii. ओवम रिपोर्टें यह सूचना उपलब्ध नहीं कराती है कि कंपनियाँ घरेलू रूप से संबद्ध वस्तु का उत्पादन कर रहीं हैं अथवा इसका आयात कर रही हैं। इस मामले में स्थिति का निर्धारण करने हेतु ओवम रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
- ix. याचिकाकर्ता ने भारत में उत्पादन, भारत में संबद्ध वस्तु के आयात और भारत में उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी की गणना करने के लिए ओवम रिपोर्ट का इस्तेमाल किया है। ओवम रिपोर्ट पर निर्भरता साफ़ तौर पर गलत और अवैध है। किसी भी जर्नल या पत्रिका में बाजार की जानकारी, आयात आंकड़ों का एक विकल्प नहीं हो सकता। हर मामले में विचाराधीन आयात की मात्रा और उत्पाद के मूल्य का निर्धारण करने के लिए डीजीसीआई एंड एस द्वारा आयात आंकड़ों पर भरोसा करना प्राधिकरण की स्थापित प्रथा है।
- x. डीजीसीआई एंड एस से अपने दम पर आयात आँकड़ों को प्राप्त करने से और इच्छुक पक्षों के लिए इसे उपलब्ध कराने से प्राधिकरण को कोई नहीं रोक सकता है। भारत की डार्ड स्टाफ मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन में बनाम भारत सरकार के सीईएसटीएटी आदेश के मामले में सामान्य मूल्य, आयात की मात्रा और मूल्य, पहुँच मूल्य आदि जैसे मानकों का निर्धारण करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा ओवम रिपोर्ट जैसी व्यापार पत्रिकाओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
- xi. ओवम रिपोर्टें मात्र भारत में दूरसंचार उपकरणों से संबंधित बाजार की सूचना ही उपलब्ध कराती है, वह भी मात्र मूल्य के संदर्भ में। ओवम रिपोर्ट भारत में एसडीएच प्रसारण उपकरण में विभिन्न कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी की सूचना उपलब्ध कराती है लेकिन इन उपकरणों के घरेलू उत्पादन या आयात किया गया होने संबंधी विवरण उपलब्ध नहीं कराती है। याचिकाकर्ता ने उल्लिखित उत्पाद के लिए अपने स्वयं के औसत बिक्री मूल्य द्वारा मूल्य के लिहाज से आयात को विभाजित करके इस रूपांतरण को किया है। स्पष्ट नहीं है कि किस आधार पर याचिकाकर्ता ने अपनी औसत बिक्री मूल्य पर विचार किया है, क्या याचिकाकर्ता ने अपने उच्च मूल्य के उत्पादों अथवा कम मूल्य के उत्पादों या इसकी कीमतों की भारित औसत के कीमतों पर विचार किया है, यह स्पष्ट किया जाना है।
- xii. अन्य देशों में बिक्री के प्रतिबंध के निराधार दावे किए गए हैं। इसके विपरीत, आवेदक ने खुद को संबद्ध देशों से कम होते आयात के साथ-साथ भारत में कम होते मांग का दावा किया है।

- xiii. आवेदक ने किसी भी न्यायोचित कारणों को उपलब्ध कराए बिना काफी गोपनीय जानकारी रखा है और यह नियम के तहत अनुमत्य नहीं है। पर्याप्त प्रथम दृष्टया सबूत और सार्थक गैर गोपनीय सारांश के अभाव में वर्तमान कार्यवाही में अपने हितों की ठीक से रक्षा करने की क्षमता काफी हद तक कम हो गई है।
- xiv. आवेदक ने पाटन और क्षति की संभावना की पुनरावृत्ति को साबित करने के लिए माध्यमिक स्रोत, ओवम से अविश्वसनीय आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। आवेदक ने ओवम आंकड़ा का उपयोग किया गया है और हुआवेई चीन की एकमात्र बाजार में हिस्सेदारी होने को हुआवेई की बाजार हिस्सेदारी के रूप में कोट किया है। यह आंकड़ा हुआवेई की बाजार हिस्सेदारी के साथ साथ हुआवेई भारत की संचयी हिस्सादारी भी शामिल करता है। इस तथ्य की पुष्टि किए बिना, प्राधिकारी को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। प्राधिकारी को जल्द से जल्द ओवम और आवेदक से स्पष्टीकरण की मांग करनी चाहिए।
- xv. ओवम ने स्वयं आंकड़े का समर्थन करने के लिए मना कर दिया है जिसे अपनी याचिका में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसका स्रोत ओवम होने की घोषणा की गई है। ईमेल द्वारा उठाए गए एक सवाल के अनुसरण में ओवम के प्रतिनिधि ने उत्तर दिया कि यह एसडीएच और दूरसंचार उपकरणों के संबंध में आयात का हिस्सा दर्शाते हुए आवेदक द्वारा दी गई संख्या का समर्थन नहीं करता है।
- xvi. आरोपित डीआई ने 'ओवम आंकड़ा' को गलत तरीके से पेश किया है जो वैसे भी एक द्वितीयक स्रोत है और हुआवेई चीन की एकमात्र बाजार में हिस्सेदारी होने को हुआवेई की बाजार हिस्सेदारी के रूप में कोट किया है। हालांकि, यह प्रस्तुत किया गया है कि उल्लिखित रिपोर्ट के रूप में परिलक्षित हुआवेई की बाजार हिस्सेदारी हुआवेई भारत और हुआवेई चीन की संचयी हिस्सेदारी है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि 266% तक उच्च शुल्क लगाने से बाजार में मांग और आपूर्ति की प्रवृत्ति को बदलने की बहुत क्षमता है। इस तरह के उच्च शुल्क के कारण, वर्तमान समीक्षा अवधि के दौरान भारत में हुआवेई चीन से आयात न्यूनतम स्तर पर था।
- xvii. ओवम अधिकारियों ने खुद कहा है कि आरोपित डीआई ने अपनी रिपोर्ट में आंकड़ों की गलत व्याख्या की है और उन्होंने आंकड़ों के इस तरह के दुरुपयोग पर अत्यंत असंतोष व्यक्त किया है जैसा डीआई द्वारा अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। उन्होंने उपयुक्त अधिकारियों को ओवम रिपोर्ट के आंकड़ों के इस तरह के दुरुपयोग के खिलाफ शिकायत दाखिल करके डीआई पर आरोप लगाने की अपनी मंशा व्यक्त की है।
- xviii. आरोपित डीआई ने जोरदार ढंग से दलील दी कि पूर्जों और घटकों के आयात के बाद सभी सहायक गतिविधियां भारत में ही की गई हैं। तथापि उनकी अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2007-08 में परिलक्षित तथ्यों के आलोक में उनका यह पक्ष विरोधाभासी है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से माना है कि उन्होंने सेलेस्टिका इंक और फ्लेक्सट्रॉनिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड जैसी वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवा कंपनियों को अपनी विनिर्माण गतिविधियां आउटसोर्स की है। इसके अतिरिक्त, इसी में उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके उत्पादों का विनिर्माण भारत और थाईलैंड में किया जा रहा है। इसके अलावा, डीजीएडी ने भी अपने अंतिम निष्कर्ष में पाया है कि आरोपित डीआई ने भारत से इतर अन्य देशों जैसे थाईलैंड, सिंगापुर, ताइवान में पीसीबी का निर्माण कार्य शुरू किया है। इसलिए स्पष्ट है कि आरोपित डीआई ने अंतिम समीक्षा संबंधी अपनी याचिका में इस तथ्य को छुपाया है चाहे उसने दावा किया है कि इसका विनिर्माण भारत में किया गया है। आरोपित डीआई ने अपने द्वारा आयात किसी भी विशिष्ट वस्तुओं का आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया है, ऐसे में यह निर्धारित करना असंभव हो जाता है कि वास्तव में कौन सी वस्तु का आयात किया जा रहा है और किस देश से। ऐसी अत्यधिक गोपनीयता स्वभाविक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है।
- xix. भारत में आयात, निर्यात मूल्य, पट्टन कीमत, पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन आदि जैसी सूचना का दावा काल्पनिक आधार पर किया गया है, जो कि कानून के प्रावधानों के विपरीत है।
- xx. याचिका में आयात की मात्रा, आयात मूल्य, सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के संबंध में कोई तथ्य नहीं है। इच्छुक पक्षों को आयात के आँकड़ें उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। आयात आँकड़ों की कोई भी वैध विश्वसनीय स्रोत के बिना पाटनरोधी जांच आयोजित की जा रही है।
- xxi. यदि याचिकाकर्ता अधिसूचना संख्या 125 /2010-सीमा शुल्क दिनांक 16 दिसम्बर 2010 में उत्पाद की गुंजाइश के अनुसार डीआरआई की सूची में आयातित वस्तुओं को वर्गीकृत करने की स्थिति में था, तो आयात आंकड़ों में आयात को आसानी से वर्गीकृत करने के साथ साथ श्रेणीबद्ध किया जा सकता था।
- xxii. यदि आयात आँकड़ों को याचिका में भी उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो, इच्छुक पक्ष गंभीर रूप से सार्थक याचिका की जांच में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।
- xxiii. संबद्ध उत्पाद की विशिष्ट प्रकृति को देखते हुए, बहुत संभव है कि पूर्जों / घटक जो जांच दायरे से बाहर हैं, को कुल आयात में शामिल कर लिया गया हो। इस पहलू की विस्तार से जांच की जानी है।

- xxiv. याचिका में संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य पर पहुंचने के लिए अनुसरण की गई कार्यप्रणाली की भी व्याख्या नहीं की गई है। याचिका कच्चे माल की लागत, सुविधाएं और उपभोज्य, मूल्यहास, श्रम और अन्य लागत और लाभ मार्जिन पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराती है। लागत से संबंधित याचिका की पूरी धारा VI को गोपनीय रखा गया है। याचिका में निहायत कमी है और याचिकाकर्ता ने याचिका में अतिरिक्त गोपनीयता का प्रयोग किया है।
- xxv. डब्ल्यूटीए पाटनरोधी समझौते के अनुच्छेद 6.5.1 और पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के उल्लंघन में आवेदक द्वारा गोपनीयता का अत्यधिक दावा :- आवेदक ने किसी भी न्यायोचित कारणों का उल्लेख किए बिना सूचना काफी गोपनीय रखी है और जो इस नियम के तहत अनुमत्य नहीं है। इस प्रकार ऐसी सूचना जो गोपनीयता की आड़ में रोकी गई है, के उदाहरण निम्नानुसार हैं: उत्पादन मात्रा; घरेलू बिक्री की मात्रा; निर्यात बिक्री की मात्रा; मात्रा में मालसूची; क्रमांक में प्रति सीओपी; क्रमांक में प्रति यूनिट बिक्री मूल्य; क्रमांक में प्रति यूनिट लाभ / (हानि); उत्पादकता; प्रतिशत में आरओसीई; प्रपत्र IV बी; प्रारूप क से सीआईआई तक में लागत सूचना; वित्तीय परिणामों का आरओसी संस्करण आदि। ओवम रिपोर्ट और आयात आकड़ा छूटाई की कार्यप्रणाली को भी गोपनीय रखने का दावा किया गया है।

(ड.2) घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

27. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध हैं:

- i. इस दलील के संबंध में कि याचिकाकर्ता द्वारा अपनाया गया आयात स्रोत बेतुका है और भारत में आयात की सही स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है, याचिकाकर्ता ने आयातक-वार आंकड़ा संग्रह किया है जो दर्शाता है कि याचिका के आंकड़ों के अनुसार आयात विचाराधीन उत्पाद के आयातों को पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार आयात विचाराधीन उत्पाद के सभी आयात को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।
- ii. इसके अलावा डीआरआई जांच ने उजागर किया है कि गैर एसडीएच या पूर्जों / घटकों के रूप में आयात का वर्णन कर पर्याप्त आयात किए जा रहे हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि यह सब आयात बिना सूचना के हो रहे हैं और सार्वजनिक सूचना के अभाव में याचिका से बाहर बने हुए हैं।
- iii. सभी उत्तरदाता निर्यातकों ने अत्यधिक गोपनीयता दावे का सहारा लिया है जो याचिकाकर्ता को अपनी टिप्पणी पूरी तरह से देने से रोकता है। गोपनीयता का दावा, नियमों के नियम 7 के अनुसार नहीं हैं। उदाहरण के लिए, प्रत्येक उत्तरदाता कंपनी ने भारत को निर्यात के लेन-देन-वार विवरण में उत्पाद विवरण का गोपनीय जानकारी के रूप में दावा किया है। गोपनीय व्यावसायिक सूचना के रूप में इस तरह की सूचना का दावा करने का कोई औचित्य नहीं है। इच्छुक पक्षों ने पूरी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया और उनके द्वारा दायर की गई सूचना के गैर गोपनीय सारांश में भी इसे नहीं दिया गया है। प्रश्नावली उत्तर का गैर गोपनीय संस्करण निहायत अपर्याप्त है। इच्छुक पक्षों ने ऐसी सूचना भी नहीं दी है जिसे नियमों के तहत दिया जाना बाध्यकर है। ऐसी सूचना भी, जो कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, की भी जानकारी गैर गोपनीय संस्करण में नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त, इच्छुक पक्षों द्वारा दायर गोपनीय होने की दावा की गई सूचना का गैर-गोपनीय सार भी उचित और पर्याप्त नहीं है ताकि याचिकाकर्ता को एक सार्थक टिप्पणी दी जा सके। इच्छुक पक्षों ने केवल खाली प्रारूप दिया है। यह स्वभाविक न्याय के सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन है।
- iv. याचिकाकर्ता ने यथानिर्धारित विस्तृत सूचना उपलब्ध कराई है और याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से संतुष्ट होने के बाद प्राधिकरण ने प्रथमदृष्टया जांच शुरू कर दी है। याचिकाकर्ता के दावे का मुकाबला करने के लिए निर्यातकों को प्रासंगिक सूचना दाखिल करने से कोई भी नहीं रोकता है। हालांकि विरोध करने वाले इच्छुक पक्ष अपने पक्ष को पुष्ट करने वाला कोई सबूत उपलब्ध कराए बिना मात्र जोरदार तर्क प्रस्तुत करने पर संयम रखा है।
- v. याचिकाकर्ता ने मात्र उन सूचनाओं पर दावा किया है जो व्यापार संवेदनशील सूचना है और सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हैं। याचिकाकर्ता ने उपलब्ध कराई गई उन सूचनाओं को छोड़ कर जो कि सार तैयार करने हेतु अतिसंवेदनशील नहीं हैं, सूचनाओं के लिए पर्याप्त गैर गोपनीय सार उपलब्ध कराया है, जैसा कि उत्तरदाता इच्छुक पक्षों ने अत्यधिक गोपनीय सूचना होने का सहारा लेकर किया है।
- vi. इस तथ्य के कारण या तो सहायक स्रोत या डीजीसीआई एंड एस आकड़ा का उपयोग कर आयातित एसडीएच उपकरण के प्रकार की पहचान करना संभव नहीं है क्योंकि एसडीएच उपकरण का आयात उपकरण के रूप में किया जा रहा है तथा आयात सीकेडी-एसकेडी या उप-असेंबलिंग करने के रूप में हैं। उत्पाद का आयात इन रूपों में होता है और तत्पश्चात भारत में उपकरण के रूप में असेंबल किया जाता और तब उपभोक्ताओं को इसकी आपूर्ति की जाती है। इसलिए, वर्तमान अवधि के दौरान किए गए एकल आयात के लिए निर्यात मूल्य निर्धारित करना संभव नहीं है।

- vii. इस संबंध में तर्क है कि निर्यातक अपने उत्तर में सूचना उपलब्ध कराने के लिए कठोर मानकों के अधीन हैं, दूसरी ओर, घरेलू उद्योग समान कठोर मानकों के अधीन नहीं है, यह प्रस्तुत किया गया है कि निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के विपरीत याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की छानबीन, जाँच के हर स्तर पर की जाती है।
- viii. याचिकाकर्ता ने जांच की अनिवार्य पहल के लिए विस्तृत तर्क उपलब्ध कराया है। तथापि चूँकि प्राधिकरण ने सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर जांच शुरू की है, अतः यह मुद्दा इस स्तर पर अप्रासंगिक हो जाता है।
- ix. याचिकाकर्ता ने जांच की शुरुआत के प्रयोजन हेतु पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराई है। नियम 5 की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा किया गया है। नियम 5 के तहत, निदेशक पदनामित प्राधिकारी को जांच शुरू करने हेतु सबूत की पर्याप्तता और सटीकता के संबंध में संतुष्ट होना आवश्यक है। प्राधिकरण ने जांच शुरू करने पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश संबंधी निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है। यह स्थापित सिद्धांत है कि जांच की प्रगति के रूप में साक्ष्य की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार होता है।
- x. प्रयोक्ता संघ ने अपनी प्रस्तुतियाँ दायर कर दी है। हालांकि, प्रयोक्ता संघ के केवल एक सदस्य ने सूचना दायर की है। अन्य सदस्यों ने आयात की मात्रा, आयात मूल्य आदि के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। जाँच शुरू करने संबंधी नोटिस प्राधिकरण को प्रासंगिक सूचना उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक पक्षों को अवसर प्रदान करता है। हालांकि संघ ने कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है जो वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक हो।

(ड 3) प्राधिकारी द्वारा जाँच

28. इस संबंध में विवाद है कि आवेदक ने पर्याप्त और सही जानकारी उपलब्ध कराकर पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 (1 ख) के मामले में एक 'विधिवत पुष्टि' याचिका दायर नहीं की है, प्राधिकारी यह पाते हैं कि वर्तमान जांच को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध दर्शाते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथमदृष्टया सबूत और अधिनियम तथा नियमों के अनुसार जांच के न्यायोचित होने के आधार पर शुरू किया गया था।

29. जहाँ तक गोपनीयता के मुद्दों का सवाल है, प्राधिकारी यह पाते हैं कि ऐसी सूचना जो गोपनीय प्रकृति की है तथा इच्छुक पक्षों द्वारा गोपनीयता के आधार पर उपलब्ध कराई गई है, को प्राधिकारी द्वारा पालन किए गए सामान्य नियमों के अनुसार गोपनीयता की जाँच करने के पश्चात जहाँ भी सनद किया जाता है, उसी प्रकार रखा जाता है। जहाँ तक संभव हो, गोपनीयता के आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षों को गोपनीयता के आधार पर दर्ज सूचना की पर्याप्त गैर गोपनीय सार प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है। इसलिए, इच्छुक पक्षों की चिंताओं का पर्याप्त रूप से समाधान किया गया है।

30. आयात स्रोत और घरेलू उद्योग के ओवम रिपोर्ट के भरोसे के संबंध में, प्राधिकारी पाते हैं कि प्राधिकारी ने डीजीसीआईएस से लेन-देन वार आयात आकड़ा प्राप्त किया है और आयात की मात्रा तथा क्षति विश्लेषण के संबंध में इस पर भरोसा किया है।

(च) पाटन का मूल्यांकन - कार्यप्रणाली और मापदंड

बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

च. 1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

31. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- क) एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना इस कारण से नहीं की जा सकती कि संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। याचिकाकर्ता एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में एक उत्पादक से ऐसी सूचना प्राप्त नहीं कर पाया है। ऐसा उत्पाद होने के कारण समान वस्तु की तुलनात्मक प्रदर्शक कीमत, निर्यातक देश अथवा प्रदेश अथवा किसी उपयुक्त तीसरे देश से निर्यात किए जाने पर तब तक निर्धारित नहीं की जा सकती, जब तक कि आयातक - वार आकड़ों के साथ - साथ विस्तृत लेन - देन आयातों के आकड़े उपलब्ध न हों। याचिकाकर्ता को ऐसी सूचना से कोई संबंध नहीं है। याचिकाकर्ता ने अपनी सर्वोत्तम उपलब्धता के अनुसार सूचना उपलब्ध कराई है।
- ख) मामला शुरू करने से पूर्व इच्छुक पक्षकारों के विचार आमंत्रित करने के लिए भारतीय कानून में कोई प्रवाधान नहीं है। इसके अलावा, अब जबकि निर्यातकों ने अपने उत्तर दाखिल कर दिए हैं, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर होगा।
- ग) यह उत्पाद घरेलू बाजार में सीमित उपभोक्तों को बेचा गया है। याचिकाकर्ता भी विभिन्न निविदाओं में भाग ले रहा है और ऐसी निविदाओं/आदेशों के बारे में जानता है, जिन्हें याचिकाकर्ता ने खो दिया है। याचिकाकर्ता को निविदा में पूछे गए विनिर्देशनों की अच्छी तरह से जानकारी है और उन्हीं विनिर्देशनों के लिए अपनी कीमतें उद्धृत की हैं। चाहे खरीद घरेलू अथवा

अन्य स्रोत से है, विचाराधीन उत्पाद और उसके विनिर्देशन आपूर्तिकर्ता के अनुसार भिन्न नहीं है। वास्तव में विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उपभोक्ताओं द्वारा निर्धारित विनिर्देशनों के अनुरूप उत्पाद की कीमत उद्धृत / प्रस्तुत की जानी चाहिए। ये सभी निविदाएं “बंद निविदा” होती हैं, लेकिन सभी आपूर्तिकर्ताओं की बिक्री टीम द्वारा और याचिकाकर्ता द्वारा गहन निगरानी रखी जाती है। याचिकाकर्ता ने कुछ ऐसी निविदाओं के ब्यौरे संकलित किए हैं, जिनमें कि याचिकाकर्ता ने भाग लिया था लेकिन संबद्ध देशों में उत्पादको को खो दिया है।

घ) याचिकाकर्ता ने रक्षात्मक तरीका अपनाते हुए याचिकाकर्ता की कीमत को निर्यात कीमत के रूप में मानकर (निर्यात कीमत इस कीमत से कम होगी) पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है। वास्तव में वास्तविक कीमत इस कीमत से कम है। इस कीमत पर विचार करके निर्यात कीमत का निर्धारण, भारत के लिए निर्यातों से जुड़े सभी व्ययों की निर्यात कीमत को समायोजित करने के बाद कारखाना बाह्य स्तर पर किया गया है।

ड.) प्रतिवादी इच्छुक पक्षकों ने यह सिद्ध करने के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया कि तेजाज द्वारा गुम की गई निविदाएं कीमत से अलग कारकों के कारण से हैं। याचिकाकर्ता उत्पाद का निर्यात विकसित देशों सहित समूचे विश्व में कर रहा है। इससे अपने आप ही याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए उत्पाद की गुणवत्ता प्रमाणित हो जाती है। इसके अलावा, अब जबकि निर्यातकों ने उत्तर दे दिया है, उनके आंकड़ों पर सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए विचार किया जाएगा। इसके अलावा, अधिकतर निविदाकारों की तकनीकी बोली हैं, जिनमें अन्य कारकों को भी शामिल किया गया है।

च) कीमत कटौती और पाटन मार्जिन का निर्धारण आयातित उत्पादों के लिए है न कि घरेलू बिक्रियों के लिए है। घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त की गई निविदाएं उनकी घरेलू बिक्रियों के संदर्भ में हैं। इस बात के बावजूद कि निर्यातकों ने उत्तर दे दिया है, उनके आंकड़ों पर सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए विचार किया जाएगा।

छ) जहां तक बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का संबंध है, वास्तविक मैट्रिक्स वही रहे जो समीक्षा जांच और मूल जांच में थे और बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के दावे को अस्वीकार करने का कारण भी वर्तमान मामले में वही रहा। अतः बाजार अर्थव्यवस्था (एम ई टी) का दावा वर्तमान जांच में भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

ज) **च. 2 निर्यातकों, आयातकों और अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

32. निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- i. निर्यातकों ने वर्तमान जांच में पूरी तरह से सहयोग किया है और इसीलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध है कि वह उनके द्वारा दिए गए व्यापक निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में दर्ज आंकड़ों के आधार पर सहयोगी निर्यातकों के लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन प्रदान करें।
- ii. ई सी आई कंपनियों के प्रचालनों अथवा स्वामित्व नामों में ऐसा कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे कि पूर्व जांच में ई सी आई को प्रदान किए गए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार पर प्रभाव पड़ सके। अतः प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वह ई सी आई कंपनियों को व्यक्तिगत मार्जिन प्रदान करे।
- iii. मात्र सरकार की शेयर धारिता होने से अपने आप ही यह अर्थ नहीं निकलता कि सरकार कंपनी कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) अपील निकाय ने चीन के कतिपय उत्पादों के संबंध में निश्चयात्मक पाटन रोधी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क, डीएस/379/एबी/आर दिनांक 11.03.2011 में संयुक्त राज्य के मामले में इसे स्पष्ट रूप में माना है। कानून में ‘राज्य हस्तक्षेप’ शब्द की व्याख्या सरकार का एक विधायिका के रूप में हस्तक्षेप किए जाने के अर्थ से है।
- iv. पूर्व में कतिपय जांचों में निर्दिष्ट प्राधिकारी विभिन्न उत्पादों [कोल्ड रोलड स्टील मामला, थियोफिलाइन और कैफीन मामला] के लिए ऐसे ही मामलों में अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करता रहा है। विचाराधीन उत्पाद की विभिन्न क्षमता की बिक्री कीमत में अन्तर होने के कारण औसत कीमत का उपयोग करना उचित नहीं है, जैसा कि आवेदक ने याचिका में किया है। आवेदक ने विभिन्न विन्यास वाले विचाराधीन उत्पाद के लिए एक समान औसत बिक्री कीमत प्रदान की है। डी जी ए डी ने अपनी संकल्पना में यह त्रुटि की है कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल प्रत्येक उपस्कर के लिए एक साझा भारित औसत पाटन मार्जिन निर्धारित किया है। यह कहा जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल प्रत्येक एस डी एच उपस्कर में विभिन्न विन्यास, कार्यात्मक क्षमता, विशेषताएं और उपयोग शामिल हैं।

- v. यह कहा जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे के तहत शामिल किया गया प्रत्येक उपस्कर अलग प्रकार का एस डी एच उपस्कर है। यह भी कहा जाता है कि पाटन रोधी नियमावली के नियम 17 (3) और अधिनियम 9 क के तहत प्राधिकारी को जांच के तहत आने वाले प्रत्येक ज्ञात उत्पादक अथवा निर्यातक के लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन निर्धारित करना होता है। तथापि, डी जी ए डी ने एकल साझा पाटन मार्जिन का निर्धारण करके और विचाराधीन उत्पाद में शामिल किए गए सभी उपस्करों के लिए एक साझा जांच करके सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और पाटन रोधी शुल्क नियमावली, 1995 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
- vi. निर्यात कीमत आवेदक की कीमत के आधार पर है न कि वास्तविक 'निर्यात कीमत' के आधार पर जो कि पाटन रोधी अधिनियम और नियमों के तहत तर्कसंगत नहीं है। इस प्रकार आवेदक मूल जांच और वर्तमान जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन के आधार पर किसी भी संभावना को सिद्ध करने में असमर्थ रहा है। यह आधार तर्कसंगत नहीं है।
- vii. याचिकाकर्ता ने केवल इतना कहा है कि उसे एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमतों अथवा एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में निर्मित सामान्य मूल्य के संबंध में कोई कीमत संबंधी ब्यौरा नहीं मिल सका है। आवेदन स्पष्ट रूप से अधूरा है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को वर्तमान जांच में सामान्य मूल्य का आकलन करने के लिए पाटन रोधी नियमावली में प्रदान किए गए पहले दो विकल्पों को देखना चाहिए।
- viii. इसके अलावा, याचिकाकर्ता का अनुरोध और सामान्य मूल्य के आंकड़ें विभिन्न अन्य देशों और यूरोपीय संघ जैसे क्षेत्राधिकार में अपनाई गई जांच प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। पाटन रोधी नियमों के अनुबंध -1 के पैरा - 7 के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई कोई भी व्याख्या यूरोपीय कमिशन द्वारा लागू किए गए और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा शेनयांग मत्सुशिता मामले में किए गए निर्णय से अलग नहीं हो सकती।
- ix. याचिकाकर्ता ने गलती से भारत में उसके द्वारा व्यय की गई लागतों के साथ सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए अपेक्षित अपनी उत्पादन की लागत की बराबरी की है। याचिकाकर्ता और चीन जन. गण. से निर्यातक, दोनों के बीच प्रत्येक कार्यात्मक पहलू में असंख्य भिन्नताओं के अलावा, अलग अलग देशों में कार्य करने वाली अलग - अलग संस्थाएं हैं। ऐसी दो संस्थाओं की लागत की लागतों की बराबरी करना गलत प्रस्ताव है। याचिकाकर्ता की उत्पादन लागत, विशेषकर चीन जन. गण. में ऐसे विदेशी उत्पादकों से अपेक्षाकृत भिन्न ही होगी, जो कि संबद्ध उत्पाद का निर्माण करने के लिए स्थानीय रूप से सभी घटक प्राप्त कर सकते हैं।
- x. याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई सकारात्मक साक्ष्य अथवा आधार प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके आधार पर उसने सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए अपनी उत्पादन की लागत अपनाई है। इस प्रकार वह डब्ल्यू टी ओ के ए डी ए के तहत साक्ष्य प्रदान करने की अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ रहा है।
- xi. यदि निर्मित सामान्य मूल्य को याचिका के आधार पर पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाता है, तो साक्ष्य के साथ सामान्य मूल्य प्रदान करने की अपेक्षा ही निरर्थक हो जाएगी क्योंकि जब भी कीमत की कटौती / कम बिक्री होती है, तो सामान्य मूल्य निर्यातक के अनुमानित पाटन व्यवहार को दर्शाएगा, चाहे वास्तविक सामान्य मूल्य के सन्दर्भ में कोई पाटन न भी हुआ हो।
- xii. सहयोगी निर्यातक के रिकार्ड से पुष्टि किए गए आंकड़ों के आधार पर पाटन रोधी शुल्क लगाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसी संकल्पना को तुच्छ माना जाना चाहिए, अन्यथा इससे ऐसी कानूनी अपेक्षा निरर्थक हो जाएगी कि आवेदक द्वारा प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध कराए जाने चाहिए और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा ऐसे साक्ष्य की सटीकता और शुद्धता के संबंध में जांच की जानी चाहिए।
- xiii. याचिकाकर्ता ने सामान्य मूल्य के आधार पर पाटन रोधी शुल्क की गणना की है, जो कि याचिकाकर्ता की कीमत है। इसके अलावा, याचिका में कटौतियों के संबंध में ऐसी कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है जिन पर याचिकाकर्ता ने कारखाना बाह्य निर्यात कीमत निकाली है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने याचिका में मूलभूत त्रुटियों पर ध्यान नहीं दिया है।
- xiv. कोई भी निविदा प्राप्त करने के लिए केवल कीमत ही एकमात्र कारक नहीं होता है। उत्पाद की गुणवत्ता, ब्रांड मूल्य, प्रतिष्ठा, बिक्री के बाद सेवा तथा निविदाएं प्रदान करने और उन्हें पूरा किए जाने के संबंध में पूर्व के अनुभव आदि सभी का मूल्यांकन निविदा प्रदान करने से पूर्व किया जाना चाहिए। यह पूर्ण रूप से संभव है कि याचिकाकर्ता को न्यूनतम कीमतें उद्धृत करने के बावजूद निविदा नमिल पाई हो क्योंकि याचिकाकर्ता अन्य मानकों में कम है। संबद्ध देशों से बैचमार्क निर्यात कीमतों के लिए याचिकाकर्ता की कीमतों का उपयोग करना गलत होगा। परिणामस्वरूप पाटन मार्जिन की गणना पूर्णतया गलत होगी।

- xv. याचिकाकर्ता को निर्यात कीमत निकालने के लिए अपनी ऐसी सभी बोलियों में अपनी कीमतों का औसत भारित मूल्य लेना चाहिए था, जिन्हें उसने प्राप्त किया अथवा प्राप्त नहीं किया। याचिकाकर्ता का यह मानना है कि प्रतिस्पर्द्धी बोलीकर्ता ही आयातित वस्तुओं की आपूर्ति करता है। यह बिल्कुल संभव है कि अन्य बोलीदाता स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं की आपूर्ति करते हो क्योंकि भारत में ऐसे कई उत्पादक हैं। याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है, जिससे यह पुष्टि हो सके कि अन्य बोलीदाता आयातित उत्पाद उपलब्ध करा रहे हैं। याचिकाकर्ता ने इसी तरह से आयातों को वर्गीकृत करके आसानी से कारखाना बाह्य कीमत और पहुंच कीमत तय की होगी जैसा कि उसने डी आर आई के लिए किया था।
- xvi. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन की गणना करने के लिए अपनाई गई गणना कार्य पद्धति उपलब्ध नहीं कराई गई है जैसा कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अनुबंध के रूप में संलग्न किए जाने का दावा किया गया है।
- xvii. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कही भी अपने इस दावे को प्रमाणित करने के लिए कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि आयातित वस्तुएं कम कीमत की हैं।
- xviii. याचिकाकर्ता द्वारा आयातक के आकड़े उपलब्ध कराए जाने जरूरी हैं क्योंकि उनके द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण के संबंध में यही प्रमाण का आधार है। निर्यातक ने डी जी सी आई एंड एस अथवा आई बी आई एस जैसे विश्वव्यापी स्रोतों से याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान किए गए आयात संबंधी आकड़ों के लिए अनुरोध किया है जैसा कि उसने पूर्व जांच में किया था।
- xix. याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई भी वास्तविक साक्ष्य प्रदान नहीं किया है कि चीन अथवा इजराइल से विचाराधीन उत्पाद का निर्यात प्रमुख बाजारों में गिरा है, जहां याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि हुवेई से निर्यात पर रोक लगाई गई है। उपरोक्त तीन देशों में बिक्री करने से हुवेई पर रोक नहीं लगाई गई है, जिससे निर्यातक की बिक्रियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

च. 3. प्राधिकारी की जांच

33. धारा 9 क (1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

परंतु यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

चीन जन. गण. में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

34. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विगत तीन वर्षों में चीन जन. गण. को भारत तथा डब्ल्यू टी ओ के अन्य सदस्यों द्वारा पाटन रोधी जांचों में गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है। चीन जन. गण. को नियमों के अनुसार निर्यातक देश अथवा व्यक्तिगत निर्यातों द्वारा इस धारणा का खंडन किए जाने के अध्यक्षीन एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश के रूप में माना गया है।
35. पाटन रोधी नियमों के अनुबंध - I के पैरा 8 के अनुसार एक गैर - बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा का खंडन तभी किया जा सकता है जबकि चीन जन. गण. से निर्यातक पैरा 8 के उप पैरा (3) में यथा विनिर्दिष्ट मानकों के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य प्रदान करे और इसके विरुद्ध तथ्यों को प्रमाणित करे। चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के सहयोगी निर्यातकों / उत्पादकों के बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार की प्रश्नावली के उत्तर में पैरा 8 के उप - पैरा (3) में यथा उल्लिखित आवश्यक सूचना / पर्याप्त साक्ष्य पदान करने हैं ताकि प्राधिकारी निम्नलिखित मानकों पर विचार कर सके कि क्या :-

- क. मूल्यों, लागतों तथा इनपुट के साथ साथ कच्चे माल, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, आउटपुट, बिक्री तथा निवेश के बारे में चीन जन. गण. में संबंधित फर्मों के निर्णय आपूर्ति और मांग को दर्शाने वाले बाजारी संकेतों के अनुसार निर्णय किया जाता है और इस संबंध में राज्य का महत्वपूर्ण हस्तक्षेप नहीं होता है तथा क्या प्रमुख इनपुट की लागत पर्याप्त रूप से बाजार की कीमतों को दर्शाती है ;
- ख. ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतें और वित्तीय स्थिति, पूर्व गैर – बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से तोड़ – मरोड़कर ली जाती है, विशेषकर परिसंपत्तियों के मूल्यहास, अन्य बट्टे खाते में डाली गई वस्तुओं, वस्तु विनिमय व्यापार और घाटे की क्षतिपूर्ति के द्वारा भुगतान के संबंध में ;
- ग. ऐसी फर्मों दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अधीन है, जिनमें फर्मों के प्रचालन के लिए कानूनी निश्चितता और स्थायित्वता की गारंटी है ; और
- घ. विनियम दर परिवर्तन बाजार की दर पर किया गया ।
36. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी द्वारा जांच प्रारंभ करने संबंधी नोटिस जारी किए जाने के परिणामस्वरूप चीन की निम्नलिखित कंपनियों ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए हैं :-
- क. जैड टी ई कारपोरेशन लि., चीन जन. गण.
- ख. हुवेई टेक्नोलोजीज कं. लि., चीन जन. गण. (हुवेई चीन)
- ग. हुवेई इंटरनेशनल पी टी ई, सिंगापुर तथा हुवेई टैक इंवेस्टमेंट कं. लि. हांगकांग (हुवेई चीन की ग्रुप कंपनियां)
- घ. अल्काटेल – लुसेंट शंघाई बेल कं. लि., चीन जन. गण.
- ड. हैंगज़ोऊ ई सी आई टेलिकम्यूनिकेशन कं. लि., चीन जन. गण.
37. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मैसर्स हुवेई टेक्नोलोजीज कं. लि., मैसर्स अल्काटेल – लुसेंट शंघाई बेल कं. लि. और मैसर्स हैंगज़ोऊ ई सी आई टेलिकम्यूनिकेशंस कं. लि. ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार की प्रश्नावली दाखिल की है और गैर – बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा का खंडन किया है । इन उत्तर देने वाले उत्पादकों और निर्यातकों की निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर और बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार की प्रश्नावली के उत्तर की जांच की गई थी । मैसर्स हुवेई टेक्नोलोजीज कं. लि., चीन तथा मैसर्स हैंगज़ोऊ ई सी आई टेलिकम्यूनिकेशन कं. लि., चीन के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था के दावे से संबंधित उनके अभिलेखों की स्थल पर ही पुष्टि की गई है। मैसर्स अल्काटेल - लुसेंट शंघाई बेल कं. लि., चीन के संबंध में उनके अभिलेखों की पुष्टि टेबल – स्टडी के आधार पर की गई थी । बाजार अर्थव्यवस्था के दावे की स्थिति, जो पुष्टि के बाद प्रकट हुई, संक्षेप में इस प्रकार है :-

मैसर्स जैड टी ई कारपोरेशन लि. चीन जन. गण. के लिए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार

38. मैसर्स जैड टी ई कारपोरेशन लि. चीन जन. गण. ने कोई भी बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रश्नावली दाखिल नहीं की थी और इस प्रकार कंपनी को एम ई टी का दर्जा प्रदान नहीं किया गया ।

मैसर्स हुवेई टेक्नोलोजीज कं. लि., चीन जन. गण. के लिए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार

39. कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए सूचना / आकड़ों की चीन में कंपनी के परिसर में स्थल पर पुष्टि की गई थी और कंपनी को एक विस्तृत सत्यापन रिपोर्ट उन पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुई जारी की गई । यद्यपि कंपनी ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एम ई टी) के दर्जे के लिए दावा किया था, लेकिन सत्यापन के दौरान कंपनी कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं और इसके प्रोमोटर्स द्वारा निवेश की गई पूंजी के स्रोत का पूरा ब्यौरा / स्रोत देते हुए दस्तावेजों के साथ साक्ष्य प्रदान नहीं कर सकी । अतः कंपनी को यह सूचित कर दिया गया था कि चूंकि यह बुनियादी दस्तावेज / सूचना, जो कि बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दर्जा प्रदान करने के लिए जांच करने हेतु महत्वपूर्ण थे, उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया है, इसलिए घरेलू बिक्रियों और इसकी संबद्ध उत्पादन की लागत से संबंधित आकड़ों के सत्यापन के साथ आगे कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं है । अतः मैसर्स हुवेई टेक्नोलोजीज कं. लि., चीन जन. गण. को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान नहीं किया गया ।

मैसर्स अल्काटेल - लुसेंट शंघाई बेल कं. लि., चीन जन. गण. के लिए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार

40. अल्काटेल - लुसेंट शंघाई बेल कं. लि. (ए एस बी) के संबंध में यह उल्लेख किया गया था कि ऐसी चार कंपनियां हैं, नामतः अल्काटेल - लुसेंट पार्टिसिपेशंस चाइना; लुसेंट टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट कं. लि.; अल्काटेल - लुसेंट चाइना इन्वेस्टमेंट कं. लि.; और चाइना हुआक्सिसन पोस्टल एंड टेलिकम्युनिकेशन इकोनॉमिक डवलपमेंट सेंटर ("चाइना हुआक्सिसन"), जिनके पास अल्काटेल - लुसेंट - शंघाई बेल कं. लि. में शेयर हैं। उनका शेयरधारिता पैटर्न क्रमशः लगभग ***% ; लगभग ***% ; लगभग ***% और लगभग ***% है। पहली तीन कंपनियां अल्काटेल - लुसेंट ग्रुप का हिस्सा हैं। चौथी कंपनी राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी है। स्टेट - ओन्ड असेट सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कमिशन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ("एस ए एस ए सी") के पास चाइना रिफार्म होल्डिंग्स कारपोरेशन लि. के माध्यम से चाइना हुआक्सिसन में ***% इक्विटी हिस्सा है, जिसके पास अल्काटेल - लुसेंट शंघाई बेल कं. लि. में ***% की हिस्सेदारी है।
41. ए एस बी के बोर्ड में *** निदेशक हैं, जिनमें से *** चाइना हुआक्सिसन से नामित हैं। शेष निदेशक मैसर्स अल्काटेल लुसेंट पार्टिसिपेशन चाइना और मैसर्स अल्काटेल - लुसेंट चाइना इन्वेस्टमेंट कं. लि. के नामित हैं। ए एस बी ने यह तर्क दिया है कि कंपनी में निर्णय लेने में निदेशक मंडल पर सरकार के नामितों का प्रभाव अथवा असर नहीं है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कंपनी में राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों की शेयर धारिता के माध्यम से सरकार की महत्वपूर्ण मौजूदगी रहती है। वास्तव में निदेशक मंडल में ***% नामिती राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें से सरकार का एक नामित व्यक्ति निदेशक मंडल का अध्यक्ष भी होता है।
42. उपर्युक्त को देखते हुए ए एस बी में इस महत्वपूर्ण राज्य भागीदारी के साथ राज्य का हस्तक्षेप होने से इंकार नहीं किया जा सकता। मूल जांच में भी यही स्थिति मौजूद थी। ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है जो प्रतिकूल दर्शाता हो। तथापि, प्राधिकारी ने यह पाया है कि ए एस बी को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दर्जा प्रदान नहीं किया जा सकता।

मैसर्स हैंगज़ोऊ ई सी आई टेलिकम्युनिकेशन कं. लि., चीन जन. गण. के लिए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार

43. मैसर्स हैंगज़ोऊ ई सी आई टेलिकम्युनिकेशन कं. लि. चीन जन. गण. (एच ई टी सी) द्वारा प्रस्तुत सूचना / आकड़ों के स्थल पर सत्यापन के आधार पर, जो चीन में कंपनी के परिसर में किया गया था, कंपनी को एक विस्तृत सत्यापन रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान किया गया था। एच ई टी सी ने यह कहा है कि वह ऐसा उत्पादक है जिसे मूल जांच में बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दर्जा मिला था और यह भी कहा है कि कंपनी की स्वामित्व संरचना अथवा प्रचालन प्रक्रिया में मूल जांच से लेकर अब तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। प्राधिकारी ने कंपनी के रिकार्ड से यह सत्यापन किया कि एचईटीसी ई सी आई, टेलिकम लिमिटेड, इजराइल (ई सी आई) के पूर्ण नियंत्रण में प्रचालित होती है जिसका आधारटेल अविव, इजराइल में है और जो एच ई टी सी की ***% स्वामी बनी हुई है, यही मामला मूल जांच में भी था। निदेशक मंडल में पूरी तरह से इजराइली नागरिक हैं और एच ई टी सी के निदेशक मंडल में कोई भी चीनी नागरिक (सरकारी अथवा अन्य) नहीं है। अतः कंपनी ई सी आई, इजराइल के पूर्ण नियंत्रण में प्रचालित होती है। कंपनी ने प्रचालन के लिए ईस्टकॉम नामक एक जॉब वर्कर को नियुक्त किया हुआ है जो कच्चा माल खरीदकर एच ई टी सी को संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति करता है। ईस्टकॉम ई सी आई, इजराइल के निर्देशों पर लगभग समस्त कच्चे माल की खरीद करता है और यह ई सी आई, इजराइल ही है, जो विभिन्न कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं के साथ समझौता करता है, उनमें से अधिकांश चीन से बाहर के अन्तर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता हैं। प्राधिकारी ने कच्चे माल की खरीद की लागत की पुष्टि की है और इसकी इजराइल में कच्चे माल की खरीद की लागत से तुलना की। एच ई टी सी ने यह दर्शाया कि चीन में सामग्रियों की लागत और उत्पादन लागत इजराइल में सामग्रियों की लागत और उत्पादन लागत से तुलनीय है। एच ई टी सी ने इस संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज भी उपलब्ध कराए हैं - i) एक ई सी आई ग्लोबल आपूर्तिकर्ता अर्थात् ई जैड सी एच आई पी के लिए सैंपल ग्लोबल सप्लाय कांट्रैक्ट, ii) एच ई टी सी और ईस्ट कॉम के बीच पूर्व टर्नकी एग्रीमेंट, iii) इजराइल और चीन में जॉब वर्क अर्थात् फ्लैक्सट्रॉनिक्स और ईस्ट कॉम के बीच कीमत की तुलना, iv) सैंपल पावर इनवॉयस, v) कच्ची सामग्री के सैंपल की सूची, और vi) सैंपल फ्रेट इनवॉयस। उपरोक्त पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने यह पाया है कि मैसर्स हैंगज़ोऊ ई सी आई टेलिकम्युनिकेशन कं. लि., चीन जन. गण. (एच ई टी सी) ने यह सिद्ध करने के लिए सूचना और पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं कि यह कंपनी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालित हो रही है और इस प्रकार से बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के दर्जे के लिए पात्र है।

चीन जन. गण. से सहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य**जैड टी ई कारपोरेशन लि. : मैसर्स हुवावेई टेक्नोलॉजिक कं. लि., तथा मैसर्स अल्काटेल लुसेंट शंघाई बेल कं. लि. के लिए सामान्य मूल्य**

44. यह मानते हुए भी कि मै0 जेटीई कारपोरेशन लि0, मै0 हुवावाई टेक्नोलॉजीज कंपनी लि0 और मै0 अल्काटेल-ल्यूसेंट शंघाई बेल कंपनी लि0 ने प्राधिकारी के साथ उसकी समीक्षा जांच में सहयोग दिया है, लेकिन वे बाजार अर्थव्यवस्था की शर्तों के अंतर्गत कार्य नहीं कर रही हैं। प्राधिकारी चीन की उपरोक्त कंपनियों पर नियमावली के अनुबंध - I का पैरा 8 लागू करने की स्थिति में नहीं है और नियमावली के अनुबंध - I के पैरा 7 के अनुसार आगे कार्रवाई की है। इन नियमों के अनुसार चीन जन. गण. में सामान्य मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित में से किसी के भी आधार पर किया जा सकता है :-

- क. किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमतों के आधार पर, अथवा
- ख. बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में निर्मित मूल्य के आधार पर, अथवा
- ग. ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत के आधार पर
- घ. यदि उपरोक्त विकल्पों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर समान उत्पाद के लिए, तर्कसंगत लाभ मार्जिन को शामिल करके समायोजित करके भारत में वास्तविक रूप से भुगतान की गई अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत सहित सामान्य मूल्य का निर्धारण कर सकता है।

45. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपरोक्त नियम की स्थिति के अनुसार प्राधिकारी के पास पहला विकल्प यह है कि यह देखा जाए कि क्या तृतीय देश की बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा संरचित मूल्य उपलब्ध है अथवा नहीं तथा इस पर निर्णय लेने के बाद कि यह उपलब्ध नहीं है, प्राधिकारी अगले विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस प्रकार वे दूसरे और तीसरे विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस संबंध में प्राधिकारी ने हितवद्ध पक्षकारों को यह लिखा था कि चूंकि इजरायल को प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना गया है और इसके अतिरिक्त कि चीन जनवादी गणराज्य की तुलना में इजरायल के विकास के स्तर को ध्यान में रखा गया है तथा इजरायल के संबंध में प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई विश्वसनीय सूचना को विधिवत ध्यान में रखने के बाद तथा साथ ही इस जांच में संबद्ध उत्पाद की जटिल प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इजरायल को प्रतिनियुक्त देश के रूप में माना जाना चाहिए तथा इजरायल में संबद्ध वस्तुओं की लागतों/कीमतों के आधार पर चीन की गौर बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनियों के लिए सामान्य मूल्य संरचित किया जाए। इस संबंध में प्रतिवादी हितवद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियां निम्नानुसार हैं :

(i) प्रतिवादी पक्षकारों ने अपनी टिप्पणियों में यह उल्लेख किया है कि यदि एचईटीसी को बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनी के रूप में माना जाता है तो उसके आंकड़ों को अपनाया जाना चाहिए क्योंकि ऐसी क्रियाविधि इस संबंध में पाटनरोधी नियम की परिभाषा के अनुरूप होगी लेकिन यदि प्राधिकारी किसी भी कारणवश एच ई टी सी को नहीं स्वीकार कर सकते हैं तो उस स्थिति में इजरायल को प्रतिनियुक्त देश के रूप में माना जाना चाहिए।

(ii) दूसरी ओर घरेलू उद्योग ने इजरायल को बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माने जाने के विरुद्ध अन्य बातों के साथ-साथ यह भी तर्क दिया है कि चूंकि गैर बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधानों को शुरू किया गया है, प्राधिकारी ने अनेक उत्पादों में पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की है जिसकी समीक्षा से ऐसा पता चलता है कि प्राधिकारी ने 81 ऐसे उत्पादों में ऐसी सिफारिशों की हैं, जिनकी जांच में चीन के अतिरिक्त अन्य देश भी शामिल थे। तथापि, प्राधिकारी ने अन्य देशों में निर्धारित सामान्य मूल्य को चीन के लिए सामान्य मूल्य के लिए आधार के रूप में नहीं अपनाया है। इसके अतिरिक्त मूल जांच के दौरान इजरायल संबद्ध देश था, फिर भी प्राधिकारी ने चीन के लिए सामान्य मूल्य के रूप में इजरायल में सामान्य मूल्य को नहीं अपनाया है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यह ऐसा मामला नहीं है कि निदेशालय इस मामले पर निर्णय लेने के समय मामले की आवश्यकताओं अथवा कानूनी प्रावधानों और तथ्यों की अनदेखी करे। ऐसी स्थिति में मौजूदा जांच में इस व्यवस्था पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है। इसके अतिरिक्त अनेक जांच में याचिकादाता घरेलू उद्योगों ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए तृतीय देश के विचारार्थ पर्याप्त सूचना/साक्ष्य देने का प्रस्ताव किया है और फिर भी प्राधिकारी ने ऐसे प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है। अनेक मामलों में तृतीय देश की बाजार अर्थव्यवस्था का मुद्दा उठाया गया है। ऐसे अनेक मामलों में घरेलू उद्योगों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि भारत में उत्पादन की वास्तविक लागत अथवा बिक्री कीमत को सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए अपनाया जाना चाहिए जोकि निधि के अंतर्गत सीधी निर्धारित अपेक्षा है। तथापि, प्राधिकारी ने बार-बार ऐसे तर्क को अस्वीकार कर दिया है और उसने तृतीय देश की बाजार अर्थव्यवस्था अथवा भारत में उत्पादन की वास्तविक लागत अथवा बिक्री कीमत को नहीं अपनाया है।

46. प्राधिकारी ने प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावों और प्रति दावों का विश्लेषण किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि (i) ईसीआई, इजरायल ने केवल उपस्करों का निर्यात भारत किया है जबकि भारत को हुआवाई टेक्नोलॉजीज कंपनी लि० के अधिकतर निर्यात कार्डों के हैं और न कि उपस्करों के तथा मै० अल्काटेल-लूसेंट शंघाई बेल कंपनी लि० ने केवल कार्डों का निर्यात ही भारत में किया है, (ii) सहयोगी निर्यातकों द्वारा निर्यातित उपस्करों के पीसीएन और कार्ड उनकी संबंधित विशेषताओं से तुलनीय नहीं हैं इसलिए उनके द्वारा निर्यातित प्रत्येक पीसीएन की कड़ी समीक्षा करने की आवश्यकता है, (iii) इस प्रयोजनार्थ ईसीआई इजरायल के सहयोग से उनके द्वारा निर्मित और निर्यातित उत्पादों की विभिन्न विशेषताओं की गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाली चीन की कंपनियों द्वारा निर्यातित उत्पादों की समान विशेषताओं के साथ तुलना करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार की स्थिति एच ई टी सी, चीन द्वारा निर्मित और बेचे गए उत्पादों के संबंध में भी है। तथापि, सहयोगी निर्यातकों के साथ पी सी एन के आंकड़ों की सहभागिता करने के संदर्भ में मै० ईसीएल इजरायल ने प्राधिकारी को लिखित रूप से यह बताया है कि (i) उनके आंकड़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वस्तुतः पीसीएन में ऐसी विशिष्ट ढांचा/सम्मिश्रण निहित है जोकि दूर संचार के ग्राहकों के डिजाइन के लिए उनके प्रयोजनार्थ है, (ii) यह सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है और इससे वाणिज्यिक पहलुओं पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ेगा जिससे उनके प्रतिस्पर्धियों को अनुचित लाभ प्राप्त होगा, (iii) इस प्रकार ई सी आई यह चाहेगा कि उसे इस मुद्दे पर गोपनीयता बनाए रखी जानी चाहिए और वह इस संबंध में प्राधिकारी पर विश्वास करना होगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के आंकड़ों का उपयोग करना अभूतपूर्व उदाहरण होगा और (iv) ईसीआई इस कारण से यह निवेदन करना चाहेगा कि चूंकि दायर किए गए निर्यातकों की प्रश्नावली के उत्तर और उसके बाद के निवेदनों में अगोपनीय आंकड़े निहित हैं, तो उनका अप्रकटन क्यों नहीं किया जा रहा है और वह उन पर विश्वास करना चाहेगा। इस जांच में सहयोगी निर्यातकों के साथ ई एस आई, इजरायल के उनके पी सी एन के संबंध में असहयोग के कारण प्राधिकारी का यह प्रस्ताव है कि इस जांच में इन गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले चीनी देशों के संरचित सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए इजरायल को प्रतिनियुक्त देश के रूप में नहीं माना जाए। इसलिए जे टी ई कॉर्पोरेशन लि०, मै० हुआवाई टेक्नोलॉजीज कं० लि० और मै० अल्काटेल-लूसेंट शंघाई बेल कं० लि० के संबंध में सामान्य मूल्य की संरचना, नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 (घ) के दूसरे परंतुक में दी गई परिभाषा के किसी भी अन्य उचित आधार पर की गई है जैसा कि मूल अंतिम निर्णय में किया गया था।

जैड टी ई कॉर्पोरेशन लि०, मै० हुआवाई टेक्नोलॉजीज कं० लि० तथा मै० अल्काटेल-लूसेंट शंघाई बेल कं० लि० के लिए सामान्य मूल्य

47. ऊपर उल्लिखित कारणों से ऐसा प्रस्ताव है कि जैड टी ई कॉर्पोरेशन लि०, मै० हुआवाई टेक्नोलॉजीज कं० लि० तथा मै० अल्काटेल-लूसेंट शंघाई बेल कं० लि० के लिए विचाराधीन उत्पाद का कार्यगत सामान्य मूल्य की संरचना नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 (घ) के दूसरे परंतुक में दी गई परिभाषा के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर की जाए।
48. मौजूदा समीक्षा जांच में भारत में ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार विचाराधीन उत्पाद का निर्यात संपूर्ण उपस्करों (एस टी एम-1, एस टी एम-4, एस टी एम-16, एस टी एम-64) के साथ-साथ कारणों के रूप में सीकेडी/एसकेडी के रूप में, असेंबलियों, पीसीबीए और क्रॉस कनेक्ट आदि के रूप में किया गया है। ई सी आई इजरायल द्वारा इसका निर्यात संपूर्ण उपस्करों के रूप में किया गया है। चीन से इसका निर्यात जे टी ई कॉर्पोरेशन और हेंगझाऊ ईसीआई टेलीकॉम द्वारा संपूर्ण उपस्करों के रूप में किया गया है। तथापि, अल्काटेल-लूसेंट शंघाई बेल कंपनी लि० ने केवल एस डी एच के प्रयोग के लिए इसका निर्यात किया है तथा हुआवाई चीन ने कारणों/पीसीबीए के साथ-साथ संपूर्ण उपस्करों के रूप में इसका निर्यात किया है। चूंकि मौजूदा जांच समीक्षा जांच है इसलिए निर्यातक कंपनियों ने पी सी एन के रूप में उपस्करों/कारणों/असेंबलियों आदि की किस्मों के बारे में संबद्ध सूचना प्रस्तुत की है।
49. इस जांच में यह प्रस्ताव किया गया है कि जे टी ई कॉर्पोरेशन लि०, अल्काटेल लूसेंट शंघाई बेल कं० लि० और हुआवाई चीन को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनियों के रूप में माना जाए। तथापि, यह प्रस्ताव है कि एच ई टी सी चीन को बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनी के रूप में माना जाए। इसके अतिरिक्त इजरायल एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है और इजरायल की ई सी आई टेलीकॉम को बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनी के रूप में माना जा रहा है। ऐसा प्रस्ताव है कि इन गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनियों के लिए सामान्य मूल्य की संरचना घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के आधार पर की जाए। इसलिए इन गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाली चीन की कंपनियों के लिए पाटन मार्जिन का परिकलन करने के साथ-साथ चीन की इन कंपनियों के साथ-साथ ई सी आई इजरायल और एच ई टी सी चीन के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए सामान्य मूल्य की संरचना करने के लिए प्रयास किए गए थे ताकि घरेलू उद्योग की पी सी एन को गैर बाजार अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनियों के साथ तुलना की जा सके। इस संबंध में इन कंपनियों के साथ घरेलू उद्योग की पी सी एन की मैपिंग/तुलना में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए घरेलू उद्योग के पीसीएन के विवरणों की सूचना इन कंपनियों को दी गई थी और इसी तरह इन कंपनियों के पीसीएन के व्यौरों के बारे में घरेलू उद्योग को उसके साथ हुए विविध औपचारिक संप्रेषणों में निर्दिष्ट किया गया था।

50. ईसीआई टेलीकॉम, इजरायल और एच ई टी सी चीन के मामले में उनके निजी आंकड़ों का उपयोग उनके सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए किया गया है। उसके बाद इन कंपनियों के पीसीएन की तुलना करने के लिए इजरायल और चीन तथा घरेलू उद्योग की सभी सहयोगी कंपनियों के तकनीकी निर्यातकों के साथ अनेक पारस्परिक बैठकें की गई थीं। प्राधिकारी द्वारा ऐसी बैठकें घरेलू उद्योग की उपस्थिति के साथ-साथ उनके साथ पृथक् रूप से भी की गई थीं। सूचीबद्ध निर्यातित प्रत्येक पीसीएन के लिए घरेलू उद्योग से कहा गया था कि वह उनका मिलान जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग में उसके द्वारा बेचे गए समान पीसीएन के साथ करे। इसी प्रकार विशिष्ट पृथक् निर्यातक कंपनी ने भी अपने पीसीएन का मिलान प्राधिकारी के साथ बैठक में घरेलू उद्योग के पीसीएन के साथ किया था। उसके बाद अधिक पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्राधिकारी द्वारा एक ओर घरेलू उद्योग के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ और दूसरी ओर पृथक् निर्यातक कंपनी के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक की थी तथा दोनों ही पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने द्वारा पृथक् रूप से की गई मैपिंग में विभिन्न विचारों का समाधान करने के लिए सहमति से समस्या का निदान करें। कुछेक पीसीएन पर इस बात पर सहमति थी कि पी सी एन की मैपिंग दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य थी अथवा पीसीएन पूरी तरह से समान नहीं थे तो वहां दोनों पक्षकार चेसिज, पावर केबल्स, पोर्ट्स आदि जैसे अतिरिक्त उपांगों को निकटस्थ समान पी सी एन से हटाने के लिए सहमत हो गए थे। उदाहरण के लिए किसी विशेष उपस्कर अथवा कार्ड के लिए घरेलू उद्योग के पी सी एन में दो पोर्ट्स शामिल हैं और इसी प्रकार के उपस्कर अथवा कार्ड में दो पाकर्ट शामिल हैं तथा वे निर्यातक कंपनी के समान उपस्कर अथवा कार्ड के पी सी एन के लगभग समान हैं तो दोनों पक्षकारों के बीच इस बात पर सहमति हो गई कि वे घरेलू उद्योग के पी सी एन से अतिरिक्त पोर्ट की कीमत को घटा लेंगे ताकि समान उपस्कर अथवा कार्ड की कीमत का परिकलन किया जा सके। कुछ पी सी एन के लिए कोई सहमति नहीं हुई थी। घरेलू उद्योग द्वारा पी सी एन मैपिंग और निर्मित पी सी एन औजारों के संबंध में गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाली चीन की तीन कंपनियों ने अपनी लिखित टिप्पणियों में भी ऐसा निवेदन किया है। इसी प्रकार घरेलू उद्योग ने भी इन तीनों कंपनियों की पी सी एन के साथ समानता के संबंध में उसके द्वारा निर्मित पीसीएन औजारों और पीसीएन मैपिंग के संबंध में भी अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं। कुछ उपस्करों और कार्डों के संबंध में समानता पर सहमति हुई है। जहां कहीं भी सहमति नहीं हो पाई है, वहां प्राधिकारी ने अपने विवेकानुसार और बुद्धिमत्ता से काम लिया है जोकि दोनों पक्षकारों के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ हुई परिचर्चा तथा लिखित टिप्पणियों पर आधारित है और उसके बाद उन्होंने स्वयं अतिरिक्त उपकरणों/संघटकों की कीमत को घटाकर पी सी एन की अपनी निजी मैपिंग की है।
51. सामान्य मूल्यों की संरचना करने के लिए सबसे पहले घरेलू उद्योग के विभिन्न प्रकार के एस डी एच उपस्करों के लिए सभी प्रमुख संघटकों की औसत कीमत को अपनाया गया है जोकि घरेलू उद्योग की सामान्य उत्पादन लागत पर आधारित है। उसके बाद प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त पीसीएन की समानता/मैपिंग की क्रिया पद्धति अपनाई गई है वहां गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाली चीन की निर्यातक कंपनियों के संघटकों के पीसीएन को या तो घरेलू उद्योग के उपस्कर के साथ उनके प्रयोग, क्षमता, अंतरभूत पोर्ट आदि के लिए समान पाया गया है अथवा वैसा ही पाया गया है, वहां ऐसे उपस्करों के लिए घरेलू उद्योग की सामान्य उत्पादन लागत को अपनाया गया है। जहां कहीं भी गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाली चीन की निर्यातक कंपनियों के उपस्करों अथवा कार्डों की पी सी एन को उनकी उपयोगिता, क्षमता, अंतरभूत पोर्ट आदि के रूप में पूर्णतया समान अथवा लगभग समान नहीं पाया गया है, वहां उपरोक्त क्रियाविधि का अनुसरण करते हुए अतिरिक्त भागों को आंशिक रूप से जोड़ दिया गया है अथवा हटा दिया गया है तथा घरेलू उद्योग के संबद्ध भागों और संघटकों की वास्तविक भारित औसत कीमत को अपनाया गया है जोकि घरेलू उद्योग के उत्पादन की सामान्य लागत पर आधारित है। सीमाशुल्क के लिए कोई समंजन नहीं किया गया है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद पर शून्य सीमाशुल्क लगता है। सामान्य मूल्य की संरचना करने के लिए घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत और एसजीए के व्ययों को अपनाया गया है। तर्कसंगत प्रतिशत के उचित लाभ मार्जिन को जोड़ने के बाद सामान्य मूल्य संरचित किए गए हैं। गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाली इन सहयोगी चीन के निर्यातकों द्वारा निर्यातित पी सी एन के लिए कार्यगत सामान्य मूल्यों को नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

मैसर्स हेंगज़ो ई सी आई टेलिकम्युनिकेशन कं. लि., चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

52. यह उत्पादक / निर्यातक, जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के तहत प्रचालित पाया गया था। जांच आरंभ करने के लिए उत्तर दाखिल करते समय उन्होंने परिशिष्ट - I प्रस्तुत किया था, जिसने घरेलू बाजार में बिक्रियों की सूचना दी थी, तथापि, सत्यापन के दौरान यह सामने आया कि घरेलू बिक्रियों में जांच की अवधि के दौरान भारत को किए गए निर्यातों की ***% से भी कम बिक्री शामिल है। इसके अलावा, अन्य तीसरे देशों को भी कोई निर्यात नहीं किया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद चूँकि परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत, सी के डी / एस के डी, सब एसंबली के रूप में है और जिस तरीके से उत्पादक उत्पाद का इनवॉयस कर रहे हैं, उस पर विचार करते हुए और साथ ही इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सामान्य मूल्य "समान वस्तु" की कीमत है और समान वस्तु के अभाव में अन्य वस्तु पर विचार किए जाने की जरूरत है, सामान्य मूल्य का निर्माण उत्पादक / निर्यातक के आंकड़ों की पुष्टि के अनुसार एस के डी / सी के डी कीमतों और उत्पादन की लागत के अनुसार अन्य लागतों तथा तर्कसंगत लाभ पर विचार करते हुए किया गया है। तदनुसार इस प्रकार से आकलित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन सारणी में दिया गया है।

चीन जनवादी गणराज्य से असहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

53. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य से किसी अन्य उत्पादक निर्यातक ने निर्यातक की प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है। तदनुसार, इस प्रकार से निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य को नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

इजराइल से सहयोगी उत्पादक / निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य

मैसर्स ई सी आई टेलिकॉम लिमिटेड इजराइल

54. कंपनी ने सामग्रियों के बिलों सहित विभिन्न परिशिष्टों में सूचना प्रदान की है, जिनकी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत को निर्यात किए गए *** पी सी एन में से केवल *** पी सी एन घरेलू बाजार में बेचा गया है। लेकिन यह भारत को निर्यात किए गए पी सी एन से मेल नहीं खाता। इस स्थिति की उत्तर देने वाले निर्यातक की सत्यापन के दौरान पुष्टि हुई है। तथापि, सत्यापन के दौरान यह बात सामने आई है कि इजराइल में घरेलू बाजार में बेचे गए काफी पी सी एन में कुछ एसेंबली/ सब एसेंबली शामिल नहीं थी, जो वही थी जो भारत को निर्यात किए गए पी सी एन में उपयोग की गई थी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद चूंकि परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत, सी के डी /एस के डी, सब – एसेंबली रूप में है और जिस तरीके से उत्पादक उत्पाद का इनवॉयस कर रहे हैं, उस पर विचार करते हुए और साथ ही, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सामान्य मूल्य “समान वस्तु” की कीमत है और समान वस्तु के अभाव में अन्य वस्तु पर विचार किए जाने की जरूरत है, सामान्य मूल्य का निर्माण उत्पादक / निर्यातक के आकड़ों की पुष्टि के अनुसार एस के डी / सी के डी कीमतों और उत्पादन की लागत के अनुसार अन्य लागतों तथा तर्कसंगत लाभ को शामिल करते हुए किया गया है। तदनुसार सामान्य मूल्य का आकलन इस प्रकार किया गया है।

इजरायल से असहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

55. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इजरायल से किसी अन्य उत्पादक निर्यातक ने निर्यातक की प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है। तदनुसार, इस प्रकार से निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य को नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

चीन जन. गण. से सहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य

मैसर्स जैड टी ई कारपोरेशन, चीन जन. गण.

56. संबद्ध उत्पादक / निर्यातक ने जांच की अवधि के दौरान सी आई एफ कीमत के आधार पर भारत को *** यू एस डॉलर मूल्य के *** विभिन्न पी सी एन वेरिएंट के *** सेट निर्यात किए हैं। प्राधिकारी द्वारा उत्पादक / निर्यातक के निर्यात संबंधी आकड़ों की पुष्टि उत्पादक / निर्यातक के कार्यालय परिसर में स्थल सत्यापन के दौरान की गई थी। अन्तर्देशीय माल भाड़े, ओवरसीज माल भाड़े, हैंडलिंग और विविध प्रभारों, ऋण लागत तथा बैंक प्रभारों को समायोजन का दावा किया गया है और कारखाना बाह्य स्तर पर पी सी एन – वार निवल निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए प्राधिकारी द्वारा इसके लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है। भारित औसत निवल निर्यात कीमत की गणना की गई है और इसे नीचे पाटन मार्जिन सारणी में दर्शाया गया है।

मैसर्स हुआवेई टेक्नोलोजीज कं. लि., चीन जन. गण. (हुआवेई, चीन)

57. मैसर्स हुआवेई टेक्नोलोजीज कं. लि., चीन जन. गण. (हुआवेई, चीन) ने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के पी सी एन वार ब्यौरे दाखिल किए थे। प्राधिकारी द्वारा सत्यापन किए गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, यह पाया गया था कि जांच की अवधि के दौरान हुआवेई चीन ग्रुप कंपनियों नामतः हुआवेई टेक्नोलोजीज कं. लि., चीन जन. गण., हुआवेई टैक इन्वेस्टमेंट कं. लि., हांग कांग और हुआवेई इंटरनेशनल प्रा. लि., सिंगापुर ने *** इनवॉयस के लिए *** पी सी एन वेरिएंट के अन्तर्गत *** पीस विचाराधीन उत्पादों का *** यू एस डॉलर मूल्य का निर्यात किया है। विचाराधीन उत्पाद का निर्माण सभी मामलों में हुआवेई चाइना द्वारा किया गया था। हुआवेई टेक्नोलोजीज कं. लि., चीन जन. गण. ने *** इनवॉयस के तहत विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया था, हुआवेई टैक इन्वेस्टमेंट कं. लि., हांग कांग ने *** इनवॉयस के तहत विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया था और हुआवेई इंटरनेशनल प्रा. लि., सिंगापुर ने *** इनवॉयस के तहत विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया था। हवाई माल भाड़े, बीमा और वेट के समायोजन का दावा किया गया है और इसकी पुष्टि की गई है तथा प्राधिकारी द्वारा कारखाना बाह्य स्तर पर पी सी एन वार निर्यात वार निवल निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए अनुमति प्रदान की गई थी। भारित औसत निवल निर्यात कीमत की गणना की गई है और इसे नीचे पाटन मार्जिन सारणी में दर्शाया गया है।

मैसर्स अल्काटेल – लुसेंट शंघाई बेल कं. लि., चीन जन. गण. (ए सी बी)

58. संबद्ध उत्पादक / निर्यातक (ए एस बी) ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद और गैर – विचाराधीन उत्पाद वस्तुएं *** सौदों में निर्यात की गई हैं। इन *** सौदों में *** पी सी एन वेरिएंट शामिल हैं, जिनमें *** यू एस डॉलर मूल्य के *** संख्या में विचाराधीन उत्पाद हैं। ए एस बी के लिए कारखाना बाह्य कीमत के निर्धारण के लिए प्राधिकारी ने इन *** पी सी एन पर विचार किया है, जिसमें विचाराधीन उत्पाद शामिल है। भारत को सभी निर्यात भारत में संगत कंपनी को पूर्व – कार्यों के आधार पर किए गए थे। ए एस बी ने निर्यात कीमत से कटौती के रूप में केवल ऋण लागत का दावा किया है। कारखाना बाह्य स्तर पर निवल निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए उसकी अनुमति दे दी गई है। तदनुसार प्रत्येक पी सी एन के संबंध में कारखाना बाह्य स्तर पर निवल निर्यात कीमत का आकलन किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित भारित औसत निवल निर्यात कीमत का उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन सारणी में किया गया है।

मैसर्स ई सी आई टेलिकॉम लि., इजराइल के माध्यम से मैसर्स हैंगज़ोऊ ई सी आई टेलिकम्युनिकेशन कं. लि., चीन जन. गण.

59. सत्यापित आकड़ों के अनुसार हैंगज़ोऊ ई सी आई टेलिकम्युनिकेशन कं. लि. ने जांच की अवधि के दौरान भारत को *** यू एस डॉलर मूल्य के *** पीस / संख्या के *** पी सी एन शेल्फों की संख्या *** के अंतर्गत शामिल किया गया है। अन्तर्देशीय माल भाड़े, ओवरसीज माल भाड़े, बीमा, स्टोरेज, ऋण लागत और वारंटी के संदर्भ में किए गए दावों की कारखाना बाह्य स्तर पर निवल निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए अनुमति दी गई है। इस प्रकार से निर्धारित की गई भारित औसत निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन सारण में यथा उल्लिखित अनुसार है।

चीन जनवादी गणराज्य से असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

60. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य से किसी अन्य उत्पादक निर्यातक ने निर्यातक की प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है। तदनुसार, इस प्रकार से निर्धारित की गई निर्यात कीमत को नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

इजराइल से सहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत**मैसर्स ई सी आई टेलिकॉम लि., इजराइल**

61. सत्यापित आकड़ों के अनुसार जांच अवधि के दौरान भारत को *** संयुक्त राज्य अमरीकी मूल्य के *** विविध पीसीएन *** शेल्फों के निर्यात किए गए। अन्तर्देशीय माल भाड़े, बीमा, स्टोरेज, ऋण लागत और वारंटी के संदर्भ में किए गए दावों की कारखाना बाह्य स्तर पर निवल निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए अनुमति दी गई है। इस प्रकार से निर्धारित की गई भारित औसत निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन सारण में यथा उल्लिखित अनुसार है।

इजरायल से असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

62. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इजरायल से किसी अन्य उत्पादक निर्यातक ने निर्यातक की प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है। तदनुसार, इस प्रकार से निर्धारित की गई निर्यात कीमत को नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

पाटन मार्जिन

63. भारित औसत निवल निर्यात कीमतों के साथ इस प्रकार से निर्धारित किए गए भारित औसत कार्यगत सामान्य मूल्यों की तुलना करने के बाद निर्धारित करने के लिए प्रस्तावित पाटन मार्जिन को नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

पाटन मार्जिन सारणी

कंपनी का नाम	भारित औसत सामान्य मूल्य (यू एस डॉलर प्रति अदद)	भारित औसत निर्यात मूल्य (यू एस डॉलर प्रति अदद)	पाटन मार्जिन (यू एस डॉलर प्रति अदद)	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज (%)
मैसर्स जैड टी ई कारपोरेशन, चीन जन. गण.	***	***	***	***	45 to 55
मैसर्स अल्काटेल – लुसेंट बेल कं. लि. चीन जन. गण. (ए	***	***	***	***	50 to 60

एस बी)					
मैसर्स हुआवेई टेक्नोलोजीज कं. लि. चीन जन. गण.	***	***	***	***	35 to 45
मैसर्स हेंगजोऊ ई सी आई टेलिकम्यूनिकेशन कं. लि. चीन जन. गण.	***	***	***	***	0 to 10
अन्य उत्पादक निर्यातक, चीन जन. गण.	***	***	***	***	110 -120
मैसर्स ई सी आई टेलिकॉम लि. इजराइल	***	***	***	***	(-) 1 to10
अन्य उत्पादक निर्यातक, इजराइल	***	***	***	***	5-15

छ. क्षति का मूल्यांकन

क्षति और कारणात्मक संबंध का निर्धारण और जांच

निर्यातकों, आयातकों और अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

64. निर्यातकों, आयातकों और अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-
- याचिकाकर्ता के बाजार अंश में वृद्धि हुई है और आयातों में गिरावट आई है।
 - मजदूरी व्यय 2010 – 11 में 100 के इंडेक्स से बढ़कर 2011 – 12 में 143 इंडेक्स प्वाइंट हो गया। मजदूरी में इतनी तेजी से वृद्धि होने का कारण यह है कि याचिकाकर्ता अपेक्षित ढंग से अपने मुनाफे में सुधार नहीं कर पाया है।
 - प्रौद्योगिकी उद्योग में यह मानक है कि एक नए उत्पाद के लिए उत्पादन की लागत प्रारंभिक अवस्था में काफी अधिक थी जबकि नई प्रौद्योगिकी बाजार में पहली बार आई है। याचिकाकर्ता की उत्पादन लागत 2012 – 13 में 54 के इंडेक्स प्वाइंट तक हो गयी। याचिका के तहत याचिकाकर्ता ने कोई नया उत्पाद अथवा प्रौद्योगिकी बाजार में आरंभ नहीं किया है, जिससे कि इतनी वृद्धि हुई।
 - याचिकाकर्ता ने निर्यात बाजार पर ध्यान देना जारी रखा जबकि उसे भारत में अपने बाजार की स्थिति में वृद्धि करने के लिए उपाय करने चाहिए थे। याचिकाकर्ता यह तर्क नहीं दे सकता कि वह निर्यात बाजार में अपनी सामान सूची (इन्वेन्ट्री) का निपटान कर रहा है। क्योंकि संबद्ध उत्पाद आदेश पर बनाए गए हैं।
 - घरेलू उद्योग की कीमत में निरंतर वृद्धि दिखाई दी जबकि उत्पाद के लिए मांग में काफी गिरावट दिखाई दी है।
 - संबद्ध देशों से आयात के बारे में सूचना न होने पर इसे केवल तर्क के रूप में ही देखा जा सकता है, जो कि तर्कसंगत नहीं है और इसका किसी निर्णायक समीक्षा जांच (एस एस आर) से कोई संबंध नहीं है।
 - यह एक अप्रमाणित दावा है कि भारत में भावी मांग पूर्णतः संबद्ध देशों के निर्यातकों से पूरी की जाएगी। इसी समय आवेदक ने अन्य देशों में संबद्ध वस्तुओं के लिए भावी मांग के बारे में कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।
 - संबद्ध उत्पाद के आयातों में, भारत में समग्र मांग में कमी के अनुरूप क्षति अवधि के दौरान कमी आई है। इसके अलावा, यह देखा जा सकता है कि संबद्ध देशों से आयात में भी उत्पादन के संबंध में गिरावट आई है। याचिकाकर्ता ने चालाकी से इस मामले में आयातों के वृद्धि के स्तर को दर्शाने के लिए संबंधित रिपोर्ट पर भरोसा किया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि पाटन मार्जिन लागू पाटन रोधी शुल्क से कम है। अतः ऐसा भारी पाटन रोधी शुल्क इस मामले में जारी रहना आवश्यक नहीं है। इतनी कम मात्रा में आयात उत्पादन और घरेलू उद्योग में बिक्री को प्रभावित नहीं कर सकते और इसीलिए घरेलू उद्योग को किसी महत्वपूर्ण क्षति के लिए यह कारण नहीं हो सकता।

- ix. याचिकाकर्ता कीमत कटौती के संबंध में कोई भी आकड़े प्रदान करने में असफल रहा। अतः याचिकाकर्ता का कीमत कटौती के संबंध में यह निष्कर्ष अस्वीकार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने इस बात का गलत निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान मामले में कीमत में कटौती हुई है क्योंकि याचिकाकर्ता ने पहुंच कीमत का गलत निर्धारण किया है। पहुंच कीमत का निर्धारण आयात के आकड़ों के समुचित विश्लेषण के आधार पर और साथ ही इच्छुक पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आकड़ों के आधार पर किया जाना है।
- x. घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध उत्पाद के कथित पाटित आयातों के संबंध में गलत गणना की गई है। एक उचित विश्लेषण करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा संबद्ध उत्पाद के लिए डी जी सी आई एंड एस आयात के संबंध में आकड़े जुटाए जाए। आयात की मात्रा में अत्यधिक भारी पाटन रोधी शुल्कों को देखते हुए क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान वृद्धि नहीं हो सकती, जो कि इस मामले में 266 प्रतिशत की यथा मूल्य दर पर है।
- xi. संबद्ध वस्तुओं की खपत की पद्धति में परिवर्तन के संबंध में घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि खपत की पद्धति में विचाराधीन उत्पाद के लिए परिवर्तन हुआ है। तथापि, उसी समय उसने यह स्वीकार किया है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग द्वारा ही दिया गया ऐसा प्रतिकूल विवरण इस बात की पुष्टि करता है कि घरेलू उद्योग अपनी सुविधा के अनुसार और जरूरत के अनुसार तथ्यों को गढ़ते रहे हैं। यहां तक कि उसने यह दावा किया है कि निर्यात के निष्पादन से संबंधित आकड़े उसने अलग से प्रदान किए हैं। तथापि, इस अनुरोध में ऐसा कोई डाटा नहीं पाया गया है।
- xii. घरेलू उद्योग द्वारा जॉब वर्कर को विनिर्माण क्रियाकलापों को आउटसोर्स किए जाने से इसकी कीमतों में वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग की कीमतों को घरेलू कीमत के लिए एक बैचमार्क के रूप में मानना गलत है। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि ऐसे जॉब वर्कर द्वारा संबद्ध वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चे माल, उपयोगी वस्तुओं, उत्पादन क्षमताओं आदि का प्रभावी उपयोग किया गया था। इसके लिए सबसे पहले ऐसे जॉब वर्कर के परिसर की जांच की जानी है और उत्पादन तंत्रों, वित्तीय प्रलेखनों, इत्यादि का एक शुष्म स्तर पर विश्लेषण किया जाना है। घरेलू उद्योग के पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह प्रमाणित कर सके कि उसकी ओर से और इसके जॉब वर्कर की ओर से संसाधनों का कारगर उपयोग किया गया है, साथ ही यह दावा करने का भी सुविधाजनक ढंग से प्रयास किया गया है कि क्षमता और क्षमता उपयोग को वर्तमान मामले में असंगत मानदंड माना जाए।
- xiii. विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में पर्याप्त गिरावट दर्ज की गई है। इससे यह पता चलता है कि कथित पाटित आयातों और आवेदक को किसी निरंतर हो रही क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं हैं, और निरंतर हो रही क्षति अन्य कारकों जैसे विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में गिरावट के कारण से है।
- xiv. आवेदक के संबंध में सभी स्रोतों से बुनियादी आयात संबंधी आकड़े, उत्पादक और पर्याप्त कारणात्मक संबंध के बारे में सूचना उपलब्ध न होने के कारण, किसी इच्छुक पक्षकार को उचित कार्यवाही के अधिकार से सामान्यतः वंचित कर दिया गया है क्योंकि वह निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष अपनी राय प्रभावी तरीके से व्यक्त करने में असमर्थ है।
- xv. याचिका का चीन में अधिक क्षमता के बारे में दावा अप्रमाणित तर्क है, जबकि यह आवश्यक है कि केवल अधिक क्षमता की मौजूदगी को न प्रदर्शित किया जाए बल्कि यह बताया जाए कि शुल्कों को हटाने की अवस्था में भारत तक ऐसी अधिक क्षमताओं को कैसे पहुंचाया जाए।
- xvi. शुल्कों से बचने के किसी भी प्रयास से कानून के संगत प्रावधान के अन्तर्गत सख्ती से निपटा जाना चाहिए लेकिन यह सुझाव देने के लिए इसका कोई तर्क नहीं है कि शुल्कों की समाप्ति होने से घरेलू उद्योग को क्षति और पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी।
- xvii. आवेदक ने कोई भी विश्वव्यापी संगत सूचना प्रस्तुत नहीं की है और ये आंकड़े निवल भारत और उसके आधार पर किसी अन्य अविश्वव्यापी स्रोत से लिए गए हैं।
- xviii. याचिका में घरेलू उद्योग के निष्पादन और संबंध देशों से आयातों के बीच कोई संबंध न होने का सुझाव दिया गया है। प्रोफार्मा IV क में प्रदान की गई क्षति संबंधी सूचना में यह सुझाया गया है कि घरेलू उद्योग को संबंध देशों से हो रहे निरंतर आयातों के कारण किसी क्षति का सामना नहीं करना पड़ा है। संबद्ध देशों से आयातों पर 266 प्रतिशत तक का अधिक पाटन रोधी शुल्क लगाया जा रहा है और यदि घरेलू उद्योग को उसके बाद भी क्षति का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसी क्षति स्वयं के कारण से है न कि कथित किसी पाटन के कारण से है।
- xix. विचाराधीन उत्पाद पर पाटन रोधी शुल्क लगाने से लेकर अब तक इतने वर्ष बीत जाने पर भी घरेलू उद्योग ने क्षमता निर्माण के लिए कोई उपाय नहीं किया है। विचाराधीन उत्पाद में कतिपय हार्ड ऐंड उपस्कर शामिल किए गए हैं, जिनके उत्पादन के लिए

आवेदक के पास क्षमता नहीं है। आवेदक को पाटन रोधी शुल्क लगाकर संरक्षण लेने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती जबकि आवेदक की कथित क्षति स्वयं के कारण और आवेदक की अक्षमताओं के कारण से है।

- xx. आवेदक का आशय अनुचित रूप से आयातों पर कब्जा करना और भारत में घरेलू बाजार पर एकाधिकार को बनाकर रखना है।
- xxi. यह पाटन और क्षति का वर्तमान स्तर नहीं है, जो महत्वपूर्ण तो है लेकिन संभावित पाटन और क्षति, एक निर्णायक समीक्षा जांच में अधिक आवश्यक होती है। निर्दिष्ट प्राधिकारी की यह प्रक्रिया रही है कि एक निर्णायक समीक्षा जांच में जांच की अवधि के उपरांत जांच की जाए। याचिकाकर्ता ने पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना का दावा करने के लिए उसे पाटन अथवा क्षति होने के बारे में बताने के लिए जांच की अवधि के बाद के आकड़े प्रदान नहीं किए हैं।
- xxii. याचिकाकर्ता ने क्षति अवधि के लिए क्षमता और क्षमता के उपयोग के संबंध में आकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं।
- xxiii. न केवल याचिकाकर्ता निरंतर हो रहे पाटन की मौजूदगी को प्रमाणित करने में असमर्थ रहे बल्कि वह यदि पाटन रोधी शुल्कों को बहाल कर दिया जाता है तो भविष्य में पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना को भी प्रमाणित करने में असफल रहा है।
- xxiv. संबद्ध उत्पाद के लिए याचिकाकर्ता के लाभ / हानि, नकद लाभ और पी बी आई टी में जांच की अवधि के दौरान काफी सुधार आया है। याचिकाकर्ता का नुकसान जांच की अवधि में न्यूनतम था, जबकि जांच की अवधि में संबद्ध देशों को आयात में वृद्धि हुई थी। याचिकाकर्ता की स्थिति में क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान काफी सुधार आया है और यह रूझान भविष्य में भी जारी रहने की संभावना है। इतने अधिक पाटन रोधी शुल्कों के बाद भी यदि याचिकाकर्ता अभी भी लाभ अर्जित करने में समर्थ नहीं है तो इसका अर्थ यह हुआ कि याचिकाकर्ता के साथ स्वाभाविक रूप से कुछ गलत हो रहा है।
- xxv. याचिकाकर्ता के आकड़ों में क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान मूल्यहास में निरंतर वृद्धि होने का संकेत है। इससे यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने नए संयंत्र और मशीनरी में काफी निवेश किया है जिसके कारण काफी अधिक मूल्यहास लागत आ रही है। यदि यह मामला है तो याचिकाकर्ता का लाभ निश्चय ही गिरावट को दर्शाएगा।
- xxvi. 2011 -12 में आर ओ सी ई - 281 इंडेक्स प्वाइंट पर था, जो 2012 - 13 में महत्वपूर्ण सुधार लाकर - 66 इंडेक्स पर आ गया। वार्षिक जांच की अवधि के दौरान आर ओ सी ई में और भी सुधार आया है, जिसमें यह - 52 इंडेक्स प्वाइंट पर आ गया।
- xxvii. वार्षिक जांच की अवधि के दौरान ब्याज लागत में काफी वृद्धि हुई। इतनी अधिक ब्याज लागत का कारण यह है कि याचिकाकर्ता अपने मुनाफे में सुधार लाने में असमर्थ रहा है।
- xxviii. याचिकाकर्ता का यह कहना गलत है कि वह अपनी कीमतें बढ़ा नहीं सका और कीमतों में कमी तथा दबाव आया है। याचिकाकर्ता की कीमतों में क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है।
- xxix. उपरोक्त में से कोई भी मानदंड यह नहीं दर्शाता कि घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। क्षति अवधि के दौरान लाभ, नकदी लाभ, पी बी आई टी और निवेश पर प्रतिफल में निरंतर सुधार आया है। हुआवेई इंडिया, जो घरेलू उद्योग होने का मजबूत दावा भी करती है, ने सार्वजनिक सुनवाई के दौरान स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि वह उसी बाजार में लाभ कमा रहा है जहां पर कि याचिकाकर्ता नुकसान होने का दावा कर रहा है। याचिकाकर्ता को किसी भी क्षति के होने का निश्चय ही कोई दूसरा कारण है न कि संबद्ध उत्पादों के आयातों के कारण से क्षति हो रही है।
- xxx. इतने अधिक संरक्षण के बावजूद घरेलू उद्योग भ्रामक रूप से वर्तमान मामले में बिना किसी समर्थनकारी आकड़े के पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा इसकी पुनरावृत्ति होने का दावा कर रहा है।
- xxxi. पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध - III के पैरा (4) के उप-पैरा (iii) के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी को गैर क्षति कीमत निकालने के लिए विगत तीन वर्षों और जांच की अवधि की सर्वोत्तम क्षमता के उपयोग पर विचार करना अपेक्षित होता है। तथापि, याचिकाकर्ता ने यहां तक कि याचिका में क्षमता उपयोग से संबंधित आकड़े भी प्रदान नहीं किए हैं। इसी प्रकार पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध - III के पैरा (4) के उप-पैरा (IX) के तहत यह प्रावधान है कि ब्याज लागत की तर्कसंगतता की जांच करते समय आवधिक ऋण के ब्यौरे, नकद ऋण की सीमा, कंपनी द्वारा जमा किए गए और लिए गए अन्य ऋणों की भी विस्तार से जांच करनी होती है।
- xxxii. याचिकाकर्ता याचिका के खंड V (कारणात्मक संबंध) में यह स्वीकार करने में असफल रहा है कि प्रौद्योगिकी में विकास एक ऐसा संगत कारक है जिसके कारण संबद्ध उत्पाद की मांग में समय के साथ-साथ कमी आ रही है। ऐसे कारक के कारण हुई क्षति संबद्ध उत्पादों का परिणाम नहीं हो सकती।

- xxxiii. सबसे पहले तो इस मामले में याचिकाकर्ता ने आयात की मात्रा की गणना करने में भारी त्रुटियों की हैं। दूसरे, उपरोक्त तर्क पर ध्यान दिए बिना, याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान किए गए आयात से संबंधित आंकड़े अपने आप ही क्षति विश्लेषण की अवधि में आयातों में गिरावट को दर्शाते हैं। तीसरे, संबद्ध उत्पाद पर इतने भारी पाटन रोधी शुल्क लगे होने को देखते हुए आयातों में वृद्धि होना संभव नहीं है।
- xxxiv. अधिशेष उत्पादन की क्षमता मौजूद होने को पहले से ही स्पष्ट रूप से क्षति की आंशका के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- xxxv. गैर-क्षति कीमतों अथवा कीमत कम करके बिक्री करने का विश्लेषण करने के संबंध में याचिका में कोई भी सूचना प्रदान नहीं की गई है। याचिकाकर्ता ने अपनी ही कीमत पर विचार किया है जिसे उसने याचिका में निर्यात कीमत के रूप में विभिन्न निविदाओं में प्रस्तुत किया है। एक प्राकृतिक सिद्धान्त के रूप में याचिकाकर्ता ने चीन जन. गण. और इजराइल, दोनों से भारत में संबद्ध उत्पाद की पहुंच कीमत निकालने के लिए अपनी ही कीमत का उपयोग किया है। याचिकाकर्ता ने पाटन रोधी नियमों के अनुबंध III के तहत प्रस्तुत सिद्धान्तों के आधार पर गैर-क्षति कीमत का निर्धारण नहीं किया है। इस प्रकार की स्वैच्छिक अवधारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
- xxxvi. जब याचिकाकर्ता ने कीमत की कटौती के संबंध में कोई सूचना ही प्रदान नहीं की है, तो यह वर्तमान मामले में कीमत में कटौती का दावा कैसे कर सकता है? इस संबंध में याचिकाकर्ता का दावा सिरे से नकार दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के आंकड़े स्वयं ही यह दर्शाते हैं कि कथित पाटन आयातों से उन पर कीमत से संबंधित कोई दबाव नहीं है जिनके कारण से उसे कम अनुकूल कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा।
- xxxvii. घरेलू उद्योग के लिए गैर-क्षति कीमत का निर्धारण करने में पाटन रोधी नियमों में एक तर्कसंगत रिटर्न दर शामिल की जानी आवश्यक है। घरेलू उद्योग के लिए यह बिल्कुल ही अनुचित होगा कि रिटर्न की इतनी अधिक दर का दावा किया जाए तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी को इतनी अधिक अनुचित गैर-क्षति कीमत के लिए जम्मेदार ऐसे रिटर्न की अनुमति प्रदान करके और इस प्रकार समग्र क्षति विश्लेषण की लीपा पोती की जाए।
- xxxviii. जांच की अवधि में संबद्ध देशों द्वारा आयात विगत दस वर्षों में सबसे कम रहा है। इसके अलावा, आयातों में अपने आप ही क्षति अवधि में 50 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। अतः आयात की मात्रा का विश्लेषण यह सिद्ध करता है कि ऐसा कुछ भी होने की संभावना का स्पष्ट रूप से कोई भी संकेत नहीं है।
- xxxix. भारत जितना बड़ा बाजार पहले था, अब उतना बड़ा बाजार नहीं रहा है। क्योंकि भारत में मांग में वर्ष 2010 – 11 की तुलना में जांच की अवधि में 60 प्रतिशत तक की गिरावट आई है, इसलिए भारत में वर्तमान में किसी संभावित निर्यात को आकर्षित करने के लिए मांग नहीं है।
- xl. हुआवेई चीन से आयातों की मात्रा जांच की अवधि के दौरान न्यूनतम स्तर पर रही है इसलिए पाटन की पुनरावृत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता है।
- xli. घरेलू उद्योग किसी “काल्पनिक क्षति” की पुनरावृत्ति को प्रमाणित नहीं कर पाया है और इसीलिए इस वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच की कार्यवाही के दौरान इस प्रश्न की आवश्यक रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। अतः घरेलू उद्योग को क्षति के निर्धारण का प्रश्न अभी भी निर्णायक समीक्षा के दौरान खुला हुआ है।
- xlii. निरंतर पाटन होने की सच्चाई आधारहीन है। निर्णायक समीक्षा के लिए जांच की अवधि के दौरान, हुआवेई इंडिया ने हुआवेई चीन से केवल पांच आयात किए हैं और यही आयात ऐसे उत्पादों का है जो घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित नहीं थे और इसीलिए ये पूर्व करारों के तहत लंबित दायित्वों को पूरा करने के लिए थे।
- xliii. हुआवेई इंडिया भारत में अपने निर्मित उत्पादों के लिए कथित ‘महत्वपूर्ण परिवर्तन’ करता है और इन्हीं उत्पादों में घरेलू उत्पादों का ‘प्रमुख हिस्सा’ होता है। अतः यह कथित ऐसे घरेलू उद्योग को ‘कड़ी प्रतिस्पर्धा’ देता है, जिनके लिए कथित घरेलू उद्योग अपने आपको सुस्थिर नहीं रख पाया। तदनुसार, यह कथित क्षति हुआवेई इंडिया द्वारा अपने विचाराधीन उत्पाद का घरेलू उत्पादन करने के संबंध में प्रस्तुत कड़ी स्पर्धा होने के कारण से है।
- xliv. घरेलू उद्योग की बिक्री और लाभ में पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने तत्काल बाद से तीव्रता से गिरावट आई है जबकि परिणाम इसके बिल्कुल विपरीत होने चाहिए। घरेलू उद्योग के निर्यातों में भी गिरावट आई है / सुधार नहीं आया है, जिन पर पाटन का प्रभाव भी नहीं पड़ा था। अतः घरेलू उद्योग के उत्पादों की बिक्री में गिरावट कथित पाटन के कारण से नहीं कही जा सकती क्योंकि घरेलू उद्योग पाटन रोधी गैर शुल्क अवधि में अधिक बिक्री दर्ज कर रहा था।

- xlv. कारणात्मकता भंग होना : प्राधिकारी को, क्षति होने और संबद्ध आयातों के बीच एक कारणात्मक संबंध स्थापित करना चाहिए। यह कहा जाता है कि वर्तमान जांच में भारी कारणात्मकता भंग हुई है, जो प्राथमिक रूप से भारतीय बाजार में अचानक से गिर रही मांगों और याचिकाकर्ता के कम निवेश के विकल्पों से प्रकट हुई है।
- xlvi. याचिकाकर्ता की अक्षमताएं : यह कहा जाता है कि याचिकाकर्ता को अपनी प्रचालनात्मक अक्षमता और खराब प्रबंधकीय निर्णयों से क्षति का सामना करना पड़ा है। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण वर्ष 2010 – 11 और 2011 – 12 में कंपनी द्वारा किया गया निर्धारित परिसंपत्ति निवेश है। यद्यपि विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में गिरावट आ रही थी लेकिन याचिकाकर्ता विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्धारित परिसंपत्तियों में भारी निवेश कर रहा था। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि खराब निष्पादन करने वाले बाजार में याचिकाकर्ता ने इतना भारी निवेश किए जाने के बावजूद नुकसान उठाते हुए हटना पड़ा था। उसके बाद याचिकाकर्ता के मुनाफे में 2010 – 11 से 2011 – 12 तक थोड़ा नुकसान होने को छोड़कर सुधार आया है, जो कि उपरोक्त से स्पष्ट है। अतः यह कहा जाता है कि विचाराधीन आयातित उत्पाद और याचिकाकर्ता को हुई क्षति के बीच कोई भी परस्पर संबंध नहीं है। स्पष्ट रूप से अन्य गैर-उत्तरदायी कारक हैं जैसे याचिकाकर्ता की अक्षमता तथा मांग में कमी आदि, जिनके कारण याचिकाकर्ता को क्षति हुई है।
- xlvi. कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की कमी : विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में काफी गिरावट आई है। यह इस बात को दर्शाता है कि कथित पाटन आयातों और आवेदक को हुई निरंतर किसी क्षति के बीच कोई भी कारणात्मक संबंध नहीं है और इसके कारण निरंतर हो रही क्षति के लिए अन्य कारक भी हैं, जैसे कि विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में गिरावट। आवेदक ने गलती से यह तर्क दिया कि संबद्ध उत्पाद के लिए मांग में आगे आने वाली संभावित निविदाओं को देखते हुए भारत में वृद्धि होने की संभावना है। सच्चाई यह है कि एस डी एच प्रौद्योगिकी शीघ्र ही प्रचलन से बाहर हो जाएगी और इसके स्थान पर डी डब्ल्यू डी एम, ओ टी एन और पी टी एन प्रौद्योगिकी आ जाएगी। ये अधिक बेहतर प्रौद्योगिकियां हैं जो ज्यादा नेटवर्क बैंडविड्थ प्रदान करती हैं और साथ ही अधिक दूरी तक अधिक गति से नेटवर्क सुलभ कराती हैं। वास्तव में, नेटवर्क आपूर्तिकर्ताओं ने पहले ही इन प्रौद्योगिकियों की ओर परिवर्तन आरंभ कर दिया है और अपनी निविदाओं में इसकी मांग करना आरंभ कर दिया है। आवेदक संबद्ध उत्पाद के लिए इसके उत्पादन में वृद्धि की आशा नहीं कर सकते हैं क्योंकि एस डी एच प्रौद्योगिकी को सभी उपयोगता धीरे-धीरे हटा रहे हैं।
- xlviii. यह स्वीकार करते हुए कि प्रौद्योगिकी में विकास के परिणामस्वरूप एक ही यूनिट में अनेक उत्पाद / कार्य उपलब्ध हैं, जो अब तक केवल अलग-अलग उत्पादों के रूप में उपलब्ध थे, इसी प्रकार प्रौद्योगिकी में विकास के परिणामस्वरूप एक ही बक्से में एस डी एच, ओ टी एन और डी डब्ल्यू डी एम प्रौद्योगिकियां एक साथ उपलब्ध हो गई हैं, जो पहले केवल अलग-अलग उत्पादों के रूप में ही उपलब्ध थी। इस महत्वपूर्ण विकास को स्वीकार करते हुए, पाटन रोधी शुल्क केवल उन्हीं वस्तुओं के लिए ही लगाया जाना चाहिए जो कि पूर्ण रूप से एस डी एच प्रौद्योगिकी से निर्मित हो, न कि ऐसे उत्पादों पर जहां एस डी एच का प्रयोग विविध प्रौद्योगिकियों वाले एक बक्से के भाग के रूप में किया गया हो।
- xlix. घरेलू उत्पादकों के समक्ष आ रही प्रतिस्पर्धा के अलावा, कथित घरेलू उद्योग के उत्पाद की मांग में गिरावट के लिए एक अन्य कारक पर भी विचार किया जाए और वह है प्रौद्योगिकी का विकास।
- i. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि इस कारण से मौखिक विचार प्रस्तुत करने के लिए हमें पुनः अवसर प्रदान करे कि याचिकाकर्ता ने अप्रैल, 2013 – मार्च, 2014 तक की जांच की अवधि के लिए याचिका दाखिल की है लेकिन प्राधिकारी द्वारा दिनांक 06.12.2014 की जांच आरंभन अधिसूचना की अवधि को तीन माह के लिए बढ़ाया गया है।
 - ii. याचिकाकर्ता ने संबद्ध देशों से आयातों के संबंध में अपनी याचिका के विभिन्न भागों / खंडों में परस्पर विरोधी सूचना प्रदान की है। याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि लागत में गिरावट से भी अधिक गिरावट बिक्री की कीमत में आई है जिसके कारण कीमत में कमी आई है। तथापि, याचिका में प्रदान की गई परस्पर विरोधी सूचना यह दर्शाती है कि कथित घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत में निरंतर और महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो जांच की अवधि में आधार वर्ष में 100 से बढ़कर 152 तक है। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि संबद्ध देशों से आयातों के कारण कथित घरेलू उद्योग पर कोई कीमत संबंधी प्रभाव नहीं पड़ा है।
 - iii. सरकारी कंपनियां निविदाएं भेज रही हैं। तथापि, घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पादों के लिए भाग नहीं ले रहा, जो इस तथ्य के आधार पर हो सकता है कि या तो घरेलू उद्योग के पास आपूर्ति करने की क्षमता नहीं है या सहायता के लिए प्रौद्योगिकी नहीं है। घरेलू उद्योग को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह सरकारी कंपनियों को विचाराधीन उत्पाद के तहत उत्पादों की घरेलू आपूर्ति के लिए निविदाओं में भाग लेने में अपनी विफलता के कारणों के बारे में स्पष्ट करे। इसके अलावा, कथित घरेलू उद्योग को भाग लेने के संबंध में तथा इस शुल्क लगाने की अवधि के दौरान ऐसी निविदाओं की सफलता की दर के बारे में ब्यौरे उपलब्ध कराने का निदेश दिया जाए।
 - iiii. घरेलू उद्योग ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी यह आरोप लगाया था कि विदेशी आपूर्तिकर्ता अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए भारतीय ग्राहकों को लंबी उधार की अवधि प्रदान कर रहे हैं। कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध विभिन्न

वर्षों के लिए घरेलू उद्योग के तुलन पत्र का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग भी अपने उपभोक्ताओं को इसी तरह से उधार प्रदान करता है और उनकी बिक्री का 50 प्रतिशत से अधिक उधार बकाया था। साथ ही औसतन 14 – 15 प्रतिशत बिक्रियां 180 से अधिक दिनों की अवधि की उधारी पर की गई थी।

- liv. घरेलू उद्योग ने यह आरोप लगाया है कि इसके उत्पादों को आयातित उत्पादों की कम कीमतों के कारण से कीमत ह्रास / गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, यह भी आरोप लगाया गया है कि घरेलू उद्योग ने आयातित उत्पादों की इतनी कम कीमत के कारण निविदाएं खो दी हैं। इस संबंध में यह कहा जाता है कि कथित घरेलू उद्योग ने कहीं भी अपने दावा को प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है कि आयातित वस्तुएं कम कीमत की हैं। यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग ने जैसा कि यह स्वीकार किया है कि उसमें आर एंड डी के लिए अधिक संभावना नहीं बची है, विचाराधीन उत्पाद (अर्थात् एस डी एच ट्रांसमिशन उपस्कर) के संबंध में आर एंड डी में शामिल नहीं हुआ है। अतः यह कहा जाता है कि यदि घरेलू उद्योग के आर एंड डी क्रियाकलाप एस डी एच ट्रांसमिशन उपस्कर के संबंध में शामिल नहीं किए गए हैं लेकिन अन्य उत्पादों (अर्थात् विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल न किए गए उत्पाद जैसे ओ टी एन/डी डब्ल्यू डी एन) के लिए किए गए हैं, तो ऐसे आर एंड डी की लागत वर्तमान समीक्षा / जांच के संबंध में असंगत मानी जानी चाहिए और उससे वर्तमान मामले में कथित पाटन के लिए क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए की गई गणना से बाहर रखा जाए। तदनुसार, यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग को उसके द्वारा किए गए आर एंड डी की प्रकृति के ब्यौरे और ऐसे आर एंड डी से क्या उत्पाद तैयार किए गए, उनके ब्यौरे प्रदान करने का निदेश दिया जाए।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

65. क्षति और आकस्मिक लिक के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- क. पाटनरोधी शुल्क के बावजूद संबंध देशों से पाटित आयात पर्याप्त बना रहा। सामान्यतः विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा आयातित एसडीएच उपकरण का परिनियोजन और विशेष रूप से विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा हुआवै उपकरण का परिनियोजन सिद्ध करता है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद घरेलू उद्योग को काफी क्षति हुई है।
- ख. पाटन-रोधी शुल्क के बावजूद भारत में कुल आयात और खपत के संबंध में संबंध आयातों में वृद्धि हुई है।
- ग. संबंध आयात काफी सीमा तक घरेलू उद्योग के कम दाम और कम विक्रय कीमतें हैं। कम दाम कीमत घरेलू उद्योग द्वारा पहले से रखी गई कम कीमतों के बावजूद है।
- घ. आयात कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करते हैं जो पाटित आयात के अभाव में हुआ होता। आयात कीमत प्रतिबंध और मंदी दोनों के कारण है। इसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग ऋणात्मक लाभ, नकद लाभ, पीबीआईटी और निवेश पर प्रतिफल का सामना करता है। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा घट गया है जबकि संबंध देशों से उसका आयात बढ़ गया है।
- ङ. इस तर्क के संबंध में कि याचिकाकर्ता ने क्षति अवधि के लिए क्षमता और क्षमता उपयोगिता संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं, याचिकाकर्ता मूल अंतिम विकर्ष परिणामों को संदर्भित करता है और विश्वास करता है जिसमें मुद्दे का समाधान कर लिया गया है।
- च. 2011-12 में घरेलू उद्योग से बिक्री घट गई है परंतु उसके बाद बढ़ गई है। यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग अपनी कीमतों आयात कीमतों के अनुरूप रखता है जबकि बिक्री मात्रा और परिणामस्वरूप उत्पादन उस अवधि में बढ़ा। हालांकि बिक्री इस मात्रा से काफी कम है जो कंपनी ने विगत में अथवा क्षति अवधि के आधार वर्ष में हासिल की है।
- छ. क्षति अवधि के दौरान बाजार में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से याचिकाकर्ता द्वारा अर्जित लाभ में गिरावट आई है। इस प्रकार पिछले वर्षों में लाभ में काफी गिरावट आई है और 2011-12 से याचिकाकर्ता को वित्तीय हानि हुई है। इसे परिणामस्वरूप निवेश पर प्रतिफल और नकद प्रवाह भी घटा है। यह ऐसी स्थिति है जबकि पाटनरोधी शुल्क अस्तित्व में है। पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति और चालू शुल्क की गैर-वृद्धि से घरेलू उद्योग की स्थिति और अधिक खराब होगी। घरेलू उद्योग इस तथ्य के कारण अपनी लाभप्रदता को बढ़ाने में सक्षम नहीं है कि आयातकर्ता इसके लिए गैर-एसडीएच का दावा करते हुए उत्पाद का आयात कर रहे हैं और कर का अपवंचन कर रहे हैं। इसलिए पाटनरोधी शुल्क का उपचारात्मक प्रभाव को समाप्त कर रहा है।
- ज. इस तथ्य के बावजूद की याचिकाकर्ता भारत की प्रथम ऑप्टिकल नेटवर्किंग उत्पाद कंपनी है जो नवाचार है और पर्याप्त बौद्धिक संपत्ति सृजित कर रही है और पाटनरोधी शुल्क होने के कारण घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा नहीं बढ़ा है। यह भारत में विचाराधीन उत्पाद के निरंतर पाटन के तथ्य के कारण इसमें गिरावट आई है।
- झ. अपनी रेंज का विस्तार करने के लिए नए उत्पाद शुरू करके याचिकाकर्ता को अपने बाजार हिस्से में वृद्धि होने की आशा थी जबकि बाजार में पाटित आयात होने के कारण पिछले वर्षों में आयातकर्ता के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।
- ञ. 2011-12 की तुलना में पीओआई के दौरान मजदूरी में काफी गिरावट आई है।

- ट. अन्य उत्पादों की तरह किसी प्रौद्योगिकी उत्पाद में प्रत्येक 6 माह में आरएंडडी किए जाने की आवश्यकता है। ग्राहकों की बढ़ती मांग के साथ उत्पादों को उन्नत किए जाने की आवश्यकता है। आरएंडडी केवल नए उत्पादों के लिए ही आवश्यक नहीं है बल्कि नए उत्पादों को उन्नत किए जाने के साथ-साथ बाजार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी आवश्यक है।
- ठ. पक्ष अपने प्रयोजनों के अनुरूप आंकड़ों की गलत ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। मूल्यहास केवल किंचित बढ़ा है।
- ड. विरोधी हितबद्ध पक्ष यह नोट करने में विफल रहे हैं कि याचिकाकर्ता ने निवेश पर ऋणात्मक प्रतिफल का सामना किया है जो स्वयं में घरेलू उद्योग द्वारा वहन की गई क्षति सिद्ध करने में अपर्याप्त है।
- ढ. घरेलू उद्योग के लिए ब्याज लागत आधार वर्ष में 100 प्वाइंट से घटकर जांच की अवधि में 71 प्वाइंट हो गई। इस अवधि में ब्याज लागत में भी गिरावट आई है।
- ण. याचिकाकर्ता के पास काफी निर्यात कार्यकलाप है। घरेलू और निर्यात में संयुक्त प्रचालनों में इसका लाभ धनात्मक रहा। तथापि निर्यात लाभ इस समय घरेलू क्षति का वित्त पोषण कर रहा है। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के आधार पर कोई भी कंपनी लंबे समय तक विद्यमान नहीं रह सकती। पाटन ने घरेलू उद्योग के लिए बहुत प्रतिकूल स्थिति सृजित कर दी है।
- त. कानूनी अपेक्षा कम दाम कीमत अथवा कीमत प्रतिबंध अथवा कीमत मंदी सिद्ध करना है। कीमत प्रभाव को सिद्ध करने के लिए कम दाम कीमत अनिवार्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने कुछ कीमत की पेशकश की है और अब विदेशी उत्पादकों द्वारा पेशकश की गई कीमत को कम सिद्ध करने का अवसर गंवा दिया है। तथापि निर्यातकों और उत्पादकों ने वर्तमान जांच के लिए प्रतिक्रिया की है। इसलिए इस चरण पर कम दाम कीमत पीसीएन-वार निर्धारित की जा सकती हैं।
- थ. याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के दौरान विक्रय कीमत में कभी विवाद नहीं बढ़ाया। तथापि, बिक्री की लागत बढ़ गई है परंतु घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि या लागत के स्तर तक वृद्धि के अनुपात में अपनी कीमतें नहीं बढ़ा सका।
- द. घरेलू उद्योग 2011-12 से वित्तीय हानि झेल रहा है। विरोधी हितबद्ध पक्षों ने तथ्यात्मक आधार के बिना अपने तर्क दिए हैं। हुआवै इंडिया के दावे के संबंध में कंपनी ने अपने अनुरोधों में कभी भी यह नहीं कहा कि वे लाभ कमा रहे हैं। न ही हितबद्ध पक्षों ने यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध कराया है कि हुआवै इंडिया विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक है अथवा यह लाभ अर्जित कर रहा है।
- ध. कम विक्रय कीमत और मार्जिन की सूचना उपलब्ध कराने के लिए कोई कानूनी अपेक्षा नहीं है। तथापि याचिकाकर्ता ने अपनी बेहतर क्षमता से सूचना उपलब्ध कराई है। अब निर्यातकों ने प्रतिक्रिया की है कि क्षति मार्जिन उनके द्वारा फाइल की गई सूचना के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
- न. याचिकाकर्ता भी दावा करता है कि प्राधिकारी को कंपनी मानदण्डों के अनुसार निवेश पर प्रतिफल के आधार पर गैर क्षति कीमत निर्धारित करनी चाहिए न कि मनमाने ढंग से 20%। अनुबंध-III में गैर-क्षति कीमत निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश की व्यवस्था है। परंतु इसे भी मामला दर मामला आधार पर देखा जाना होगा। मूल मामले में प्राधिकारी के अंतिम विकर्ष परिणाम संदर्भित किए गए हैं और इन पर निर्भर है।
- प. याचिकाकर्ता अनुरोध करता है कि प्रौद्योगिकी में विकास का अभिप्राय एक नई प्रौद्योगिकी जो पिछली को प्रतिस्थापित करे, से है। उदाहरण के तौर पर सीडीआर से पैन ड्राइव। तथापि प्रौद्योगिकी का उन्नयन एक प्राकृतिक सिद्धांत है और ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए समय-समय पर प्रत्येक प्रौद्योगिकीय उत्पाद का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता है। कोई एसडीएच उपकरण (i) वायस और डाटा को डिजिटल सिग्नलों में कंवर्ट करता है (ii) इन्हें पैकेट्स में बंडल करता है (iii) उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करता है तथा (iv) ग्राहक को डिलिवर करने के लिए उन्हें डिकोड करता है और उन्हें वाइस और डाटा में सेग्रिगेट करता है। वाइस और डाटा का अधिक प्रयोग होने के एसडीएच उपकरण की क्षमता बढ़ाने उन्नयन किए जाने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने और उत्पाद को अधिक दक्ष बनाने के लिए एसडीएच उपकरण का समय-समय पर उन्नत किए जाने की आवश्यकता है। इस उन्नयन प्रक्रिया में काफी आरएंडडी की आवश्यकता है। इस प्रकार विचाराधीन उत्पाद का लगातार उच्च वर्जनों में उन्नयन किया जा रहा है जो विभिन्न नामों से बेचे जा रहे हैं। विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद का कार्यक्षेत्र इसके किसी भी रूप में 'एसडीएच ट्रांसमिशन उपकरण' है और इसमें विचाराधीन उत्पाद के सभी उन्नत वर्जन शामिल हैं।
- फ. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि पाटन और उसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति प्रारंभिक चरण में पूर्व निर्धारित अवधि के लिए मानी गई है। बाद के किसी भी परिवर्तन का इससे कोई संबंध नहीं है। विरोधी हितबद्ध पक्षों का पूर्वग्रह जांच की अवधि और इसकी संगतता की सत्यता से दूर ले जाएगा।
- ब. उच्च संरक्षण के बावजूद घरेलू उद्योग लगातार पाटन का सामना कर रहा है और इसे क्षति हो रही है। भारतीय बाजार में भारी मात्रा में आयात हो रहा है और पाटन रोधी शुल्क के भुगतान से बचने और उत्पाद भारत में लाने के लिए सभी प्रकार की पद्धतियों का

सहारा ले रहा है। डीआरआई जांच पहले ही इसे सिद्ध कर चुकी है। पाटनरोधी शुल्क समाप्ति की स्थिति में इन आयातकर्ताओं को घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाने के लिए पाटित आयात के लिए खुली पहुंच होगी।

भ. पाटनरोधी शुल्क आयात अपने आप में आयात के विरुद्ध नहीं है। पाटनरोधी शुल्क अनुचित आयात के विरुद्ध है। सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर याचिकाकर्ता ने प्रमाणित किया है कि लगातार पाटन हो रही है जो घरेलू उद्योग की क्षति का कारण है और पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने की स्थिति में संभावित पाटन और क्षति को सिद्ध करने के लिए अपने आप में पर्याप्त है।

म. विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में कमी निम्नलिखित कारकों की वजह से है :

क. 2जी स्पेक्ट्रम घोटालों के कारण सरकारी स्वामित्व/नियंत्रित कंपनियों द्वारा अधिप्राप्ति में काफी कमी।

ख. एमटीएनएल और बीएसएनएल वित्तीय कठिनाइयों से जूझ रहे हैं।

ग. अत्यधिक प्रतिस्पर्धा गैर-लाभप्रद प्रशुल्क स्तर हुआ।

घ. पुनः वर्गीकरण और अनुचित वर्गीकरण-डीआरआई जांच ने पता लगाया है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात को किस प्रकार गैर-एसडीएच घोषित किया जा रहा है और अनुचित वर्गीकृत किया गया है जिससे आगे कम मांग हुई।

य. मांग में गिरावट के कारण याचिकाकर्ता क्षति उठा रहा है। यह अनुरोध किया गया है कि पाटन क्षति का अकेला अथवा प्रमुख कारण होना आवश्यक नहीं होगा।

कक. यदि भारत संभावित निर्यात के लिए बड़ा बाजार नहीं बना रहता है तो किस प्रकार सभी निर्यातकों को शुल्क के विस्तार से आपत्ति है। पाटनरोधी शुल्क का अपवंचन भारतीय बाजार में पाटित उत्पाद में आयातकर्ताओं की हताश को सिद्ध करता है। यह स्पष्ट रूप से पाटन के जारी रहने की संभावना और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति को दर्शाता है।

खख. हितबद्ध पक्ष का यह कथन कि 266% उच्च शुल्क लगाने से बाजार में मांग और आपूर्ति के रूख को काफी परिवर्तित करने की क्षमता है, यह स्वयं सिद्ध करता है कि शुल्क लगाने के कारण आयात नियंत्रित हो गया है और पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने से चीन से आयात में वृद्धि होगी।

प्राधिकारी द्वारा जांच

66. प्राधिकारी द्वारा किया गया जांच विश्लेषण हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का तथ्यतः समाधान करता है। तथापि हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए और संगत माने गए और प्राधिकारी द्वारा समाधान किए गए विशेष अनुरोध यहां नीचे दिए गए हैं:

A. मात्रा प्रभाव

आयात मात्रा का निर्धारण

67. प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से विचाराधीन उत्पाद से संबंधित आयात के आंकड़े मंगाए थे जिस डी जी सी आई एस ने प्राधिकारी को उपलब्ध करा दिया था। प्राधिकारी ने अनेक विगत जांच में अपनाई गई पद्धति के अनुसार डी जी सी आई एंड एस द्वारा यथासूचित आयात की मात्रा को अपनाया है। तदनुसार, निर्धारित आयात की मात्रा को नीचे दर्शाया गया है :

आयात	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई (वार्षिकीकृत)	पीओआई (अप्रैल, 2013- जून, 2014)
संबद्ध देश						
-चीन पीआर	संख्या	18	4,847	5,206	1907	2,384
-इजराइल	संख्या	37,954	20,100	5,180	9,583	11,979
समग्र रूप से संबद्ध देश	संख्या	37,972	24,947	10,386	11,490	14,363
अन्य देश	संख्या	1,441	1,127	1,077	2,483	3,104
कुल आयात	संख्या	39,413	26,074	11,463	13,973	17,467

68. यह देखा गया है कि चीन से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में मूल वर्ष से लेकर वर्ष 2012-13 तक वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच अवधि में उसमें गिरावट आई है। इसी प्रकार इजरायल से वर्ष 2010-11 से लेकर 2012-13 तक आयात में गिरावट आई है लेकिन विगत वर्ष की तुलना में जांच अवधि में आयातों में वृद्धि हुई है।

मांग का निर्धारण

69. प्राधिकारी ने घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में देश में संबद्ध वस्तुओं की मांग अथवा प्रत्यक्ष खपत निर्धारित की है। इस प्रकार निर्धारित की गई मांग निम्नलिखित तालिका में देखी जा सकती है :

मांग	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई (वार्षिकीकृत)	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	संख्या	20,069	6,263	5,970	6,454	8,067
अन्य की बिक्री	संख्या	7,379	3,407	2,093	2,138	2,673
संबद्ध देशों से आयात						
-चीन पीआर	संख्या	18	4,847	5,206	1907	2,384
-इजराइल	संख्या	37,954	20,100	5,180	9,583	11,979
संपूर्ण देश में संबद्ध देशों से आयात	संख्या	37,972	24,947	10,386	11,490	14,363
अन्य देशों से आयात	संख्या	1,441	1,127	1,077	2,483	3,104
कुल मांग/खपत	संख्या	66,861	35,744	19,526	22,565	28,206
कुल मांग में घरेलू उद्योग की बिक्री	%	30	18	31	29	29
कुल मांग में अन्य की बिक्री	%	11	9	10	8	8
कुल मांग में संबद्ध देशों से आयात						
-चीन	%	0	14	27	9	9
-इजराइल	%	57	57	27	43	43
कुल मांग में संपूर्ण रूप से संबद्ध देशों से आयात	%	57	71	54	52	52
कुल मांग में अन्य देशों से आयात	%	2	3	6	11	11
कुल मांग/खपत	%	100	100	100	100	100

70. यह देखा गया है कि मूल वर्ष से लेकर वर्ष 2012-13 तक संबद्ध वस्तुओं की कुल मांग में प्राप्त रूप से गिरावट आई है और उसके बाद उनकी मांग में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की बिक्रियों में मूल वर्ष की तुलना में समग्र जांच अवधि में गिरावट का पता चला है। इसके अतिरिक्त कुल मांग में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के कुल आयातों में आधार वर्ष की तुलना में क्षति अवधि के दौरान मामूली सी वृद्धि हुई है।

आयात की मात्रा और बाजार हिस्सा

71. पाटित आयात की मात्रा के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में उत्पादन अथवा खपत निरपेक्ष रूप से अथवा सापेक्ष रूप से पाटित आयात में काफी वृद्धि हुई है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II(ii) में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है : -

“पाटित आयात की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेगा कि क्या भारत में उत्पादन अथवा खपत में निरपेक्ष अथवा सापेक्ष रूप में पाटित आयात में काफी वृद्धि हुई है”

72. संबद्ध देशों से पाटित आयात का बाजार हिस्सा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

आयात	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई (वार्षिकीकृत)	पीओआई (अप्रैल, 2013- जून, 2014)
संबद्ध देश		18	4,847	5,206	1907	2,384
-चीन पीआर	संख्या	37,954	20,100	5,180	9,583	11,979
-इजराइल	संख्या	37,972	24,947	10,386	11,490	14,363
समग्र रूप से संबद्ध देश	संख्या	1,441	1,127	1,077	2,483	3,104
अन्य देश	संख्या	39,413	26,074	11,463	13,973	17,467
कुल आयात	संख्या	66,861	35,744	19,526	22,565	28,206
कुल मांग/खपत	संख्या	28,178	9,769	9,669	11,773	14,716
कुल भारतीय उत्पादन	संख्या					
आयात में बाजार का हिस्सा:						
संबद्ध देश-		0.05	18.59	45.42	13.65	13.65
-चीन	%	96.30	77.09	45.19	68.58	68.58
-इजराइल	%	96.35	95.68	90.60	82.23	82.23
समग्र रूप से संबद्ध देश	%	3.65	4.32	9.40	17.77	17.77
अन्य देश	%					
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देश से आयात:		96.35	95.68	90.60	82.23	82.23
कुल आयात	%	56.79	70.23	53.70	51.81	51.81
मांग	%	135	255	107	98	98

73. यह देखा गया है कि समस्त क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के कुल आयातों के संबंध में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है लेकिन यह अभी भी विशेष रूप से बना हुआ है। इसके अतिरिक्त भारत में संबद्ध वस्तुओं की कुल मांग के संबंध में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के बाजार के हिस्से में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त जबकि प्रतिशत के रूप में संबद्ध देशों से आयात विशेष रूप से बने हुए हैं, फिर भी भारतीय उत्पादन के उत्पादन प्रतिशत में गिरावट आई है।

B. लाभ प्रभाव

74. कीमतों पर पाटित आयात के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि भारत के समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयात द्वारा दाम कीमत पर्याप्त कम रही है। काफी मात्रा के लिए कीमतें कम हुई हैं अथवा इस प्रकार का आयात अन्यथा कीमत वृद्धि रूकी है जो अन्यथा काफी मात्रा तक बढ़ी होती।

कम दाम कीमत

75. संबद्ध देशों के संबंध में कीमत कटौती का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से सहकारी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर के आधार पर जांच अवधि के लिए संबद्ध देशों के लिए पहुंच मूल्य का निर्धारण किया है। ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि क्षति अवधि के लिए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों में पी सी एन के साथ पीसीएन की मैपिंग/मिलान करना संभव नहीं था क्योंकि डी जी सी आई एंड एस के आयात के आंकड़ों में पी सी एन संरचित करने के लिए पूरी सूचना शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक ग्राहक अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एस डी एच उपस्कर अधिप्राप्त करता है। एक स्टेशन पर ग्राहक द्वारा प्रयुक्त किए गए एस डी एच उपस्कर दूसरे स्टेशनों पर प्रयुक्त किए गए एस डी एच उपस्करों से उसकी वास्तविक और दृष्टिगत गुण क्षमताओं के कारण भिन्न हो सकते हैं। इसलिए, जांच अवधि के लिए सहयोगी निर्यातकों की निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के साथ घरेलू उद्योग की संबद्ध वस्तुओं की अलग-अलग पीसीएन की मैपिंग/तुलना की गई है क्योंकि इन पक्षकारों ने पीसीएन वार ब्यौरे प्रस्तुत किए थे। जांच अवधि के लिए संबद्ध देशों से सहयोगी निर्यातकों के लिए इस प्रकार से निर्धारित किए गए पहुंच मूल्य के साथ घरेलू उद्योग की निवल बिक्रियों की वसूली (एन एस आर) की तुलना करने से ऐसा पता चला है कि चीन जनवादी गणराज्य के संबंध में कीमत कटौती का मार्जिन अत्यधिक है और इजरायल के संबंध में यह नगण्य है।

क्रम सं	विवरण	यूनिट	पीओआई (अप्रैल, 2013-जून, 2014)
क	चीन पीआर		
	उतराई कीमत	रूपए/संख्या	***
	निवल बिक्री प्राप्ति	रूपए/संख्या	***
	कम दाम कीमत	रूपए/संख्या	***
	कम दाम कीमत	%	***
	कम दाम कीमत रेंज	%	35 to 50
ख	इजराइल		
	उतराई लागत	रूपए/संख्या.	***
	निवल बिक्री प्राप्ति	रूपए/संख्या.	***
	कम दाम कीमत	रूपए/संख्या.	***
	कम दाम कीमत	%	***
	कम दाम कीमत रेंज	%	(-) 180 to 195
ग	संबद्ध देश		
	कम दाम कीमत	रूपए/संख्या.	***
	कम दाम कीमत	%	***
	कम दाम कीमत रेंज	%	(-) 35 to 50

कम बिक्रय कीमत

76. संबद्ध देशों के संबंध में कम कीमत पर बिक्री का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की समान क्षति रहित कीमत के साथ सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर के आधार पर संबद्ध देशों के लिए पहुंच मूल्य का निर्धारण किया है। ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि क्षति अवधि के लिए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों में पी सी एन के साथ पीसीएन की मैपिंग/मिलान करना संभव नहीं था क्योंकि डी जी सी आई एंड एस के आयात के आंकड़ों में पी सी एन संरचित करने के लिए पूरी सूचना शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक ग्राहक अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एस डी एच उपस्कर अधिप्राप्त करता है। एक स्टेशन पर ग्राहक द्वारा प्रयुक्त किए गए एस डी एच उपस्कर दूसरे स्टेशनों पर

प्रयुक्त किए गए एस डी एच उपस्करों से उसकी वास्तविक और दृष्टिगत गुण क्षमताओं के कारण भिन्न हो सकते हैं। तथापि, जांच अवधि के लिए सहयोगी निर्यातकों की निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के साथ घरेलू उद्योग की संबद्ध वस्तुओं की अलग-अलग पीसीएन की मैपिंग/तुलना की गई है क्योंकि इन पक्षकारों ने पीसीएन वार ब्यौरे प्रस्तुत किए थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न सहयोगी निर्यातकों द्वारा निर्यात किए गए उत्पाद की विशेषताएं भिन्न हैं क्योंकि उनमें से कुछ उत्पादों का निर्यात केवल उपस्करों के लिए किया गया है और कुछ का निर्यात उपस्करों के साथ-साथ कार्डों अथवा केवल कार्डों के लिए ही किया गया है और घरेलू उद्योग ने केवल उपस्करों का ही उपयोग किया है। इसलिए सहयोगी निर्यातकों के पीसीएन के साथ घरेलू उद्योग की अधिकतर पी सी एन की मैपिंग/तुलना, घरेलू उद्योग के घटकों और संघटकों की लागत के आधार पर इन पी सी एन की लागत की संरचना करके की गई है। इसमें उन उपस्करों को शामिल नहीं किया गया है जोकि पीसीएन के समान हैं। इसके फलस्वरूप, प्रत्येक पृथक सहकारी निर्यातक के लिए घरेलू उद्योग की एनआईपी भिन्न है। चीन जनवादी गणराज्य के लिए सहकारी निर्यातकों की औसत एन आई पी को लिया गया है। पहुंच मूल्य के साथ घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत (एन आई पी) की तुलना करने से निर्धारित किए गए कम कीमत पर बिक्री के मार्जिन को नीचे दर्शाया गया है।

विवरण	यूओएम	चीन पीआर	इजराइल
एनआईपी	रूपए/संख्या.	***	***
उतराई लागत	रूपए/संख्या.	***	***
कम दाम कीमत	रूपए/संख्या.	***	***
कम दाम कीमत	%	***	***
कम दाम कीमत	% रेंज	70 to 80	(-) 5 to -10

कीमत प्रतिबंध एवं कीमत मंदी

77. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या विचाराधीन उत्पाद घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की कीमतों का मूल्यहास अथवा न्यूनीकरण कर रहे हैं, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार घरेलू उद्योग के लिए बिक्रियों की लागत और बिक्री राजस्व की प्रवृत्तियों पर विचार किया है। संबद्ध सूचना निम्नानुसार है :

पैरामीटर	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई
बिक्री की लागत	रूपए/संख्या	***	***	***	***
रुख	सूचकांक	100	174	186	196
विक्रय कीमत	रूपए/संख्या	***	***	***	***
रुख	सूचकांक	100	116	161	159

78. यह देखा गया है कि हालांकि समस्त क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कम कीमत पर बिक्री में वृद्धि हुई है फिर भी बिक्रियों की लागत की प्रवृत्तियों से ऐसा पता चलता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में तदनुरूपी बिक्री कीमत से काफी अधिक वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप कीमत में हास और न्यूनीकरण हुआ है।

घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक प्राचलों की जांच

79. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II की अपेक्षा है कि क्षति के निर्धारण के लिए इस प्रकार के उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुगत जांच की जानी चाहिए। नियमावली में आगे यह व्यवस्था है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयात के प्रभाव की जांच में सभी संबंधित आर्थिक कारकों और वास्तविक एवं बिक्री में संभावित कमी, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिफल अथवा क्षमता उपयोग, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर संभावित ऋणात्मक प्रभाव, रोजगार, मजदूरी, पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता और क्षमता रहित उद्योग की स्थिति युक्त सूचकों का वस्तुगत और निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति प्राचल नीचे दिए गए हैं।

क्षमता और क्षमता उपयोग:

80. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि इस उद्योग में उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण भाग उत्पाद का डिजाइन और विकास है। विनिर्माण और उसके विस्तार की वास्तविक प्रक्रिया आंतरिक हो सकती है अथवा आवश्यकता पर निर्भर करते हुए बाहर से ली जा सकती है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि संयंत्र और मशीनरी कोई अभिवृद्धि किए बिना यह भारत की संपूर्ण मांग को पूरा कर सकता है क्योंकि इस उद्योग में उत्पादक इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग सर्विसेज भागीदारों जिनके पास भारत की अगले दस वर्ष की आवश्यकताओं को पूरा करने की काफी क्षमता है, की क्षमताओं से फायदा उठा सकता है। दूसरे शब्दों में क्षमता और क्षमता उपयोग आवश्यक डिजाइन और विकास तथा अपनी वैश्विक आपूर्ति चेन की व्यवस्था करने के लिए योग्य कार्मिक प्रतिनियुक्त करने के लिए कंपनी की बौद्धिक संपदा और सक्षमता अवश्य दिखाई देनी चाहिए। इस कारण याचिकाकर्ता के पास भारतीय मांग को पूरा करने के लिए काफी क्षमता है। इसे ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि क्षमता उपयोग वर्तमान मामले में असंगत प्राचल माना जाए।
81. याचिकाकर्ता ने किसी हितवद्ध पक्ष ने यह विवाद नहीं होने का दावा भी किया है कि विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन बहुत विशेष है। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उत्पादन करने की क्षमता वास्तव में उपयुक्त प्राचल नहीं है और वर्तमान मामले की परिस्थितियां कई कारकों पर निर्भर करते हुए बाहर से लिए गए भाग उत्पाद कार्यकलाप के लिए विनिर्माता को निर्णय लेना है। प्राधिकारी का मानना है कि इस स्कोर पर याचिकाकर्ता का दावा सही है।

उत्पादन और बिक्री मात्रा

82. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री मात्रा में हुआ परिवर्तन नीचे दर्शाया गया है:

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई (वार्षिकीकृत)	पीओआई
उत्पादन	संख्या	***	***	***	***	***
सूचकांक	रुख	100	32	37	48	48
घरेलू बिक्री	संख्या	***	***	***	***	***
सूचकांक	रुख	100	31	30	32	32

83. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग का उत्पादन रुख यह दर्शाता है कि आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 में उत्पादन में काफी गिरावट आई है परंतु 2011-12 से वार्षिकीकृत पीओआई तक इसने काफी वृद्धि का रुख दर्शाया है। घरेलू बिक्री रुख दर्शाता है कि आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 और 2012-13 में घरेलू बिक्री में भी काफी गिरावट आई है परंतु वार्षिकीकृत पीओआई में घरेलू बिक्री में वृद्धि का रुख दर्शाया है।

कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक:

84. जैसा कि पहले कहा गया है कि विदेशी उत्पादकों द्वारा पेश किए जा रहे आयात की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की विक्रय कीमत से काफी कम है। आयातित उत्पाद कीमत और घरेलू उद्योग कीमत के बीच काफी कीमत अंतर के परिणामस्वरूप उपभोक्ता अपनी मांग के भाग के लिए आयातित उत्पाद की ओर बढ़ गए हैं। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग को उसी उपभोक्ता के लिए अपनी बाढ़ की आपूर्तियों के लिए अपनी कीमतें घटानी पड़ी है बल्कि बाजार में भी दूसरे उपभोक्ताओं की आपूर्तियों में भी अपनी कीमतें घटानी पड़ी है।
85. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चाइनीज आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पेश की गई कीमतों में अत्यधिक गिरावट आई है। विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से निरंतर प्रतिस्पर्धा और कारोबार की हानि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग प्रत्येक उत्तरोत्तर ऑफर के साथ अपनी कीमतें घटा रहा है। इसलिए भारतीय बाजार में कीमत मंदी का प्रभाव स्पष्ट रूप से है।

लाभ/हानि

86. घरेलू उद्योग की लाभ/हानि इसके घरेलू प्रचालनों के संबंध में निर्धारित की गई है। जांच की गई सूचना नीचे दर्शाई गई है

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	पी-पीओआई(ए)	पीओआई
लाभ/हानि	रुपए लाख में	***	***	***	***	***
सूचकांक	रुख	100	1161	518	777	777
नकद लाभ	रुपए लाख में	***	***	***	***	***
सूचकांक	रुख	100	(116)	23	(22)	(22)
आरओआई	%	***	***	***	***	***
सूचकांक	रुख	100	(484)	(112)	(338)	(338)

87. यह देखा जा सकेगा कि घरेलू उद्योग क्षति अवधि के दौरान हानि उठा रहा है। तथापि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई हानि बढ़ गई है। जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग नकद हानि और निवेश पर ऋणात्मक प्रतिफल की हानि उठा रहा है।

माल सूची

88. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन विस्तृत विनिर्दिष्टियों के आधार पर पक्का आर्डर लेने के पश्चात किया जाता है और ये वस्तुएं मालसूची में रखी जाती हैं। प्राधिकारी मानते हैं कि मालसूचियां घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाने वाले प्राचल नहीं हैं।

रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

89. नीचे दी गई सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि मुख्यतः क्षमताओं में वृद्धि के कारण 2012-13 से रोजगार में कमी आई है और घरेलू उद्योग की मजदूरी स्थिति बड़ी है परंतु प्रतिदिन उत्पादन की दृष्टि से उत्पादकता और प्रतिकर्मचारी उत्पादन में गिरावट दर्शाई गई है:

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई(ए)	पीओआई
रोजगार	सं.	***	***	***	***	***
रुख	सूचकांक	100	101	91	79	79
उत्पादकता	संख्या/दिन	***	***	***	***	***
रुख	सूचकांक	100	31	34	48	48
मजदूरी	रुपए लाख में	***	***	***	***	***
रुख	सूचकांक	100	126	103	101	101
मजदूरी	रुपए/एमटी	***	***	***	***	***
रुख	सूचकांक	100	399	274	209	209

धन जुटाने की क्षमता

90. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि संयंत्र और मशीनरी में निवेश वर्तमान मामले में एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। वास्तविकता यह है कि इस उद्योग में धन की आवश्यकता अचल परिसंपत्तियों की तुलना में कार्यचालन पूंजी के कारण अधिक है। इसलिए धन जुटाने के लिए इस उद्योग की क्षमता घरेलू उद्योग की लाभप्रदाता के वर्तमान स्तर से गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है।

क्षति का निर्धारण

91. विभिन्न हितवद्ध पक्षों और की गई जांच द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह निर्णय करते हैं कि भारत में संबद्ध आयात में निरपेक्ष रूप से (मात्रा और मूल्य दोनों में) और सापेक्ष रूप से उत्पादन और खपत में वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान आयात कीमतों में काफी गिरावट आई है। आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में काफी कमी हुई है। आयात बाजार में विचाराधीन उत्पाद की कीमतों को घटा रहा है। लाभ, बाजार हिस्से और निवेश पर प्रतिफल, नकद प्रवाह

और वृद्धि की दृष्टि से घरेलू उद्योग का निष्पादन खराब हो गया है। तथापि, क्षति अवधि के दौरान उत्पादन और बिक्री की मात्रा बढ़ी है परंतु घरेलू उद्योग ने बाजार में अपने उत्पादों की बिक्री करने में बहुत से कारोबारी अवसर गंवा दिए हैं। प्राधिकारी ने यह माना है कि क्षमता उपयोग और मालसूची घरेलू उद्योग की क्षति का सूचक नहीं है। पाटनरोधी शुल्क विद्यमान होने के बावजूद लाभ, निवेश पर प्रतिफल और नकद प्रवाह में गिरावट आई है। तथापि, इनमें सुधार अन्य प्राचलों की स्थिति खराब होने के कारण बहुत दूर है। चालू अवधि के दौरान निष्पादन की खराब स्थिति काफी अधिक और मूर्त स्वरूप में है।

आकस्मिक लिंक और अन्य कारकों का विश्लेषण

92. इसकी कम दाम कीमतों, कम विक्रय कीमतों और कीमतों में तेजी और मंदी प्रभाव की दृष्टि के घरेलू बाजार की कीमतों पर पाटित आयातों की अतिरिक्त क्षति और मात्रा एवं कीमतों के प्रभाव के अस्तित्व की जांच करने पर प्राधिकारी ने भी इस बात की जांच की है कि क्या पाटनरोधी भारतीय नियमावली और करार के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य सूचक प्राचलों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान दिया है। इसलिए निम्नलिखित प्राचलों की जांच की गई है:
 - i. अन्य देशों से आयात- जांच के अंतर्गत शामिल नहीं हुए देशों से आयात कम है अथवा संबद्ध देशों से आयात कीमतों की तुलना में कीमत अधिक है और इसलिए घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित नहीं करता।
 - ii. मांग में संकुचन- क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग काफी बढ़ी है। इसलिए मांग में संभव संकुचन घरेलू उद्योग की क्षति का कारण नहीं हो सकता।
 - iii. खपत का तरीका- खपत के तरीके में कोई विशेष परिवर्तन नोट नहीं किया गया है।
 - iv. प्रतिस्पर्धा की शर्तें- वस्तुओं का मुक्त आयात किया जा सकता है। आवेदक संबद्ध वस्तुओं का प्रमुख उत्पादक है। इसलिए घरेलू प्रतिस्पर्धा घरेलू उद्योग की क्षति का कारण नहीं हो सकती। प्रतिस्पर्धा अथवा व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाओं की शर्तों का कोई अन्य साक्ष्य प्राधिकारी के संज्ञान में नहीं लाया गया है।
 - v. प्रौद्योगिकी में विकास – यह नोट किया गया है कि पीयूसी के अंतर्गत शामिल एसडीएच मदों जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी, से संबंधित प्रौद्योगिकी में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए थे।
 - vi. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन – रिकार्ड पर ऐसा साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शा सके कि डीआई के निर्यातकों का यहां ऊपर माने गए इसके निष्पादन पर कोई प्रभाव पड़ा है।
 - vii. उत्पादकता- कुल उत्पादन की दृष्टि से घरेलू उद्योग की उत्पादकता में सुधार हुआ है। इसलिए यह घरेलू उद्योग की क्षति का कारण नहीं हो सकता।

93. उपरोक्त गैर-आरोपण दर्शाता है कि चीन के पाटित आयात के अलावा किसी अन्य कारक ने घरेलू उद्योग को प्रभावित किया है।

आकस्मिक लिंक प्रमाणित करने वाले कारक

94. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन का विश्लेषण दर्शाता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयात के कारण घरेलू उद्योग का निष्पादन अत्यधिक खराब हो गया है। इसलिए पाटित आयात और घरेलू उद्योग की क्षति के बीच आकस्मिक लिंक निम्नलिखित आधार पर प्रमाणित है:
 - क. पाटित आयात कीमतें और इसके परिणामस्वरूप संबद्ध देशों से आयात की उतराई कीमत में अत्यधिक गिरावट आई है जिससे काफी कम दाम कीमतें हुईं। प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में घरेलू उद्योग को कीमते कम करनी पड़ी थी।
 - ख. घरेलू उद्योग द्वारा क्रय कीमतों की कमी ने लाभ, नकद प्रवाह और डीआई के निवेश पर प्रतिफल को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।
 - ग. आयात कीमतों में गिरावट के लिए घरेलू उद्योग ने प्रतिक्रिया की है तथापि पर्याप्त धनात्मक कम दाम कीमत से संबद्ध देशों से आयात के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई। प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में कमी हुई।
 - घ. मांग में वृद्धि और घरेलू उद्योग द्वारा विक्रय कीमतों में कमी के बावजूद आयात की उतराई कीमतों में काफी कमी के कारण घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई। इससे घरेलू उद्योग का विकास बाधित हुआ।
 - ड. विदेशी उत्पादकों द्वारा ऑफर की जा रही काफी कम कीमतों ने अपने उत्पादन और बिक्री के स्तर को बढ़ाने से घरेलू उद्योग में रूकावट डाली है जो पाटन के नहीं होने के कारण हो सकता था।

95. इसलिए प्राधिकारी ने यह निर्णय लेने के लिए प्रस्तावित किया है कि घरेलू उद्योग ने काफी क्षति झेली है और क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयात के कारण हुई है।

क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

96. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित गैर क्षति कीमत की क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए निर्यात के उतराई मूल्य से तुलना की गई है। भारत में आयातित माडल के लिए गैर क्षति कीमत निर्धारित करके तुलना की गई है। प्रत्येक आयातित माडल के लिए पृथक-पृथक तुलना की गई है और क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है। तत्पश्चात संबद्ध आयात मात्राओं पर विचार करते हुए भारत और क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है। क्षति मार्जिन निम्नानुसार निकाला गया है

क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

देश	उत्पादक/निर्यातक	एनआईपी (रूपए प्रति पीसीएएन)	पहुंच मूल्य (रूपए प्रति पीसीएएन)	क्षति मार्जिन (रूपए प्रति पीसीएएन)	क्षति मार्जिन % (रूपए प्रति पीसीएएन)	क्षति मार्जिन की सीमा % (रूपए प्रति पीसीएएन)
चीन जनवादी गणराज्य	मेसर्ज जेडटीई कार्पोरेशन लिमिटेड	***	***	***	***	45-55
	मेसर्ज एल्काटेल- ल्यूसेंट शंघाई बैल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	50-60
	मेसर्ज हुआवेई टेक्नालोजीस कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	35-45
	मेसर्ज हेंगझोऊ ईसीआई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	75-85
	सभी अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	90-100
इजरायल	मेसर्ज ईसीआई टेलीकोम लिमिटेड	***	***	***	***	(-)5 to (-)10
	सभी अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	215-225

पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना

घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

97. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना के लिए घरेलू उद्योग ने अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए अनुसार अनुरोध किया है :

- पीओआई के दौरान पर्याप्त पाटन मार्जिन प्रमाणित करता है कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन के जारी रहने और तीव्र होने की संभावना है।
- पाटनरोधी शुल्क जारी रहने पर भी संबद्ध देशों से आयात बढ़ने का रूख है जो यह दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में आयात बढ़ेगा।
- विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए संबद्ध देशों में उत्पादक भारी क्षमता बनाए रखते हैं। पाटनरोधी शुल्क की बहाली की स्थिति में आयात की ममात्रा और बढ़नी निश्चित है।
- आयात की उतराई कीमत पाटनरोधी शुल्क के बिना घरेलू उद्योग की कम दाम कीमत है। इसलिए पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से काफी प्रतिकूल मात्रा होने और घरेलू उद्योग पर कीमत प्रभाव पड़ने की संभावना है।

- v. जिस कीमत पर हुआवै चीन अन्य देशों को पीयूसी निर्यात कर रहा है उन कीमतों जिन पर चीन हुआवै भारत को पीयूसी निर्यात कर रहा है, की तुलना में काफी अधिक है। वास्तविकता यह है कि हुआवै चीन की तीसरे देशों की कीमतें भारत को हुआवै चीन द्वारा पीयूसी निर्यात करने में अपनाई जा रही भेदभावपूर्ण कीमतें सिद्ध करती हैं।
- vi. विचाराधीन उत्पाद के लिए भारतीय बाजार अत्यधिक कीमत संवेदनशील है। कीमत प्रमुख दृष्टिकोण होने के कारण उपभोक्ता अपने स्रोत निर्धारित करते हैं। वास्तविकता यह है कि सभी आर्डर कीमतों की तुलना के आधार पर दिए जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति होने के कारण बाजार में संबद्ध देशों से इस प्रकार के कम कीमत आयात की उपलब्धता निश्चित रूप से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव का कारण होगा।
- vii. प्रमुख उत्पादकों की संबद्ध वस्तुएं यूएस, यूके और आस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख देशों में उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं है। भारतीय बाजार बहुत बड़ा होने के कारण और चाइनीज उत्पादकों के लिए इस प्रकार के बाजार बंद होने के पाटित आयात पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में भारतीय बाजार में आने की संभावना है।
- viii. भावी निविदाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में मांग बढ़ने की संभावना है। इस तथ्य के साथ-साथ पाटन के जारी रहने और यूएस, आस्ट्रेलिया और यूके जैसे प्रमुख देशों द्वारा चाइनीज उत्पादकों को सामग्री प्रतिबंधित किए जाने से पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटित आयात भारतीय बाजार में आने की संभावनाएं हैं।
- ix. डीआरआई विचाराधीन उत्पाद के आयात के विरुद्ध जांच कर रहा है। यदि पाटनरोधी शुल्क लागू रहने के समय कर अपवंचन की इस प्रकार की प्रवृत्ति विद्यमान रहती है तो इस बात की सुदृढ़ संभावना है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों से पाटित आयात काफी मात्रा में भारतीय बाजार में आ जाएगा। पाटन की संभावना से संबंधित कारक क्षति और वर्तमान मामले में संभावना से संबंधित है और इन पर विश्वास किया जा सकता है।
- x. संबद्ध देशों के उत्पादकों के पास काफी क्षमता है जो यह सिद्ध करती है कि शुल्क की बहाली की स्थिति में भारत में निर्यात तीव्र हो जाएगा।
- xi. वर्तमान पीओआई में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों धनात्मक और काफी हैं। कम दाम कीमत भी धनात्मक है।
- xii. आयात कीमतें घरेलू उद्योग की विक्रय कीमतों से काफी कम हैं। इसलिए उपभोक्ता पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में आयातित उत्पाद की तरफ जाएंगे जिससे उत्पाद के आयात में काफी वृद्धि होगी।
- xiii. घरेलू उद्योग पहले ही पाटित आयात कीमतों जो घरेलू उद्योग की विक्री की लागत से कम हैं, के कारण कीमतों में मंदी झेल रहा है। पाटनरोधी शुल्क की बहाली की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटित आयात से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी विक्रय कीमत कम करनी होगी, यह विक्री की लागत से भी कम है। इससे कीमत क्षति तीव्र होगी।
- xiv. पाटनरोधी शुल्क की अवधि के दौरान आयातकर्ता यह दावा करते हुए आयात कर रहे हैं कि पाटनरोधी शुल्क बचाने के लिए यह गैर एसडीएच होगा। पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में उन्हीं आयातकर्ताओं द्वारा भारी मात्रा में पाटित आयात लाए जाने की संभावना है।
- xv. संभावित क्षति को सिद्ध करने के लिए अधिशेष क्षमताओं को प्राचलों में से एक प्राचल माना गया है। तथापि पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना सिद्ध करने के लिए घरेलू उद्योग के लिए निरंतर पाटन और क्षति स्वयं में पर्याप्त है।
- xvi. आयात का न्यूनतम स्तर यह सिद्ध नहीं करता कि पाटित आयात की पुनरावृत्ति नहीं होगी। हुआवै 266% पाटनरोधी शुल्क आकर्षित करता है। आयात की कम मात्रा पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को सिद्ध करती है और पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में आयात में वृद्धि होने की संभावना है। विगत में मात्रा कम होने के समय अथवा संबद्ध देशों से शून्य आयात होने पर प्राधिकारी ने वही पाटनरोधी शुल्क लगाया है। याचिकाकर्ता प्राधिकारी को वही दृष्टिकोण अपनाने का अनुरोध करता है।
- xvii. याचिकाकर्ता ने अन्य देशों में हुआवै उत्पादों पर विक्री प्रतिबंध के संगत साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। ये दस्तावेज पब्लिक डोमेन पर भी उपलब्ध हैं। इस प्रकार के तथ्य नकारकर कंपनी ने इसकी साख पर गंभीर संदेह किए हैं और उसके तर्क दिए हैं।
- xviii. भावी मांग के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने के लिए कोई कानूनी अपेक्षा नहीं है। याचिकाकर्ता को यह सिद्ध करना अपेक्षित है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति की संभावना होगी।
- xix. पाटनरोधी शुल्क का अपवंचन भारतीय बाजार में पाटित उत्पाद लाने में आयातकर्ताओं की हताशा सिद्ध करता है। यह स्पष्ट रूप से पाटन जारी रहने की संभावना और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति दर्शाता है।

विरोधी हितवद्ध पक्षों द्वारा अनुरोध

98. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना के संबंध में विरोधी हितवद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. मूल अवधि और बाद की अवधियों के बीच आयात की मात्रा: याचिकाकर्ता ने निश्चयपूर्वक कहा है कि पिछले मामलों के साथ-साथ चालू अवधि में सूचित आयात की मात्रा यह दर्शाएगी कि संबद्ध देशों के मामले में आयात की मात्रा शुल्क लगाए जाने के बावजूद 'पर्याप्त अधिक' बना रहा। यह अनुरोध किया गया है कि याचिकाकर्ता के अनुरोध उनके द्वारा रिकार्ड में रखे गए तथ्यों से विरोधाभासी हैं जो दर्शाते हैं कि जांच की अवधि में संबद्ध देशों द्वारा आयात पिछले दस वर्षों में सबसे कम है। इसके अतिरिक्त क्षति की अवधि में ही आयात में 50% की कमी देखी गई है। इसलिए आयात मात्रा का विश्लेषण सिद्ध करता है कि इस प्रकार की संभावना का स्पष्ट रूप से कोई संकेत नहीं है।
- ii. स्वतंत्र रूप से निपटान योग्य वर्तमान और विदेशी उत्पादकों के साथ संभव क्षमताएं: यह अनुरोध किया गया है कि संबद्ध देशों में मौजूदा अतिरिक्त क्षमताओं की सीमा सिद्ध करने के लिए रिकार्ड पर कोई साक्ष्य दर्शाने के लिए याचिका में कुछ भी प्रतीत नहीं होता। यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता का दावा साक्ष्यों द्वारा बिना सिद्ध किए रहा। इसलिए साक्ष्य द्वारा निश्चयात्मक परिपुष्ट विश्लेषण रिकार्ड पर रख जाने तक आगे कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित नहीं है।
- iii. भारतीय बाजार में कीमत आकर्षण: याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि यदि पाटन रोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की अनुमति दी जाती है तो संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कम दाम कीमतों की संभावना है। यह स्पष्ट नहीं है कि याचिकाकर्ता ने किस आधार पर दावा किया है कि कोई वास्तविक विश्लेषण अथवा याचिका में साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया प्रतीत होता है। अब याचिकाकर्ता ने पुनः उन्हें परिपुष्टि करने के साक्ष्य बिना कोरा दावा भेजा है। इसके अतिरिक्त याचिका में कोई दावा नहीं है कि कम दाम संबद्ध देशों से पाटित कीमत का परिणाम होगा। केवल संभावित कम दाम कीमत का दावा करना शुल्क को अनंतकाल तक जारी रखने के लिए कारण नहीं हो सकता।
- iv. उत्पाद और भारतीय बाजार की कीमत संवेदनशीलता की दृष्टि से घरेलू उद्योग की अतिसंवेदनशीलता-याचिकाकर्ता अपना दावा पुनः परिकल्पित कम दाम कीमतों के आधार पर करता है। जैसा कि ऊपर दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता के अनुमान अत्यधिक काल्पनिक दावे पर निर्भर करते हैं और किसी साक्ष्य के पूरी तरह से अभाव को ध्यान में रखते हुए नकारे जाने की जरूरत है।
- v. भारतीय बाजार में संबद्ध देशों द्वारा धारित बाजार हिस्सा: यह सच है कि संबद्ध देशों का बाजार हिस्सा पर्याप्त है और किसी भी तरीके से यह संकेत नहीं करता कि शुल्क समाप्त करने से पाटन अथवा परिणामी क्षति होगी।
- vi. अन्य देशों में बिक्री प्रतिबंध: याचिकाकर्ता का दावा यह है कि संबद्ध देशों में प्रमुख उत्पादकों को यूएस, यूके और आस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख देशों में उत्पादों की बिक्री करने की अनुमति नहीं है। इसलिए चूंकि भारत एक 'भारी बाजार' है और यदि शुल्क समाप्त करने की अनुमति दे दी जाती है तो 'पाटित' आयात के भारतीय बाजार में प्रवेश करने की संभावना है। यद्यपि याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई वास्तविक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जो चीन अथवा इजराइल से विचाराधीन उत्पाद का निर्यात वास्तव में इन प्रमुख बाजारों में घटा है।
- vii. भारत में मांग में भावी वृद्धि: याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि इस गिरती मांग के भविष्य में बढ़ने की संभावना है। यह दावा नेटवर्क ऑफ स्पेक्ट्रम और वीएसएनएल निविदाओं द्वारा कुछ आसन्न निविदाओं पर आधारित है- जिनके लिए पुनः अभी तक कोई साक्ष्य अथवा प्रमाणीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। किसी भी स्थिति में यह अनुरोध किया गया है कि किसी क्षति की संभावना मांग में भावी वृद्धि का आधार सिद्ध नहीं होती। क्षति मांग में वृद्धि के अकेले विश्लेषण पर आधारित नहीं माना जा सकता। मांग में वृद्धि याचिकाकर्ता के उत्पादों की मांग जैसे अन्य क्षति प्राचलों के संबंध में देखी जानी है। इसलिए मांग में वृद्धि और अन्य क्षति प्राचलों के बीच सह संबंध नहीं होने के कारण यह प्रकथन अस्वीकृत किया जाना चाहिए।
- viii. राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा कुछ जांच: याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि डीआरआई विचाराधीन उत्पाद के आयात के विरुद्ध जांच कर रहा है। याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया है कि उसे इस प्रकार की जांच के व्यौरों के बारे में कोई सूचना नहीं है। तथापि इस जांच के बारे में कोई सूचना नहीं होने को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता का विश्वास है कि ये जांच पाटन अथवा क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना का संकेत है। बिना स्वीकारे यह कल्पना करना कि कुछ उत्पादक शुल्क अपवंचन के लिए जांचाधीन है। इसलिए शुल्क समाप्त किए जाने और उसकी

संभावना के प्रभाव के साथ अब भी कोई सह-संबंध नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता के प्रकथन को पूरी तरह से नकार दिया जाना चाहिए।

- ix. याचिकाकर्ता ने इस बात पर बल दिया है कि यदि उपरोक्त में से एक भी शर्त पूरी होती है तो शुल्क को समाप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तथापि जैसा उपरोक्त से सिद्ध है कि यदि उपरोक्त में से एक भी शर्त साक्ष्य अर्थात् विधिवत रूप से पुष्टि से परिपुष्ट होती है। इसलिए उपरोक्त कारणों से याचिका अस्वीकृत कर दी जानी चाहिए।
- x. आवेदन में नियम 23 में निर्धारित विद्यमान शुल्क जारी रखने की शर्तों को पूरा करने के लिए सूचना नहीं है। आवेदक ने कुछ परिकल्पित आधार पर याचिका में काफी पाटन मार्जिन निर्धारित किया है। परंतु मामले की सच्चाई यह है कि आवेदक द्वारा स्वयं उपलब्ध कराया गया है कि निर्यात कीमत आवेदक की कीमत पर आधारित है और वास्तविक कीमत पर आधारित नहीं है जो एडी अधिनियम और नियमावली के तहत असमर्थनीय है।
- xi. आवेदक का यह दावा कि शुल्क लगाने के बाद भी आयात काफी बने रहना किसी विश्वसनीय सूचना पर आधारित नहीं है। आवेदक द्वारा दावा किया गया आयात कुछ परिकल्पित आधार पर आधारित है जिसका कोई साक्ष्यात्मक मूल्य नहीं है। इस प्रकार आवेदक इस शीर्षक के अंतर्गत भी किसी संभावित पहलू को सिद्ध करने में विफल रहा है।
- xii. आवेदक के अनुसार संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन आर्डर के लिए किया गया था और उन्होंने क्षमता को उपयुक्त प्राचल मानने का अनुरोध किया था। उनकी अपनी क्षमता के तर्क को ध्यान में रखते हुए आवेदक यह कैसे परिकल्पना कर सकता है कि विदेशी उत्पादकों के पास पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता है।
- xiii. आवेदक ने संबद्ध वस्तुओं से आयातित पीयूसी की वास्तविक कीमत के बारे में कोई तथ्यात्मक सूचना उपलब्ध कराए बिना कीमत आकर्षण पर झूठा दावा किया है।
- xiv. याचिका में ऐसी कोई सूचना नहीं है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्णय ले सके कि शुल्क समाप्त किए जाने से घरेलू उद्योग के लिए पाटन और क्षति जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना हो सकती है। आवेदन में दी गई सूचना से स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि शुल्क समाप्त किए जाने से घरेलू उद्योग के लिए पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति हाने की संभावना नहीं है।
- xv. आवेदक का यह दावा है कि शुल्क लगाने के बाद भी आयात काफी बने रहना किसी विश्वसनीय सूचना पर आधारित नहीं है। आवेदक द्वारा दावा किया गया आयात कुछ परिकल्पित आधार पर आधारित है जिसका कोई साक्ष्यात्मक मूल्य नहीं है। इस प्रकार आवेदक इस शीर्षक के अंतर्गत भी किसी संभावित पहलू को सिद्ध करने में विफल रहा है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

99. वर्तमान जांच चीन पीआर और इजराइल से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है। नियमावली के तहत प्राधिकारी को यह निर्धारित करना है क्या पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना न्यायसंगत है। इसके लिए यह जांच करनी भी अपेक्षित है कि शुल्क लगाना क्षति पाटन को समाप्त करने के प्रस्तावित उद्देश्य को पूरा करता है।
100. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जहां तक हूवेई चीन, जैडटीई कारपोरेशन लि., चीन और एल्काटेल-न्युसेंट संघाई बैल का. लि., का संबंध है, इन कंपनियों के संबंध में वर्तमान में पीओआई में निरंतर पाटन और क्षति सिद्ध होने के कारण पञ्चः पीओआई आकड़ों की जांच के साथ संभावित विश्लेषण की कोई संभावना नहीं है। जहां तक एचईटीसी, चीन का संबंध है, उनके आंकड़ों की पुनः जांच करने से यह पता चला है कि जांच की अवधि में नगण्य (**% से भी कम) पाटन हुआ है और इस संबंध में प्राधिकारी ने भारत के साथ-साथ तीसरे देशों को जांच की अवधि के बाद किए गए निर्यातों की जांच की है और यह पाया है कि इनका पाटन नहीं हुआ। अतः पाटन की कोई संभावना नहीं है। जहां तक ई सी आई टेलिकम, इजरायल का संबंध है यह देखा गया है कि जांच की अवधि में भारत को और जांच की अवधि के बाद भारत के साथ-साथ तीसरे देशों को विचाराधीन उत्पादों के निर्यात पाटित कीमतों पर नहीं थे और इस प्रकार यदि शुल्क को हटा लिया जाता है तो ई सी आई टेलिकम, इजरायल से पाटित आयातों की कोई संभावना नहीं है। तथापि, प्राधिकारी ने संभावना का विश्लेषण किया है। जहां तक विदेशी उत्पादकों के पास स्वतंत्र रूप से प्रयोज्य वर्तमान और संभावित क्षमताओं के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे का संबंध है, घरेलू उद्योग द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है, जिसने स्वयं ही यह दावा किया है कि चूंकि सहायक सामानों का निर्माण बाहर से करवाया गया है इसलिए इससे क्षमता का कोई अधिक संबंध नहीं है। भारतीय बाजार की आकर्षक कीमतों, उत्पाद की मूल्य संवेदनशीलता के संदर्भ में घरेलू बाजार की संवेदनशीलता, भारत में मांग को प्रभावित करने वाले अन्य देशों में बिक्री प्रतिबंध, भारतीय बाजार में संबद्ध देशों द्वारा रखे गए बाजार के हिस्से और भारत में मांग में भावी वृद्धि के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे के बारे में यह देखा गया है कि वास्तव में एस डी एच प्रौद्योगिकी के लिए मांग में गिरावट आ रही है क्योंकि नई प्रौद्योगिकियों को तरजीही दी जा रही है जिससे भावी मांग में वृद्धि होना असंभव हो रहा है। इस प्रकार से घरेलू उद्योग के इन दावों में कोई दम नहीं है।

राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा अनेक जांचों के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे के बारे में यह देखा गया है कि वर्तमान जांच इसके स्वतंत्र तथ्यों और गुणों पर आधारित है।

पञ्चः प्रकटीकरण विवरण टिप्पणियां

(क) विरोधी हितबद्ध पक्षों की पञ्चः प्रकटीकरण टिप्पणियां

101. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विरोधी हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए पञ्चः प्रकटीकरण विवरण अनुरोध पुनरावृत्ति स्वरूप के हैं और पहले ही प्रकटीकरण विवरण के संबंध में देखे गए हैं। विरोधी हितबद्ध पक्षों ने संक्षेप में निम्नलिखित पञ्चः प्रकटीकरण विवरण अनुरोध दायर किए हैं :-

- (1) मौजूदा निर्णायक समीक्षा जांच गैर-कानूनी है, क्योंकि कानूनी रूप से कोई वैध पाटन-रोधी शुल्क विद्यमान नहीं है। मूल जांच के दौरान अनेक हितबद्ध पक्षकारों ने माननीय सीईएसटीएटी को अंतिम निर्णय के खिलाफ अपीलें दायर की थीं। माननीय सीईएसटीएटी ने मामले को निर्दिष्ट प्राधिकारी को वापस भेज कर इन अपीलों का निपटारा किया था। माननीय सीईएसटीएटी ने मामले को निर्दिष्ट प्राधिकारी को वापस भेज कर सिद्धांततः दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 की अधिसूचना संख्या 14/2/2009-डीजीएडी और दिनांक 16 दिसंबर, 2010 की सीमा शुल्क की अधिसूचना संख्या 125/2010 द्वारा जारी किए गए अंतिम निर्णय को रद्द कर दिया था। माननीय सीईएसटीएटी ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को निर्देश दिया था कि वह हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर पुनर्विचार करें। इसके अनुसरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पक्षकारों को निर्णय-पश्चात सुनवाई का अवसर प्रदान किया था तथा दिनांक 10 फरवरी, 2012 की अधिसूचना संख्या 14/2/2009-डीजीएडी द्वारा नया अंतिम निर्णय जारी किया था। तथापि, वित्त मंत्रालय ने इस नए अंतिम निर्णय के अनुसरण में कोई सीमा शुल्क की अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। इसलिए यह तर्क देने से तसल्ली नहीं हो जाती है कि सीमा शुल्क की विगत अधिसूचना जारी रहेगी क्योंकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपनी नए अंतिम निर्णय में विगत निर्णय की संपुष्टि की थी क्योंकि माननीय सीईएसटीएटी ने सीमा शुल्क विगत अधिसूचना को पहले से रद्द कर दिया था। चूंकि नए अंतिम निर्णय के अनुसरण में कोई सीमा शुल्क की अधिसूचना जारी नहीं की गई थी, इसलिए इस संबंध में अब तक वसूल किए गए पाटन-रोधी शुल्क सहित की गई सभी प्रकार की कार्रवाई तथा मौजूदा निर्णायक समीक्षा जांच गैर-कानूनी है। निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए यह विवेकपूर्ण होगा कि वह मौजूदा निर्णायक समीक्षा जांच को तत्काल समाप्त कर दें।
- (2) निर्णायक समीक्षा जांच को जांच शुरू किए जाने की तारीख से 12 महीनों के भीतर पूरा कर दिया जाना चाहिए। जैसा कि पाटन-रोधी नियमावली के नियम 23 (2) में प्रावधान निहित है, मौजूदा मौजूदा निर्णायक समीक्षा जांच गैर-कानूनी है, क्योंकि निर्दिष्ट प्राधिकारी इसे 12 महीनों के भीतर पूरी करने में विफल रहे हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी को निर्णायक समीक्षा की समय अवधि को बढ़ाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और पाटन-रोधी नियमावली में उन्हें ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है। पाटन-रोधी नियमावली के नियम 23 (2) का उल्लंघन करने के लिए मौजूदा निर्णायक समीक्षा गैर-कानूनी है और इसे तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए।
- (3) प्रकटीकरण विवरण में टिप्पणियां देने के लिए दिया गया समय अपर्याप्त था क्योंकि प्रतिवादियों को लंबे प्रकटीकरण विवरण की जांच करने और उन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए केवल पांच कार्य दिवसों का समय ही दिया गया था। इससे प्रतिवादियों पर अपने हितों की प्रभावशाली ढंग से रक्षा करने के लिए गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- (4) पुनः निवेदन किया जाता है कि सीमाशुल्क विभाग इस तथ्य के बावजूद भी एकल आधार पर आयातित संघटकों/संभागों/कलपुर्जों पर भी पाटन-रोधी शुल्क वसूल कर रहा है, जब कि उन्हें प्राधिकारी द्वारा विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से अलग रखा गया है। हितबद्ध पक्षकारों को जांचक्षेत्र से बाहर रखे गए उत्पादों पर पाटन-रोधी शुल्कों का भुगतान करने का अनुचित भार सहना पड़ा है। इसलिए अनुरोध है कि शुल्क तालिका में इस आशय का एक पृथक नोट उल्लिखित करके उत्पाद के कार्य-क्षेत्र के बारे में स्पष्ट किया जाए कि एकल आधार पर आयातित किए गए "प्रिंटेड सर्किट सहित "संघटक/पार्ट्स" विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर हैं और इसलिए उन पर पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है"। एक "प्रिंटेड" सर्किट बोर्ड में इंसुलेटिड बोर्ड शामिल होता है जिस पर उचित कंडक्टर लेमिनेटिड होते हैं। ऐसे कंडक्टर फोटो केमिकल फेचिंग प्रक्रिया अथवा डिपोजिशन से बनाए जाते हैं। एक "प्रिंटेड" सर्किट बोर्ड में ऐसी कोई बाह्य सामग्री लगी नहीं होती है, जो कि "प्रिंटेड" सर्किट बोर्ड में उद्दिष्ट स्लॉटों/स्थानों/पोजिशन में लगाई अथवा फिक्स की जाती है। ऐसे "प्रिंटेड" सर्किट बोर्ड न तो एसडीएच उपस्कर होते हैं और न ही उसके पार्ट/संघटक होते हैं।

- (5) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह पाया है कि एसटीएम-256, निरंतर उत्पाद के कार्य-क्षेत्र का भाग बना रहेगा। प्रतिवादियों का यह निवेदन है कि स्वीकार्यतः जांच अवधि के दौरान एसटीएम-256 का भारत में आयात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसे लगाए जाने के लिए देश में उसके तकनीकी अनुमोदन/अनुमति प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में जब कि भारत में उसका इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है, कोई भी प्रयोक्ता उसे प्राप्त करने की आवश्यकता प्रकट नहीं करेगा और उसके फलस्वरूप यह स्वभाविक है कि एसटीएम-256 का भारत में निर्यात नहीं किया जा सकता है और न ही भारतीय प्रयोक्ताओं के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उसकी आपूर्ति की जा सकती है। इसलिए अनुरोध है कि उपरोक्त प्रेक्षण में संशोधन किया जाए और निर्दिष्ट प्राधिकारी एसटीएम-256 को उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखने की कृपा करें।
- (6) विचाराधीन उत्पाद में एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर्स (एडीएम) (केवल एसडीएच अनुप्रयोग के लिए), मल्टीपल एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर्स (एमएडीएम) (केवल एसडीएच अनुप्रयोग के लिए) तथा डिजिटल क्रॉस कनेक्ट (डीएक्ससी) (केवल एसडीएच अनुप्रयोग के लिए) को शामिल किया गया है। इससे ऐसा पता चलता है कि उत्पाद की परिभाषा में ऐसा उल्लेख नहीं है कि ये उत्पाद एसडीएच उपस्कर हैं। परिभाषा में ऐसा उल्लेख है कि विचाराधीन उत्पाद में ऐसे उत्पादों को तभी शामिल किया जाता है जबकि उन्हें एसडीएच अनुप्रयोगों के लिए बनाया गया हो, हालांकि ऐसी वस्तुएं एसडीएच उपस्कर नहीं होती हैं, लेकिन उन्हें केवल एसडीएच उपस्कर के साथ प्रयुक्त करने के लिए बनाया जाता है। वास्तव में ऐसी वस्तुएं ऐसे उपस्कर होते हैं जिन्हें एसडीएच उपस्कर और अन्य नेटवर्क/ब्रॉड बैंड उपस्करों के बीच प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे उपस्करों का प्रयोग, एसडीएच उपस्कर के रूप में ऑप्टिकल फाइबर में ध्वनि अथवा डाटा का पारगमन करने के लिए नहीं किया जाता है और इन्हें विचाराधीन उत्पाद से बाहर रखा जाना चाहिए।
- (7) यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि मेसर्स तेजा ऐसे ब्रॉडबैंड अथवा सेल्युलर उपस्कर का विनिर्माण नहीं करता है। तथापि, यदि उपस्करों के कुछ पापुलेटिड बोर्ड (जिनकी प्रोद्योगिकी एसडीएच की है) को ऐसे उपस्करों का विनिर्माण करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो वे पाटन-रोधी शुल्क के अध्वधीन होते हैं। भारत में ऐसे उपस्करों का विनिर्माण नहीं होता है।
- (8) बहुविध उत्पादों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाना गैर-कानूनी है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने के अपने निर्धारण में अनेक वस्तुओं को शामिल किया है जो कि गैर-कानूनी है। प्राधिकारी को नियम 4 (ख) के अंतर्गत "ऐसी वस्तुओं का पता लगाना होता है जिन पर पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाना है"। जबकि मौजूदा मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने के लिए वस्तुओं की गलत पहचान की है।
- (9) प्रतिवादियों का यह निवेदन है कि मूल जांच के दौरान पीटीएन को उत्पाद के कार्य-क्षेत्र में स्वेच्छा पूर्वत मनमाने ढंग से शामिल किया गया था। जबकि दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 के अधिसूचना संख्या 14/2/2009-डीजीएडी द्वारा अधिसूचित किए गए अंतिम निर्णय में पीटीएन को उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा गया था, फिर भी उपरोक्त निर्णय के संबंध में दिनांक 22 अक्टूबर, 2010 की अधिसूचना संख्या 14/2/2009-डीजीएडी द्वारा जारी किए गए शुद्धि पत्र में पीटीएन को मनमाने ढंग से उत्पाद के कार्य-क्षेत्र में उसके एक भाग के रूप में शामिल कर लिया गया था। जहां तक कि हितबद्ध पक्षकारों को मूल जांच के दौरान उत्पाद के कार्य-क्षेत्र में इस प्रकार का परिवर्तन करने पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान नहीं किया गया था। कम से कम मौजूदा समीक्षा में निर्दिष्ट प्राधिकारी को गुणावगुण के आधार पर इसकी जांच करनी चाहिए कि क्या पीटीएन को उत्पाद के कार्य-क्षेत्र का एक भाग माना जाना चाहिए। इस संबंध में यह नोट किया जाए कि एसडीएच और पीटीएन दोनों ही पूर्णतया भिन्न प्रकार की प्रोद्योगिकियां हैं जो कि भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। पीटीएन अथवा पैकेट ट्रांसमिशन नेटवर्क का उपयोग ईथरनेट सेवाओं की प्रदानगी के लिए किया जाता है। हालांकि पीटीएन, पीडीएच और एसडीएच दोनों प्रकार की सेवाएं (इसके दोनों किस्मों के कार्य होते हैं) प्रदान कर सकता है, फिर भी यह नोट किया जा सकता है कि मूल जांच और निर्णायक समीक्षा केवल एसडीएच ट्रांसमिशन उपस्कर/एसडीएच ट्रांसमिशन प्रोद्योगिकी तक ही सीमित है और न की यह दोहरी अथवा बहुविध कार्य करने वाले उपस्कर के लिए है। इसलिए पीटीएन को उत्पाद के कार्य-क्षेत्र का एक भाग नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह बहुविध कार्य करने वाला उपस्कर है।
- (10) चूंकि मौजूदा जांच निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए प्राधिकारी का ऐसा कोई दायित्व नहीं है कि विगत में विचाराधीन उत्पाद के गलत ढंग से निर्धारण करने की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए। भारत में और अन्यत्र ऐसे अनेक मामले हैं, जिनमें प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र को कम कर दिया है। इस प्रकार मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद का निर्णय, प्राधिकारी के लिए ऐसा खुला और बंद मामला नहीं है कि जिस पर निर्णायक समीक्षा जांच में और जांच नहीं की जाए। मौजूदा मामले में गुणावगुण के आधार पर विचाराधीन उत्पाद में से पीटीएन जैसी कुछ मदों को बाहर रखे जाने का मामला बनता है जिस पर प्राधिकारी पुनर्विचार कर सकते हैं। यह भी उल्लेख किया जाता है कि पीटीएन जिसका अभिप्राय पैकेट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से है, पूर्णतया एक भिन्न उत्पाद है और यह घरेलू उद्योग की मूल याचिका

अथवा जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना के अनुसार कभी भी विचाराधीन उत्पाद नहीं था तथा न ही उसमें पीटीएन उत्पाद का किसी प्रकार का कोई उल्लेख किया गया था।

- (11) चीन से सहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन, चीन में प्रचलित वास्तविक कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए। मौजूदा मामले में एचईटीसी, चीन ने जांच में पूरा सहयोग दिया है और उसे बाजार आर्थिक व्यवस्था का दर्जा (एमईटी) भी दिया गया है। इसलिए सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क (1) (ग) के अभिभावी उपबंधों को ध्यान में रखते हुए यह अधिक उपयुक्त होगा कि चीन से निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ एचईटीसी के लागत और कीमत संबंधी आंकड़ों पर विचार किया जाए, क्योंकि इन्हें लागत और कीमत प्रधान बाजार अर्थव्यवस्था की सही स्थिति निर्दिष्ट करने के लिए प्राधिकारी द्वारा स्वीकार करने योग्य पाया गया है। प्रकटीकरण विवरण इस संबंध में पूर्णतया मूक है कि चीन की उस कंपनी की कीमतों को, जिसे बाजार आर्थिक व्यवस्था का दर्जा (एमईटी) दिया गया है, चीन से अन्य उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार्य क्यों नहीं किया जा सकता है।
- (12) जेडटीई कार्पोरेशन लिमिटेड, मेसर्ज हुआवेई टेक्नालोजीस कंपनी लिमिटेड और मेसर्ज एल्काटेल-ल्यूसेंट शंघाई बैल कंपनी लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए ईसीआई की सूचना का प्रयोग करने के लिए कोई वैध अथवा कानूनी आधार नहीं है। इन कंपनियों के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन करने के प्रयोजनार्थ ईसीआई की सूचना को अपनाने के लिए एक मात्र आधार ईसीआई का उसकी पीसीएन में अंशदान करने के प्रति मनाही प्रतीत होता है। यह आधार इन कारणों से विद्यमान नहीं है कि इन कंपनियों के लिए बीओक्यू का डिजायन, उनके निजी पीसीएन के आधार पर बनाया जाता है और इसका डिजायन ईसीआई के पीसीएन के आधार पर नहीं होता है। इसलिए ईसीआई का पीसीएन कोई महत्व नहीं रखता है। इसके अतिरिक्त पृथक निर्यातक के लिए पीसीएन के लिए बीओक्यू का निर्णय लिए जाने पर प्राधिकारी को मात्र ईसीआई द्वारा यथा सूचित पृथक पार्ट्स और संघटकों की कीमतों को ही ध्यान में रखना होता है। ईसीआई द्वारा गोपनीयता के दावे के संबंध में कोई समझौता नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अन्य पक्षकारों को न तो पीसीएन और न ही पृथक पार्ट्स और संघटकों की कीमतों को प्रकट करना आवश्यक होता है। इसका पूर्णतया कोई स्पष्ट कारण नहीं है कि प्राधिकारी, इन कंपनियों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग की अत्यधिक बढ़ाई गई कीमतों/लागतों को ध्यान में रखने के बजाए मेसर्ज ईसीआई के संघटकों की कीमत/लागत पर विचार क्यों नहीं कर सकता है।
- (13) शंघाई मेट्सुशिता एस. बैटरी कंपनी लिमिटेड बनाम एक्सआईड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य (2005) 3 एससीसी 39 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने संपुष्ट रूप से यह पाया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी अंतिम विकल्प का तभी प्रयोग कर सकता है, जब कि पहली दोनों विधियां निःशक्त हो गई हों। यह निवेदन किया जाता है कि इस मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश अर्थात् इजरायल की कीमतों और संरचित मूल्य के बारे में पहले से ही सूचना उपलब्ध थी, क्योंकि ईसीआई इजरायल ने इस जांच में पूरा सहयोग दिया है और उसने निर्दिष्ट प्राधिकारी को अपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास अन्य देशों को निर्यात के लिए ईसीआई इजरायल की कीमतों के बारे में सूचना भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त चूंकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने हेंगझाऊ ईसीआई, चीन जनवादी गणराज्य को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा भी प्रदान किया है, इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी हेंगझाऊ ईसीआई की उत्पादन की कीमतों अथवा लागत संबंधी आंकड़ों को सुगमता से अपना सकता था। यह कहना सही नहीं है कि यदि ईसीआई इजरायल अथवा हेंगझाऊ ईसीआई के आंकड़ों पर विचार किया जाता तो पीसीएन की तुलना करना संभव नहीं हो पाता। यह नोट किया जाए कि ईसीआई इजरायल और हेंगझाऊ ईसीआई दोनों ने भारत को पूर्ण उपस्कर निर्यात किए हैं। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने भी भारत में पूर्ण उपस्करों की आपूर्ति की है। यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी पीसीएन की तुलना करने के लिए घरेलू उद्योग के लागत के आंकड़ों से उपस्करों के विभिन्न पार्ट्स की लागत का चयन कर सकते हैं, तो उसी विधि को ईसीआई इजरायल और हेंगझाऊ ईसीआई के लिए भी अपना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कंपनियों ने भी निर्दिष्ट प्राधिकारी को अपनी लागत के आंकड़े दिए होंगे जिनके आधार पर उनके सामान्य मूल्य का परिकलन किया गया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को कम से कम एचईटीसी, चीन के सामान्य मूल्य को अपनाना चाहिए। एल्काटेल-ल्यूसेंट शंघाई बैल कंपनी लिमिटेड (एएसबी) का यह निवेदन है कि यदि चीन जनवादी गणराज्य से सहयोगी निर्यातकों से वाणिज्यिक रूप से स्वीकृत कीमतें उपलब्ध होती हैं, तो ऐसे अन्य निर्यातकों के लिए भी उन्हीं को अपनाया जाना चाहिए, जिन्हें बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा स्वीकृत नहीं किया गया है।
- (14) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने एएसबी को मात्र इस आधार पर बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा स्वीकृत नहीं किया है कि कंपनी में राज्य की शेयर धारिता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच के दौरान अपीलकर्ता द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार करने में विफल हुए हैं। एएसबी का यह निवेदन है कि कंपनी में शेयरधारिता होना मात्र स्वतः एक ऐसा आधार नहीं होता है, जिससे

निर्यातक को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। हुआवाई चीन द्वारा जांच के दौरान सभी संबद्ध दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद भी निर्दिष्ट प्राधिकारी ने बिना कोई वैध कारण से उसे भी बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे से वंचित रखा है।

- (15) इस मामले में घरेलू उद्योग के साथ निर्यातकों द्वारा निर्यातित उत्पादों के लिए पीसीएन की तुलना करना बहुत जटिल कार्य है, क्योंकि इस विश्लेषण के आधार पर पाटन-रोधी शुल्क की मात्रा तय की जाती है। यह निवेदन किया जाता है कि एएसबी ने इस संबंध में विस्तृत प्रेक्षण प्रस्तुत कर दिए थे कि घरेलू उद्योग के सभी पीसीएन किन कारणों से एएसबी के किसी भी पीसीएन के समतुल्य नहीं थे। ऐसे मुख्य कारण हैं (1) एएसबी ने केवल कार्डों का ही निर्यात किया था जबकि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान संपूर्ण एसडीएच ट्रांसमिशन उपस्कर की आपूर्ति की थी और (2) घरेलू उद्योग के पीसीएन अत्यधिक विन्यास के थे, क्योंकि लगभग सभी पीसीएन एक से अधिक प्रोद्योगिकी नामतः एसडीएच + ओटीएन आदि का समर्थन कर रहे थे, जिसके कारण ऐसे पीसीएन की लागत, एएसबी के पीसीएन की लागत से अत्यधिक थीं, जो कि एक प्रकार (केवल एसडीएच) का ही कार्य करते हैं और उनकी उत्पादन लागत अपेक्षाकृत कम है। ऐसे प्रमुख अंतरों के बावजूद प्राधिकारी ने 10 पीसीएन पर एएसबी की टिप्पणियों को खारिज कर दिया और उसने घरेलू उद्योग की लागत के आधार पर ऐसे पीसीएन की लागत की संरचना करने के लिए अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल किया। प्रतिवादियों का निवेदन है कि ऐसा दृष्टिकोण अपनाए जाने के कारण एएसबी को ऐसी आशंका है कि पीसीएन की ऐसी तुलना उचित और पारदर्शी नहीं है, जैसा कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दावा किया है, क्योंकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पीसीएन की तुलना करने के लिए अपने निजी विवेकाधिकार का प्रयोग किया है जो कि निरंकुश प्रतीत होता है। इसलिए यह निवेदन है कि ऐसे दृष्टिकोण के कारण एसीबी के लिए परिकलित किया गया पाटन और क्षति का मार्जिन सही प्रतीत नहीं होता है और एसीबी की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए सभी पीसीएन के लिए इनका दुबारा परिकलन किया जाना चाहिए।
- (16) एएसबी के निर्यात पाटित/क्षति कीमतों पर नहीं किए जाते हैं। इस तथ्य की संपुष्टि, एएसबी के कारोबार-वार निर्यात आंकड़ों के साथ-साथ एएसबी की सभी निविदाओं में उद्धृत कीमतों से होती है, जो कि उसने घरेलू बाजार के लिए गंवा दी है। एएसबी ने इन निविदाओं में पर्याप्त रूप से अधिक कीमतें उद्धृत की हैं, जबकि घरेलू उद्योग ने काफी कम कीमतें उद्धृत की हैं। एएसबी की कीमतों में से पाटन-रोधी शुल्क को निकालने के बाद भी उसकी कीमतें बहुताधिक थीं। इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि एएसबी ने जांच अवधि और क्षति का विश्लेषण करने की अवधि के दौरान कभी भी वस्तुओं को पाटित नहीं किया है और वह भविष्य में भी ऐसा ही करती रहेगी। इसलिए एएसबी के संबद्ध वस्तुओं के आयातों से किसी भी प्रकार के पाटन होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की कोई संभावना नहीं है।
- (17) जांच में विचाराधीन उत्पाद का गलत ढंग से निर्धारण करने, घरेलू उद्योग के गुणों में कमी होने और उसके दर्जे के दावे, पाटन के आरोपण और उसकी संभाव्यता और पुनरावृत्ति होने तथा घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति होने के आरोपण, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण करने की क्रिया-विधियों आदि जैसे विभिन्न विवादास्पद मुद्दों के बारे में हुआवेई ने साक्ष्यों और समर्थक दस्तावेजों के साथ प्राधिकारी के समक्ष अपने अनेक अधिप्रमाणिक तर्क प्रस्तुत किए हैं, जिनकी अभी तक उतनी गंभीरता से जांच नहीं की गई है, जितनी की ऐसे निवेदनों के लिए आवश्यक है।
- (18) हुआवेई के लिए पाटन मार्जिन का प्रस्तावित निर्धारण अत्यधिक त्रुटिपूर्ण है जिसके फलस्वरूप प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए अनुचित क्रियाविधि प्रस्तावित की गई है। जबकि इस तर्क को दोहराते हुए कि हुआवेई को घरेलू उद्योग का दर्जा नहीं दिया जाना अनुचित है, जैसा कि सत्यापन रिपोर्ट में उनकी टिप्पणियों में उल्लेख किया गया है, यहां पुनः आग्रह किया जाता है कि प्राधिकारी के लिए यह और भी न्यायोचित नहीं है कि वह अपने पास उपलब्ध उत्तम विकल्पों की अनदेखी करते हुए हुआवेई के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए एक अनुचित पद्धति को अपनाएं। हुआवेई को घरेलू उद्योग का दर्जा नहीं दिए जाने पर प्राधिकारी ने दुर्भाग्यवश नियमावली में क्रमानुसार प्रदान किए गए विकल्पों में से सीधे अंतिम विकल्प पर ही विचार किया है, जो कि वास्तविक रूप से अदा की गई कीमत अथवा भारत में देय कीमत है, जिसमें उचित लाभ का विधिवत् समंजन करना शामिल है। ऐसा कोई भी न्यायोचित कारण नहीं है, जिसने प्राधिकारी को विकल्पों के क्रम में प्रारंभिक विकल्प पर विचार करने से रोका हो, हालांकि प्राधिकारी ऐसे आधार पर सूचना का इस्तेमाल करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र हैं और यह अभी भी उपलब्ध है। प्राधिकारी का यह प्रस्ताव कि पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में दिए गए क्रमानुसार विकल्पों में से अंतिम विकल्प को हुआवेई के लिए अपनाना न केवल अनुचित है, बल्कि ऐसा दृष्टिकोण प्राधिकारी द्वारा स्वतः विगत निर्णयों से असंगत भी है। निर्दिष्ट प्राधिकारी का कार्यालय, एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय के समान है, इसलिए उसके लिए समान रूप से यह महत्वपूर्ण है कि वह ऐसे मामले में विगत पद्धतियों का अनुसरण करें जिनके कानूनी प्रावधानों के प्रभाव समान हैं।

- (19) हुआवेई का निवेदन है कि प्राधिकारी का यह विशेषाधिकार है कि वह उत्तम उपलब्ध सूचना का उपयोग करे और मौजूदा मामले में प्राधिकारी ने अपने इस विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं किया है और उसने हुआवेई के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण, भारतीय उत्पादक के उत्पादन की लागत के आधार पर किया है, जो कि अत्यधिक विकृत है तथा वास्तविकता से काफी दूर है। घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत का हुआवेई द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य से कोई संबंध नहीं है तथा ऐसे आधार का इस्तेमाल करने के कारण हुआवेई के निर्यातों के मामले में अत्यधिक और अवास्तविक पाटन मार्जिन का निर्धारण हुआ है। प्राधिकारी इजरायल से उत्पादक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को बिना किसी कठिनाई के गोपनीय रख सकते थे और उसका प्रयोग अभी भी हुआवेई के मामले में कर सकते हैं। इस प्रकार हुआवेई पर पाया गया आरोपित पाटन मार्जिन, कंपनी द्वारा किए गए पाटन की किसी वास्तविक स्थिति का परिणाम नहीं है, बल्कि यह प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई एक गलत, अनुचित और त्रुटिपूर्ण क्रिया-विधि का परिणाम है। याचिकादाता की लागत, उन्हें स्वयं विदित आत्मघाती कारणों से अवास्तविक रूप से बहुताधिक है और हुआवेई को ऐसी अत्यधिक अनुचित लागत के कारण घाटा उठाना पड़ रहा है, जो कि हुआवेई के लिए निर्धारित किए जाने वाले प्रस्तावित अत्यधिक पाटन मार्जिन से पता चलता है।
- (20) हुआवेई के संबंध में निर्धारण करने के लिए प्रस्तावित कोई भी सकारात्मक पाटन मार्जिन मात्र गलत सामान्य मूल्य का परिणाम है और एक निष्पक्ष और उपयुक्त तरीके से पाटन मार्जिन का निर्धारण होने से हुआवेई द्वारा किए गए निर्यातों के मामले में कोई पाटन प्रदर्शित नहीं होगा। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित कार्य प्रणाली और प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रस्तावित कार्य प्रणाली यह सुझाव देती है कि याचिकाकर्ता ने भारतीय लागत पर विचार किया क्योंकि केवल सामान्य मूल्य का आधार ही चीन जन.गण. से निर्यातों पर पाटनरोधी शुल्क को चपत लगाने का एक मात्र रास्ता है और जैसा कि नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में उल्लिखित है, किसी अन्य उचित आधार पर कोई पाटन मार्जिन नहीं होगा। अतः प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी निरंतर पाटन रोधी शुल्क लगाने के लिए याचिकाकर्ता की व्यर्थ पुकार पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस प्रकार न तो निरंतर पाटन और क्षति का कोई मामला है और न ही पाटन और क्षति होने की कोई संभावना है।
- (21) मौजूदा जांच के शुरू होने से लेकर अब तक हुआवेई द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि याचिकादाता ने अत्यधिक गोपनीयता बनाए रखी है और जहां तक कि प्रकटीकरणविवरण में भी कोई विशेष प्रकट नहीं किया गया है। हुआवेई का प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह सामान्य मूल्य के प्रयोजनार्थ याचिकादाता के उत्पादन की पीसीएन-वार लागत के बारे में उचित प्रकटीकरण करें। हुआवेई को इस प्रकार की सूचना का अप्रकटीकरण किए जाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हुआवेई पर पाटन का समग्र आरोप, याचिकादाता के उत्पादन की लागत (सीओपी) पर आधारित है। जब कि याचिकादाता के उत्पादन की लागत (सीओपी) का हुआवेई पर अत्यधिक कुप्रभाव पड़ा है, तो ऐसी स्थिति में पीसीएन-वार लागत के ब्यापारों अथवा कम से कम सार्थक सीमा तक उनको प्रकट नहीं करने का कोई औचित्य नहीं बनता है और यह अत्यधिक अनुचित है।
- (22) जेडटीई के पीसीएन के लिए तैयार किए गए बीओक्यू में अनेक संघटक शामिल होते हैं, जिनकी या तो कोई आवश्यकता नहीं होती है अथवा जो कि आवश्यकता से अधिक मात्रा में होते हैं, जिन्हें जेडटीई के पीसीएन के लिए बनाए गए बीओक्यू में शामिल/एकीकृत किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि ऐसा घरेलू उद्योग के कहने पर किया गया है और इसी कारणवश जेडटीई पूर्ण पारदर्शिता बरतने और घरेलू उद्योग से प्राप्त टिप्पणियों का प्रकटीकरण करने का अनुरोध कर रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन है कि जेडटीई ने प्राधिकारी से प्रकटीकरणविवरण के साथ जो बीओक्यू प्राप्त किए हैं, उनमें ऐसे अनेक संघटक शामिल हैं, जो कि मूल बीओक्यू में संघटित नहीं थे। तदनुसार प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह जेडटीई के लिए बनाए गए बीओक्यू पर जेडटीई द्वारा सुझाए गए संशोधन पर घरेलू उद्योग की ऐसी टिप्पणियां प्रस्तुत करें, जिन पर प्राधिकारी द्वारा जेडटीई के लिए बनाए गए बीओक्यू पर विचार किया गया है। इसके साथ ही प्राधिकारी से यह भी अनुरोध है कि वह जेडटीई के लिए बीओक्यू के संशोधन पर उसकी टिप्पणियों पर भी विचार करें।
- (23) मूल जांच से लेकर अब तक एक विवदास्पद मुद्दा यह है कि मेसर्स तेजा नेटवर्कस लिमिटेड को किसी भी प्रकार की कल्पना मात्र से पाटन-रोधी नियमावली में दी गई परिभाषा के भीतर एक “घरेलू उद्योग” नहीं माना जा सकता है तथा निर्णायक समीक्षा जांच में भी यह मुद्दा निरंतर बना हुआ है। मेसर्स तेजा नेटवर्कस लिमिटेड कुछ और नहीं तो बस एक ऐसी कंपनी मात्र है, जो कि कुछ पार्ट्स का आयात करने के बाद संबद्ध वस्तुओं की कुछ असेम्बली करने के कार्य में लगी हुई है और नियम 2 (ख) के अंतर्गत उसे एक घरेलू उद्योग माना जाना तर्कसंगत नहीं है। वह घरेलू उद्योग बनने के योग्य नहीं है। एक विकल्प के रूप में हुआवेई पर घरेलू उद्योग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विचार किया जाना चाहिए। हुआवेई द्वारा किए गए आयात और उसके निर्यात के साथ संबंध होना ऐसा कोई कारण नहीं है कि उनके तर्क को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया जाए। प्राधिकारी ने विगत में भी ऐसी कंपनियों पर विचार किया है, जिन्होंने घरेलू उद्योग के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आने

पर भी अपने विवेकाधिकार के अंतर्गत आयात किए हैं। यह ऐसा कोई मामला नहीं है कि हुआवेई का व्यवहार, एक व्यापारी सरीखा है। हुआवेई इंडिया मुख्यतया एक ऐसा उत्पादक है, जिसे घरेलू उद्योग माना जा सकता है।

- (24) निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे बौद्धिक सम्पदा धारक पर विचार करने के लिए इच्छुक है जो कि भारत में घरेलू उद्योग के रूप में विनिर्माण नहीं करता है, जबकि दूसरी ओर वह हुआवेई इंडिया को घरेलू उद्योग नहीं मान रहे हैं, हालांकि उसके पास भारत में बौद्धिक सम्पदा है और वह भारत में संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माता भी है। इससे ऐसा पता चलता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने तेजा नेटवर्कस लिमिटेड और हुआवेई इंडिया को घरेलू उद्योग के दर्जे की जांच करने के लिए भिन्न और निरंकुश मानक अपनाए हैं। यह निवेदन किया जाता है कि यदि तेजा नेटवर्कस लिमिटेड को घरेलू उद्योग का दर्जा देने पर विचार किया जाता है, तो हुआवेई इंडिया को भी घरेलू उद्योग का दर्जा देने पर भी विचार किया जाए क्योंकि इन दोनों कंपनियों के तथ्य और परिस्थितियां समान प्रतीत होती हैं। इसके अतिरिक्त भारत में उत्पादन की सूचना प्रदान करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के अन्य उत्पादकों के बारे में कोई सूचना प्रदान नहीं की है।
- (25) हुआवेई इंडिया को घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए। इसमें कोई विवाद नहीं है कि हुआवेई इंडिया, जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का घरेलू उत्पादन करने में लगा हुआ था और इसलिए उसे भी घरेलू उद्योग के रूप में माना जाना चाहिए था तथा उसके इस दावे को इस कारण से अस्वीकार नहीं कर दिया जाना चाहिए कि वह हुआवेई, चीन से संबंधित है तथा उसने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। वास्तव में जांच अवधि के दौरान हुआवेई इंडिया द्वारा किए गए आयात नगण्य थे जो कि उस समय लंबित उसके संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के निमित्त थे।
- (26) एसबी निवेदन किया है मौजूदा मामले में ईसीआई, इजरायल के लिए नकारात्मक पाटन मार्जिन परिकलित किया गया था। इस तथ्य के बावजूद भी निर्दिष्ट प्राधिकारी, क्षति का विश्लेषण करने में पाटित आयातों की कुल मात्रा में से ईसीआई, इजरायल के गैर-पाटित आयातों को बाहर रखने में विफल रहे हैं। ऐसी कमी से मौजूदा मामले में क्षति विश्लेषण को गंभीर रूप से विकृत किया है।
- (27) प्रतिवादियों का यह निवेदन है कि क्षति प्राचलों का विश्लेषण करने से ऐसा पता चलता है कि घरेलू उद्योग को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं हो रही है और आरोपित पाटन और क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। यह नोट किया जाए कि निर्णायक समीक्षा में कानूनी अवसीमा की जांच की जाए कि क्या पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने पर पाटन और क्षति के निरंतर बने रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। ऐसा प्रतीत होता है कि क्षति का विश्लेषण करने की अवधि में भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग में तेजी से गिरावट आई है। इसी तरह संबद्ध वस्तुओं के आयातों में भी गिरावट आई है। ऐसी आशा है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में निरंतर गिरावट आती रहेगी, क्योंकि एसडीएच ट्रांसमिशन प्रोद्योगिकी अब अप्रचलित होती जा रही है। प्रयोक्ता अब धीरे-धीरे डीडब्ल्यूडीएम और ओटीएन जैसी नवीनतम प्रोद्योगिकियों का इस्तेमाल करने की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। यह निवेदन किया जाता है कि घरेलू उद्योग के समक्ष अब वास्तविक चुनौती इस बात की है कि प्रयोक्ता बेहतर प्रोद्योगिकियों की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं और वे संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं कर रहे हैं।
- (28) जबकि घरेलू उद्योग घाटे और निवेश पर प्रतिलाभ में गिरावट दर्शा रहा है, फिर भी यह मानना चाहिए कि एसडीएच ट्रांसमिशन प्रोद्योगिकी परिसमाप्ति के चरण पर है। इसलिए घरेलू उद्योग को इससे अधिक लाभ और प्रतिलाभ होने की आशा नहीं करनी चाहिए क्योंकि प्रयोक्ता उन्नत प्रोद्योगिकियों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। घरेलू उद्योग के लिए यह मुख्य चुनौती है और न कि संबद्ध वस्तुओं के आयात।
- (29) घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का अन्य कारण घरेलू उद्योग द्वारा निविदाओं को प्राप्त करने के लिए कीमत संबंधी उद्यमशील नीति को अपनाना है। घरेलू उद्योग की कीमतें इतनी कम हैं कि क्षति विश्लेषण की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने लगभग सभी बोलियां जीत ली हैं। प्रतिवादियों के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा उद्धृत की गई कीमतें, निर्यातकों द्वारा उद्धृत की गई कीमतों से अत्यधिक कम थीं।
- (30) घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से निरंतर आयात होने के कारण कोई क्षति नहीं हुई है। संबद्ध देशों से होने वाले आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाता है जो कि 266% तक अधिक है तथा यदि घरेलू उद्योग को इसके बाद भी कोई क्षति हुई है, तो उससे ऐसा सिद्ध होता है कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का निःसंदेह कोई अन्य कारण है और पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है।
- (31) निर्यात अभिमुखीकरण भी, यदि कोई है, घरेलू बाजार में क्षति होने का मुख्य कारण है। याचिकादाता के निर्यात में आधार वर्ष में 100 से लेकर जांच अवधि में 554 तक की अत्यधिक वृद्धि हुई है।

- (32) जेडटीई कि प्राधिकारी से अनुरोध है कि घरेलू उद्योग के संघटकों की कीमत में ऐसा समायोजन किया जाए जिस पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी का विचार करने का प्रस्ताव है। ऐसा इस तथ्य पर आधारित है कि घरेलू उद्योग, संबंधित उत्पाद के पार्ट और संघटकों का विनिर्माता अथवा उत्पादक नहीं है और उसने उन्हें अन्य देशों से आयात किया है। इसमें पत्तन प्रभार (भारतीय पत्तन), विदेशी परिवहन (मूल पत्तन से भारत तक) और अंतर्देशीय परिवहन (पार्ट/संघटक के निर्यातक की फेक्टरी से ले कर मूल पत्तन तक), विदेशी समुद्री बीमा (मूल पत्तन से भारत तक), पत्तन प्रभार (मूल पत्तन), अंतरदेशीय परिवहन (भारतीय पत्तन से घरेलू उद्योग की फेक्टरी तक), पार्ट/संघटक के जॉब वर्कर/निर्यातक के मानक लाभ को समायोजित किया जाना चाहिए।
- (33) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए वास्तविक उत्पादन और घरेलू बिक्रियों के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं। ये मात्रा के महत्वपूर्ण प्राचल हैं और इनका प्रकटन, प्रकटीकरणविवरण में किया जाना चाहिए। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता, घरेलू बिक्रियों और निर्यात के संपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत करें जो कि प्राधिकारी द्वारा विचारित सुसंगत पद्धति है।
- (34) संभावित विश्लेषण करने के लिए कोई वैध अथवा कानूनी आधार विद्यमान नहीं है। यह निवेदन किया जाता है कि हुआवेई चीन, जेडटीई कार्पोरेशन लिमिटेड, चीन और एल्काटेल-ल्यूसेंट शंघाई बैल कंपनी लिमिटेड, चीन के लिए संभावित विश्लेषण करने के लिए प्रकटीकरण विवरण में उल्लिखित कारण यह है कि जांच अवधि के दौरान निरंतर पाटन और क्षति होने की संपुष्टि हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में प्राधिकारी का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि संभावित विश्लेषण नहीं करने के लिए प्रकटीकरणविवरण में उल्लिखित किया गया कारण, विधि में किसी भी जगह पर नहीं दिया गया है और न ही यह प्राधिकारी की सुसंगत पद्धति के अनुसार है। इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन किया जाता है कि प्राधिकारी ने इस तथ्य के बावजूद कि जांच अवधि के दौरान निरंतर पाटन और क्षति हुई है, अनेक मामलों में संभावित विश्लेषण किया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमारा प्राधिकारी से अनुरोध है कि मौजूदा जांच में भी संभावित विश्लेषण किया जाए।
- (35) हुआवेई संभावित पहलु पर प्रस्तावित निर्णय का खंडन करता है। इस तथ्य के पूर्वग्रह के बिना कि मौजूदा मामले में इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उत्पाद के संबंध में मांग में असामान्य किस्म से गिरावट आई है, कुछ ऐसे प्रेक्षण भी हैं कि निरंतर पाटन और क्षति हो रही है तथा उसकी संभावना होना स्वभाविक रूप से एक तर्क असंपुष्ट तर्क है, कारणात्मक संबंध की जांच करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह निवेदन किया जाता है कि मौजूदा मामले में इस समय न कोई पाटन और क्षति हो रही है और न ही पाटन और क्षति होने की कोई संभावना है। यह समग्र मामला याचिकादाता द्वारा उठाया गया है जो कि विनिर्मित तथ्यों पर आधारित है तथा जहां तक कि वह संबद्ध वस्तुओं का वास्तविक उत्पादक बनने के योग्य भी नहीं है। याचिकादाता एक आभूषण के रूप में शुल्कों को निरंतर सुनिश्चित रखने का प्रयास कर रहा है, जो कि पाटन-रोधी करार की आवश्यकता के अनुसार अस्वीकार्य है और ऐसा दावा करने का कोई औचित्य नहीं है कि शुल्क की समाप्ति पर पाटन और क्षति होने की संभावना है।
- (36) कीमत में कटौती होने का परिकलन केवल जांच अवधि के लिए किया गया है, जबकि प्राधिकारी की सुसंगत पद्धति यह होती है कि उसका परिकलन, क्षति अवधि अर्थात् जांच अवधि और उससे पूर्व 3 वर्ष के लिए किया जाए। प्राधिकारी ने अनेक मामलों में उक्त पद्धति को अपनाया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह समग्र क्षति अवधि के लिए कीमत में कटौती होने का परिकलन करें।
- (37) यह निवेदन किया जाता है कि प्रकटीकरण विवरण में कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण विश्लेषण में पहुंच मूल्य पर विचार नहीं किया गया है जो कि प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली सुसंगत पद्धति का उल्लंघन है। प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली सुसंगत पद्धति के अनुसार कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण विश्लेषण करते समय पहुंच मूल्य पर विचार किया जाए। प्राधिकारी ने अनेक मामलों में ऐसी पद्धति का अनुसरण किया है। तदनुसार प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण विश्लेषण करते समय पहुंच मूल्य पर भी विचार करें।
- (38) सार्वजनिक सुनवाई होने तक घरेलू उद्योग द्वारा आयात की मात्रा और मूल्य तथा बाजार के अंशदान संबंधी सूचना के लिए ओब्रम रिपोर्ट पर ही विश्वास किया गया है। यह नोट किया जाता है कि प्रकटीकरण विवरण में पहली बार इस जांच में डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया गया था। यदि प्राधिकारी ने इस जांच में डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास करने का निर्णय लिया था, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह दायित्व बनता था कि वह सभी हितबद्ध पक्षकारों को इसके बारे में सूचित करें तथा सभी हितबद्ध पक्षकारों को डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी को सभी हितबद्ध पक्षकारों को कम से कम डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े, प्रकटीकरण विवरण के साथ उपलब्ध कराए जाने चाहिए थे ताकि वे उन आंकड़ों की जांच करने तथा उन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की स्थिति में हो सकें। डीजीसीआईएंडएस के

आंकड़ों पर पूर्णतया विश्वास करने से क्षति के प्राचलों में पूर्णतया परिवर्तन हो जाता है और घरेलू उद्योग को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह क्षति की अद्यतन सूचना प्रस्तुत करे जो कि इस मामले में नहीं किया गया है।

- (39) निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिका में किया गया अनुरोध, पाटन-रोधी नियमावली के नियम 23 (1 ख) के अनुसार विधिवत् अधिप्रमाणित नहीं था। इसके अतिरिक्त प्रतिवादियों ने घरेलू उद्योग के संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा और मूल्य के लिए ओवुम रिपोर्ट पर विश्वास करने पर कड़ी आपत्ति की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रतिवादियों के ऐसे प्रतिवाद को यह मानते हुए एक तरफ रख दिया कि उसने आयात की मात्रा और क्षति विश्लेषण के लिए डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों पर विचार किया है। यह निवेदन किया जाता है कि मात्र इस कारण से कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों पर विश्वास किया है, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका में व्याप्त दोषों का निवारण नहीं हो जाता है।
- (40) घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन पत्र के साथ-साथ अपने लिखित निवेदनों में विशेष रूप से ऐसा दावा किया है कि उसने प्रकटीकरण विवरण में प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए आयात के आंकड़ों की तुलना में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। घरेलू उद्योग ने पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध का दावा करने के लिए विशेष रूप से अत्यधिक आयातों की मात्रा का उल्लेख किया है तथा जांच शुरू करने को यथोचित ठहराया है। तदनुसार हमारा प्राधिकारी से अनुरोध है कि इस जांच को यथाशीघ्र समाप्त कर दिया जाए क्योंकि इसके विपरीत ऐसे दृष्टिकोण से घरेलू उत्पादकों को ऐसी जांच शुरूआत करवाने के लिए मनगढ़ंत अथवा आयात के भ्रामक आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
- (41) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने एचईटीसी, चीन के लिए सही निर्धारण किया है, क्योंकि वह एक पूर्णतया विदेशी स्वामित्वाधीन और नियंत्रित कंपनी है तथा वह बाजार अर्थव्यवस्था की दशाओं में कार्य कर रही है और उसकी लागत इजरायल की लागत से तुलनीय है। इसके अतिरिक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी ने एचईटीसी और ईसीआई के लिए भी पृथक मार्जिन का सही तरीके से निर्धारण किया है। तथापि, इन कंपनियों का यह निवेदन है कि उन्हें एचईटीसी के लिए मार्जिन के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय से वंचित रखा गया है। रिकार्ड में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जिनकी जांच मौके पर भी की गई है, नकारात्मक पाटन मार्जिन का स्पष्ट पता चलता है। इसलिए निर्यातकों का निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध है कि वह इस पर विचार करें।
- (42) ईसीआई और एचईटीसी द्वारा प्रस्तुत किए गए अपूर्ण आंकड़ों के संबंध में लगाए गए विभिन्न आरोपों के संबंध में निर्यातकों का यह निवेदन है कि उन्होंने रिकार्ड पर संपूर्ण विक्रयों के आंकड़े प्रस्तुत कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त निर्यातकों ने जांच किए जाने के समय अपनी विस्तृत बहियां और रिकार्ड भी प्रस्तुत किए थे तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए उन्हें उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया था ताकि वे इस बात से संतुष्ट हो सकें कि भारत को किए गए समस्त निर्यात सही तरीके से सूचित किए गए हैं। मात्रा, कीमत, पीएनसी, लागत और मार्जिन सहित निर्यातकों के आंकड़ों के सभी तत्वों ने निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्ण संतुष्टि कर दी थी। इसलिए निर्यातकों की सत्यता के संबंध में लगाए गए किसी भी आरोप पर विचार नहीं किया जाए।
- (43) चीन के संबंध में यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि प्रतिस्पर्द्धी कारकों के कारण एचईटीसी से निर्यातित उत्पाद की पहुंच कीमत को घरेलू उद्योग के उत्पाद की कीमत से पर्याप्त रूप से कम कीमत पर नहीं माना जा सकता है। इसलिए एचईटीसी को उसके लिए परिकलित किए गए अधिक क्षति मार्जिन पर आपत्ति है, जबकि तथ्य यह है कि वस्तुओं को घरेलू बाजार में तुलनीय कीमतों पर बेचा गया है। इसलिए एचईटीसी का निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह क्षति मार्जिन के ऐसे परिकलन पर पुनर्विचार करें।
- (44) यह निवेदन किया जाता है कि निर्णायक समीक्षा का उद्देश्य इसकी जांच करना है कि क्या विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण पाटन और क्षति होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए पाटन-रोधी शुल्क को लगाए रखने की आवश्यकता है। अधिनियम में किए गए प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय सरकार ऐसे पाटन-रोधी शुल्क की अवधि को बढ़ा कर पांच वर्ष तक कर सकती है, यदि उसे ऐसा आभास होता है कि ऐसे शुल्क को समाप्त करने के फलस्वरूप पाटन अथवा क्षति के निरंतर बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इन प्रावधानों में ऐसी व्यवस्था है कि उसी पाटन-रोधी शुल्क को आगे जारी रखा जाए जो कि मूल जांच में लगाया गया था। इसलिए यह निवेदन किया जाता है कि यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे पाटन-रोधी शुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनसे अनुरोध है कि वे उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मूल जांच के दौरान लगाए गए पाटन-रोधी शुल्क की मात्रा को नहीं बढ़ाएं। निर्दिष्ट प्राधिकारी उसी दर पर शुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं जो कि मूल जांच के अनुसरण में लगाया गया था।
- (45) इसके अतिरिक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी यह नोट कर सकते हैं कि अनेक हितबद्ध पक्षकारों ने मूल जांच को और उसके अनुसरण में सीमा शुल्क की अधिसूचना को माननीय सीईएसटीएटी के समक्ष चुनौती दी थी। ऐसी आशा है कि माननीय सीईएसटीएटी आगामी दो से तीन सप्ताहों के भीतर इन अपीलों का निपटान करने के लिए अंतिम आदेश जारी कर देगा।

इसको ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे ऐसी अपीलों का निपटान करने के लिए माननीय सीईएसडीएटी द्वारा जारी किए जाने वाले अंतिम आदेश के बाद ही मौजूदा समीक्षा में अपना अंतिम निर्णय जारी करें ताकि इस मामले में एक उचित निर्धारण किया जा सके।

(ब) घरेलू उद्योग की पश्चः प्रकटीकरण टिप्पणियां

102. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अधिकांश पश्चः प्रकटीकरण विवरण अनुरोध पुनरावृत्ति स्वरूप के हैं और पहले ही प्रकटीकरण विवरण के संबंध में देखे गए हैं। घरेलू उद्योग द्वारा पश्चः प्रकटीकरण विवरण अनुरोध संक्षेप में निम्नलिखित हैं :-

- (1) भारतीय बाजार में आयात पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं। पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम से अधिक है, बल्कि यह पर्याप्त भी है। वर्तमान जांच अवधि के दौरान पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों ही सकारात्मक और पर्याप्त हैं।
- (2) आयात, घरेलू उद्योग की कीमतों में काफी कटौती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आयात, घरेलू कीमतों का ह्रास और न्यूनीकरण भी कर रहे हैं।
- (3) पाटित आयातों के कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण के पड़ने वाले प्रभाव के फलस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी कमी आई है। वास्तव में लाभ इस सीमा तक घट गया है कि घरेलू उद्योग को अब वित्तीय घाटे होने लगे हैं और उसे नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिलाभ होने लगा है।
- (4) घरेलू उद्योग को पाटित आयातों की कीमतों के कारण पहले से ही कीमत ह्रास का नुकसान हो रहा है जो कि घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत से बहुत कम हैं। ऐसी स्थिति में पाटन-रोधी को समाप्त कर दिए जाने पर घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए अपनी बिक्री कीमत में और कटौती करनी पड़ेगी जिसके कारण उसे बिक्रियों की लागत से कम पर बेचने पर विवश होना पड़ेगा, जिससे उसको घोर कीमत क्षति होगी।
- (5) संबद्ध देश से उत्पादकों के पास अत्यधिक क्षमता उपलब्ध है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में भी भारत में निर्यात और गहन होंगे।
- (6) याचिकादाता का यह निवेदन है कि विगत निर्णयों में प्राधिकारी ने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) और पापुलेटिड सर्किट बोर्ड में यह कहते हुए भिन्नता की है कि पीसीबी विनिर्माता द्वारा विकसित किए गए डिजाइन के अनुसार पापुलेटिड है और उसके बाद सॉफ्टवेयर को लोड करने के अतिरिक्त उन्हें शेल्फ में व्यवस्थित करने और सर्किट में सुव्यवस्थित ढंग से लगाने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने यह भी बताया है कि पीसीबी विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र के भीतर आते हैं। विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर होने की स्थिति तभी उत्पन्न होती है, जबकि ऐसे पीसीबी, एसडीएच उपस्कर के उत्पादन के निमित्त नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन किया जाता है कि इस कारणवश कि पीसीबी, विनिर्माता की सम्पत्ति है और एसडीएच उपस्कर के उत्पादन करने के सिवाए इसका और किसी तरह से उपयोग नहीं होता है, इसलिए पीसीबी विचाराधीन उत्पाद का ही एक भाग होता है।
- (7) यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने हुआवेई इंडिया को एक अयोग्य घरेलू उद्योग माना है। तथापि, याचिकादाता ने यह तर्क दिया था कि हुआवेई इंडिया घरेलू उत्पादक नहीं बनता है। वास्तव में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मूल जांच में अपने व्यापक निर्णय को रिकार्ड किया है, जो कि इस प्रकार है : (क) उत्पादन का तात्पर्य क्या है और (ख) हुआवेई, वीएमसीएल और पृथ्वी कैसे घरेलू उद्योग नहीं बनता है। वास्तव में हुआवेई इंडिया ने यह स्वीकार किया है कि उसने अपने संघटकों को बाहर से प्राप्त किया है और उन्हें भारत में असेम्बल किया है और उत्पाद को बनाया है।
- (8) ईसीआई के मामले में पाटन मार्जिन के संबंध में प्रकटीकरण विवरण में बताया गया है कि सामान्य मूल्य उत्पादक के उत्पादन की लागत पर आधारित है और उसमें "उचित लाभ" जोड़ा गया है। याचिकादाता का यह निवेदन है कि नियम में कंपनी द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ के आधार पर उचित लाभ को जोड़ने का प्रावधान निहित है। इस प्रकार प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ के आधार पर उचित लाभ को जोड़ें। याचिकादाता का प्राधिकारी से यह भी अनुरोध है कि वह तृतीय देश के निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन का निर्धारण करें और उसके बाद यह निर्णय लें कि क्या पाटन और क्षति होने की कोई संभावना नहीं है।
- (9) हुआवेई चीन और हुआवेई इंडिया द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के प्रत्युत्तर से यह स्पष्ट पता चलता है कि किसी भी परिस्थिति में इन पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के प्रत्युत्तर, अत्यधिक अपर्याप्त हैं, जिसके कारण उन्हें पृथक मार्जिन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हुआवेई इंडिया ने प्राधिकारी के समक्ष स्वतः यह दावा किया है कि भारतीय मांग में उसका अंशदान बहुत अधिक है। इसके साथ ही हुआवेई चीन अथवा हुआवेई इंडिया द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के

प्रत्युत्तर से ऐसा पता नहीं चलता है कि उनके द्वारा इस प्रकार की कोई बिक्री की गई है। यदि हुआवेई इंडिया द्वारा इतनी अधिक भारतीय मांग को पूरा किया जाता है, तो उससे ऐसा पता चलता है कि हुआवेई ने भारतीय बाजार में एसडीएच उपस्करों की काफी अधिक मात्रा में बिक्री की है। जबकि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के प्रत्युत्तरों से ऐसा पता चलता है कि हुआवेई द्वारा इस प्रकार की बिक्रियां नहीं की गई हैं। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि हुआवेई चीन और हुआवेई इंडिया ने प्राधिकारी को उत्तर देते समय विशेष सूचना को छिपा कर रखा है।

- (10) इस मामले से यह स्पष्ट होता है कि हुआवेई इंडिया ने संघटकों के नाम से एसडीएच ट्रांसमिशन उपस्करों को लाने का प्रयास किया है और वह पाटन-रोधी शुल्कों का भुगतान करने से बची है। उपभोक्ताओं द्वारा इस प्रकार से अधिप्राप्त किए गए एसडीएच ट्रांसमिशन उपस्कर तथा उस पर डीआरआई की कार्रवाई/निर्णय से यह स्पष्टतया प्रमाणित हो जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र के भीतर भारत में किन वस्तुओं का आयात किया गया है। ऐसी किसी भी परिस्थिति में याचिकादाता का प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह इस तथ्य को स्पष्ट करें कि प्राधिकारी ने ऐसे उत्पाद के आयातों को कैसे माना है, जिसमें देश में डीआरआई और अन्य प्राधिकारियों ने यह माना है कि यह वास्तव में विचाराधीन उत्पाद के आयात ही हैं। यदि देश में अन्य प्राधिकारियों ने इन आयातों को विचाराधीन उत्पाद के आयात ही माना है तो ऐसी स्थिति में प्राधिकारी उसे भिन्न नहीं मान सकते हैं। प्राधिकारी ने मेलामाईन के मामले में हाल ही में लिए गए अंतिम निर्णय का हवाला दिया है, जिसमें प्राधिकारी ने डीआरआई से ऐसी सूचना मांगी थी। डीआरआई द्वारा जारी किए गए अनेक कारण बताओ नोटिस और लगाए गए दंड को ध्यान में रखते हुए मौजूदा मामले में भी इसी दृष्टिकोण को अपनाया जा सकता था। इसको ध्यान में रखते हुए याचिकादाता द्वारा प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह प्रश्नावली के उत्तरों को इस आधार पर अस्वीकार कर दें कि पक्षकार ने भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयात के संबंध में पर्याप्त सूचना प्रदान नहीं की है।
- (11) घरेलू उद्योग के एसडीएच पीसीएन मैपिंग बनाम हुआवेई, चीन के मामले के संबंध में हुआवेई चीन ने अपने निवेदन में यह उल्लेख किया है कि उसने जांच अवधि के दौरान भारत को केवल तीन एसडीएच उपस्करों और नौ कार्डों/पीसीबीए के निर्यात किए हैं। निर्यात किए गए तीन उपस्करों के विन्यास के लिए पीसीएन के परिचायक के बतौर थे। इसके अतिरिक्त हुआवेई ने यह भी उल्लेख किया है कि इन तीनों उपस्करों के पीसीएन, जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा बेचे गए तीन उपस्करों के पीसीएन के लगभग समनुरूप हैं और इस तथ्य को प्राधिकारी ने स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में मेसर्स तेजा का यह निवेदन है कि (क) घरेलू उद्योग द्वारा बेचे गए तीन उपस्करों के पीसीएन, हुआवेई द्वारा निर्यातित तीन उपस्करों के पीसीएन समनुरूप नहीं हैं और ये उनके उपयोग, क्षमता और इंटरफेस पोर्ट्स आदि की दृष्टि से भिन्न हैं। प्राधिकारी की उपस्थिति में इन तथ्यों को हुआवेई, चीन और घरेलू उद्योग दोनों द्वारा स्वीकार भी किया गया है। यह नोट किया जाता है कि निर्यातक के पीसीएन और घरेलू उद्योग के पीसीएन में असमानता होने के प्रत्येक मामले में प्राधिकारी ने सदैव घरेलू उद्योग के पीसीएन को संघटित करने वाले पार्ट्स और संघटकों के बिल में वास्तविक भारित औसत कीमत का प्रयोग करते हुए घरेलू उद्योग के उत्पादन की सामान्यकृत लागत के साथ तुलना की है। तथापि, हुआवेई, चीन के पीसीएन के तीन उपस्करों के मामले में इस क्रियाविधि का अनुसरण नहीं किया गया है और प्राधिकारी ने उसके बजाए हुआवेई, चीन द्वारा आपूर्ति किए गए लगभग समान पीसीएन पर विचार किया है। इस प्रकार अन्य निर्यातकों के लिए लागू की गई क्रिया-विधि और हुआवेई, चीन के लिए लागू की गई क्रिया-विधि के बीच असंगति विद्यमान है, जैसा कि प्रकटीकरणविवरण के पृष्ठ 55-56 में उल्लेख किया गया है, (ख) हालांकि घरेलू उद्योग के प्रत्येक पीसीएन के लिए सामग्री के विस्तृत बिल (बीओएम) के बारे में प्रत्येक निर्यातक को सूचित किया गया है, ताकि पीसीएन के प्रत्येक आयातक का घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत की वास्तविक भारित औसत कीमत के साथ उचित सामंजस्य और समायोजन सुनिश्चित किया जा सके, फिर भी निर्यातक के पीसीएन के लिए इसी स्तर पर पार्ट/संघटक के ब्यौरे घरेलू उद्योग को नहीं दिए गए हैं। इससे घरेलू उद्योग के हितों पर घोर प्रतिकूल पड़ा है तथा (घ) घरेलू उद्योग द्वारा निर्यातक की पीसीएन के लिए की गई समस्त सामान्यकृत लागत की संरचना, बिना किसी पृष्ठ भूमि अथवा अन्य पर्याप्त प्रमाणों के आयातकों द्वारा दी गई बहुत सीमित विन्यास संबंधी सूचना के आधार पर की गई है। इसके परिणाम स्वरूप संरचित किया गया अंतिम सामान्य मूल्य, घरेलू उद्योग के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण प्रतीत होता है।
- (12) निर्यातकों के पीसीएन के लिए घरेलू उद्योग द्वारा सभी सामान्यकृत लागत की संरचना, बिना किसी पृष्ठ भूमि अथवा अन्य पर्याप्त प्रमाणों के आयातकों द्वारा प्रदान की गई विन्यास संबंधित बहुत सीमित सूचना का आधार पर की गई है। इसके परिणाम स्वरूप संरचित किया गया अंतिम सामान्य मूल्य, घरेलू उद्योग के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण प्रतीत होता है।
- (13) घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत को अनुबंध-3 {पैरा 4 (3)} में उल्लिखित परिभाषा के भीतर नहीं माना जाना चाहिए और क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए उत्पादन की वास्तविक लागत पर विचार किया जाना चाहिए।

- (14) क्षति रहित कीमत का निर्धारण अनुचित है और यह पाटन विधि के उद्देश्य और लक्ष्य के विपरीत है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिलायन्स इंडस्ट्रीज बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में प्रतिपादित किया है।
- (15) उत्पादन सुविधाओं का अपर्याप्त उपयोग नहीं हुआ है। चूंकि अनुबंध-3 में अपर्याप्त उपयोग होने के कारण क्षति को पृथक् किए जाने का प्रावधान है, इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी अपर्याप्त उपयोग की कल्पना करते हुए एनआईपी को कम नहीं करेंगे।
- (16) यह निर्धारण करने के लिए अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि क्या जांच अवधि के दौरान उत्पादन क्षमताओं के अपर्याप्त उपयोग होने के कारण कम क्षमता उपयोग हुआ है अथवा नहीं।
- (17) कारखाना गत लागत स्तर पर एनआईपी का निर्धारण करने का तात्पर्य यह नहीं है कि एनआईपी और आयातों की पहुंच कीमत की तुलना करने के समय पट्टन पर एनआईपी कारखाना गत और पहुंच कीमत होनी चाहिए। प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार का विवेचन करना और पद्धति को अपनाना, नियमावली और साम्यता के सिद्धांतों तथा प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है।
- (18) जहां तक कि सीएस-3 के अंतर्गत भी कमीशन को कम बिक्री के शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसलिए एनआईपी का परिकलन करते समय कमीशन को शामिल किया जाए। यदि विदेशी उत्पादक ने कमीशन का भुगतान किया है, तो उसे पहुंच कीमत के एक भाग के रूप में माना जाता है, जबकि नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग द्वारा अदा किए गए कमीशन को शामिल नहीं किया जाता है।
- (19) एनआईपी का परिकलन करते समय फैक्टरी से गोदाम तक की परिवहन की लागत को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। गोदाम कुछ और नहीं हो तो भी उसे वह कंपनी की फैक्टरी के गेट तक माना जाता है। एनआईपी का निर्धारण करने के समय सभी निर्यातकों को स्वामित्व के अंतरण होने तक इसको ध्यान में रखना चाहिए।
- (20) नियम 4 (7), नियम 4 (6) के विपरीत है। चूंकि नियम 4 (6) पूर्णतया सीएस-3 के अनुरूप है, लेकिन ऋण को गैर-लागत मद के रूप में नहीं माना जाएगा और एनआईपी का निर्धारण करते समय उसको शामिल किया जाना चाहिए।
- (21) नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ के प्रयोजनार्थ अचल परिसंपत्तियों को सकल मूल्य आधार में शामिल किया जाना चाहिए और न कि निबल आधार पर। बल्कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसी अचल परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन मूल्य पर विचार करना चाहिए जिनकी मूल लागत/प्रतिस्थापन लागत की तुलना में पर्याप्त रूप से मूल्य ह्रास हुआ है।
- (22) निर्दिष्ट प्राधिकारी को क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए आयातों पर प्रतिकारी शुल्क तथा घरेलू उद्योग की एनआईपी में उत्पाद शुल्क को अवश्य जोड़ना चाहिए। यदि उत्पाद शुल्क को क्षति रहित कीमत के साथ नहीं जोड़ा जाता है तथा प्रतिकारी शुल्क को आयातों की पहुंच कीमतों के साथ नहीं जोड़ा जाता है, तो क्षति मार्जिन अनुपातिक रूप से कम होगा।
- (23) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत की तुलना, आयातों की पहुंच कीमत के साथ तभी करनी चाहिए, जबकि उसमें परिवहन लागतों को जोड़ दिया गया हो। घरेलू उद्योग की एनआईपी की तुलना, आयातों की पहुंच कीमत के साथ संबद्ध भाड़े को शामिल किए बिना करने से उचित तुलना प्रतीत नहीं होगी और इसके फलस्वरूप उद्योग को हो रही क्षति का बहुत कम अनुमान लग जाएगा।
- (24) यदि एनआईपी के साथ घरेलू उद्योग द्वारा अदा किए गए बिक्री कर को नहीं जोड़ा जाता है, तो अनुपातिक सीमा तक क्षति मार्जिन कम निर्दिष्ट होगा, क्योंकि आयातों पर विशेष अतिरिक्त शुल्क लगता है।
- (25) बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, छूट, कमीशन आदि कारखाना गत स्तर पर देय हैं और इसलिए इस तथ्य से कि कारखाना गत स्तर पर क्षति मार्जिन का निर्धारण किया जा रहा है, यह स्पष्ट नहीं होता है कि उसमें बिक्री कर और उत्पाद शुल्क को नहीं जोड़ा जा सकता है।
- (26) फिबकोम इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत में विचाराधीन उत्पाद की एक घरेलू उत्पादक है, पाटन-रोधी शुल्क का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई क्रिया-विधि को पढ़ कर आश्चर्य चकित हुई है, विशेषकर इस तथ्य को देख कर कि 266% की मौजूदा दर की तुलना में हुआवेई पर 35% और 45 % के प्रस्तावित शुल्क दर लागू की गई है तथा चीन जनवादी गणराज्य में सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों पर शुल्क के प्रतिशत में अत्यधिक कटौती की गई है, जो कि 266%, से घटा कर मात्र 90 % - 100 % कर दिया गया है।

- (27) फिब्रोम इंडिया लिमिटेड को हुआवेई, चीन के ऐसे आंकड़ों को स्वीकार किए जाने पर भी आश्चर्य हुआ है, जिनमें उसने घरेलू उद्योग को ज्ञात तथ्य के विरुद्ध तीन उपस्कारों और नौ कार्डों/पीसीबी/ए को प्राप्त करने का दावा किया है, जबकि उसे एसडीएच उत्पादों के लिए भारी शुल्क का अपवंचन करने में लिप्त पाया है तथा वोडाफोन, आईडिया, टाटा टेली सर्विसिज पर ऐसा करने के लिए दंड लगाया गया है। इनफेक्ट टाटा टेली सर्विसिज ने शुल्क का अपवंचन करने को स्वीकार कर लिया है, जिससे पता चलता है कि एसडीएच की आपूर्ति हुआवेई द्वारा की गई थी। हुआवेई द्वारा इन सभी निर्यातों के बारे में डीजीएडी को सूचित नहीं किया गया है। हुआवेई द्वारा ऐसा करना, तथ्यों को अत्यधिक रूप से छिपाना है।
- (28) फिब्रोम इंडिया लिमिटेड ने आगे यही दोहराया है कि वह भारत में विचाराधीन उत्पाद की एक घरेलू उत्पादक कंपनी है। फिब्रोम इंडिया लिमिटेड को पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद भी देश में ऐसे उत्पाद के निरंतर पाटन होने के कारण अत्यधिक क्षति हुई है। जबकि घरेलू उद्योग को होने वाली मौजूदा क्षति का मुख्य कारण, पाटन-रोधी शुल्क की प्रवंचना करना है और पाटन-रोधी शुल्क में और कटौती कर दिए जाने से घरेलू कंपनियों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- (29) भारतीय घरेलू कंपनियों के लिए निधियों की उच्च लागत होना, विदेशी विक्रेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने की प्रमुख चिंता है, क्योंकि इन कंपनियों को सस्ती निधियां प्राप्त नहीं होती हैं। इसके साथ ही इन विक्रेताओं को भुगतान की दीर्घावधिक शर्त स्वीकार्य है जो कि एक वर्ष तक हो सकती है।
- (30) उठाए गए तर्कों के आलोक में प्रदान की गई सूचना और किए गए निवेदनों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी को पाटन-रोधी शुल्क को उसके मौजूदा रूप में, तरीके से और मात्रा में आगे कायम रखने पर विचार करना चाहिए।
- (31) घरेलू उद्योग का यह निवेदन है कि पाटन-रोधी शुल्क को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के सीआईएफ मूल्य (शुल्क के सम मूल्य पर) के प्रतिशत के रूप में लगाया जाए, क्योंकि विचाराधीन उत्पाद में अनेक प्रकार के उत्पाद शामिल हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के उत्पादों की संबद्ध लागत और कीमतों में भिन्नता है, जो कि उनके विन्यास पर निर्भर करती है।

(ग) प्राधिकारी द्वारा जांच

103. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और विरोधी हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अधिकांश पञ्चः प्रकटीकरण विवरण अनुरोध पुनरावृत्ति स्वरूप के हैं और पहले ही प्रकटीकरण विवरण के संबंध में देखे गए हैं और उपयुक्त शीर्षकों के अंतर्गत अंतिम विकर्ष परिणाम अधिसूचना में पुनः देखे गए हैं। फिर भी प्राधिकारी ने निम्नानुसार संगत मानी गई सीमा तक इन मुद्दों का समाधान किया है :-

- (1) चीन से कुछ सहयोगी निर्यातकों के इस दावे के संबंध में कि मौजूदा निर्णायक समीक्षा गैर-कानूनी है, क्योंकि इस समय कोई वैध पाटन-रोधी शुल्क विद्यमान नहीं है और इस प्रकार निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए यह विवेकपूर्ण होगा कि वह मौजूदा निर्णायक समीक्षा को तत्काल समाप्त कर दें, प्राधिकारी नोट करते हैं कि दिनांक 10 फरवरी, 2012 के वापस किए गए अंतिम निर्णय में प्राधिकारी की यह अवधारणा है कि प्राधिकारी द्वारा पहले अधिसूचित किए गए अंतिम निर्णय में किसी प्रकार का संशोधन किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी और इसके अतिरिक्त प्राधिकारी द्वारा निर्णय पश्चात की गई सुनवाई के फलस्वरूप दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 की अंतिम निर्णय की अधिसूचना के किसी भी भाग में भी कोई संशोधन किए जाने की आवश्यकता नहीं थी। यह समझना उपयुक्त होगा कि माननीय सीईएसटीएटी ने अपने वापसी के आदेश में प्राधिकारी को स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया है कि*“अंतिम निर्णय में किए गए किसी भी संशोधन पर सरकार द्वारा तभी विचार किया जाएगा जब पाटन—रोधी शुल्क लगाने की प्रतिवादित अधिसूचना में आवश्यक संशोधन कर दिए जाएंगे।”*
- (2) चीन से कुछ सहयोगी निर्यातकों के इस दावे के संबंध में कि मौजूदा निर्णायक समीक्षा गैर-कानूनी है, क्योंकि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस पर 12 महीनों के भीतर निर्णय देने में विफल रहे हैं, जैसा कि पाटन-रोधी नियमावली के नियम 23 (2) में उल्लिखित है, माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने रिट याचिका (सी) 2310/2015 में पहले से ही 06.01.2016 को अपना निर्णय जारी कर दिया है, जिसमें यह बताया गया है कि केन्द्रीय सरकार को समीक्षा को पूरा करने के लिए 6 महीने तक का समय बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है।
- (3) एएसबी चीन के इस दावे के संबंध में कि प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए दिया गया समय अपर्याप्त है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि दिया गया 9 दिनों का समय पर्याप्त था तथा सभी हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटीकरण विवरण पर व्यापक टिप्पणियां दे दी हैं।

- (4) चीन से कुछ सहयोगी निर्यातकों के इस दावे के संबंध में कि हितवद्ध पक्षकारों को ऐसे उत्पादों पर भी पाटन-रोधी शुल्क का भुगतान करने के लिए अनुचित कठिनाई हो रही है, जो कि इस जांच से बाहर हैं और इसलिए एक पृथक नोट जारी किया जाना चाहिए जिसमें ऐसा उल्लेख हो कि "प्रिंटीड सर्किट बोर्ड सहित एकल आधार पर आयातित संघटक/पार्ट्स विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर हैं", प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद शीर्ष के अंतर्गत ऐसी अपेक्षा का पहले से ही समाधान कर दिया गया है।
- (5) प्रतिवादी हितवद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में कि एसटीएम- 256, एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर्स (एडीएम) (केवल एसडीएच अनुप्रयोग के लिए), मल्टीपल एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर्स (एमएडीएम) (केवल एसडीएच अनुप्रयोग के लिए), डिजीटल क्रॉस कनेक्ट (डीएक्ससी) (केवल एसडीएच अनुप्रयोग के लिए) का बाहर रखा जाए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद शीर्ष के अंतर्गत इसका व्यापक स्पष्टीकरण दिया गया है कि इन उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर क्यों नहीं रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त जहां तक ब्रोड बैंड अथवा सेल्युलर उपस्करों का संबंध है, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद की टिप्पणी 3 में यह उल्लिखित कर दिया है कि "जब एसडीएच का आयात अन्त्य ब्रोडबैंड/ सेल्युलर उपस्कर के एक अंश के रूप में किया जाता है तो पाटन-रोधी शुल्क का भुगतान आयातों के केवल एसडीएच के भाग पर ही देय होगा। इसी प्रकार जब अन्त्य ब्रोडबैंड/सेल्युलर उपस्कर का आयात एसडीएच उपस्कर के रूप में किया जाता है, तो पाटन-रोधी शुल्क का भुगतान आयातों के केवल एसडीएच के भाग पर ही देय होगा"।
- (6) प्रतिवादी हितवद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में कि मल्टीपल उत्पादों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाना गैर-कानूनी है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद में केवल एसडीएच उत्पाद ही शामिल हैं।
- (7) प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रतिवादी हितवद्ध पक्षकारों ने अपने अपने प्रकटीकरण के उपरान्त के विवरण में दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 की अन्तिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/2/2009-डीजीएडी में ड्यूटी टेबल में नोट 4 जिसे दिनांक 22 अक्टूबर, 2010 के शुद्धि पत्र संख्या 14/2/2009 के साथ पढ़ा जाए और उसे आगे दिनांक 10 फरवरी, 2012 के अन्तिम निर्णय संबंधी अधिसूचना संख्या 14/2/2009 के साथ पढ़ा जाए, "निष्कासन सूची" से पीटीएन को हटाने के संबंध में प्राधिकारी के निर्णय का विरोध किया है। इस संबंध में प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड टेलिकम सर्विसेज प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (सी ओ ए आई), नई दिल्ली के अनुसार टेलिकम इंजीनियरिंग सेंटर (टी ई सी), दूर संचार विभाग, नई दिल्ली से उन्हें यह तकनीकी परामर्श मिला है कि टेलिकम इंजीनियरिंग सेंटर (टी ई सी) की तकनीकी राय में एसडीएच और पीटीएन (आईपी-एमपीएलएस/ एमपीएलएस -टीपी इत्यादि, प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर रहे) अलग अलग हैं। दूसरी ओर घरेलू उद्योग ने यह दावा करते हुए अपने तकनीकी इनपुट दिए हैं कि उच्च क्षमता वाले आंकड़ों/ ब्रॉड बैंड ट्रेफिक के लिए पिछले कुछ वर्षों से विकसित हुए एसडीएच उपकरण जिनका कि कई उद्योगों द्वारा पीटीएन नाम से एक नई श्रेणी के उपकरण के रूप में विपणन किया गया था और इस प्रकार से पीटीएन को एसडीएच श्रेणी के उपकरण के रूप में भी वर्गीकृत किया जाना चाहिए। प्राधिकारी का यह विचार है कि वर्तमान जांच चूंकि निर्णायक समीक्षा जांच है इसलिए प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे को मूल जांच के अनुसार ही रखा और तदनुसार ड्यूटी टेबल में नोट 4 को बनाए रखा क्योंकि इसका दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 की अन्तिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/2/2009-डीजीएडी जिसे दिनांक 22 अक्टूबर, 2010 के शुद्धि पत्र संख्या 14/2/2009 के साथ पढ़ा जाए और उसे आगे दिनांक 10 फरवरी, 2012 के अन्तिम निर्णय संबंधी अधिसूचना संख्या 14/2/2009 के साथ पढ़ा जाए, में उल्लेख था।
- (8) प्रतिवादी हितवद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में कि चीन से सहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन, एच ई ए टी सी, चीन के आंकड़ों के आधार पर किया जाए, जिसने कि समीक्षा जांच में पूरा सहयोग दिया है और उसको बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा भी प्रदान किया गया है तथा साथ ही मेसर्स जेडटीई कापॉरेशन लिमिटेड, मेसर्स हुआवेई टेक्नालॉजीस कंपनी लिमिटेड और मेसर्स एल्काटेल-ल्यूसेंट शंघाई बैल कंपनी लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए ईसीआई की सूचना का इस्तेमाल करने के लिए कोई वैध अथवा कानूनी आधार विद्यमान नहीं है, सिवाए इस आधार के कि इन कंपनियों के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन करने के प्रयोजनार्थ उसके पीसीएन की सहभागिता करने में ईसीआई की प्रत्यक्ष मनाही है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने प्रतिवादी हितवद्ध पक्षकारों के इन दावों का निदान कर दिया है और ऊपर स्पष्ट किए गए वैध कारणों से प्राधिकारी इस जांच में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली चीन की इन कंपनियों के संरचित सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए इजरायल को एक प्रतिनियुक्त देश नहीं मान सकते हैं। इस संबंध में प्राधिकारी के समक्ष कोई नया ठोस तथ्य अथवा प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- (9) ए एस बी के इस दावे के संबंध में कि निरिष्ट प्राधिकारी ने इस आधार पर ए एस बी को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा देने से मना कर दिया है कि कंपनी में राज्य की शेयर धारिता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी में न केवल राज्य की शेयर धारिता अधिक है, बल्कि राज्य के प्रतिनिधि निदेशक मंडल में नामित की भी विशेष प्रतिशत है, जिसमें से सरकार का एक नामित निदेशक मंडल का अध्यक्ष भी है। इस प्रकार राज्य की दखल अंदाजी से वर्जित नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्राधिकारी यह दोहराते हैं कि एएसबी को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।
- (10) जहां तक हुआवेई चीन के इस दावे का संबंध है कि उसके एमईटी के दावों को गलती से अस्वीकृत कर दिया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच के दौरान कंपनी कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं के पूरे ब्योरे/स्रोतों और उसके प्रवर्तकों द्वारा निवेश की गई पूंजी के स्रोतों के बारे में दस्तावेजों के साथ प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकी थी। इसलिए कंपनी को सूचित कर दिया गया था कि चूंकि उसने ऐसे मूल दस्तावेजों/सूचना को, जो कि बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे की जांच करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, उपलब्ध नहीं कराया था, इसलिए घरेलू विक्रयों और उत्पादन से संबद्ध लागत से संबंधित आंकड़ों की जांच करना यथोचित नहीं था। इसलिए मेसर्स हुआवेई टेक्नालॉजीस कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा स्वीकृत नहीं किया गया था।
- (11) प्राधिकारी नोट करते हैं कि उनके द्वारा पीसीएन से पीसीएन तक की गई तुलना/मैपिंग के संबंध में सहयोगी निर्यातकों और घरेलू उद्योग दोनों द्वारा उनके पश्च प्रकटीकरण विवरण में दी गई टिप्पणियों का खंडन किया है कि यदि कुछ पीसीएन के मामले में उन्हें प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई मैपिंग/तुलना करने की पद्धति स्वीकार्य नहीं है। इस संबंध में प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि निर्यातकों ने प्राधिकारी की उस मैपिंग पर आपत्ति नहीं की है जिसमें उन्हें मैपिंग स्वीकार्य थी लेकिन घरेलू उद्योग ने उसके प्रति आपत्ति व्यक्त की है। इसी प्रकार घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी की उस मैपिंग पर आपत्ति नहीं की है जोकि उन्हें स्वीकार्य थी लेकिन निर्यातकों ने उस पर आपत्ति की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसका कारण यह है कि एसडीएच उपस्कर/कार्ड आदि की विभिन्न क्षमता बेशी अथवा गैर-बेशी, विभिन्न क्रॉस कनेक्ट क्षमता, प्रयुक्त इंटरफेसों की संख्या, ऑप्टिकल रीच आदि आदि भिन्न हैं। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रारंभ में प्राधिकारी ने निर्यातकों के केवल 5 अंकों वाले पीसीएन (जैसे कि 43बी.400के.सीए. एस) के बारे में घरेलू उद्योग को अवगत कराया था। इसी प्रकार पीसीएन से पीसीएन तक की तुलना की गई थी। घरेलू उद्योग ने केवल 15 अंकों के पीसीएन के आधार पर अपनी बीओक्यू तैयार की थी। तथापि, बाद में उसमें और स्पष्टता, पारदर्शिता और सार्थकता लाने के लिए तथा साथ ही इस कारण से कि पीसीएन से पीसीएन की तुलना को कठिन पाया गया था क्योंकि घरेलू उद्योग के उपस्करों के साथ निर्यातित उपस्करों/कार्डों में भिन्नता व्याप्त थी, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और निर्यातकों के बीच पारस्परिक बैठकें आयोजित की थीं जिसमें पीसीएन द्वारा कवर किए गए उपस्करों/कार्डों के विस्तृत विवरणों को शामिल किया गया था जैसे कि उनकी क्षमता क्या है, क्या यह बेशी है अथवा गैर-बेशी उपस्कर है, इसकी क्रॉस कनेक्ट क्षमता क्या है, उक्त उपस्कर में कितने इंटरफेसिज प्रयुक्त किए गए हैं, उपस्कर की ऑप्टिकल रीच क्या है आदि। उसके बाद घरेलू उद्योग ने उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर इन निर्यातकों द्वारा निर्यातित विभिन्न उपस्करों/कार्डों/पीसीबीए के लिए अपनी बीओक्यू की पुनः संरचना की थी। यही कारण है कि केवल 15 अंकों वाले पीसीएन के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा तैयार की गई बीओक्यू को बाद में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाद/पीसीएन के पूरे विवरण के आधार पर संशोधित कर दिया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसकी प्रकृति/किस्म आदि क्या है। इसमें कुछ नए पार्ट्स/संघटकों, इंटरफेसिज को जोड़ा गया अथवा कुछेक को हटाया गया है। प्राधिकारी ने उसके बाद घरेलू उद्योग के बीओक्यू को स्वीकार करने की बजाए ऐसी और अधिक पारस्परिक बैठकें आयोजित कीं ताकि सहमति से निर्णय लिया जा सके क्योंकि अधिकतर पीसीएन में सही तुलना और मैपिंग करना संभव नहीं था क्योंकि उनमें भिन्नता, जटिलताएं और उपस्करों/कार्डों के अंत प्रयोग में भिन्नता थी लेकिन साथ ही कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार की मैपिंग के प्रति पूर्णतः सहमत नहीं था। इसलिए प्राधिकारी को संभावित मैपिंग पर सहमति जुटाने के लिए अपने निजी विवेक और बुद्धिमत्ता का उपयोग करना पड़ा था जोकि घरेलू उद्योग और निर्यातकों के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ हुई परिचर्चा पर आधारित था। इस संबंध में यह समझने की आवश्यकता है कि उदाहरणतः एल्काटेल के मामले में अधिकतर पीसीएन के लिए प्राधिकारी द्वारा की गई तुलना/मैपिंग को अल्काटेल द्वारा स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार, हुआवेई चीन और जैड टी ई ने भी कुछ तुलना/मैपिंग को स्वीकार किया है और कुछेक का प्रतिवाद किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि घरेलू उद्योग के उपस्करों की तुलना में निर्यातित विभिन्न कार्डों/उपस्करों की क्षमता, अंतःप्रयोग आदि में भिन्नता है, इसलिए उनमें कुछ संघर्ष होना स्वाभाविक है। निर्यातक यह चाहते हैं कि घरेलू उद्योग का बीओक्यू किस तरह होना चाहिए और घरेलू उद्योग यह चाहता है कि प्राधिकारी को बीओक्यू को अपनाना चाहिए। वास्तव में यही कारण है कि पश्च प्रकटीकरण विवरण की टिप्पणियों में घरेलू उद्योग के साथ-साथ निर्यातकों ने प्राधिकारी द्वारा की गई तुलना/मैपिंग को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया है। तथापि, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और निर्यातकों की पश्च प्रकटीकरण विवरण में की गई टिप्पणियों के आधार पर उन पीसीएन की तुलना और मैपिंग की पुनः जांच की है जोकि विवादास्पद है और वे यह पाते हैं कि प्राधिकारी द्वारा की गई तुलना/मैपिंग सही है क्योंकि यह निर्यातकों और घरेलू उद्योगों के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ किए गए विचार-विमर्श पर आधारित थी तथा इसका आकलन सामान्य रूप से स्वीकार्य तकनीकी विशेषताओं अथवा उद्योग में प्रचलित उपस्करों/कार्डों के विकल्पों के आधार पर उनके निजी विवेक पर आधारित थी और इस प्रकार मैपिंग/तुलना में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

- (12) प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में कि उन्होंने घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा और मूल्य के लिए ओवम रिपोर्ट पर विश्वास करने पर कड़ी आपत्ति प्रकट की है और इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिका दोषयुक्त थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा प्राप्त करने के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है और इस प्रकार प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के ऐसे दावे का कोई महत्व नहीं है।
- (13) प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में कि ईसीआई, इजरायल के लिए नकारात्मक पाटन मार्जिन का परिकलन किया गया था और इस तथ्य के बावजूद भी प्राधिकारी क्षति का विश्लेषण करने में पाटित आयातों की कुल मात्रा में से ईसीआई, इजरायल के गैर-पाटित आयातों को बाहर रखने में विफल रहे हैं, इसलिए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उसने जो कार्रवाई की है वह सही है क्योंकि प्राधिकारी ने अपनी प्रक्रिया के अनुसार क्षति का आकलन करने के लिए कुल मांग का आकलन करने के लिए इजरायल से हुए समग्र आयात की मात्रा को देखा है। अतः प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के दावे का कोई औचित्य नहीं है।
- (14) प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में कि क्षति विश्लेषण के प्राचलों से ऐसा पता चलता है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है तथा आरोपित पाटन और क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की कार्रवाई के दौरान व्यापक जांच करने से ऐसा पता चला है कि आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में काफी कटौती कर रहे हैं। इसके साथ ही ऐसे आयात घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की कीमतों का ह्रास भी कर रहे हैं। जांच अवधि के दौरान पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद भी घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ, नकदी प्रवाह और विकास की दृष्टि से गिरावट आई है।
- (15) अत्यधिक गोपनीयता बनाए रखे जाने के प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग के दावे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी सूचना को जो कि प्रकृति से गोपनीय है और जिसे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान किया गया है, प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई सामान्य पद्धति के अनुसार जहां कहीं भी आवश्यक हुआ है वहां उसकी गोपनीयता की जांच करने के बाद उसे गोपनीय माना गया है। इसलिए हितबद्ध पक्षकारों की ऐसी चिंताओं का पर्याप्त रूप से निदान कर दिया गया है।
- (16) प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में कि प्राधिकारी द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को डीजीसीआईएंड एस के कारोबार-वार आयात के आंकड़े प्रदान नहीं किए गए हैं, जिसके कारण घरेलू उद्योग का क्षति विश्लेषण जोखिम में पड़ जाता है, प्राधिकारी ने यही दोहराया है कि जहां तक आयात के आंकड़े प्राप्त करने का संबंध है, डीजीसीआईएंड एस द्वारा एसडीएच उपस्करों और एसडीएच उपस्करों के पार्ट्स के लिए टैरिफ संहिता के लिए यथा प्रदत्त समेकित आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया है कि जहां तक कीमत में कटौती होने और कम कीमत पर बिक्री करने का संबंध है, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर के आधार पर संबद्ध देशों के लिए पहुंच मूल्य का निर्धारण किया है और ऐसा करना इस लिए आवश्यक था क्योंकि क्षति अवधि के लिए डीजीसीआईएंड एस के आंकड़ों में पीसीएन से पीसीएन तक की मैपिंग/तुलना करना संभव नहीं था क्योंकि डीजीसीआईएंड एस के आंकड़े पीसीएन की संरचना करने के लिए पूरी सूचना नहीं देते हैं, जबकि सहयोगी निर्यातकों और घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के लिए पीसीएन-वार ब्यौरे दिए हैं और इस प्रकार इन निर्यातकों और घरेलू उद्योग के लिए पीसीएन से पीसीएन तक की मैपिंग/तुलना की गई थी। इस दावे के संबंध में कि कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण का विश्लेषण करने के लिए पहुंच मूल्य पर विचार नहीं किया गया है और ऐसा करना प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली सुसंगत पद्धति का घोर उल्लंघन करना है, प्राधिकारी ऐसा मानते हैं कि ऐसे दावे का इसलिए कोई महत्व नहीं है, क्योंकि कीमत ह्रास/कीमत न्यूनीकरण के लिए बिक्रियों की लागत की तुलना, बिक्रियों की कीमत से की जाती है।
- (17) प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में कि ऐसी स्थिति में जबकि प्राधिकारी, पाटन-रोधी शुल्क की मात्रा का निर्णय लेते हैं, पाटन-रोधी शुल्क की मात्रा, ऐसे शुल्क से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो कि मूल जांच के दौरान लगाया गया था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्णायक समीक्षा, एक स्वतंत्र जांच है और यदि निर्णायक समीक्षा की जांच अवधि के आंकड़ों की आवश्यकता होगी, तो प्राधिकारी शुल्क में संशोधन कर सकते हैं, जैसा कि प्राधिकारी ने विगत में अनेक निर्णायक समीक्षा जांच में किया है। इसके अतिरिक्त माननीय सीईएसटीएटी ने भी विचाराधीन अपीलों पर अभी तक कोई अंतरिम अथवा अंतिम आदेश जारी नहीं किया है।
- (18) घरेलू उद्योग के इस दावे के संबंध में कि संबद्ध देशों के उत्पादकों के पास अत्यधिक क्षमता विद्यमान है, जिससे सिद्ध होता है कि शुल्कों को रद्द कर दिए जाने की स्थिति में भी भारत में उनके निर्यात गहन होंगे, प्राधिकारी नोट करते हैं कि

घरेलू उद्योग का ऐसा दावा असंगत है, क्योंकि प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि हुआवेई चीन, एचईटीसी चीन, एल्काटेल-ल्यूसेंट और जेड टीई कंपनियां, विचाराधीन उत्पाद को पाटित कर रही हैं और इसीलिए उन्होंने उन पर पाटन-रोधी लगाए जाने की सिफारिश की है। लेकिन फिर भी घरेलू उद्योग ने सहयोगी निर्यातकों के पास अतिरिक्त क्षमता होने के अपने दावे के संबंध में कोई ठोस और पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए हैं।

- (19) प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में कि निर्दिष्ट प्राधिकारी, एक ऐसे बौद्धिक सम्पदा धारक को, जो कि भारत में विनिर्माण नहीं करता है, घरेलू उद्योग के रूप में मानने के लिए इच्छुक हैं, जब कि दूसरी ओर वह हुआवेई इंडिया को घरेलू उद्योग मानने पर विचार नहीं कर रहे हैं, हालांकि उसके पास भारत में बौद्धिक परिसम्पदा के साथ-साथ भारत में संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण करने की क्षमता विद्यमान है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे विभिन्न तर्क दिए हैं, जिनमें तेजा नेटवर्कस लिमिटेड को जिसका कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख अंशदान है, पात्र घरेलू उद्योग के दर्जे के बारे में प्रश्न उठाए गए हैं। तथापि, विस्तृत जांच करने के बाद प्राधिकारी की ऐसी अवधारणा है कि तेजा नेटवर्कस लिमिटेड का जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अंशदान रहा है तथा वह नियम 2 (ख) में उल्लिखित परिभाषा के भीतर घरेलू उद्योग बनता है और जो कि पाटन-रोधी नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार घरेलू उद्योग के दर्जे के मानदंड को संतोषजनक ढंग से पूरा करता है।
- (20) हुआवेई इंडिया के इस दावे के संबंध में कि उसे पात्र घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हर जांच अपने तथ्यों और गुण-दोष पर आधारित होती है और इसलिए पूर्व जांचों में लिए गए किसी भी अन्य निर्णय का संदर्भ देने का विचाराधीन जांच के मामले में कोई संबंध नहीं है। प्राधिकारी दोहराते हैं कि चूंकि हुआवेई इंडिया, हुआवेई चीन के पूर्ण स्वामित्वाधीन उसकी एक सामूहिक कंपनी है और उसने मौजूदा निर्णायक समीक्षा जांच में जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है तथा आयातकों की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं, इसलिए मौजूदा निर्णायक समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ हुआवेई को पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में उल्लिखित परिभाषा के भीतर घरेलू उद्योग माने जाने के दावे का कोई महत्व नहीं है।
- (21) तीसरे देश के निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन का निर्धारण करके पाटन के संभावना का विश्लेषण करने के अनुरोध के संबंध में और उसके बाद यह मानते हुए कि क्या कोई पाटन और क्षति की संभावना नहीं है, प्राधिकारी ने तीसरे देश के निर्यातों के लिए ई सी आई इजरायल के आंकड़ों का विश्लेषण किया है और यह पाया कि निर्यातक ने पाटित कीमतों पर तीसरे देश को निर्यात नहीं किया है। जहां तक चीन से सहयोगी निर्यातकों का संबंध है, प्राधिकारी ने काफी जांचों में यह विचार किया है कि यदि जांच की अवधि में कोई पाटन और क्षति हुई है तो कोई संभावित विश्लेषण करने की कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि जांच की अवधि में मार्जिन के आधार पर शुल्क लगाया जाएगा।
- (22) पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के दावे के बारे में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि मांग में गिरावट आई है, लेकिन भारत में उत्पादन और खपत की अपेक्षाकृत तथा संपूर्ण रूप से संबद्ध आयात अत्यधिक बने रहे हैं। साथ ही ऐसे आयात, बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। ऐसे आयात घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में ह्रास भी कर रहे हैं। जांच अवधि के दौरान पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद भी घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में शुल्क लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ, नकदी प्रवाह और विकास के रूप में गिरावट आई है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में अत्यधिक गिरावट आई है।
- (23) घरेलू उद्योग के इस दावे के संबंध में कि प्राधिकारी ने प्रिंटीड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) और पापुलेटिड सर्किट बोर्ड में यह कहते हुए भिन्नता की है कि पीसीबी विनिर्माता द्वारा विकसित किए गए डिजाइन के अनुसार पापुलेटिड है और उसके बाद सॉफ्टवेयर को लोड करने के अतिरिक्त उन्हें शेल्फ में व्यवस्थित करने और सर्किट में सुव्यवस्थित ढंग से लगाने की आवश्यकता होती है और इसके अतिरिक्त पीसीबी विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र के भीतर इस कारण से आते हैं क्योंकि यह विनिर्माता की परिसम्पत्ति होते हैं तथा एसडीएच उपस्कर के उत्पादन में इसको प्रयुक्त किए जाने के सिवाए इसका कोई और उपयोग नहीं होता है, प्राधिकारी ने पहले से ही यह निर्णय दिया है कि पापुलेटिड सर्किट बोर्ड/असेम्बलीज (एसडीएच के प्रयोग के लिए ही हैं), विचाराधीन उत्पाद के ही भाग हैं। तथापि, प्राधिकारी ने यह भी निर्धारित किया है कि प्रिंटीड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) स्वभाविक रूप से पार्ट्स और संघटक हैं और इस प्रकार यदि एकल आधार पर प्रिंटीड सर्किट बोर्ड का आयात किया जाता है, तो वे विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर होंगे।
- (24) घरेलू उद्योग के इस दावे के संबंध में कि प्राधिकारी ने ईसीआई इजरायल के मामले में उत्पादक की उत्पादन लागत के आधार पर पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है और उसमें "उचित लाभ" को जोड़ दिया है, जबकि प्राधिकारी को नियमावली के

अनुसार कंपनी द्वारा अर्जित किए गए वास्तविक लाभ के आधार पर लाभ को जोड़ना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उन्होंने सामान्य पद्धति का अनुसरण किया है, क्योंकि ईसीआई इजरायल जो कि बाजार अर्थव्यवस्था वाला निर्यातक है, की घरेलू बिक्रियां, भारत में निर्यात बिक्रियों के पांच प्रतिशत से कम हैं।

- (25) एनआईपी का निर्धारण करने और विभिन्न कारखाना-गत व्ययों और करों से संबंधित घरेलू उद्योग के विभिन्न निवेदनों के संबंध में जिनमें एनआईपी का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत को सामान्यकृत नहीं किया जाना चाहिए शामिल है, प्राधिकारी की यह अवधारणा है कि घरेलू उद्योग की एनआईपी का निर्धारण, पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-3 में उल्लिखित आधार पर किया गया है, जो कि प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली सुसंगत पद्धति है। इसके लिए समस्त अस्वीकार्य खर्चों को ध्यान में नहीं रखा गया है तथा अनुबंध-3 में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि गैर-क्षति कीमत का आकलन करते समय व्यय पर विचार नहीं किया जाएगा। जहां तक रिलायन्स इंडस्ट्रीज के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संबंध है, जिस पर संबंधित घरेलू उद्योग ने विश्वास किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त निर्णय के बाद पाटन-रोधी नियमावली में अनुबंध-3 को शामिल कर लिया गया है तथा इस प्रकार यह लागू हो गया है और प्राधिकारी द्वारा इसका सुसंगत रूप से अनुपालन किया जा रहा है। जहां तक कमीशन को शामिल करने के बारे में घरेलू उद्योग के निवेदन का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हालांकि यह सीएस-3 के अंतर्गत यह स्वीकार्य करने योग्य खर्च है, फिर भी अनुबंध-3 इसे एनआईपी के परिकलन में शामिल करने की अनुमति नहीं देता है।
- (26) जहां तक समान इकाइयों के मामले अथवा जांच की अवस्था में घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए लागतों के निर्धारण के लिए वास्तविक उत्पादन संबंधी आंकड़ों को अपनाने का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा सुझाया गया मत (उत्पादन इत्यादि के लिए अपेक्षित समय के संबंध में) तकनीकी तर्कों पर आधारित नहीं है। इसके अलावा निर्मित उत्पाद प्रौद्योगिकीय उत्पाद हैं जिनका सीमित समय होता है, चाहे वास्तविक रूप से उत्पादित अथवा बेची गई इकाइयों की संख्या कितनी भी हो।
- (27) प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास अपनी स्वयं की कोई संस्थापित क्षमता नहीं होती। विचाराधीन उत्पाद जॉब कॉट्रैक्ट आधार पर इलैक्ट्रॉनिक कॉट्रैक्ट निर्माताओं से आउटसोर्स आधार पर निर्मित कराए जाते हैं। वास्तव में घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि वह अपने स्वयं के पास कोई संस्थापित क्षमता हुए बिना ही प्राप्त आदेशों का निष्पादन करने की स्थिति में है और ई एम एस के उपयोग के कारण क्षमता कोई रुकावट नहीं है। अतः गैर-क्षति कीमत के निर्धारण के सिद्धांतों के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध -3 के पैरा 4 (iii) के तहत विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किया गया है। कई अन्य ऐसी ही जांचों में यह कार्य प्रणाली निरंतर प्रयोग में लाई गई है। नियमों का संगत उद्धरण नीचे दिया गया है:-

“ उत्पादन क्षमताओं के अक्षम उपयोग द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति, यदि कोई हो, तो उसे अप्रभावित करने के लिए पिछले तीन वर्षों की अवधि और जांच की अवधि के दौरान उत्पादन क्षमताओं के बेहतर उपयोग और जांच की अवधि की दरों पर विचार किया जाए। ”

- (28) घरेलू उद्योग के इस दावे के संबंध में कि हुआवेई चीन और हुआवेई इंडिया द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तरों से ऐसा स्पष्ट पता चलता है कि इन पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर उन्हें पृथक मार्जिन स्वीकृत करने के लिए अत्यधिक रूप से अपर्याप्त हैं क्योंकि इन उत्तरों में विशेष सूचना को छिपा कर रखा गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हुआवेई, चीन द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्यात आंकड़ों की प्राधिकारी द्वारा विधिवत् जांच की गई है और उसके बाद ही उनके लिए पृथक पाटन मार्जिन का परिकलन किया गया है। हुआवेई इंडिया को पाटन-रोधी नियमावली में उल्लिखित परिभाषा के भीतर घरेलू उद्योग के रूप में उपयुक्त पात्र नहीं माना गया है।
- (29) घरेलू उद्योग के इस दावे के संबंध में कि हुआवेई इंडिया ने संघटकों के नाम से एचडीएच ट्रांसमिशन उपस्कर लाने का प्रयास किया है और उसने पाटन-रोधी शुल्क की अपवचना की है तथा उपभोक्ताओं द्वारा इस प्रकार से एसडीएच उपस्कर अधिप्राप्त किए गए हैं तथा उन पर डीआरआई की कार्रवाई/निर्णय से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र के भीतर भारत में किन वस्तुओं का आयात किया गया है तथा डीआरआई द्वारा इस संबंध में अनेक प्रकार के कारण बताओं नोटिस जारी किए गए हैं और दंड लगाए गए हैं और प्राधिकारी को डीआरआई से सूचना प्राप्त करनी चाहिए थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हुआवेई, चीन द्वारा प्रस्तुत किए गए आयात के आंकड़ों की विधिवत् जांच की गई है और उसके बाद ही उन्हें पृथक पाटन मार्जिन स्वीकार किया गया है। इसलिए प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार इस मुद्दे का समाधान, उसके गुणावगुण के आधार पर किया है। प्राधिकारी का यह भी विचार है कि किसी भी मामले में डीआरआई की कार्रवाईयां, पाटन-रोधी कार्रवाईयों से स्वतंत्र होती हैं और इस प्रकार यदि डीआरआई को ऐसा

पता चलता है कि कुछ निर्यातक/आयातक विधि का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो डीआरआई ऐसे मामले में अपनी क्रिया-विधि के अनुसार उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेगा।

- (30) फिब्रोम इंडिया लिमिटेड द्वारा विद्यमान दर के आधार पर हुआवेई के लिए प्रस्तावित शुल्क की दरों के लिए अपनाई गई क्रिया-विधि पर उठाए गए प्रश्न के साथ-साथ चीन जनवादी गणराज्य में सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों पर शुल्क के प्रतिशत के अत्यधिक कटौती किए जाने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि मौजूदा निर्णायक समीक्षा, एक स्वतंत्र जांच है, जिसमें पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का परिकलन, जांच अवधि के लिए सत्यापित आंकड़ों के आधार पर, पीसीएन से पीसीएन की मैपिंग/मिलान करने की पारदर्शी और व्यापक क्रिया-विधि का अनुसरण करने के बाद ही किया गया है और इस प्रकार इसमें विगत मार्जिन की कोई प्रासंगिकता नहीं है।
- (31) घरेलू उद्योग के इस दावे के संबंध में कि पाटन-रोधी शुल्क को, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के सीआईएफ मूल्य (शुल्क के सम मूल्य पर) के प्रतिशत के रूप में लगाया जाने की सिफारिश की जाए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसने आयातों के सीआईएफ के प्रतिशत के रूप में शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

104. प्राधिकारी स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना भारत में उत्पाद के कीमत स्तर को प्रभावित कर सकता है। तथापि पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। दूसरी तरह पाटनरोधी उपाय पाटन प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त करेंगे, घरेलू उद्योग के पाटन को रोकेंगे और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में सहायता करेंगे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय किसी भी तरह संबद्ध देशों से आयात का प्रतिबंधित नहीं करेंगे और इसलिए अंतिम प्रयोक्ता के लिए उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित करेंगे। अंतिम प्रयोक्ता अब भी आपूर्ति के दो अथवा अधिक स्रोत बनाए रख सकेंगे।

105. पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन के अनुसूचित व्यापार कार्यों द्वारा घरेलू उद्योग के लिए क्षति के कारण को सामान्य रूप से दूर करना है। ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्क उपाय करने से उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

घ. निष्कर्ष

106. किए गए दावों, उपलब्ध कराई गई सूचना और हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोधों तथा इस अंतिम निष्कर्ष में रिकार्ड किए गए अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पाटन एवं परिणामी क्षति तथा पाटन और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति होने की संभावना की स्थिति के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी निम्नलिखित विकर्षण परिणाम निकालते हैं:

क. जहां तक हुआवेई चीन, जैडटीई कारपोरेशन लि., चीन और एल्काटेल-लूसेंट संघाई बैल का. लि. का संबंध है इन कंपनियों से जांच की अविधि में संबद्ध वस्तुओं का निरंतर पाटन है जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के लिए क्षति पाटित आयात के कारण हुई है।

ख. जहां तक एचईटीसी, चीन का संबंध है, उनके आंकड़ों की पुनः जांच करने से यह पता चला है कि जांच की अवधि में नगण्य (**% से भी कम) पाटन हुआ है और इस संबंध में प्राधिकारी ने भारत के साथ-साथ तीसरे देशों को जांच की अवधि के बाद किए गए निर्यातों की जांच की है और यह पाया है कि इनका पाटन नहीं हुआ। अतः पाटन की कोई संभावना नहीं है। जहां तक ई सी आई टेलिकम, इजरायल का संबंध है यह देखा गया है कि जांच की अवधि में भारत को और जांच की अवधि के बाद भारत के साथ-साथ तीसरे देशों को विचाराधीन उत्पादों के निर्यात पाटित कीमतों पर नहीं थे और इस प्रकार यदि शुल्क को हटा लिया जाता है तो ई सी आई टेलिकम, इजरायल से पाटित आयातों की कोई संभावना नहीं है।

द. सिफारिशें

107. उपरोक्त निष्कर्ष निकाले जाने पर प्राधिकारी का मत है कि संबद्ध देशों से आने वाली अथवा निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग को इसकी परिणामी क्षति की क्षतिपूर्ति करने के लिए पाटनरोधी उपाय की सिफारिश किए जाने की आवश्यकता है।

108. प्राधिकारी द्वारा कम शुल्क नियमावली का पालन करते हुए प्राधिकारी कम पाटन मार्जिन और क्षति के मार्जिन के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग के लिए क्षति समाप्त हो सके। तदनुसार नीचे दी गई शुल्क तालिका में उल्लिखित पाटन शुल्क जो आयात के सीआईएफ मूल्य के प्रतिशत के रूप में होगा, संबद्ध देशों से आने वाली निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं की तारीख से लगाए जाने की सिफारिश करता है।

शुल्क तालिका

क्रम सं.	शीर्ष/उपशीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	इकाई
1.	851762 तथा 851770	नीचे विवरण के अनुसार ***सिंक्रोनस डिजिटल हाईआर्की ट्रांसमिशन इन्क्रिपमेंट	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	मैसर्स जैडटीई कारपोरेशन लि.	मैसर्स जैडटीई कारपोरेशन लि.	48.42	आयात के सीआईएफ मूल्य का %
2.	यथोक्त	यथोक्त	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	एल्काटेल-लूसेंट संघाई बैल का. लि.	एल्काटेल-लूसेंट संघाई बैल का. लि.	54.09	यथोक्त
3.	यथोक्त	यथोक्त	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	मैसर्स हुआवै टैक्रोलॉजी का. लि. चीन पीआर	(i)मैसर्स हुआवै टैक्रोलॉजी का. लि. चीन जन.गण., अथवा (ii) हुआवेई टैक इन्वेस्टमेंट कं. लि., हांग कांग, अथवा (iii)हुआवेई इंटरनेशनल प्रा. लि., सिंगापुर	37.73	यथोक्त
4.	यथोक्त	यथोक्त	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	मैसर्स हंगजोउ ईसीआई टेलीकम्यूनिकेशन का. लि.	मैसर्स ईसीआई टेलीकोम लि., इजराइल	शून्य	यथोक्त
5.	यथोक्त	यथोक्त	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	उपरोक्त क्रम सं. 1,2,3 और 4 के अतिरिक्त कोई अन्य	कोई भी	86.59	यथोक्त
6.	यथोक्त	यथोक्त	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. के अतिरिक्त कोई अन्य	कोई भी	कोई भी	86.59	यथोक्त
7.	यथोक्त	यथोक्त	कोई भी	चीन जन.गण.	कोई भी	कोई भी	86.59	यथोक्त
8.	यथोक्त	यथोक्त	इजराइल	इजराइल	मैसर्स ईसीआई टेलीकोम लि.	मैसर्स ईसीआई टेलीकोम लि.	शून्य	यथोक्त
9.	यथोक्त	यथोक्त	इजराइल	इजराइल	उपरोक्त क्रम सं. 8 के अतिरिक्त कोई अन्य	कोई भी	9.42	यथोक्त
10.	यथोक्त	यथोक्त	इजराइल	चीन जन.गण. अथवा इजराइल	कोई भी	कोई भी	9.42	यथोक्त

क्रम सं.	शीर्ष/उपशीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	इकाई
				के अतिरिक्त कोई अन्य				
11.	यथोक्त	यथोक्त	चीन जन.गण. के अतिरिक्त कोई अन्य	इजराइल	कोई भी	कोई भी	9.42	यथोक्त

****टिप्पणी 1.** विचाराधीन उत्पाद में 'सिंक्रोनस डिजिटल हार्डआर्की ट्रांसमिशन उपकरण अर्थात् एसटीएम-1, एसटीएम-4, एसटीएम-16, एसटीएम-64, एसटीएम- 256, सीकेडी, एसकेडी रूप में असेंबल्ड, इसकी संभावित ब्रॉडबैंड/सेल्युलर उपकरण के साथ इसकी असेंबलियां और सब असेंबलियां अथवा फिट किए गए उपकरण शामिल हैं। विचाराधीन उत्पादों में एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर्स(एडीएम)(केवल एसडीएच अनुप्रयोगों के लिए) मल्टीपल एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर्स (एमएडीएम) (केवल एसडीएच अनुप्रयोगों के लिए) तथा डिजिटल क्रॉस कनेक्ट (डीएक्ससी)(केवल एसडीएच अनुप्रयोग के लिए) पोपुलेटेड सर्किट बोर्ड (केवल एसडीएच अनुप्रयोग के लिए) तथा उपकरण के एक भाग के रूप में आयातित पार्ट्स/कंपोनेंट भी शामिल हैं। जब तक कि वे उपकरण के साथ अथवा इसकी असेंबली/ सब असेम्बलियों के साथ आयातित किए जाते हैं। विचाराधीन उत्पाद में साफ्टवेयर से अभिप्राय एसडीएच से है जो इन उपकरणों का एक महत्वपूर्ण भाग है और जिसे उपकरण के एक भाग के रूप में अथवा पृथक रूप से खरीदा जा सकता है तथापि स्टैंडएलोन आधार पर आयातित उपकरण/पार्ट्स विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

****टिप्पणी 2.** एसडीएच उपकरण अनिवार्यतः ऑप्टिकल फाइबर के जरिए सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। एसडीएच उपकरण से अभिप्राय इलेक्ट्रिकल कॉपर मीडियम और माइक्रोवेव रेडियो मीडियम के जरिए ट्रांसमिशन से है। अकेले ऑप्टिकल फाइबर के जरिए डाटा ट्रांसमिट करने वाले एसडीएच उपकरण पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के अध्याधीन है।

****टिप्पणी 3.** जब एसडीएच का आयात संभावित ब्रॉडबैंड/सेल्युलर उपकरण के एक भाग के रूप में किया जाता है तो आयात के एसडीएच भाग पर ही एडी शुल्क देय होगा। इसी प्रकार जब संभावित ब्रॉडबैंड/सेल्युलर उपकरण का आयात एसडीएच उपकरण के एक भाग के रूप में किया जाता है तो एडी शुल्क आयात के एसडीएच भाग पर ही देय होगा।

****टिप्पणी 4.** इसके किसी भी रूप में गैर एसडीएच होने के कारण पीडीएच, सीडब्ल्यूडीएम, डीडब्ल्यूडीएम, माइक्रोवेव सिस्टम, जीपीओएन, डीएसएलएएम, एमएसएएन, बीआईटीएस, राउटर्स, पीडीएसएन, एसजीएसएन, एमजी डब्ल्यू, बीटीएस, बीएससी, एमएससी, ओएनटी, एचएलआर, एचएसएस और एमआरपी पीयूसी के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं और इसलिए एडी शुल्क लगाने के अध्याधीन नहीं है।

****टिप्पणी 5.** माइक्रोवेव रेडियो ट्रामिनल्स जिनमें एसडीएच ट्रांसमिशन उपकरण के लिए एसटीएम-1 इंटरफेस हो सकता है और फिजिकल मीडिया के रूप में काम करता है ताकि रेडियो और एसडीएच उपकरण के बीच कनेक्टिविटी में सक्षम करने हेतु एडी शुल्क के भुगतान के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया है।

109. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा यथानिर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 तथा 9क के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी शुल्क शामिल होंगे।

110. केन्द्र सरकार द्वारा इस जांच परिणाम पर आधारित आदेश के विरुद्ध खिलाफ कोई अपील सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी।

ए. के. भल्ला, अतिरिक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th February, 2016

(Final Findings)**Subject: Sunset Review of anti-dumping duty imposed on the imports of Synchronous Digital Hierarchy Transmission Equipment originating in or exported from China PR and Israel -reg.**

F. No 15/20/2014-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules or the AD Rules) thereof;

A. BACKGROUND OF THE CASE

2. Whereas, the Designated Authority (hereinafter referred also to as the Authority or DA) had issued a Public Notice dated 21st April 2009, initiating the anti-dumping duty investigation concerning imports of Synchronous Digital Hierarchy Transmission Equipment [hereinafter referred to as SDH Equipment or the subject goods or the Product Under Consideration (PUC)] originating in or exported from China PR and Israel (hereinafter referred to as the subject countries). The Authority, having regard to the Act and the Rules, investigated the matter and then recommended imposition of provisional anti dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries vide Notification dated 7th September, 2009, and provisional antidumping duties were imposed by the Ministry of Finance vide Notification No. 132/2009-Customs dated 8th December, 2009.
3. And whereas the Authority issued Final Findings Notification No 14/2/2009-DGAD dated 19th October, 2010, recommending imposition of the anti-dumping duties on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries and the antidumping duties were imposed by the Ministry of Finance vide Notification No.125/2010-Customs dated 16th December, 2010.
4. And whereas some interested parties filed appeals before the Hon'ble Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT), Principal Bench, New Delhi, challenging the Final Findings dated 19th October, 2010 and the Customs Notification No.125/2010-Customs dated 16th December, 2010. The Hon'ble CESTAT, after extensively hearing the interested parties and the domestic industry, remanded the matter back to the Authority for affording post-decisional hearing to the appellants and other interested parties, if any, and for making such modifications to the Final Findings as might be necessary as a result of such post decisional hearing. The Authority, vide its Final Findings Notification No 14/2/2009-DGAD dated 10th February, 2012, issued its post decisional Final Findings confirming the Final Findings earlier notified vide Notification No. 14/2/2009-DGAD dated 19th October, 2010.
5. And whereas in terms of the Rules, M/s Tejas Networks Limited (hereinafter referred to as the petitioner or the applicant) representing the Domestic Industry approached the Authority with an application requesting for continuation of the antidumping duties in force imposed by the Central Government vide Notification No.125/2010-Customs dated 16th December, 2010. The request is based on the grounds that dumping has continued in spite of imposition of antidumping duty on the import of the subject goods from the subject countries and the domestic industry continues to suffer injury on account of dumping from the subject countries as the form and quantum of anti dumping duty in force has been insufficient. The petitioner has further argued that expiry of the measure against the subject countries would be likely to result in continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The petitioner also claims that the revocation of anti-dumping measures would result in intensified dumping and consequent injury to the domestic industry and, therefore, the duty is required to be continued for a further period of five years.
6. And the Authority, on the basis of prima facie evidence given by the petitioner, initiated the sunset review (SSR) investigation in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of the AD Rules, vide Notification No.15/20/2014-DGAD dated 6th December, 2014, to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The Ministry of Finance, vide its Notification No 1/2015 dated 5th January, 2015 extended the anti dumping duty imposed vide Customs Notification No 125/2010-Customs dated 16th December, 2010, up to 7th December, 2015.

B. PROCEDURE

7. The procedure described below has been followed in this investigation:

- (i) The Authority notified the embassies of the subject countries in India about the receipt of application before proceeding to initiate the investigation in accordance with the Rules.
- (ii) The Authority issued a public notice No.15/20/2014-DGAD dated 6th December, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the sunset review anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.
- (iii) The Authority sent copy of the initiation notification dated 6th December, 2014 to the embassies of the subject countries in India, known exporters from the subject countries, known importers and other interested parties, and the domestic producers, as per available information. The known interested parties were requested to file questionnaire responses and make their views known in writing within the prescribed time limit. Copies of the letter and questionnaires sent to the exporters were also sent to embassies of the subject countries along with a list of known exporters/producers, with a request to advise the exporters/producers from the subject countries to respond within the prescribed time limit.
- (iv) The copy of the non-confidential version of the application filed on behalf of the applicant was made available to the known exporters, other domestic producers and the embassies of the subject countries in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
- (v) The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the sunset review to the following known producers/exporters/representative organizations in the subject countries and gave them opportunity to make their views known in writing within the prescribed time limit in accordance with the Rules:
 - a) Huawei Technologies Co., Ltd, China
 - b) Wuhan Fiberhome International, China
 - c) ZTE Corporation Ltd., China
 - d) Hangzhou ECI Telecommunications Co. Ltd., China
 - e) Hi Silicon Technologies Ltd, China
 - f) ECI Telecommunication Co. Ltd. Israel
 - g) Alcatel Lucent Shanghai Bell Co. Ltd., China
 - h) UT Starcom Ltd China, Hong Kong
 - i) UT Starcom Ltd, Hangzhou, China
 - j) Ciena Corporation, USA
 - k) Ceragon Networks Ltd, Israel
 - l) RAD DATA Communication, Israel
 - m) China Chamber of Commerce for import and export of machinery and electronics products, China
- (vi) In response to the initiation of the subject investigation, the following producers/exporters from the subject countries responded by filing questionnaire response:
 - a) ZTE Corporation Ltd., China PR
 - b) Huawei Technologies Co. Ltd., China PR
 - c) Huawei International PTE, Singapore
 - d) Huawei Tech Investment Co. Ltd., Hong Kong
 - e) Hangzhou ECI Telecommunications Co. Ltd., China PR
 - f) ECI Telecom Co. Ltd. Israel
 - g) Alcatel Lucent Shanghai Bell Co. Ltd.
- (vii) The Market Economy Treatment (MET) questionnaire was also forwarded to the known producers/exporters in China PR and the embassy of China PR in India with the request to provide relevant information to the Authority within the prescribed time limit. The following producers/exporters from the subject countries filed MET questionnaire response:
 - a) Huawei Technologies Co. Ltd., China PR
 - b) Hangzhou ECI Telecommunications Co. Ltd., China PR
 - c) Alcatel Lucent Shanghai Bell Co. Ltd.

- (viii) The questionnaires were sent to the following known importers/users/associations of subject goods in India, calling for necessary information, in accordance with the Rules:
- a) Aircel Limited
 - b) Prithvi Information System
 - c) Dishnet Wireless Limited
 - d) Punjab Communications Limited
 - e) Bharati Airtel Limited
 - f) HTL GST
 - g) Bharat Sanchar Nigam Limited
 - h) Huawei Telecommunications (India) Co. Pvt. Ltd. (Huawei India)
 - i) Tata Teleservices Limited
 - j) ZTE India
 - k) Tata Teleservices (Maharashtra) Limited
 - l) ECI India
 - m) Idea Cellular Limited
 - n) Alcatel Lucent
 - o) Vodafone Essar Limited
 - p) Nokia Siemens Networks
 - q) Railtel Corporation of India Limited
 - r) Ericsson
 - s) Tata Communications
 - t) Himachal Futuristic Communications
 - u) Reliance Communications Limited
 - v) ICOMM
 - w) Shyam Telelinks
 - x) Vuppalamritha Magnetic Components Ltd, Hyderabad
- (ix) In response to the above notification, importers questionnaire response has been filed by the following:
- a) Huawei Telecommunications (India) Co. Pvt. Ltd.
 - b) M/s Alcatel-Lucent India Ltd.
 - c) ECI Telecom India Pvt Ltd.
- (x) Further, Huawei Technologies Co. Ltd., Huawei Telecommunications (India) Co. Pvt. Ltd., Huawei Tech Investment Co. Ltd. and Huawei International PTE Ltd. have filed combined legal submissions on the initiation.
- (xi) Legal submissions have also been filed on the initiation by the Association of Unified Telecom Service Providers of India & Cellular Operators Association of India, New Delhi and Telecom Equipment Manufacturers Association of India.
- (xii) The period of investigation for the purpose of the present review is April, 2013 to June, 2014. However, injury analysis covered the periods April, 2010-March, 2011, April, 2011-March, 2012, April, 2012-March, 2013 and the POI.
- (xiii) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange for details of transaction wise imports data of the subject goods for the past three years, including the period of investigations, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DGCI&S imports data for computation of the volume and value of imports.
- (xiv) The Authority has examined the information furnished by the domestic producer to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject

goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

- (xv) In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in an oral hearing held on 18th September, 2015. The following, who presented their views in oral hearing, filed their written submissions of the views expressed orally:
 - a) Huawei Group companies
 - b) Alcatel-Lucent Shanghai Bell Group companies
 - c) ECI Group companies
 - d) Idea Cellular Ltd.
 - d) Fibcom India Ltd.
 - e) Association of Unified Telecom Service Providers of India and Cellular Operators Association of India, New Delhi.
 - f) Telecom System Design & Manufacturers Association and Telecom Equipment & Services Export Promotion Council.
 - g) ZTE Corporation Ltd.
 - h) Tejas Networks Ltd.
- (xvi) The submissions made by the interested parties during the course of this investigation have been considered by the Authority, wherever found relevant, in this investigation.
- (xvii) The verification of the information and data submitted by the domestic industry and the responding exporters was carried out to the extent deemed necessary.
- (xviii) The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- (xix) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.
- (xx) At the request of the Authority, the Central Government granted extension of time upto 05.03.2016 for completing the investigation and notifying the final findings.
- (xxi) A Disclosure Statement containing the essential facts in this investigation which would have formed the basis of the Final Findings was issued to the interested parties on 18.01.2016. The post Disclosure Statement submissions were received from the domestic industry and opposing interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this Final Findings Notification.
- (xxii) *** in this Final Findings Notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- (xxiii) The average exchange rate of 1US\$ = Rs. 60.77 prevailing during the POI has been adopted by the Authority in this investigation.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

- 8. The product under consideration as defined below the duty table in the original Final Findings Notification No. 14/2/2009 dated 19th October, 2010 read with Corrigendum No 14/2/2009 dated 22nd October, 2010 and further read with Final Findings Notification No. 14/2/2009 dated 10th February, 2012, was as under:

***Note 1. The product under consideration will include "Synchronous Digital Hierarchy transmission equipment, viz. STM-1, STM-4, STM-16, STM-64, STM-256 in assembled, CKD, SKD form, its assemblies and sub-assemblies or fitted with eventual broadband / cellular equipment. Product under consideration will also include Add Drop Multiplexers (ADM) (For SDH Application only), Multiple Add Drop Multiplexers (MADM) (For SDH Application only), and Digital Cross Connect (DXC) (For SDH Application only), Populated Circuit Boards (For SDH Application Only) and parts / components imported as a part of equipment, so long they are imported along with the equipment or its assemblies / subassemblies. The Product under consideration will also include Software meant for SDH, which is an integral part of these equipments, which may be bought either as a*

part of the equipment or separately. However components/ parts imported on a standalone basis are outside the purview of Product under Consideration

***Note 2. SDH Equipment essentially transmits signals through the medium of Optical Fibre. There may be SDH equipment meant for transmission through electrical Copper Medium or Microwave Radio Medium. The SDH Equipment transmitting the data through optical fibre alone shall be subject to levy of antidumping duty.*

***Note 3. When SDH is imported as a part of eventual broadband /cellular equipment, the AD Duty shall be payable only on the SDH portion of the imports. Similarly when eventual Broadband /Cellular equipment is imported as a part of the SDH equipment, the AD Duty shall be payable only on the SDH portion of the imports.*

***Note 4 PDH, CWDM, DWDM, Microwave systems, GPON, DSLAM, MSAN, BITS, Routers, PDSN, SGSN, MGW, BTS, BSC, MSC, ONT, HLR, HSS and MRP being non-SDH in any of its form are outside the scope of PUC and therefore not subject to levy of AD Duty.*

***Note 5. Microwave Radio Terminals which could have an STM-1 interface to the SDH transmission equipment and act as a physical media to enable the connectivity between the radio and the SDH equipment are outside the purview of payment of AD Duty*

C.1 Submissions made by the Domestic Industry

9. The following submissions have been made by the domestic industry (DI) with regard to product under consideration and its scope:
 - i. The product under consideration in the present petition is “Synchronous Digital Hierarchy transmission equipment, its accessories, associated software and its essential parts & components, in assembled, CKD, SKD form or fitted with eventual broadband/cellular equipment”.
 - ii. SDH transmission equipments are also known as multiplexers, Add Drop Multiplexers (ADM), Multiple Add Drop Multiplexer (MADM), digital cross-connects. Populated PCBs, Power supply, Lasers, Chassis and software meant for SDH transmission equipment, etc. consist of essential parts of a SDH transmission equipments and are within the scope of the product under consideration provided the said components are meant for SDH transmission equipment application only.
 - iii. SDH transmission equipments can be bought either as transmission equipments or forming part of another equipment, e.g., broadband and/or cellular (both GSM and CDMA) equipment. SDH transmission equipments forming part of broadband and/or cellular equipments are also within the scope of the product under consideration.
 - iv. Product under consideration is an assembly of a number of electronic components and/or electronic printed circuit boards, which are designed to perform the specific intended function of multiplexing for combined lower speed signals into high-speed signals for transmission through optical fiber over distances (short or long). Since, among other applications, these are installed at Base Transmission Stations, switch exchanges and other point of presence, SDH equipments installed at different locations may differ in terms of the associated properties.
 - v. Different SDH equipment are comparable in term of essential product characteristics including physical and optical, production technology, manufacturing process, R&D development, software capabilities, functions and usage, etc. Accordingly, various SDH equipments are one like product for the purpose of present investigation.
 - vi. The product under consideration can be imported either as complete equipment, or in CKD, SKD or even component form. Further, a number of accessories are required for connecting/installing SDH transmission equipment in the network (E1 cables, PCM cables, power cables, racks, workstations, etc.). Software is an integral part of these equipments, which may be bought either as a part of the equipment or separately. These all are also within the scope of the product under consideration.
 - vii. The key effort involved in the production of the subject goods is in the development of technology. Substantial research & development efforts are put in by the producers globally in design & development of the subject goods, the extent of which may be gauged by the fact that about 60% of the manpower deployed is in design & development of the product under consideration.
 - viii. The core of production is in technology, know-how, design and development of the product. The actual process of manufacturing is, in fact, a much smaller part of the total activity involved in the production and supply of subject goods and comprises complex assembling of a large number of components on a PCB (populated PCBs) and then assembling and testing them as finished products.
 - ix. The production in the present product is an activity comprising design and development of complex hardware, embedded software and network management software as well as the final assembly and testing of the finished product. The petitioner, the producers in subject countries and other global players, all undertake combination of all these activities.

- x. The production process can be divided into the fifteen step criteria mentioned in the original Final Findings.
- xi. Any consumer of the product insists on a combination of all the above before placing orders on any party. Further, some of the consumers in India insist on sales & support being extended by someone from India. Therefore, the producers in subject countries have set up their own/related enterprises in India in order to provide sales and support services.
- xii. The design and development of the subject goods involves significant amount of resources on research and development. The petitioner has developed significant amount of intellectual property over the years. In similar fashion, the foreign producers have also developed significant amount of intellectual property over the years.
- xiii. The petitioner and major global players in this industry outsource a significant part of component manufacturing to specialized producers (Electronic Contract Manufacturers). These companies, who undertake a significant part of component manufacturing activities, are, however, mere job processors, having no knowledge whatsoever about the technology and design & development involved in the product. These job processors lack the knowledge of intellectual property required in production of the subject goods.
- xiv. The Indian Rules and WTO Agreement of Antidumping do not prescribe anything with regard to scope of the product under consideration, nor have these prescribed the parameters that should be considered for describing/ specifying the product under consideration.
- xv. The petitioner researched upon a large number of cases investigated by India, EC and the US in support of its claim of scope of product under consideration. These include decisions of the US ITC in the matters of Certain Tow-Behind Lawn Groomers and Parts Thereof from China PR; Diamond Sawblades and Parts Thereof From China PR and Korea; Gray Portland Cement and Cement Clinker From Japan; Hand Trucks and Certain Parts Thereof From China PR; Large Newspaper Printing Presses and Components Thereof, whether Assembled or Unassembled from Japan and Mechanical transfer presses from Japan. Further, the petitioner referred to decisions of the EC in the matters of Ironing boards, Steel tube and pipe fittings, Compact Disc Players (CDP).
- xvi. "SDH equipment" includes products in its various forms, different names and supplied in different forms. Multiplexers, Add Drop Multiplexers (ADM), Multiple Add Drop Multiplexer (MADM), digital cross-connects are different names of the same product. Populated PCBs, Power supply, Lasers, Chassis and software meant for SDH transmission equipment are various sub-set of the product.
- xvii. The product can be supplied in assembled form or broken into these various sub-sets of the product. An exporter can export either the finished ready to use equipment, or in sub-assembly, cards, CKD/SKD conditions and carry out the remaining operations in India (involving negligible value addition). Further, the product can be produced and supplied in various sizes to meet specific customer requirement.
- xviii. The way SDH equipment is produced and used and the jurisprudence emerging out of various cases investigated by various investigating authorities establish that the scope of the product under consideration is not wide in the present case. Further, inclusion of parts/components is fully justified, considering the production activities relating to the product under consideration.
- xix. The petitioner has sought imposition of anti-dumping duties only on parts/ components for SDH application.
- xx. The petitioner has referred to the decision of EC in the matter of fasteners and argued that the fact of no production of some particular component/part of the product does not disqualify a company from seeking protection on the product. The domestic industry should be engaged in production of the product and is not required to be offering parts of the product in the market.
- xxi. The petitioner has sought inclusion of parts and components as (a) these are specifically designed for production of SDH equipments, (b) these have no other application but for production of the product, (c) production of the product from the stage of parts/components/assemblies/sub-assemblies involves only a screw driver technology and, therefore, exclusion of these from the scope would imply permitting imports of these at dumped prices, which would lead to continued dumping and injury in spite of imposition of anti dumping duties. The domestic industry also raised a question that if anti-dumping duties on product under consideration is justified, why imports of such items should be permitted and why such imports would not cause injury to the domestic industry. The domestic industry has also contended that the Authority can specify that such duty on parts, components, sub-assemblies can be implemented on declaration basis and the same can be specified in the relevant customs notification as well.
- xxii. DWDM Multiplexors and PDH multiplexors are different products. The Authority may specifically clarify the same to eliminate all doubts unnecessarily created by some interested parties. Further, the Authority may consider such other arguments of opposing parties with regard to appropriate descriptions and clarify the same in the final findings in order to ensure clarity at the time of implementation of the duty.
- xxiii. It is well settled law that the product description remains dispositive and customs classifications are given only

for convenience. Merely because import of a product has been reported under a classification specified under an anti dumping duty notification, the same does not imply that anti dumping duty would be charged on the same.

- xxiv. With regard to claims of the interested parties to specifically exclude certain products, the domestic industry has claimed as follows –
- i. STM-1, 4, 16 - There is no dispute for inclusion of these types.
 - ii. STM-64 - The domestic industry has produced and supplied these. The claim is without basis. The company produces STM-64 which are also DXC. The mere fact that Tejas did not bid in a specific tender for a specific product type for a specific customer doesn't mean that the company does not produce the particular product. Non participating in a particular tender does not imply that the company is not manufacturing the particular product.
 - iii. STM-256 - There is no requirement so far for STM-256 in India. STM-256 is nothing but SDH equipment. None of the consumers has deployed STM-256 and also there is no approved specification (TEC GR) for STM-256 system. A product can be produced only if demand/requirement for the same exists. It is understood that none of the telecom operators in India has deployed any STM-256 system and even worldwide only very few telecom operators have deployed STM-256 in their network. Tejas has already made significant R&D investments in developing STM-256 technology and Tejas can provide STM-256 capabilities on its systems, as and when required.
 - iv. Multiplexers - Multiplexers is a broad term. SDH equipments also have multiplexers. Domestic industry has produced and supplied these. These have been imported in India. The Authority may, however, clarify that only SDH multiplexers are within the scope of the product under consideration
 - v. DWDM - These are not SDH equipments and are beyond the scope of product under consideration. The interested parties have sought this exclusion only to confuse the Authority.
 - vi. Parts & components of SDH equipments - These cannot be excluded.
- xxv. The eventual consumers are interchangeably consuming goods supplied by domestic and foreign producers. All major telecom service providers in India like BSNL, Bharti, Aircel are buying Huawei product and Tejas product and that too for the same network, same application and against the same specification.
- xxvi. Multiplexers or other equipments operating on DWDM technology are not covered under the PUC. The petitioner supplies SDH multiplexer or DXC.
- xxvii. Tejas manufactures both SDH products and carrier Ethernet products. Tejas will pay the applicable duty if it will source dual usage components for SDH use and if the same is within the product scope. The petition is only in respect of one article, albeit in its various forms. The rules nowhere prevent inclusion of different forms of an article within the scope of the product under consideration. There may hardly be any investigation conducted so far wherein product under consideration did not have multiple forms.
- xxviii. SDH equipment, accessories, associated software, parts and components, Populated PCBs, Power supply, lasers, Chassis, EI cables, PCM cables, power cables, racks, collectively form an SDH equipment (excluding work stations). Individually, none of these have any end use. For example, a tube light requires a tube, a choke, a starter and a base. It cannot be said that each of these four items are different articles, merely because they have their own distinguished character.
- xxix. The requirements of rule 5 are to be satisfied in respect of product under consideration and not individual forms of the product under consideration. The product under consideration is SDH transmission equipment. When the "different technology equipment" is imported with "SDH-1 interfaces", then duties will not be imposed on the full value of "different technology equipment" but only on the parts related with SDH-1 technology.

C.2 Submissions made by exporters/importers/ users/other interested parties

10. With regard to the product under consideration and its scope, the following submissions have been made by the exporters/importers/users/other interested parties:
 - (i) There is a mismatch in the product scope proposed by the domestic industry and the product scope based on which the present initiation has taken place and, therefore, does not account for a "Duly Substantiated Request". In a sunset review, the product scope ought to remain the same as the original investigation. The domestic industry has requested for a sunset review on a product scope which is much wider than the product under consideration on which duties are presently applicable. However, if the initiation has taken place based on the above petition itself, then the present initiation is in contravention of the requirements of the Anti-dumping Rules, particularly because the present Petition is for a different product scope and, therefore, does not account for a "Duly Substantiated Request". It is critical to note that any continuation of duties cannot take place for a different product scope as compared to the product scope in the original investigation. The

Designated Authority, being a quasi-judicial authority, cannot deviate from its earlier decisions and is bound to follow its earlier decisions for consistency and predictability. The Authority in the past as a practice held that product scope cannot be enlarged in reviews.

- (ii) The scope of PUC cannot be expanded at the time of sunset review and no new product can be brought within its scope. The alleged domestic industry has demanded the expansion of the PUC by way of inclusion of Printed Circuit Boards which are also called as Bare Boards. Printed Circuit Boards are being imported by the alleged domestic industry itself from the subject country (China) as per the original final findings.
- (iii) The Applicant should disclose transaction wise information including description and volume of imports made by them so that the other interested parties would also get a chance to see whether the imports made by the Applicant are that of PUC or not. In absence of the same, the Authority should not accept the uncorroborated claims of the Applicant.
- (iv) The Applicant neither manufactures STM 64 and STM 256 nor sells these products. Therefore, it cannot be alleged by the Applicant that it is suffering injury on account of imports of these products. DGAD should not continue with these incorrect and illegal inclusion within the scope of PUC.
- (v) The alleged DI had claimed in the original investigation that it had provided STM-64 in commercial quantities to BSNL. DI has never participated in any tender process for STM-64 till date. The same has been confirmed by BSNL vide letter dated 17.10.2009. Accordingly, there arises no question of commercial supply of STM-64 to BSNL by the alleged DI. The DGAD, in the final findings, changed its stand and claimed that during the on the spot verification, it was found that such product had been supplied in commercial quantities to Quicktel (and not BSNL). No entity by the name of Quicktel had obtained orders from BSNL. Therefore, it is submitted that the claim of the alleged DI in this regard is absolutely false and malicious.
- (vi) The alleged domestic industry has never entered the Indian domestic market for STM-256. STM-256 has never been imported into India and moreover, the technical approvals/permissions for the deployment of STM-256 are not yet in place in India. When this basic condition has not been met, the question of inclusion of STM-256 within the PUC and thereby imposition of ADD does not arise.
- (vii) Further, STM-1, 4, 16, 64 and 256 etc. are substantially different articles, as per own admission by the Applicant in the Petition. Therefore, these products should not have been clubbed together under a broad category of PUC by the Applicant in its Petition. STM-256 is neither imported into India nor is it deployed in India. Therefore, it would not be fair to include STM-256 within the scope of PUC.
- (viii) STM-Interface may be there in other telecom equipments also and these STM Interface need not only be STM-1 Interface. Therefore, any product other than SDH having STM Interface to SDH transmission equipment and acting as physical media to enable connectivity between the radio and SDH equipment must be outside the purview of PUC.
- (ix) The PUC manufactured by the Applicant does not have the same physical and technical characteristics. The technology used by the Applicant is obsolete and it supplied low end SDH equipment whereas exporters from outside India manufacture all categories of transmission equipment, which can be managed in a single Network Management System (NMS) or Operations Support System (OSS).
- (x) Certain products have been wrongly included within the ambit of PUC by the Applicant after publication of Final Finding without affording an opportunity to us to be heard. As also mentioned in the Petition, SDH is based upon standard ITU-T Standard No. G 707. Therefore, it is requested to specifically exclude OTN from the scope of PUC since it is neither SDH product nor based upon ITU-T Standard No. G 707 which is meant for SDH but due to non specific exclusion of the same from the PUC, it is causing confusion among the custom authorities.
- (xi) PTN was originally mentioned in the exclusion list as per Note 4 of the Final Findings dated 16.10.2010, but later through amendment, it was removed from the exclusion list causing confusion thereby. It is submitted that this was done unilaterally without affording us an opportunity of being heard. PTN was neither a part of the original investigation, nor was covered under the PCN devised. PTN is not an SDH equipment and, therefore, it is/was not covered under PUC and hence appropriate clarification should be issued by the Authority at the earliest in this regard to avoid confusion and unnecessary litigations and delays in clearance of our products.
- (xii) Further, the present request of the Applicant to include Printed Circuit Boards (PCBs) within the scope of PUC on the ground that PCBs are being imported in increased quantities for manufacture of PCBAs and to avoid payment of anti-dumping duty is unwarranted. It is submitted that it is an admitted fact by the Applicant in the Preliminary Findings in the Final Findings in the original investigation that the Applicant itself imports PCBs from China and the Applicant has raised this point to put undue pressure upon the DGAD so that its

attention is diverted from the point that PCBAs (Populated Circuit Board Assemblies), which are not being manufactured by the Applicant, remain within the scope of PUC.

- (xiii) Further, despite the customs notification no. 125/2010 dated 16/12/2010 clearly stating in regard to the Populated Circuit Board Assemblies that they should be for SDH application only; and only when they are imported along with the equipment or its assemblies or subassemblies, still the customs authorities have gone ahead and demanded duty on such PCBAs, even when they are not being imported along with the SDH transmission equipment.
- (xiv) Classification of PCNs cannot reflect the characteristics of the product concerned. PCN serves fair comparison purposes in an anti-dumping investigation by classifying the PUC into numerous sub-categories, which is needed essentially to reflect cost and price differences among each of the specified PCN. However, the accounting system, sales of activities, costing structure and management of a company are not set up on the basis of PCN because a company that is engaged in the production of the PUC is interested in gaining overall profits along with the progress of installation of the concerned equipment into proper operation.
- (xv) There is lack of clarity in the present investigation with regard to the inclusion of components. The Authority should clarify that the present scope includes only full SDH products and not components. If indeed components are included, then the Authority may clarify that only components exclusively used for SDH are part of the product scope.
- (xvi) DXC has been erroneously included in the PUC on the ground that it is an SDH transmission equipment. DXC is not an SDH transmission equipment. It has a different functionality vis-à-vis an SDH transmission equipment. While an SDH transmission equipment is used for multiplexing and transport applications, DXC is used for traffic grooming and switching functions. The domestic industry had sought protection against SDH transmission equipment. However, the PUC has erroneously included in it a switching equipment also. While every STM equipment will have some digital cross connect functions, DXC is a specific device designed to perform cross connect functions only. Accordingly, it is submitted that DXC is not an SDH transmission equipments. While an SDH transmission equipment is used for multiplexing and transport applications, DXC is used for traffic grooming and switching functions. Without prejudice to the aforementioned, it is submitted that the alleged DI had sought protection against SDH transmission equipment, the PUC has erroneously included in it a switching equipment also. On the basis of the aforementioned, it is submitted that DXC ought to be kept outside the scope of PUC in as much as it is not an SDH transmission equipment and the ADD levy is only to be restricted to SDH.
- (xvii) The description of the product under consideration is far from providing any clarity for customs purposes. It is, therefore, requested to the DGAD that the scope of PUC be very precise stating technical specifications, so that there is no scope of ambiguity in interpreting the PUC by the customs authorities. It may kindly be laid down that neither the equipment OTN nor DWDM, which are different technology than SDH, nor the cards, PCBs used therein resulting in a non-SDH output, can be considered to be the PUC.
- (xviii) The claim of the petitioner that SDH equipment imported into India in component form in different baskets cannot be excluded from the scope of the product under consideration is without merit. The components and parts which are not imported along with the equipment / its assemblies / sub-assemblies or are imported on a standalone basis are outside the scope of the investigation. Therefore, it is requested to clarify the product scope.
- (xix) The customs department is collecting anti-dumping duties even on components / parts imported on a standalone basis and other products which are outside the purview of Product under Consideration. Therefore, it is requested to clarify the product scope so that the interested parties do not have to suffer the undue hardship in the form of payment of the anti-dumping duties even on those products which are outside the scope of this investigation in case the Authority decides to extend the duties in force.
- (xx) It is further submitted that the SDH capacity of DI accepted by them of the cross connect only extends to a maximum of 320g for STM-64. On perusal of relevant products of alleged DI (TJ1400, TJ1600, TJ1400 PTN, TJ1600 PTN, TJ1100, TJ1270, TJ1100ME, TJ1500, TJ1600, TJ2031, TJ2051, TJ5500) available in their website it is observed that they have not developed higher technology such as 1000g as claimed. If DI had achieved such a technical advancement it would have mentioned the same in its website. The alleged DI has not shared relevant details/ information on their capabilities except a public statement during the PH and nothing is available in the public domain including in their website to substantiate their claim. The claim of alleged DI in this regard vis-à-vis customer supply evidence may be verified by the DGAD.
- (xxi) Therefore, it is clear that even for SDH application where the requirement is of 1.2 TB, i.e., including any equipment beyond 320g, obviously the domestic industry is not in a position to supply such equipment and such equipment for this reason itself have to be kept outside the purview of imposition of any ADD. Thus, even if the equipment is of SDH specification in the example cited, the same cannot invite ADD. Similarly,

having regard to the maximum cross connect capacity made available by DI for STM-1, STM-4 and STM-16, there should be ADD restricted to only such cross connect capacities irrespective of the baseless claims of the alleged DI. Regard should be paid to the factual position that DI is not even known for higher speed and it has even admitted to the same to the customers.

- (xxii) It is submitted that if any of the items are imported not for SDH application, such items cannot be subjected to anti-dumping duty under the notification 125/2010 – Custom dated 16/12/2010. However, owing to the ambiguous definition of the PUC, it has been seen that the customs authorities have gone way beyond in interpreting the definition of product under consideration and have even assumed the goods falling under the OTN and DWDM category to be covered within the scope of PUC. For instance, the customs authorities has issued show cause notices to the interested parties in regard to the OSN 9500, the cards which are used for DWDM output, as to why ADD should not be paid on them.
- (xxiii) There is a duty demand also on certain imports which include coloured OTN line cards which support line rates different from STM 64 based on G. 707. Thus, even if the equipment imported are designed to support OTN line rates based on G. 709 and coloured interfaces based on G. 694, which being non SDH and clearly outside coverage of ADD, the customs authorities have still endeavored to levy duty on them.
- (xxiv) As it has already been acknowledged by note no. 5 of the operating part of the final findings that microwave radio terminals having an STM-1 interface to the SDH transmission equipment and act as a physical media to enable the connectivity between the radio and the SDH equipment are outside the purview of ADD, similar clarification may be issued in the course of these proceedings to the effect that the interfaces which are not specific to the SDH equipment should not form a part of the PUC, e.g., Routers, OTN, DWDM, CWDM, MS-OTN, PTN, Switches, MPLS, MPLS-TP, GPON, DSLAM, MSAN, BITS, DLC, BSC, MSC, SGSN, GGSN, PDSN, HLR, HSS, MRP, MGW, Microwave, etc. or any other telecom equipment other than SDH having any kind of STM interface such as STM-1, 4, 16, 64 and 256 meant to connect to act as a physical media to enable the connectivity between aforesaid products and SDH equipment are outside the purview of ADD, since in the past due to lack of appropriate clarification, litigation has resulted.
- (xxv) There is also a stand taken in the show cause notices to the interested parties that the cards themselves are to be regarded as SDH equipment which is fundamentally wrong.
- (xxvi) Further despite the customs notification 125/2010 dated 16/12/2010 clearly stating in regard to the Populated Circuit Board Assemblies that they should be for SDH application only; and only when they are imported along with the equipment or its assemblies or subassemblies, still the customs authorities have gone ahead and demanded duty on such PCBAs, even when they are not being imported along with the SDH transmission equipment.
- (xxvii) It may please be appreciated that the current notification regarding imposition of ADD on SDH transmission equipment, has resulted in the levy of ADD on SDH technology rather than SDH product per se. It is pertinent that in order to remove all ambiguities the PUC also needs to be clearly defined to remove even an iota of doubt. The scheme of taxation under customs is based on classification of products rather than technology. Hence, the necessity to define the product precisely and not by way of technology.
- (xxviii) The ADD is not required to be paid whenever SDH equipment is being imported on the items, e.g., power cables, chassis, patch cords, connectors, rack, etc. since these are regarded as accessories. Consequently, when the DWDM/OTN etc. technology equipment are imported, any attempts on the part of the customs department to levy ADD on the specious reasoning that some interfaces have SDH technology therein may kindly be discountenanced and deprecated severely by the authority for the reasons that the items imported are geared to a totally different technology and no part of it can be subjected to ADD for the reasons that such equipment do not fall under that heading 851762 covering SDH equipment and also for the reason the interfaces in these equipment can never be said to be for SDH application only which is the paramount criteria for levying ADD. Even as per the general interpretative rules to the CTA, the essential character of the entire DWDM/OTN equipment including its constituents is only attributable as DWDM/OTN and for this reason also no part of the DWDM/OTN equipment can be subjected to ADD as representing SDH technology.

C.3 Examination by the Authority

11. A number of interested parties have disputed the scope of the product under consideration on a number of grounds. Since the present investigation is for sunset review of the anti dumping duty already levied, the scope of the product under consideration should normally remain the same as that of the original investigation. However, some of the interested parties have vehemently disputed inclusion of certain types of products under the category of the "Product Under Consideration" or the "Subject Goods" and sought certain clarification on the product scope as also exclusion of some product types. The Authority notes that the majority of these submissions are repetition of what was claimed earlier during the course of the original investigation and nothing new in the form of hard evidence has been provided to the Authority by the opposing interested parties

to change the product scope in the present sunset review investigation. The main issues raised by the opposing interested parties, though already settled, are still examined as follows:

- a. STM-64: The petitioner Tejas Network has produced and sold STM-64 in the Indian and overseas markets as was verified by the Authority. STM 64, therefore, will not be excluded from the product scope and it will remain part of the PUC.
- b. STM-256: Admittedly, STM-256 has neither been imported during the period of investigation in the sunset review investigation nor supplied by the domestic industry. In fact, the interested parties agreed that technical approvals/permissions to deploy SDH-256 are not even in place in the country. The Authority, however, observes that a claim for exclusion of a particular type cannot be entertained unless the same has been exported to India during the relevant period, as the fact of non supply of the like article by the domestic industry cannot be established unless the type is exported to India. The Authority, therefore, holds that no grounds have been made out in the present sunset review investigation justifying exclusion of STM- 256 from the product scope.
- c. PTN: Regarding the claim of the opposing interested parties that SDH and PTN are completely different technologies serving different needs and thus PTN be kept out of the scope of the Product Under Consideration in the sunset review investigation, the Authority notes that this issue has already been settled in the earlier Final Finding and the present investigation being the sunset review investigation, the Authority will retain the Note 4 in the Duty Table as it was in the Final Findings Notification No. 14/2/2009-DGAD dated 19th October, 2010, read with Corrigendum No 14/2/2009 dated 22nd October, 2010 and further read with Final Findings Notification No 14/2/2009 dated 10th February, 2012.
- d. Digital Cross Connects (DXC): The interested parties have argued for exclusion of digital cross connect. It has been stated in the previous findings that the investigation has shown that digital cross connect are actually the equipment used in telecommunications networks that allows lower-level signals to be rearranged and interconnected among higher-level signals. Digital cross connect can be produced in SDH technology and other technologies. Digital cross connect equipment of SDH technology is clearly SDH equipment. Digital cross connect of SDH technology has been produced and supplied by the petitioner during the investigation period. The cost and price information included in the injury information and injury margin assessment includes the production and sale of digital cross connect of SDH technology. The Authority, therefore, holds that digital cross connect of SDH technology are rightly within the scope of the product under consideration. However, since digital cross connects are produced in other technologies as well, it is clarified again that digital cross connect of other technologies are beyond the purview of the product under consideration and the present sunset review investigation.
- e. Parts and Components: The petitioner has again sought inclusion of parts and components claiming that (a) these are specifically designed for production of SDH equipments, (b) these have no other application but for production of the product under consideration, (c) production of the product from the stage of parts/components/assemblies/sub-assemblies involves only a screw driver technology and, therefore, exclusion of these from the scope would imply permitting imports of these at dumped prices, which would lead to continued dumping and injury in spite of imposition of anti dumping duties. The domestic industry also raised a question that if anti-dumping duties on product under consideration is justified, why imports of such items should be permitted and why such imports would not cause injury to the domestic industry. In this regard, the Authority holds that the issue of non-inclusion of imports of stand-alone parts and components in the scope of the PUC has already been settled in the original investigation and the domestic industry has not provided any evidence justifying inclusion of imports of stand-alone parts and components in the scope of the PUC. The Authority, therefore, reiterates its stand in the present sunset review investigation that parts and components imported on stand-alone basis are outside the scope of the product under consideration.
- f. The domestic industry has also demanded the expansion of the PUC by way of inclusion of Printed Circuit Boards, which are also called Bare Boards. The Authority notes that the Printed Circuit Boards fall in the category of parts and components only. Further, it is a settled position in the original final findings that Printed Circuit Boards have been imported by the domestic industry itself from one of the subject countries, viz., China PR. If the domestic industry has not imported Printed Circuit Boards during the period of investigation of the present sunset review investigation, it cannot turnaround and claim that now their nature has changed and thus these should be included in the PUC. The Authority, therefore, reiterates its stand that Printed Circuit Boards imported on stand-alone basis are outside the scope of the product under consideration.

- g. As regards the clarifications sought in the product scope, the Authority has addressed all the concerns on inclusions and exclusions from the product scope in the previous findings and the Authority notes that the product under consideration in all its forms as provided in the original Final Findings Notification No 14/2/2009 dated 19th October, 2010 read with Corrigendum No 14/2/2009 dated 22nd October, 2010 and further read with Final Findings Notification No 14/2/2009 dated 10th February, 2012, is subject to present investigation.
- h. The product under consideration is classified under Chapter 85 of the Customs Tariff Act, 1975. It is further classified under the heading 851762 and 851770 of schedule-I of Custom Tariff Act as per Indian Trade Classification. The classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.
12. Rule 2(d) with regard to “like article” provides as under: -
- “like article” means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation”.
13. The Applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods produced by the applicant and exported from the subject countries. The subject goods produced by the applicant and imported from subject countries are having comparable characteristics in terms of parameters such as product characteristics including physical and optical, production technology, manufacturing process, R&D, software capabilities, functions and usage, etc.
14. The present application filed is for the review, continuation and enhancement of the quantum of the anti-dumping duty in force, and the issue of like article has been already dealt with in the previous investigations. In the earlier investigation, the Authority has already held that the subject goods produced by the domestic industry is like article to the subject goods imported from the subject countries and no new evidence has been provided by the opposing interested parties in this investigation that the subject goods produced by the domestic industry are not like article to the subject goods imported from the subject countries.
15. Product Control Number (PCN) System: The product under consideration is produced and sold in a number of different types and variants. Different types and variants are produced to meet specific customer requirements. In order to ensure fair comparison between normal value and export price, the Authority has segregated the product under consideration into different types based on parameters such as transmission capacity; cross connect capacity, E1 interfaces, electrical interfaces, optical interfaces, optics types, etc. etc. The Authority evolved a product control system (PCN) running into 15 digits. In the original investigation, all interested parties were directed to provide information on cost and price separately for each PCN. Although some attempt at standardization of parameters has been made by evolving the PCN criteria, such products are by their very nature not amenable to standardization as they are completely non-standardized, made to suit the requirements of each network, functioning on a different frequency, contained diverse modules, the addition or deletion of which would lead to wide variation in costs and the costs were dependent on the interplay of technology, hardware and software used etc. Since the present investigation is the sunset review investigation, the basic PCN remain the same as were in the original investigation.
16. After examining the relevant submissions and claims of the domestic industry and the opposing interested parties, the Authority concludes that the product under consideration will remain as defined below the duty table in the original Final Findings Notification No 14/2/2009 dated 19th October, 2010 read with Corrigendum No 14/2/2009 dated 22nd October, 2010 and further read with Final Findings Notification No 14/2/2009 dated 10th February, 2012, i.e., as under:

***Note 1. The product under consideration will include “Synchronous Digital Hierarchy transmission equipment, viz., STM-1, STM-4, STM-16, STM-64, STM-256, in assembled, CKD, SKD form, its assemblies and sub-assemblies or fitted with eventual broadband / cellular equipment. Product under consideration will also include Add Drop Multiplexers (ADM) (For SDH Application only), Multiple Add Drop Multiplexers (MADM) (For SDH Application only), and Digital Cross Connect (DXC) (For SDH Application only), Populated Circuit Boards (For SDH Application Only) and parts / components imported as a part of equipment, so long they are imported along with the equipment or its assemblies / subassemblies. The Product under consideration will also include Software meant for SDH, which is an integral part of these equipments, which may be bought either as a part of the equipment or separately. However components/ parts imported on a standalone basis are outside the purview of Product under Consideration.*

***Note 2. SDH Equipment essentially transmits signals through the medium of Optical Fibre. There may be SDH equipment meant for transmission through electrical Copper Medium or Microwave Radio Medium. The SDH Equipment transmitting the data through optical fibre alone shall be subject to levy of antidumping duty.*

***Note 3. When SDH is imported as a part of eventual broadband / cellular equipment, the AD Duty shall be payable only on the SDH portion of the imports. Similarly, when eventual Broadband / Cellular equipment is imported as a part of the SDH equipment, the AD Duty shall be payable only on the SDH portion of the imports.*

***Note 4. PDH, CWDM, DWDM, Microwave systems, GPON, DSLAM, MSAN, BITS, Routers, PDSN, SGSN, MGW, BTS, BSC, MSC, ONT, HLR, HSS and MRP being non-SDH in any of its form are outside the scope of PUC and, therefore, not subject to levy of AD Duty.*

***Note 5. Microwave Radio Terminals which could have an STM-1 interface to the SDH transmission equipment and act as a physical media to enable the connectivity between the radio and the SDH equipment are outside the purview of payment of AD Duty.*

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.I Submissions made by the Exporters/Importers/ users/other Interested Parties

17. With regard to scope of the domestic industry and standing, following submissions have been made by the exporters/importers/users/other interested parties:
 - i. Huawei Telecommunications (India) Private Ltd. (Huawei India) has claimed that it is involved in the manufacturing of STM-1, STM-4, STM-16, STM-64, Add Drop Multiplexers for SDH Application, Multiple Add Drop Multiplexers for SDH Application, Digital Cross Connect for SDH Application and Populated Circuit Boards for SDH Application in India. The company has DTA Factory Manufacturing License for manufacturing telecommunication equipment including PUC and a Central Excise Registration Certificate has been issued to it. The Company has supplied SDH Equipment covered under PUC to customers in Indian market including Idea Cellular Limited, Sify Technologies Limited, Bharti Airtel Limited, Alstom T&D India Ltd, Dishnet Wireless Limited, Aircel Limited, Vodafone Cellular Limited among others.
 - ii. The Authority, in its Final Finding dated 19.10.2010 in the original investigation, arrived at the finding that there are 15 steps which constitute 'production' with respect to the PUC. Further, while a Company need not undertake each of these activities, it is possible that some of these steps might involve one or more sub-processes which might be carried out independently, or some of these processes may be integrated by some Company. Huawei India also stated that the company is producing the PUC at its plant site in Chennai where components are assembled and substantial transformation takes place for the manufacture of the PCBA.
 - iii. The development of software makes the Applicant Tejas Networks the producer of the software and not producer of the SDH equipment, which is produced using various components and software being only one of the inputs. These activities can best be considered to be activities related to manufacturing of SDH equipment and not manufacturing the SDH equipment itself.
 - iv. The Applicant Tejas Network should share the details of its Research & Development (R&D), i.e., is it for the manufacture of the PUC or other products, what is the cost, what is the real manufacturing cost by the Applicant which is the sole criteria etc., as it has been maintaining the stand that 60% of its manpower is engaged in the R&D and then itself is claiming that SDH product which was forming the part of the PUC has become obsolete technology.
 - v. The Applicant Tejas Network does not satisfy the criteria of standing under Rule 2(b) of the AD Rules. Even if the Applicant holds a major proportion of domestic production, it still does not meet the requirement of Rule 2(b) as it is an importer itself.
 - vi. Huawei India has made substantial investments in India during the last 4 to 5 years; satisfies the 15 production criteria listed as all the activities are being undertaken in India itself at their facility; has imported very few items falling under the scope of the subject product during the POI in the present sunset review investigation; essentially maintains a focus on domestic production itself and has become the biggest producer in India and this has been recognized by the DoT as well. Huawei India in fact was making profits in India in the same market where the Applicant has been claiming losses even after such high protection in the form of anti-dumping duties. The Authority is urged to re-examine the status of the domestic industry and clarify to all interested parties as to who is the actual domestic industry.
 - vii. The Authority should independently seek capacity and production data from other producers. Such data should also be provided to all interested parties for examination and comments. It is to be noted that none of the producers mentioned has expressed support for the petition.
 - viii. It is neither the intent of the WTO Agreement on Anti-Dumping nor of the Anti-Dumping Rules that a straight jacketed formula should be adopted while defining the "domestic industry", suiting the requirement and interpretation of the law by the Applicant and thereby render all other domestic producers, on one or other ground as per the demand of the Applicant, ineligible for the status of 'domestic industry'.

- ix. Huawei India, after the Final Findings in the original investigation, now undertakes the manufacturing of finished goods in India is a domestic producer and, therefore, it should not be treated as an importer of the PUC. The criterion adopted by the Applicant to classify domestic producer and importers of PUC is incorrect and contrary to the Anti-Dumping Rules.
- x. The Authority should treat Huawei India as a domestic producer and verify the locus standi of the Applicant as Domestic Industry and it should consider information submitted by Huawei India at the time of deriving non-injurious price.
- xi. On incorrect interpretation of the Domestic Industry, the Applicant has tried to classify Indian producers who manufacture the PUC by transforming the imported components into PUC as importers. Even the act of assembling imported components to get a final product which is different in nature from the assembled components would amount to the manufacture and the same proposition has even been admitted by the Authority in para 30 (ii) of the Final Findings.
- xii. The Applicant Tejas Network has original significant part of manufacturing PCBA to specialized Electronic Manufacturing Service (EMS) providers. This should have precluded the Applicant from forming part of the DI. There has been admission to this effect by the Applicant in the Annual Reports of 2007-08, in its petitions, in the Final Findings and various other filings of 2009 made by the Applicant.
- xiii. The Applicant Tejas Network is not engaged in the manufacture of PCBA as the activity of populating the PCBAs is not done by the Applicant and this activity is outsourced to Electronic Manufacturing Services (EMS). Furthermore, software is also embedded on PCBA through the EMS. The PCBAs are thus manufactured by EMS and not by the Applicant and, therefore, the requirement of the Rule 2(b) read with para 30 (ii) of the Final Findings are not being met.
- xiv. The criterion of R&D applied by the Applicant for determining the status of 'Domestic Industry' is erroneous and legitimate Indian producers such as those who purchased components and had them assembled for sales of the product concerned have been wrongly excluded. R&D is a part of periodical cost forming an integrated full cost of production of a given product. In some circumstances, the cost of R&D is capitalized until a product is being developed for commercial purposes, and then begins amortization.
- xv. The Authority contradicted itself in providing for R&D activity as parameter for deciding domestic producer status, while on the other hand rejecting the plea of IPR for determining Country of Origin in case of CIENA.
- xvi. The Anti-Dumping Rules do not recognize the expense towards R&D, IPR and technical know-how for the purpose of determining value addition and to determine the activity of manufacturing. In this regard reference may kindly be made to Rule 25. Therefore, post the original Final Findings, even the Anti-Dumping Rules have specifically excluded from its ambit the criteria of IPR, technical know-how etc., thus aligning the Anti-Dumping Rules with the other laws such as Excise Laws for the purpose of determining the process of manufacturing, test for which is to determine visible substantial transformation of the input into output. This also goes in line with Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules wherein it has been mandated that the Domestic Industry must be engaged in the manufacturing and other connected activities. Here no departure can be made to the requirement of the "manufacturing" in the guise of some other activities such as R&D, IPR etc.
- xvii. The activity of populating a printed circuit board amounts to manufacture as per CCE, Madras v Coromandal Electronics, reported as 1997(90)ELT443. It is the EMS who has to be treated as the manufacturer of the PCBAs which is used to assemble for final product i.e. SDH by the Applicant.
- xviii. The Applicant has cleverly considered itself and a few others as domestic producers and has simply regarded all other producers in India as importers.
- xix. There is no requirement under the AD Rules to meet the 15 point criteria to satisfy that a company is undertaking production in India. The domestic industry argued that research and development is the most important component out of the 15 criteria. However if the domestic industry's contention is accepted, many other foreign companies who have invested billions of dollars in India would fail to qualify as domestic producers.
- xx. For most of the modern manufacturing in India, technology is being utilised under "right to use" model or "technology transfer agreements". Merely because a company is not undertaking research and development in India or does not have IPRs in India, it cannot be said that such a company is not a producer in India.
- xxi. The facts in the present review have completely changed from the time of original investigation. Other producers are now undertaking substantial production activities in India and the Authority is urged to verify the same. Huawei India submits that the 15 criteria adopted by the Authority to construe who is a producer in India should be disregarded in the present review as such criteria have no legal basis.

- xxii. The Applicant Tejas Network, on page 81 of the petition, in its letter dated 5 September 2014, states that it has not imported the subject product. On page 82A of the petition, however, information about the Applicant's imports has been provided. It has to be clarified at the earliest what the Petitioner has imported. If the Applicant has imported the subject product, it does not qualify as domestic industry in the present review. The Designated Authority is, therefore, urged to direct the Applicant to disclose to interested parties its data on imports of the subject product. From industry sources and a letter by the association COAI dated 19 February 2015, it is understood that Petitioner is an importer of the subject product. Therefore, the Authority should terminate the present investigation.
- xxiii. There is no clarity on whether Huawei India is a part of the domestic industry or not. The analysis of the injury has to be in context to the domestic industry. This reasoning is affirmed by Rule 11 of the AD rules. Even if Huawei India is excluded from the scope of domestic industry, there must be immediate clarity on the issue and a clear determination must be made by the Authority at the earliest.
- xxiv. Huawei India is not merely a trading company but it has been undertaken Research and Development activities on a much larger scale than the Applicant and manufacturing activities too at substantial level. It is providing employment to approximately 5700 Indian employees and its investments in India are more than INR 1700 crore, carrying on its operations in India since the year 2000.
- xxv. Out of the list of 15 listed activities, the activities in the nature of 'soldering and EMS activity', 'integration', 'preparation of test jigs', 'assembly', 'testing' (i.e., all activities related to actual manufacturing) have been outsourced by the alleged DI to EMS (job workers) and only the R&D, product blue print and development activities have been under taken by the alleged DI on its own. The case of CIENA, wherein most of the 15 activities, including the complete R&D with respect to the products in question, have been undertaken by CIENA in USA, the Authority imposed anti-dumping duty on CIENA only on the ground that such products have originated from China. Applying the test laid down by the Authority in CIENNA's case, the alleged Domestic Industry which also imports PCBAs from China and/or other countries should be ousted from the definition of 'domestic industry', irrespective of the fact that R&D has been undertaken by it in India.
- xxvi. The petitioner is primarily engaged only in the ancillary activities connected with manufacture, i.e., research and development of product design, and not in the actual manufacture of the product under consideration. It is a settled principle of law that Printed Circuit Boards being made into PCBAs by addition of capacitors, transistors, resistors and other components amounts to manufacture. This principle has been upheld in CCE, Madras V. Coromandal Electronics [1997 (90) ELT 443]; CC, Goa V. D-link India Pvt. Ltd. [2014 (306) ELT 479 (Tri. – Mumbai)]
- xxvii. The intention of the legislature is also to exclude expenses incurred by the alleged domestic industry towards job work, while computing the non-injurious price. Such provisions are further indicative of the fact that for a producer to be considered as the domestic industry, it is pertinent for such producer to be engaged in the manufacture of the subject goods (PUC) by itself.
- xxviii. Since the alleged DI's contribution in the production is negligible, they clearly account for less than 25% of the total domestic production, and cannot claim injury.
- xxix. The alleged DI has claimed that the PCBAs manufactured by it are unique and the propriety of the alleged DI. It has also maintained that it imports such PCBAs (job work manufactured) from Thailand and Singapore. In this regard, it is requested that the country of origin reflected in the Bills of Entry for such imports of PCBAs from Thailand and Singapore be scrutinized.
- xxx. The alleged DI has itself admitted that the actual process of manufacturing is a much smaller part of their total activity, and the alleged DI is mainly focusing on Design and Development of the subject goods. It is their self-admission that about 60% of manpower deployed by them is in design and development of the product under consideration. The objective/ purpose of the R&D undertaken by the alleged DI is not clear as STM -256 has been developed by the overseas suppliers many years ago while the alleged DI is not known for anything beyond STM-1, 4 and 16.
- xxxi. There is no clarity as to the nature of such R&D activities undertaken by the Applicant Tejas Network. During the oral hearing held on 18.09.2015, the alleged DI admitted that there is not much scope of R&D left with regard to SDH transmission equipment. It is clear that the alleged DI is not engaged in R&D with respect to the PUC. If the alleged DI's R&D activities are not undertaken with respect to SDH transmission equipment, but some other products then the cost of such R&D ought to be regarded as irrelevant to the present review/investigation and thereby, kept out of the computation undertaken for the determination of injury margin for the alleged dumping in the present case.
- xxxii. It is further submitted that despite the fact that R&D has been undertaken by Fibcom outside India, during the oral submissions, the alleged DI has supported Fibcom's submission that it has undertaken the manufacture of the PUC in India, and accordingly, it ought to be included in the category of 'domestic industry'. In this regard,

it is submitted that similarly, Huawei India (one of the members of COAI) by the same logic, should also be considered as 'domestic industry'/domestic producer. Further, it is submitted that Huawei India set up its factory in 2010 and has commenced domestic production of the PUC from 2011 onwards after making substantial investments in India and has not turned itself merely into trading of the goods. Accordingly, Huawei India should also be included as one of the parties constituting the 'domestic industry'. Alleged Domestic Industry is attempting to gain monopoly in the market and forcing the consumer industry whose interests are much wider and directly connected to the public interest to buy obsolete and non-competing products of the alleged DI.

- xxxiii. The alleged domestic industry is of the view that the Authority had held in the final findings of the original investigation that only if an entity performed the above 15 steps in India, it would be regarded as a producer of the subject product in India. However, it is submitted that nowhere in those final findings is there any observation by the Authority. The domestic industry is incorrectly interpreting the final findings in the original investigations.
- xxxiv. Further, there is no legal requirement under the AD Rules that an entity must undertake the 15 steps mentioned above to become eligible to be a producer in India. Further, there is no requirement under the law that only if an entity performed research and development in India and had IPRs in India, it would be considered as a producer in India. Therefore, the domestic industry's arguments should be rejected.
- xxxv. Further, the domestic industry has relied on Ovum Reports to arrive at standing. It is submitted that Ovum Reports merely provide names of companies and their share in the market in value terms based on market information. Ovum Reports do not provide information on whether companies are domestically producing the subject product or importing the same. Therefore, Ovum Reports cannot be relied upon to determine standing in this case.

D.2 Submissions made by the Domestic Industry

- 18. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to standing and scope of the domestic industry:
 - i. The petitioner provided information which is adequate and accurate and the same clearly establishes that the petitioner's production constitute a major proportion in Indian production.
 - ii. Huawei India cannot be considered as domestic manufacturer under the rules.
 - iii. Indian producers are companies who are undertaking production activity in India and who need to import parts/components from various global sources, including the subject countries, just like import of raw materials any domestic industry would have found to have been doing in numerous investigations conducted by the Designated Authority. So long as these imports constitute imports of inputs, the petitioner does not have any grievance on such imports.
 - iv. Third country producers are companies such as Ciena. These companies might need to buy components from global sources, including subject countries. Further, these companies use EMS services located in China.
 - v. Chinese or Israel companies who are manufacturing SDH equipment must pay duties whether they supply finished SDH equipment or in SKD/CKD form or in component form. If these companies export SDH equipment in component form, the remaining input required for the production process is technical know-how (which is Chinese) and the soldering services (which is a screw driver technology). These companies can, therefore, easily import SDH equipment in components form following customs clearance procedure, while bringing technical know-how into the country without customs clearance.
 - vi. SDH equipment supplier - There are parties who are exporting SDH equipment to India in any of the forms well clarified in the final findings, admitting it as export of a product that falls within the scope of the product under consideration and paying appropriate ADD.
 - vii. The Petitioner had earlier established that activities carried out by the company constitute production and activities carried out by other companies such as Prithvi, Huawei and VMCL did not constitute production. The Petitioner had advanced number of arguments which were brought out by the Authority in the findings and are summarized below. Petitioner reiterated following submissions made by the Petitioner at the time of original investigation and referred to the final findings in the original investigation:
 - a) Meaning of production cannot be the same in all products. Production for the purpose of the present investigations shall imply that production activity which results in "production" of the "product under consideration". Further, the product is identifiable in terms of a number of parameters such as product characteristics, production technology, production process, functions & usage, pricing and customs classification. There are several steps/stages involved in the production of SDH equipment which include conceptualization, preparation of detailed drawings and designs (blueprint).

- b) Based on operational requirements, Tejas identifies the specific components required and develops various kinds of software elements, which would make such hardware functional with regard to the desired operation. Based on the blueprint for the hardware, and the software developed, a fully functional prototype is produced. This 'prototype' contains both the hardware as well as the embedded software necessary for the operation of the equipment and its compatibility with other equipment in the network, as seen through a network management system. Prototype developed by Tejas is tested using test specifications and testing software. A fully functional prototype is comprised of chassis, racks, PCB, cables software etc. After testing of SDH prototype, instructions are given to EMS for soldering of components on PCB as per Tejas requirement. Various softwares are also provided to the EMS on a carrier media, for carrying out certain assembly line operations, principally soldering activities. The soldered non-functional PCBs are supplied by EMS to Tejas manufacturing facility in India as SDH equipment until integrated and tested with Tejas customized components such as chassis, racks, cables, software elements. Integration activity is followed by rigorous testing, debugging and quality control. The testing, debugging & reworking activity includes development of special test jigs, test specifications and testing software which is critical in manufacturing process of SDH equipment.
- c) Anti-Dumping Law does not define as to what would constitute "production" or "manufacture". The scope of the term "domestic producer" would have to be inferred with reference to the purpose and object of Section 9A of the Act and the Rules made there under. Further, Rules differentiate between domestic industry and domestic manufacturer. Not all domestic producers are domestic industry.
- d) Definition of "manufacture" under other legislations cannot be imported for the purposes of understanding the scope of domestic industry under dumping law. This principle has been well set out in the recent decision of the Hon'ble Supreme Court in the case of Qazi Noorul HHH Petrol Pump Vs. Deputy Director, ESI Corporation reported in 2009 (240) ELT 481 (SC).
- e) There are numerous statutes, which define the term "manufacture", "manufacturing process" or "manufacturer". These include, for example, Factories Act, 1948, Special Economic Zone Act, 2005, Central Excise Act, 1944, Consumer Protection Act, 1986, Beedi and Cigar Workers Act, 1966 and Standard of Weights and Measures Act, 1976, and Foreign Trade Policy. The definition of production under these statutes are significantly different, which establishes that merely because a company pays excise duty and is therefore recognized as a producer under Excise Law and should not be treated as a producer for the purpose of the present law as well.
- f) Under Anti-Dumping Law, the considerations relevant for determining producer would be factors such as the level of investment in India, technical expertise involved in the activities carried out, extent of value addition in India, employment levels and other costs and activities carried out in India, which result in the production of the article.
- g) A very significant part of the value of the product is attributable to the software developed in India, which is partially loaded at the stage of assembly by the EMS, partially used for testing, debugging & reworking in India and also provided to users for functioning of SDH network. Development of software also constitutes production of goods.
- h) The Constitution Bench of the Hon'ble Supreme Court considered whether the term "goods" would include software and, therefore, whether development of software would constitute production of goods.
- i) Tejas develops software in India, a part of which is provided to the EMS on a carrier media and such activity constitutes production of "goods" by Tejas.
- j) Tejas also carries out substantial activities after the goods are returned from the EMS. At this stage the product is not functional as SDH equipment and is in an intermediate stage of production. Assembly and testing activities done by Tejas using "in house" developed software, test specifications & test procedures. Tejas also develops other SDH software elements like "network management software, element management software, application software etc." which are necessary for the functioning of the SDH network.
- k) With regard to the argument that the job worker is also a manufacturer, Tejas has argued that where the entire process is carried out by the job worker, he may acquire the status of manufacturer. However, in a case where only a part of the production activity is outsourced and substantial activities are carried out by the manufacturer, it cannot be said that the identity as manufacturer of the finished article is lost on account of outsourcing of certain processes.
- l) The Hon'ble Supreme Court in the case of Shree Ram Vinyal & Chemical Industries Vs. CC, Mumbai reported in 2001 (129) ELT 278 (SC) has held that assembly cannot be equated with the expression manufacture. In the case of United Telecoms Ltd vs. CC, Bangalore reported in 2009 (241) ELT 380 (T), it has been held that mobile phones do not become so, until the software is loaded by the manufacturer. Therefore, whether mere assembly would be manufacture would depend on the facts of each case. Merely

because one or two of the processes involved in the production of the SDH equipment are outsourced, it cannot be said that Tejas is not a producer of SDH equipment.

- m) Under the normal definition of manufacture, the activities carried out by VMCL and Prithvi would not have constituted manufacture, but for the deeming provisions under the Central Excise Act. A deeming provision is to be construed strictly and only for the purpose of the Act in which it is enacted.
 - n) The Petitioner provided a comparative of the various activities done by Tejas and Importers. Petitioner argued that production for the purpose of the present product implies activities such as Specification development and designing of Hardware and Software based on research & development carried out, collaborative components development with suppliers, Proto Type Product Development, Development of Network Management Software in India, Development of Element Management Software in India, Development of Test Procedures, Test Specifications and Testing software in India, Product verification w.r.t. the specifications and quality of Hardware and Software in India, Complete Verification w.r.t. the specifications and quality of the complete SDH proto type (hardware + software combined), Manufacturing of boards, Installation of Software in SDH Hardware, Final Assembly & Testing of the complete SDH box (hardware + software), Post Sales bug fixes, Post Sales “product features enhancement /upgrades”, Post Sales – Spares Supply/Technology Support and claimed that Tejas performs all these operations necessary to be considered as a producer, whereas Prithvi, VMCL merely carry out assembly operations in India. Huawei does most of its operations outside India.
 - o) Tejas has made huge investments to establish customer support and service centers in India. Tejas is capable of doing “installation services, enhancements, bug fixes” for its products within India.
 - p) Tejas identified various components and their procurement & development in or outside India and argued that taking help of EMS is substantially different from taking help in design & development itself. In case of VMCL and Prithvi, it is de-facto Huawei who is the producer of the product concerned, with assembly operations (if any) left to the VMCL and Prithvi. In case of Tejas, the company is the producer, with soldering operations left to EMS contractors.
 - q) With regard to activities of EMS, petitioner submitted that it is well accepted globally that EMS companies are only a contract manufacturer, with no ownership of product rights, IPR or knowhow, and they are only job-workers, who provide soldering/testing services to electronic products from different industries.
 - r) Petitioner has also relied upon USITC consideration of six factors to determine whether a company is a producer of product concern or not. These are:
 - the extent and source of a firms capital investment;
 - the technical expertise involved in U.S. production activity;
 - value added to the product in the United States;
 - employment levels;
 - quantities and types of parts sourced in the United States; and
 - any other costs and activities in the United States leading to production of the like product, including where production decisions are made.
 - s) The Petitioner has also referred to emerging jurisprudence in various books on Dumping and Subsidies by M/s. Stranbook & Hooper, The Law and Procedures Governing the Imposition of Anti-dumping and Countervailing Duties in the European Community by M/s. Clive Stanbrook and Philip Bentley, A Handbook on Anti-dumping Investigations by Judith Czako, Johann Human and Jorge Miranda, Cambridge University Press, Antidumping and Countervailing Duty Handbook of the United States International Trade Commission. Petitioner also referred to a number of decisions of the EC, India and US authorities.
- viii. DRI has conducted investigations against importers and demanded 6 telecom companies including Vodafone, Airtel, Idea etc to pay over Rs. 427 crores for allegedly evading anti-dumping duty while importing SDH equipment. Further the reports state that the officials had specific information available about telecom companies misinterpreting the SDH either as non SDH or part of other equipment, so as to avoid anti-dumping duty. It is all the more important for the Authority to clarify the product under consideration so that such practices adopted by the importers can be prevented and the anti-dumping duty can serve its purpose.
- ix. Huawei India is not a manufacturer of the product under consideration for following reasons:
- a. Unlike Tejas, “Huawei India” has not developed any kind of SDH related software like “embedded software, testing software or management software”, which is essential for manufacturing of SDH boxes.

- b. Huawei India is not involved in SDH product conceptualization, research & design and development of fully functional SDH prototype before the EMS stage. Even assembly and testing operation after EMS stage are carried out using specifications and software elements provided by their Chinese technology partner Huawei China. Huawei India's capabilities are limited to merely carrying out the instructions given by Huawei, China.
- c. Huawei India merely carry out assembly operations in India and its claim of "domestic producer" is baseless. Most of the operations relating to production are done outside India by Huawei China and hence Huawei India cannot be a domestic producer. In fact, companies such as Prithvi and VMPL have even not participated in the present investigations
- d. Major R&D activities are not carried out by Huawei India in India. The company is using the technology of its parent company and does not own its software.
- e. R&D expenses account for a significant proportion of money spent in various "Value Added Activities" related with product manufacturing (over and above the material cost). Thus R&D is the primary activity in product creation. In addition to R&D and technology development, which are the major activities, Tejas also does rigorous assembly and testing of "Like Products" based on the "Test Procedures and Specifications" developed in India by Tejas product design team in India. In contrast, Huawei India does not do any technology development or R&D for the subject products and even the final assembly and testing of imported products is done as per the specifications given by their foreign technology providers/manufacture based in subject countries.
- f. Huawei India does not have technological infrastructure to do "enhancements bug fixes" within India and they rely on their foreign technology providers/manufacturers to provide "enhancements & bug fixes". The fact that despite claiming to be a SDH producer, they don't even have their own "product documentation" (they are providing products of Huawei China for testing purposes), blatantly establishes the fact that they are only importers and traders, rather than a domestic producer of SDH.
- g. Further Huawei India claims to be manufacturing SDH Equipment models which were already developed by its parent company. Huawei India would not have or has not invested capital to carry out or has carried out R&D activities for such models, which are already developed and deployed by Huawei China.
- h. Huawei India has been filing the tenders and referring supplies made by Huawei China for showing its previous supply history. Therefore, it shows that Huawei India does not have its own capabilities of production of product under consideration in India and has to depend on its parent company to procure tenders. The petitioner fails to understand as to how if the two companies are separate legal entity, Huawei India can provide Huawei China's products for testing purposes in the tender documents.
- i. Huawei India imports bare PCBs and SMT device. After importing these, only populating the PCB and assembling the card is left to be carried out in India. Populating of PCB is being done by specialized entities and assembling cards is a screw driver technology. Huawei India is thus claiming itself as a producer by getting PCB populated by some other company and merely undertaking assembly of cards in India.
- j. The volume of production claimed by Huawei India is nothing but on the basis of the production facilities of Huawei China
- k. TRAI has distinguished between Indian product and Indian manufactured products. The products claimed to be manufactured by Huawei India is not an Indian product and, therefore, the company cannot be considered as manufacturer of the product in India.
- l. Electronic Manufacturing Services (EMS) contractors are substantially different from taking help in design & development itself. In case of Huawei India, it is de-facto Huawei China who is the producer of the product concerned, with assembly operations (if any) left to Huawei India. In the case of Tejas, the company is the producer, with soldering operations left to EMS contractors.
- m. Globally it is well accepted that EMS companies are only a contract manufacturer, with no ownership of product rights, IPR or knowhow, and they are only job-workers, who provide soldering/testing services to electronic products from different industries. Infact Huawei India is also taking services of EMS companies.
- n. Even if it is considered that Huawei India is an Indian manufacturer, the same is related to the exporter of the product under consideration and has imported the product. The company has filed Importer questionnaire response as well, while Huawei China has filed exporter's questionnaire response.

Therefore, the company in any case is ineligible domestic industry and the production of the company cannot be considered for determining standing.

- x. The petitioner should be considered as eligible domestic manufacturer to file the present petition, notwithstanding that supplemental imports of components or sub- assemblies have been made by them.
- xi. TEMA (Telecom Equipment Manufacturers Association), an industry association in India, confirmed that Tejas is the majority SDH player and affirms our stance as to who is a producer and who is an importer/trader.
- xii. Other domestic producers, like Fibcom India Ltd (Fibcom) and Coral Telecom, clearly support Tejas stand and do not consider importers/assemblers like Huawei India, who merely imports products of foreign technology, as domestic SDH producer.
- xiii. The Authority held in the original findings that (a) production of petitioner constitutes a major proportion in the Indian production, (b) imports made by the petitioner from the subject countries do not constitute imports of the product under consideration as these are multi use components and not stand alone components, (c) imports made by the petitioner from the subject countries in any case are negligible, to disqualify the petitioner from being treated as domestic industry within the meaning of Rule 2(b), (d) without prejudice to the fact that activity conducted by parties such as Huawei is not sufficient to consider them as a producer, they are not, in any case, eligible producer because of significant imports made by them.
- xiv. As regards eligibility of the petitioner, the petitioner has been importing some stand alone components from non subject countries and subject countries, details of which are contained in the petition. Further details shall be provided, if required by the Authority now or during the course of the investigations. The stand alone components do not constitute import of the product under consideration, as the Authority has specifically excluded imports of the parts/components from the scope of the product under consideration in the original final findings.
- xv. The focus of the petitioner remains in original undertaking complete production process as identified by the Authority at the time of original investigation. It is specifically confirmed that all the activities found relevant by the Authority for holding that a company is a producer were being undertaken at the time of original investigations and are being undertaken at present by the petitioner. Further, the petitioner has been carrying on the essential production activities involved in production and sale of the product under consideration. The Petitioner submits that it is without basis that the activities of the petitioner are limited to mere R&D. In fact, it is be appreciate that the petitioner has sold equipment worth over Rs. 1000 crores over the current injury period itself and the petitioner has been in existence for the past 14 years.
- xvi. The activities being performed by the petitioner at present are the same as were being performed by the petitioner at the time of original investigation. Even at the time of original investigation, the petitioner was importing some parts/components from China. The petitioner has imported some parts/components from China even in the present period as well. Thus, the imports of parts/components made by the petitioner from China in any case should not disentitle the petitioner from being treated as domestic industry.
- xvii. The imports of such components made by the petitioner constitutes an insignificant percentage in relation to (i) total imports of the subject goods from subject countries to India during the POI (ii) the total Indian production, (iii) domestic sales of the domestic industry and, (iv) the total demand for subject goods in India.
- xviii. As regards the argument that Huawei India has become the biggest producer in India and the same has been recognized by the DoT and the company is earning profits, it is submitted that nothing has been provided either by Hauwei India or any other interested party to prove the same.
- xix. The names of the claimed other producers listed by the parties have not established themselves to be a domestic manufacturers of the product under consideration. Further these companies have also not opposed the petition. Further TEMA (Telecom Equipment Manufacturers Association), an industry association in India, confirmed that Tejas is the majority SDH player and affirms our stance as to who is a producer and who is an importer/trader. Other domestic producers, like Fibcom and Coral Telecom, clearly support Tejas' stand.
- xx. The R&D activity is not only integral but also most critical part of the production process. Without designing and development, it is not possible to produce the product concern. The fact that the IPR is created in India, is owned by the Indian company which is under Indian management, is the most critical fact. It must be noted that EMS activity is an incremental value-added activity. Tejas first develops the complete product prototype in India and then Tejas shares with EMS necessary specifications of products for large scale soldering of PCBA. EMS functions on job work basis and they merely execute Tejas' instructions for soldering PCB. Post EMS activities like assembly, integration and testing activities are carried out in India. Tejas uses EMS companies in India, as well as abroad, on job-work basis, as and when needed.
- xxi. Further the opposing interested parties have not demonstrated as to how the 15 point criteria have changed. The petitioners have demonstrated in detail as to how Huawei India cannot be considered as Indian manufacturer of

- the product under consideration in its written submissions. No other company has claimed to be a manufacturer of the product under consideration.
- xxii. Carrying out research and development in India by Huawei India does not make Huawei India as a manufacturer of product under consideration. Research and development need to be of product under consideration and exclusively for Huawei India product and not for other group companies. It is requested to the Authority to visit the plant of Huawei India and see what all activities are carried out in their premises.
 - xxiii. As regards DTA manufacturing license for manufacturing telecom equipment to Huawei India, it does not mean that the company is actually manufacturing the product concern.
 - xxiv. As regards Central Excise Registration Certificate to Huawei India, the petitioner refers and rely on the final findings in the original investigation wherein the Authority stated that mere excise registration or payment of excise duty does not mean the company is a manufacturer of the product. The petitioner requests the Authority to follow the same approach.
 - xxv. The Authority after detailed analysis in the original investigation, had determined what all activities would be termed as manufacturing of the product concern and on that basis the domestic industry can be defined. A company who does not own the IPR of the product and does mere assembly operation for a foreign product cannot be considered as a domestic industry of the product under consideration in an anti-dumping investigation.
 - xxvi. Huawei India itself agrees that they are only assembling the components and the Authority has clearly given its finding that mere assembly cannot be considered as manufacturing of the product under consideration. The Authority nowhere stated that while a Company need not undertake each of these activities, it is possible that some of these steps might involve one or more sub-processes which might be carried out independently, or some of these processes may be integrated by some Company. As regards inclusion of parts and components, assembly and sub assembly, the Authority has given detailed reasoning in the original final findings which is referred and relied upon.
 - xxvii. The definition of manufacturer in the Central Excise Act cannot be applied for anti-dumping duty investigations.
 - xxviii. As regards Huawei's market share, it is submitted that both Huawei China and Huawei India along with their other related companies have filed questionnaire response and dumping and injury margin would be established on the basis of their data.

D.3 Examination by the Authority

19. The arguments have been made by various interested parties questioning Tejas Networks Ltd's standing as eligible domestic industry with major proportion in the total Indian production. Further, Huawei India has also claimed that it is Huawei India who is the major manufacturer of the product concern as against Tejas Networks Ltd and thus has the standing to be treated as the domestic industry and not Tejas Network. However, Tejas Networks has contended that it is the eligible domestic industry with major proportion in the total Indian production and Huawei India, who has claimed to be a manufacture of the product under consideration, is in fact the importer of the product and not a manufacturer and thus cannot be treated as eligible domestic industry.
20. The Authority notes that Rule 2(b) provides as follows:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are relate to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.
21. The Authority notes that the principle requirement under Rule 2(b) of the Anti Dumping Rules is that *such producers who are claiming to be the domestic industry are not related to the exporters of the alleged dumped article or themselves importers thereof*. In this regard, the Authority has noted that Huawei Telecommunications (India) Co. Pvt Ltd (Huawei India) by its own admission is a related party of Huawei Technologies Co. Ltd, China RP (Huawei China). Also, Huawei India has imported the PUC in the Period Of Investigation of the present sunset review investigation and filed importers questionnaire response. Since Huawei India is a fully owned group company of Huawei China and has also imported the PUC in the POI of the present sunset review investigation and filed the importers questionnaire response, Huawei India will not be considered the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Anti Dumping Rules for the purpose of the present sunset review investigation.
22. The application has been filed by M/s Tejas Networks Limited on behalf of the domestic producers of the subject goods in India. Further, on the basis of information furnished by the petitioner, the Authority notes that the petitioner has made imports of some standalone components from countries not under investigations and some standalone components have been imported from China PR. The Authority notes that this fact does not

disqualify the petitioner from being considered as a domestic industry under Rule 2(b). Also, the imports of standalone parts or components made by petitioner in any case do not constitute imports of the product under consideration.

23. As to whether Tejas Network constitutes “Domestic Industry” of the product concern in India, the Authority notes that as per the information on record, Tejas Networks Ltd is the major producer of the subject goods and its production constitutes major proportion of the total Indian production as can be seen from the table below.

		2010-11	2011-12	2012-13	POI (April, 13 – June, 2014)	POI Annualised
Tejas Networks	Nos	***	***	***	***	***
Others	Nos	***	***	***	***	***
Total		28,178	9,769	9,669	14,716	11,773
Tejas Networks	%	74	67	80	85	85
Others	%	26	33	20	15	15

24. After detailed examination the Authority holds that Tejas Networks Ltd accounts for a major proportion of the total domestic production of the subject goods during the POI and constitutes domestic industry within the meaning of the Rule 2 (b) and satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Anti-dumping Rules.
25. The Authority also notes that a number of interested parties have disputed as to what constitutes production of SDH equipments; whether assembly operation should be considered as production; whether there is any legal requirement under the AD Rules to meet the 15 point criteria to satisfy that a company is undertaking production in India, etc. The Authority has carefully considered these arguments and notes that the issue has arisen in view of the peculiarities of the product, production process followed and the nature of activities carried out by the companies who are engaged in the manufacturing or assembling of the product under consideration in India and the subject countries. In this regard, the Authority notes that in the Final Findings dated 19th October, 2010 of the original investigation, the Authority had already concluded (i) that it would be appropriate to consider the meaning of production on case by case basis as a universal definition of production would not be appropriate, (ii) that in fact, different laws and regulations have defined/treated different meaning of production as is evident from different meaning/interpretation of production under different laws, (iii) that the meaning of production is required to be considered having regard to the specific law and regulation, the specific definitions and interpretation given therein and the objective and purpose for which the law has been created, (iv) that for the purpose of anti-dumping duties, in the present case, for example, it would be grossly inappropriate to hold that a company is a domestic producer merely because it is undertaking certain incremental production activities and (v) that for the purpose of anti-dumping law, the goods must be considered to have been produced only if the inputs undergo a “substantial transformation” into output. The Authority, therefore, notes that this issue has already been settled in the Final Findings of the original investigation and no new facts have come up in the Review investigation warranting the Authority to have a different view in the matter.

E. MISCELLANEOUS ISSUES

E.1 Submissions made by the Exporters/Importers/ users/other Interested Parties

26. Following miscellaneous submissions have been made by the exporters/importers/users/other interested parties:
- The argument of compulsory initiation is a gross misinterpretation of Rule 23(1B) of the Anti-Dumping rules and Article 11.3 of the Anti-Dumping Agreement. The Petitioner continues to rely upon an erroneous interpretation of other case laws to substantiate its arguments.
 - The response of the Petitioner is deficient and the it has merely made assertions without providing any information or justification warranting confidentiality on the issues raised by the Domestic Industry. Information such as Extracts from Ovum Report, Dumping price, Injury Margin and price undercutting based on price offered by Tejas for lost orders/ offers. With respect to the injury information provided by the Petitioner, they have not provided any figures with respect to Capacity Utilization. No index figures or summaries provided.
 - The Petition contains information for a different period than the period of investigation. It is clear from a bare reading of Annexure I that the dumping so determined under Rule 10 and the Annexure must pertain, without exception, to the period of investigation. By extension, it also means that dumping (and calculations thereof),

wherever it appears in the Rules, must also pertain to the period of investigation – including Rule 5. Designated Authority has therefore failed in fulfilling its obligation to assess the accuracy and adequacy of the evidence in the application.

- iv. The present petition contains incomplete information, which is insufficient for the purposes of the present initiation. The Authority acted in violation of Article 5.3 of the WTO ADA by not examining the sufficiency of evidence presented along with the petition.
- v. The Petitioner has either not provided requested information at all or has not provided any basis or supporting evidence of the information provided in the petition. Petitioner has also refrained from providing any meaningful summary of the information provided by it on confidential basis. Petitioner has failed to provide a statement of reasons why information provided on confidential basis is not susceptible to summarization.
- vi. The Authority on its part cannot treat all the information as confidential merely because the party providing the information requests confidentiality.
- vii. In the petition, Petitioner was required to give a justification for claiming return on capital employed in Section VI – Costing Information. However, despite the requirement, Petitioner has claimed the information as confidential and chose not to reply and give an explanation.
- viii. Ovum Reports do not provide information on whether companies are domestically producing the subject product or importing the same. Ovum Report cannot be relied upon to determine standing in this case.
- ix. Petitioner has used Ovum Reports to calculate the production in India, imports of the subject product in India and market share of producers in India. reliance on Ovum Reports is patently incorrect and illegal. Market information in any journal or magazine cannot be a substitute to import statistics. It is the established practice of the Authority to rely on import statistics by DGCI&S to determine the import volume and value of product under consideration in every case.
- x. Nothing stops the Authority from procuring import statistics on its own from DGCI&S and provide the same to the interested parties. Trade journals such as Ovum Reports cannot be relied upon by the Designated Authority to determine parameters such as normal value, import volume and value, landed price etc. in view of CESTAT order in *Dye Stuff Manufacturers Association of India v. Government of India*.
- xi. Ovum Reports only provide market information pertaining to telecommunication equipment in India that too in value terms only. Ovum Reports provide market share of various companies in SDH transmission equipment in India but does not provide details on whether these equipment were domestically produced or imported. Petitioner has done this conversion by dividing imports in value terms by its own average selling price for the subject product. It is not clear on what basis Petitioner has considered its average selling price; whether Petitioner has considered prices of its high value products or low value products or weighted average of its prices has to be clarified.
- xii. There are unsubstantiated claim of sales restrictions in other countries. On the contrary, the Applicant itself has claimed shrinking demand in India along with a shrinking import from subject countries.
- xiii. The Applicant has kept considerable information confidential without providing any justifiable reasons and this is not permissible under the Rules. Capability to properly defend our interests in the present proceedings has been substantially reduced in the absence of sufficient prima facie evidence and meaningful non-confidential summaries.
- xiv. Applicant has used unreliable data from secondary source, Ovum, to prove recurrence of dumping and likelihood of injury. The Applicant has used Ovum data and has quoted the market share of Huawei to be the sole market share of Huawei China. The market share of Huawei in this data includes cumulative share of Huawei India as well. Without verifying this fact, Authority should not proceed further. Authority must seek explanations from Ovum and Applicant at the earliest.
- xv. Ovum itself has refused to support the data which has been furnished by the Applicant in its Petition, source of which has been declared to be Ovum. Pursuant to a query raised by Huawei vide an email, representative of Ovum has responded that it does not support the numbers projected by the Applicant showing share of imports in relation to SDH and telecom equipment.
- xvi. Alleged DI has misrepresented the 'Ovum data' which is anyway a secondary source, and quoted the market share of Huawei to be the sole market share of Huawei China. However, it is submitted that the market share of Huawei as reflected in the said report is the cumulative share of Huawei India and Huawei China. Further, it is submitted that the imposition of duty as high as 266% has the capability to greatly change the trend of demand and supply in the market. On account of such high duty, the import from Huawei China to India during the period of the present review, was at a minimal level.
- xvii. Ovum officials have themselves said that alleged DI has erroneously interpreted the data in their report and they have expressed extreme disgruntlement on such misuse of the data as mentioned in their report by the alleged DI.

They have also expressed their intention to take alleged DI into account by filing a complaint against such misuse of Ovum report's data, to the appropriate authorities

- xviii. The alleged DI has vehemently argued that after the import of parts and components all the ancillary activities take place in India. However, this stand is contradictory to the extent of the fact reflected in their Annual Report 2007-08, wherein they have clearly admitted that they have outsourced their manufacturing activities to global electronic manufacturing services companies such as Celestica Inc. and Flextronics International Ltd. Further, they have also admitted therein, that their products are being manufactured in India and Thailand Further even the DGAD in its Final Findings observes that the alleged DI has undertaken manufacturing of PCB in countries other than India like Thailand, Singapore, Taiwan, etc. It is therefore clear that the alleged DI has concealed this fact in its petition for the sunset review, in as much as it has claimed that its manufacturing is in India. The alleged DI has also not provided the data of any specific goods imported by it, thereby making it impossible to determine what goods are actually being imported and from which country. Such excessive confidentiality is the in the violation of the principle of natural justice.
- xix. Information such as imports into India, export price, landed price, dumping margin, injury margin etc. are claimed on hypothetical basis, which is contrary to the provisions of law.
- xx. The petition does not contain any evidence with respect to import volume, import value, Normal Value and Export price. Import statistics have not been provided to the interested parties. An anti-dumping investigation is being conducted without any valid credible source of import statistics.
- xxi. If Petitioner was in a position to classify imported items in the DRI's list as per the product scope in Notification No. 125/2010-Customs dated 16 December 2010, it could have easily classified or categorized imports in the import statistics as well.
- xxii. If the import statistics are not even provided in a petition, the interested parties are severely hampered in meaningfully examining the petition.
- xxiii. Given the peculiar nature of the subject product, it is quite possible that parts/components that are outside the scope of the investigation might have been included in total imports. This aspect has to be investigated in detail.
- xxiv. The methodology followed to arrive at the normal value for the subject countries is not even explained in the petition. The petition provides no information on raw material cost, utilities and consumables, depreciation, labour and other costs and profit margin. Entire Section VI of the petition pertaining to costing has been kept confidential. The petition is grossly deficient and Petitioner has exercised excess confidentiality in the petition.
- xxv. Excessive claim of confidentiality by the Applicant in violation of Article 6.5.1 of the WTO AD Agreement and Rule 7 of the Anti-Dumping Rules:-The Applicant has kept considerable information confidential without providing any justifiable reasons and this is not permissible under the Rules. Instances of information which have been withheld under the garb of confidentiality are as follows: Production volume; Domestic Sales volume; Export Sales volume; Inventory in volume; COP per unit in Indexed; Selling price per unit in Indexed; Profit/(Loss) per unit in Indexed; Productivity; ROCE in percentage; Proforma IV-B; Costing Information in Format A to CII; ROC version of financial results etc. Ovum Reports and methodology in sorting import data has also been claimed confidential.

E.2 Submissions made by Domestic Industry

27. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:

- i. As regards the argument that the import source adopted by the petitioner is absurd and does not reflect the correct position of imports into India, the petitioner procured importer wise data which shows that imports as per petition data does not reflect full extent of the imports of the product under consideration. Imports as per DGCIS data does not reflect all the imports of the product under consideration.
- ii. Further DRI investigations have revealed that substantial imports are taking place by describing imports as non-SDH or parts/components. It is thus evident that all these imports are getting unreported and remained excluded from the petition because of absence of public information
- iii. All the responding exporters have resorted to excessive confidentiality claim which has completely prevented the Petitioner from offering its comments. The confidentiality claims are not in accordance with Rule 7 of the rules. For instance, every responding company has claimed product description as confidential information in the transaction wise details of exports to India. There is no justification for claiming such information as confidential business information. The interested parties have claimed entire information as confidential and not provided even the non confidential summary of the information filed by them. Non-confidential version of the questionnaire response is grossly inadequate. The interested parties have not disclosed all such information that they are obliged to disclose under the Rules. Even information that is publicly available has not been disclosed in the non-confidential version. Further the interested parties have not filed proper and sufficient non confidential summary of the information

claimed confidential so as to enable the petitioner to give meaningful comments. The interested parties have merely given blank formats. This is in direct violation to principles of natural justice.

- iv. The petitioner has provided detailed information as prescribed and the Authority after being prima facie satisfied by the information provided by the petitioner has initiated the investigation. Nothing prevents the exporters to file relevant information to counter the claims of the petitioner. However opposing interested parties have restraint themselves by only providing blatant arguments without providing any evidence to corroborate the same.
- v. The petitioner has only claimed those information which are business sensitive information and otherwise not available in the public domain. The petitioner has provided sufficient non confidential summaries to the information provided except for those which are not susceptible to summarization unlike the responding interested parties who have resorted to excessive confidential information.
- vi. It is not possible to identify type of SDH equipment imported using either secondary source or DGCI&S data due to the fact that the imports of SDH equipment is not being made as equipment and the imports are in CKD-SKD or sub-assembly form. The product has been imported in these forms and thereafter assembled in India in the form of equipment and then supplied to the consumers. Therefore, it is not feasible to determine export price for individual imports made during the present period.
- vii. As regards the argument that exporters are subject to rigorous standards for providing information in their responses, the domestic industry, on the other hand is not subject to the same rigorous standards, it is submitted that the information provided by the petitioner is scrutinized at every stage of investigation unlike information by exporters.
- viii. The petitioner has provided detailed reasoning for compulsory initiation of investigation. However, since the Authority has on the basis of positive evidence initiated the investigation, the issue is irrelevant at this stage.
- ix. The petitioner has provided sufficient information for the purpose of initiation of investigation. The requirements of Rule 5 have adequately been met. Under Rule 5, the Director Designated Authority is required to be satisfied with regard to adequacy and accuracy of evidence for the purpose of initiation of investigations. The Authority has not recorded a finding recommending anti-dumping duties upon initiation of investigations. It is a well established principle that quantity and quality of evidence improves as an investigation progresses.
- x. The user association has filed its submissions. However, only one member of the user association has filed information. Other members have not provided any information regarding their volume of imports, import price etc. The notice of initiation provides opportunities to interested parties to provide relevant information to the Authority. The Association has, however, provided no information whatsoever which is relevant to the present investigation.

E.3 Examination by the Authority

28. As regards the contention that Applicant has not filed a 'duly substantiated' petition in terms of Rule 23(1B) of the Anti-Dumping Rules by providing sufficient and accurate information, the Authority notes that the present investigation was initiated by the authority only after being satisfied that there is sufficient prima facie evidence showing dumping, injury and causal link and justifying initiation of the investigation in accordance with the Act and Rules.
29. As far as confidentiality issues are concerned, the Authority notes that the information which are confidential in nature and provided by the interested parties on confidential basis have been treated so wherever warranted after due examination of the confidentiality claims as per the general practice followed by the Authority. To the extent possible, parties providing information on confidential basis are directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. Therefore, the concerns of the interested parties have been adequately addressed.
30. As regards the import source and reliance of the domestic industry on the Ovum Report, the Authority notes that the Authority has received transaction wise import data from DGCIS and relied upon it for import volume and injury analysis.

F. ASSESSMENT OF DUMPING – METHODOLOGY AND PARAMETERS

Market Economy Treatment, Normal Value, Export Price and Dumping Margin

F.1 Submissions made by Domestic Industry

31. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the Market Economy Treatment, normal value, the export price and dumping margin:
 - a) The Normal Value cannot be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not publicly available. The petitioner has not been able to procure such information from a producer in a market economy third country. The product being such, the

comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country cannot be determined unless detailed transaction wise imports along with importer wise data is available. The petitioner is not privy of such information. The petitioner has provided information to the best of its availability.

- b) The Indian law does not provide for inviting views of the interested parties before initiation of the case. Further, now that the exporters have filed their response, the dumping margin and injury margin would be based on the data provided by the exporters.
- c) The product is sold in domestic market to limited customers. The petitioner is also participating in various tenders and is aware of the tenders/orders which are lost by the petitioner. Petitioner is well aware of the specifications asked in the tenders and quoted its prices for the same specifications. Whether the purchase is from domestic or other sources, the product under consideration and its specification do not vary depending on the supplier. In fact, different suppliers must quote/offer price of the product conforming to the specifications laid down by the consumers. All these tenders are "closed tenders", but closely monitored by the sales team of all the suppliers and the petitioner. The Petitioner has compiled details of some of such tenders where the petitioner participated but lost to the producers in the subject countries
- d) The petitioner has determined dumping margin considering the petitioner's price as export price (export price as such would be lower than this price), taking conservative approach. The real price is in fact lower than this price. Considering this price, the export price has been determined at ex-factory level, after adjusting the export price to all the expenses associated with exports to India
- e) Nothing has been provided by the opposing interested parties to prove that the tenders lost by Tejas are due to factors other than price. The petitioner has been exporting the product world wide including the developed countries. This itself establishes the quality of product offered by the petitioner. Further, now that the exporters have responded, their data would be considered for determination of normal value and dumping margin. Further, most of the tenders have technical bid which take into account the other factors.
- f) The undercutting and dumping margin have to be determined for imported products and not for domestic sales. The tenders won by the domestic industry are with respect to their domestic sales. Notwithstanding, now that the exporters have responded, their data would be considered for determination of normal value and dumping margin.
- g) As regards market economy treatment, the factual matrix remains the same since the original investigations and the reasons for rejection of MET claim in the original investigation hold good in the present case as well. Therefore, the Market Economy Treatment (MET) claim should not be accepted in the present case as well.

F.2 Submissions made by exporters, importers and other interested parties

32. The following submissions have been made by the exporters, importers and other interested parties with regard to MET, normal value, export price and dumping margin:
 - i. The exporters have cooperated in full in the present investigation and, therefore, the DA is requested to allocate an individual margin to the cooperating exporters based on the figures placed on record in their comprehensive questionnaire responses.
 - ii. There has been no material change to the operations or ownership of ECI companies which could impact the Market Economy Treatment accorded to ECI in the previous investigation. The Authority is, therefore, requested to allocate an individual margin to ECI companies.
 - iii. A mere government shareholding would not by itself mean that the government is interfering in the affairs of the exporting company. The WTO Appellate Body in the case of United States - Definitive Anti-dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China, DS379/AB/R dated 11.03.2011 has categorically held it. The phrase 'state interference' in the statute should be interpreted to mean interference of the government as a legislator.
 - iv. In the past, in certain investigations, the DA has been determining separate dumping margins in similar cases for different products [Cold Rolled Steel Case and Theophylline & Caffeine Case]. Because of the difference in selling price of different capacity of PUC, it is not fair to use average price as has been done by the Applicant in the Petition. The Applicant has provided uniform average selling price for PUC with different configurations. The DGAD has erred in its approach in as much as it has determined a common weighted average dumping margin for each of the equipment included within the scope of PUC. It is submitted that each SDH equipment included within the scope of PUC has different configuration, functional capacity, characteristics and use.
 - v. It is submitted that each of the equipment included under the scope of PUC is a separate type SDH equipment. It is further submitted that under Section 9A and Rule 17(3) of the Anti-Dumping Rules, the Authority has to determine an individual margin of dumping for each known producer or exporter under investigation. However, the DGAD by

determining a single common dumping margin and by undertaking a common investigation for all the equipment included in the PUC has contravened the provisions of the Customs Tariff Act, 1975 and the ADD Rules, 1995.

- vi. The export price is based on Applicant's price and not actual 'export price' which is untenable under the AD Act and Rules. Thus, the applicant failed to prove any likelihood aspect based on dumping margin determined in the original investigation and the current investigation. This ground is untenable.
- vii. The Petitioner has simply stated that it could not find any price details with respect to the prices in a market economy third country or the constructed normal value in a market economy third country. The application is clearly incomplete. The Designated Authority must exhaust the first two options provided in the AD Rules to arrive at the normal value in the present investigation.
- viii. Further, the Petitioner's submission and data on normal value is inconsistent with the investigating practices followed in various other countries and jurisdictions such as the EU. Any interpretation adopted by the Designated Authority for Para 7 of Annexure I to the AD Rules cannot be different from that applied by the European Commission as well as the Hon'ble Supreme Court of India's holding in Shenyang Matsushita case.
- ix. The Petitioner has erroneously equated its cost of production required for the computation of normal value with the costs incurred by it in India. Petitioner and the exporter from China PR are completely different entities functioning in different countries, in addition to innumerable variations in every functional aspect between the two. To equate the costs of two such entities is an absurd proposition. Petitioner's cost of production would be relatively different than such foreign producers, especially in China PR, who can procure all components locally to manufacture the subject product.
- x. The Petitioner has adduced no positive evidence or basis on which it adopted its cost of production for computing the normal value, thus, failing the test of evidentiary requirements under the WTO ADA.
- xi. If constructed normal value is fully accepted based on the petition, then the requirement to provide normal value with evidence will become redundant because whenever there is price undercutting/underselling, the normal value will show the assumed dumping behavior of the exporter even though there may not be any dumping with reference to actual normal value.
- xii. Anti-dumping duty may be imposed on verified figures from the cooperating exporter's records. But such an approach is required to be deprecated, otherwise it will render redundant the legal requirement that an applicant should make available prima facie evidence and the Designated Authority must examine the accuracy and correctness of such evidence.
- xiii. The Petitioner has calculated dumping margin based on the normal value which is based on its cost of production and export price which is the price of Petitioner. Further, the petition does not provide any information on the deductions that Petitioner has considered while arriving at the ex-factory export price. The Designated Authority has failed to notice these fundamental flaws in the petition.
- xiv. Pricing alone is not the only factor that is relevant to gain a tender. Quality of the product, brand value, reputation, after sales service and prior experience in honouring and completing tenders are all evaluated before award of tenders. It is quite possible that Petitioner lost tenders despite quoting the lowest prices because Petitioner lacked in other parameters. It would be incorrect to use Petitioner's prices to benchmark export prices from subject countries. As a result, dumping margin calculation would be grossly incorrect.
- xv. The Petitioner should have taken weighted average of its prices in all the bids which it had won as well as lost to arrive at the export price. The Petitioner assumes that a competing bidder only supplies imported items. It is quite possible that other bidders are providing locally manufactured products as there are so many producers in India. Petitioner has provided no evidence that corroborates that other bidders are providing imported products. Petitioner could have easily determined ex-factory export price and landed price by categorizing imports in a similar manner as it did for the DRI.
- xvi. The computation methodology followed by the DI for computation of the normal value and dumping margin has not been provided as claimed by the DI to have been enclosed as annexure.
- xvii. The DI has nowhere provided any evidence to substantiate its claim that the imported goods have lower pricing.
- xviii. The importers data needs to be provided by the Petitioner as it forms the basis of the averments regarding injury analysis that are made by them. The exporter requests for the import data to be provided by the Petitioner from a reliable source such as the DGCI&S or IBIS as was done in the previous investigation.
- xix. The Petitioner has provided no actual evidence that exports of the product under consideration from China or Israel have declined to major markets where petitioners claimed that exports from Huawei are banned.

F.3 Examination of the Authority

33. Under section 9A (1) (c), the normal value in relation to an article means:

- (i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or
- (ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:
 - (a) Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
 - (b) The cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section(6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of exporter there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

Determination of Normal Value for producers and exporters in China PR

34. The Authority notes that in the past three years China PR has been treated as a non-market economy country in the anti-dumping investigations by India and other WTO Members. China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the Rules.
35. As per Paragraph 8 of Annexure I of the Anti-dumping Rules, the presumption of a non-market economy can be rebutted, if the exporters from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) of Paragraph 8 and establish the facts to the contrary. The cooperating exporters/producers of the subject goods from China PR are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Authority to consider the following criteria as to whether:
- a. the decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
 - b. the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
 - c. such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms; and
 - d. the exchange rate conversions are carried out at the market rate.
36. The Authority notes that consequent upon the initiation notice issued by the Authority in the present sunset review investigation, the following Chinese companies have filed exporter's questionnaire response:
- a. ZTE Corporation Ltd., China PR
 - b. Huawei Technologies Co. Ltd., China PR (Huawei China)
 - c. Huawei International PTE, Singapore and Huawei Tech Investment Co. Ltd., Hong Kong (Group companies of Huawei China)
 - d. Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd., China PR
 - e. Hangzhou ECI Telecommunications Co. Ltd., China PR
37. The Authority notes that M/s Huawei Technologies Co. Ltd.; M/s Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd. and M/s Hangzhou ECI Telecommunication Co. Ltd. have filed market economy treatment(MET) questionnaire as well and rebutted the non-market economy presumption. The exporters questionnaire responses and the market economy treatment questionnaire responses of these responding producers and exporters were examined. The on

the spot verification of records relating to market economy claim was carried out in respect of M/s Huawei Technologies Co. Ltd., China and M/s Hangzhou ECI Telecommunication Co. Ltd., China. In respect of M/s Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd., China, the verification of their records was done on the table-study basis. The position on the market economy claim, arising out of the verifications, is summed up as below.

Market Economy Treatment for M/s ZTE Corporation Ltd., China PR

38. M/s ZTE Corporation Ltd, China PR, did not file the Market Economy Treatment questionnaire and thus the MET status was not granted to the company.

Market Economy Treatment for M/s Huawei Technologies Co., Ltd., China PR

39. On the spot verification of the information/data submitted by the company was conducted at the premises of the company in China and a detailed verification report was issued to the company with an opportunity to offer comments thereon. Though the company had claimed Market Economy Treatment (MET) status, yet during the verification, the company could not provide evidence backed with documents about the complete details/sources of raw material suppliers and the sources of capital invested by its promoters. Therefore, the company was informed that since these basic documents/information which are crucial for examining the market economy treatment status have not been made available, there was no justification in going ahead with the verification of the data pertaining to the domestic sales and its related cost of production. The market economy status to M/s Huawei Technologies Co., Ltd., China PR was, therefore, not granted.

Market Economy Treatment for M/s Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd., China PR

40. In respect of Alcatel Lucent-Shanghai Bell Co. Ltd., (ASB), it was noted that there are four companies, namely, Alcatel-Lucent Participations China; Lucent Technology Investment Co. Ltd.; Alcatel-Lucent China Investment Co., Ltd. and China Hua Xin Postal and Telecommunication Economic Development Centre ("China Huaxin"), who hold the shares in Alcatel Lucent-Shanghai Bell Co. Ltd. Their shareholding pattern is about ***%; about ***%; about ***%; and about ***% respectively. The first three companies are part of Alcatel-Lucent Group. The fourth company is a state-owned company. State-owned Assets Supervision & Administration Commission of the People's Republic of China ("SASAC"), through China Reform Holdings Corporation Ltd., holds a ***% equity stake in China Huaxin, which in turn holds ***% stake in Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co., Ltd.
41. There are 8 Directors in the Board of ASB, out of which, 4 are nominees of China Huaxin. The remaining directors are nominees of M/s Alcatel-Lucent Participations China and M/s Alcatel-Lucent China Investment Co., Ltd. ASB has contended that the decision making in the company is not affected or influenced by the government nominees on the Board of Directors. However, the Authority notes that the company has significant government presence through shareholdings by state-owned enterprises. In fact, ***% nominees on the Board of Directors represent the State, out of which, a government nominee is also the Chairman of the Board of Directors.
42. In view of the above and with this significant state participation in ASB, state interference cannot be ruled out. Similar position existed during the original investigation also. There is nothing on the record, which indicates to the contrary. Therefore, the Authority proposes to hold that ASB cannot be granted market economy treatment status.

Market Economy Treatment for M/s Hangzhou ECI Telecommunication Co. Ltd, China PR

43. On the spot verification of the information/data submitted by M/s Hangzhou ECI Telecommunication Co. Ltd, China PR (HETC) was conducted at the premises of the company in China and a detailed verification report was issued to the company with an opportunity to offer comments thereon. HETC submitted that it is a producer which received Market Economy Treatment in the original investigation, and that there were no material changes to the ownership structure or operating processes of the company since the original investigation. The Authority verified from the records of the company that HETC operates under the complete control of ECI Telecom Limited, (ECI) which is based in Tel Aviv, Israel, and who continues to be the 100% owner of HETC, which was also the case in the original investigation. The Board of Directors comprises entirely of Israeli citizens and there are no Chinese (government or otherwise) citizens on the Board of Directors of HETC. The company, therefore, operates under the complete control of ECI, Israel. The company operates by engaging a job-worker known as Eastcom, which procures raw materials and supplies the subject goods to HETC. Eastcom purchases raw materials almost entirely on the instructions of ECI, Israel, and it is ECI, Israel which negotiates with various raw material suppliers, most of whom are international suppliers outside China. The Authority verified the cost of the raw material procurement and compared it with the raw material procurement in Israel. HETC demonstrated that the cost of materials and production in China is comparable to the cost of materials and production in Israel. HETC also provided the following documents in this behalf- i) Sample global supply contract for one of ECI's global suppliers, i.e., EZCHIP, ii) Full Turnkey Agreement between HETC and Eastcom, iii) Price Comparison between jobwork in Israel and China, i.e., Flextronics and Eastcom, iv) Sample

Power Invoices, v) Raw Material Sample List, and vi) Sample Freight Invoices. Considering the above, the Authority proposes to hold that M/s Hangzhou ECI Telecommunication Co. Ltd, China PR (HETC) has provided information and sufficient evidence to prove that the company is operating under market economy conditions and is, thus, entitled for Market Economy Treatment status.

Normal Value for cooperative producers/exporters from China PR

44. M/s ZTE Corporation Ltd.; M/s Huawei Technologies Co. Ltd. and M/s Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd. have cooperated with the Authority in his review investigation. However, having concluded they are not operating under market economy conditions, the Authority is not in a position to apply Para 8 of Annexure 1 to the Rules to the above named Chinese companies and has proceeded in accordance with Para 7 of Annexure- I to the Rules. According to these Rules, the normal value in China PR can be determined on any of the following basis:
- On the basis of the price in a market economy third country, or
 - The constructed value in a market economy third country, or
 - The price from such a third country to other countries, including India.
 - If the normal value cannot be determined on the basis of the alternatives mentioned above, the Designated Authority may determine the normal value on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India for the like product duly adjusted to include reasonable profit margin.
45. The Authority notes that as per the above rule position, the first option for the Authority is to see whether the price or constructed value in the market economy third country is available or not, and after having concluded that the same is not available, the Authority may move to the next option and likewise to the second and third option. In this regard, the Authority had written to the interested parties that since Israel has been treated as a market economy country by the Authority and further, keeping in view the level of development in Israel vis-a-vis China PR and, after having given due account to the reliable information made available to the Authority in respect of Israel as also the complex nature of product in question in this investigation, why Israel should not be adopted as the surrogate country and to construct the normal value for Chinese non-market economy companies on the basis of the costs/prices of the subject goods in Israel. In this regard, the following views have been offered by the opposing interested parties and the domestic industry:
- The opposing interested parties have offered their comments that if HETC is being treated as a market economy company then its data should be adopted as this methodology will be in line with the AD rule position in this regard but if the Authority, for any reason cannot accept HETC then Israel should be adopted as a surrogate country.
 - The Domestic Industry, on the other hand, has argued against adopting Israel as a market economy country saying inter-alia that since the introduction of the non market economy provisions, the Authority has recommended anti dumping duties in a large number of products, scrutiny of which shows that the Authority has made recommendations in 81 products wherein the investigations involved another country in addition to China. However, the Authority has not adopted the normal value determined in other countries as the basis for normal value for China. Further, Israel was subject country at the time of original investigation as well, yet the Authority has not adopted normal value in Israel as the normal value for China. It would thus be seen that it is not a case that the Directorate was unmindful of the requirements or legal provisions and facts of the case while deciding this case. Such being the case, there is no occasion to even consider this route now in the present investigations. Further, in a number of investigations, the petitioning domestic industries have proposed with sufficient information/evidence for consideration of third country for determination of normal value and yet the Authority rejected such proposals. The issue of consideration of market economy third country has arisen in a number of cases. It has been pleaded by the domestic industries in several of these cases that actual cost of production or selling price in India should be adopted for determination of normal value, which is a direct prescribed requirement under the law. The Authority has, however, repeatedly rejected the argument and has not adopted actual cost of production or selling price in a market economy third country or in India.
46. The Authority has analysed the claims and counter claims of the opposing interested parties and the domestic industry. The Authority notes that (i) ECI, Israel has exported only the equipments to India whereas majority of the exports of Huawei Technologies Co., Ltd. to India are of the Cards and not equipments and M/s Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd. has exported only the Cards to India (ii) the PCNs of equipments and cards exported by the cooperative exporters are not strictly comparable with respect to their respective features and, therefore, a close scrutiny of each PCN exported by them is required (iii) and for this purpose, co-operation from ECI, Israel for making proper comparison of various features of the products produced and exported by them with the corresponding features of the products exported by these non-market economy Chinese

companies is required. Similar is the position in respect of the products produced and sold by HETC, China. However, with reference to the sharing of the PCN data with the cooperating exporters, M/s ECI, Israel, in a written communication to the Authority, has stated that (i) their data should not be shared since it is a matter of fact that the PCN contains the unique structure/configuration which the telecom customers design for their use, (ii) this information is not available in public domain and will seriously compromise the commercial aspects which may give an undue advantage to their competitors, (iii) thus ECI would like to seek confidentiality on this issue and would like to rely upon the practice of the Authority in this behalf, wherein it is unprecedented for the data of the exporters/others interested parties to be shared inter-se and (iv) ECI would like to submit that the exporters questionnaire filed and subsequent submissions contain the non-confidential data along with the reasons as to why the same is not being disclosed and would like to rely upon the same. Due to non-cooperation of ECI, Israel for sharing their PCNs with the cooperative exporters in this investigation, the Authority proposes not to consider Israel as a surrogate country for determining the constructed normal value of these non-market economy Chinese countries in this investigation. Therefore, the normal value in respect of ZTE Corporation Ltd.; M/s Huawei Technologies Co., Ltd. and M/s Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd. has been constructed on any other reasonable basis in terms of second proviso of Para 7 (d) of Annexure 1 to the Rules, as was done in the original Final Findings.

Normal Value for ZTE Corporation Ltd.; M/s Huawei Technologies Co. Ltd. and M/s Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd.

47. For the reasons mentioned above, the ex-works Normal Value of the product under consideration for M/s ZTE Corporation Ltd.; M/s Huawei Technologies Co. Ltd. and M/s Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd. is to be constructed based on the facts available in terms of second proviso of Para 7 (d) of Annexure 1 to the Rules.
48. In the present sunset review, the product has been exported in the form of full equipments (STM-1, STM-4, STM-16, STM-64) as well as in the CKD/SKD forms in the shape of cards, assemblies, PCBAs, Cross Connects etc. as per the requirement of the customers in India. It has been exported by ECI, Israel in the form of full equipments. From China, it has been exported by ZTE Corporation and Hangzhou ECI Telecom in the form of full equipments. However, Alcatel-Lucent Shanghai Bell Company Ltd has exported only cards for SDH use and Huawei China has exported full equipments as well as cards/PCBAs. The present investigation being a review investigation, exporting companies have submitted the relevant information regarding the type of equipments/cards/assemblies etc in the form of PCNs.
49. In this investigation, ZTE Corporation Ltd, Alcatel-Lucent Shanghai Bell Company Ltd and Huawei China are to be treated as the non-market economy companies. However, HETC, China is to be treated as a market economy company. Further, Israel is market economy country and ECI Telecom from Israel is being treated as a market economy company. The normal value for these non-market economy companies is to be constructed on the basis of the cost of production of the domestic industry. Therefore, to construct the normal values for the purpose of calculating the dumping margin for these non-market economy Chinese companies as also to determine the injury margin for these Chinese companies as well as ECI, Israel and HETC, China, efforts were made to match the PCNs of the domestic industry with those of the non-market economy and market economy companies. In this regard, to bring about fairness and transparency into mapping/comparing of the PCNs of the domestic industry with those of these companies, the PCN details of the domestic industry were shared with these companies and likewise, the PCN details of these companies were shared with the domestic industry by various formal communications.
50. In the case of ECI Telecom, Israel and HETC, China, their own data has been used to determine their normal value and export price. Thereafter, several one-to-one meetings were held with the technical experts of all the cooperative companies from Israel and China and the domestic industry for matching the PCNs of these companies. These meetings were held with them separately as well as in the presence of the domestic industry by the Authority. For each of the listed exported PCNs, the domestic industry was asked to match these to the nearest PCN sold by it in the domestic market during the Period of Investigation. Likewise, the individual exporting company matched their PCNs with those of the domestic industry in the meetings with the Authority. Then, for the sake of more transparency, common meetings were held by the Authority with the technical experts of the domestic industry on one side and the technical experts of the individual exporting company on the other side and both the parties were requested to thrash out the difference of opinion in the mapping done by both of them separately to arrive at a consensus. On some PCNs there was consensus in the sense that either the PCN mapping was acceptable to both the parties or where the PCNs did not match completely, both the parties agreed to notionally remove the extra parts like chassis, power cables, ports etc from nearly matching PCNs. For example, if the PCN of the domestic industry for a particular equipment or card included 2 ports and the nearly matching PCN for the similar equipment or card of the exporting company included 1 port, then consensus was arrived at by both the parties for deducting the price of the extra port from the PCN of the domestic industry to calculate the price of the nearly matching equipment or card. For some PCNs, there was no consensus. The three non-market economy Chinese companies submitted their written comments also on the PCN mapping and the

PCN tools prepared by the domestic industry. Likewise the domestic industry has also submitted its comments on the PCN mapping and the PCN tools prepared by it with respect to the matching done with the PCNs of these three companies. In respect of some equipments and cards, there was consensus in matching. Wherever there was a deadlock, the Authority has used its own prudence and wisdom based on the discussions with the technical experts of both the parties and their written comments and thereafter mapped the PCNs by deducting the price of the extra parts/components appropriately on its own.

51. For constructing the normal values, firstly, the weighted average price of all the major components for the SDH equipments of different types of the domestic industry has been adopted based on the domestic industry's normated cost of production and the information provided by the domestic industry. Thereafter, wherever based on the above PCN matching/mapping methodology adopted by the Authority, the PCNs of the equipments of these non-market economy Chinese exporting companies were found to be either completely matching or nearly matching with the equipment of domestic industry in terms of their usage, capacity, interface ports etc., the domestic industry's normated cost of production for these equipments has been adopted. Wherever the PCNs of the equipments or the cards of these non-market economy Chinese exporting companies were not found to be either completely matching or nearly matching in terms of their usage, capacity, interface ports etc., extra parts were notionally added or removed by following the above mentioned methodology and the average price of the relevant parts and components of the domestic industry has been appropriately adjusted. No adjustment has been made for customs duty since the PUC is attracting zero customs duty. Conversion cost and SGA expenses of the domestic industry have been adopted for constructing the normal values. After adding a reasonable profit margin, the normal values have been constructed. The weighted average ex-works normal values for the PCNs exported by these non-market economy cooperative Chinese exporters are as shown in the Dumping Margin Table below.

Normal Value for M/s Hangzhou ECI Telecommunication Co. Ltd, China PR

52. This producer / exporter was found to be operating under the market economy conditions as explained above. While filing the response to the initiation, they had submitted appendix-1 which reported the sales in the domestic market. It, however, came to the notice during the verification that the domestic sales constituted less than 5% of the exports made to India during the POI. Further, there are also no exports to third countries. The Authority notes that the product under consideration being in the finished, semi finished, CKD/SKD, sub-assemblies forms, and considering the manner in which the producers are invoicing the product, as also considering the fact that normal value is the price of "like article" and in the absence of identical article, another article is required to be considered, the normal value in this case considering the SKD/CKD prices and other costs as per the cost of production as per verified data of the producer / exporter plus reasonable profit. Accordingly, the normal value worked out is as indicated in the Dumping Margin Table below.

Normal Value for non-cooperative exporters from China PR

53. The Authority notes that no other producer/exporter from China PR has submitted the exporter's questionnaire response. Therefore, the normal value is determined based on the facts available. Accordingly, the normal value so determined is as indicated in the Dumping Margin Table below.

Normal Value for cooperative producer/exporter from Israel

M/s ECI Telecom Ltd. Israel

54. The company has provided information in various appendices, along with Bill of Materials, which has been examined by the Designated Authority. The Authority notes that *** PCNs are exported to India and only *** PCNs have been sold in the domestic market, but these are not matching with the PCNs exported to India. This position got confirmed during the verification of the responding exporter. It, however, came to the notice during the verification that a number of PCNs sold in the domestic market in Israel did contain some assemblies / sub-assemblies which were the same as used in the PCNs exported to India. The Authority notes that the product under consideration being in the finished, semi finished, CKD/SKD, sub-assemblies forms, and considering the manner in which the producers are invoicing the product, as also considering the fact that normal value is the price of "like article" and in the absence of identical article another article is required to be considered, the normal value in this case has to be constructed by considering the SKD/CKD prices and other costs as per the cost of production as per verified data of the producer / exporter plus reasonable profit. Accordingly, the normal value so worked out is as indicated in the Dumping Margin Table below.

Normal Value for non-cooperative exporters from Israel

55. The Authority notes that no other producer/exporter from Israel has submitted the exporter's questionnaire response. Therefore, the normal value is determined based on the facts available. Accordingly, the normal value so determined is as indicated in the Dumping Margin Table below.

Export Price for cooperative producers/exporters from China PR**M/s ZTE Corporation, China PR**

56. The subject producer/exporter has exported *** sets of *** different PCN variants to India for US\$ *** on CIF price basis during the POI. The export data of the producer/exporter was verified during on the spot verification at the office premises of the producer/exporter by the Authority. Adjustments on account of inland freight, overseas freight, handling & misc. charges, credit cost and bank charges have been claimed and the same have been allowed by the Authority for the determination of the PCN wise net export price at ex-factory level. Since both input and output VAT rate is the same, there is no adjustment on account of VAT. The weighted average net export price has been calculated and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

M/s Huawei Technologies Co., Ltd. China PR (Huawei China)

57. M/s Huawei Technologies Co., Ltd. China PR (Huawei China) had filed PCN wise details of the exports of the product under consideration to India during the period of investigation. As per the records of the company verified by the Authority, it was found that during the POI, Huawei China group companies, namely, Huawei Technologies Co., Ltd. China PR; Huawei Tech Investment Co., Ltd., Hong Kong and Huawei International Pte Ltd., Singapore, have exported *** pcs of the product under consideration for CIF value US\$ *** under *** PCN variants against *** invoices. The product under consideration had been manufactured by Huawei China in all the cases. Huawei Technologies Co., Ltd. China PR had exported the PUC under *** invoices; Huawei Tech Investment Co., Ltd., Hong Kong had exported the PUC under *** invoice and Huawei International Pte Ltd., Singapore, had exported the PUC under *** invoice. Adjustments on account of airfreight and insurance have been claimed and the same have been verified and allowed by the Authority for the determination of the PCN wise net export price at ex-factory level. Since both input and output VAT rate is the same, there is no adjustment on account of VAT. The weighted average net export price has been calculated and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

M/s Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd., China PR (ASB)

58. The subject producer/exporter (ASB) has exported PUC and non-PUC items in *** transactions during the POI. These *** transactions include *** PCN variants having quantity of *** PUC numbers, with a CIF value of US\$ ***. For determination of ex-factory export price for ASB, the Authority has considered these *** PCNs which cover the PUC. All the exports to India were made on ex-works basis to its related company in India. ASB has claimed only credit cost as deduction from the export price. The same has been allowed for determination of net export price at ex-factory level. The net export price at ex-factory level in respect of each PCN has been worked out accordingly. Since both input and output VAT rate is the same, there is no adjustment on account of VAT. The weighted average net export price so determined is as indicated in the Dumping Margin Table below.

M/s Hangzhou ECI Telecommunication Co. Ltd, China PR through M/s ECI Telecom Ltd. Israel

59. As per the verified data, Hangzhou ECI Telecommunication Co. Ltd, has exported *** PCN variants covered under *** numbers of shelves to India during the POI for CIF value US\$ ***. Adjustments claimed on account of Inland Freight, Overseas Freight, Insurance, Storage, Credit Cost and Warranty as verified have been allowed for determination of Net Export Price at ex-factory level. Since both input and output VAT rate is the same, there is no adjustment on account of VAT. The weighted average net export price so determined is as indicated in the Dumping Margin Table below.

Export Price for non-cooperative exporters from China PR

60. The Authority notes that no other producer/exporter from China PR has submitted the exporter's questionnaire response. Therefore, the export price is determined based on the facts available. Accordingly, the exports price so determined is as indicated in the Dumping Margin Table below.

Export Price for cooperative producers/exporters from Israel**M/s ECI Telecom Ltd. Israel**

61. As per the verified data, they have exported *** PCN variants covered under *** number of shelves to India during the POI for CIF value US\$ ***. Adjustments claimed on account of Inland Freight, Insurance Cost, Storage, Credit Cost Expenses and Warranty as verified have been allowed for determination of Net Export Price at ex-factory level. The weighted average net export price so determined is as indicated in the Dumping Margin Table below.

Export Price for non-cooperative exporters from Israel

62. The Authority notes that no other producer/exporter from Israel has submitted the exporter's questionnaire

response. Therefore, the export price is determined based on the facts available. Accordingly, the exports price so determined is as indicated in the Dumping Margin Table below.

Dumping Margin

63. After comparing the weighted average ex-works Normal Values so determined with the weighted average Net Export Prices, the dumping margins so determined are as indicated in the Dumping Margin Table below.

Dumping Margin Table

Name of the company	Weighted Average Normal Value (US\$ Per No)	Weighted Average Export Price (US\$ Per No)	Dumping Margin (US\$ No)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin Range (%)
M/s ZTE Corporation, China PR	***	***	***	***	45 to 55
M/s Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd., China PR	***	***	***	***	50 to 60
M/s Huawei Technologies Co. Ltd. China PR	***	***	***	***	35 to 45
M/s Hangzhou ECI Telecommunication Co. Ltd, China PR	***	***	***	***	0 to 10
All other producers/exporters from China PR	***	***	***	***	110-120
M/s ECI Telecom Ltd., Israel	***	***	***	***	(-)1 to 10
All other producers/exporters from Israel	***	***	***	***	5-15

G. ASSESSMENT OF INJURY

Determination and Examination of Injury and Causal Link

Submissions made by the exporters, importers and other interested parties

64. The following are the submissions made by exporters, importers and other interested parties regarding injury and causal link:
- The market share of the petitioner increased and that of the imports declined.
 - Wages sharply increased to 143 indexed points in 2011-12 from 100 indexed points in 2010-11. Such sharp increase in wages may be the reason that the Petitioner is not able to improve its profitability in a desirable manner.
 - It is a norm in the technology industry that cost of production for a new product is quite high during initial stages when a new technology is introduced in a market for the first time. Cost of production then substantially reduces over time. The Petitioner's cost of production has increased from 54 indexed points in 2012-13 to 72 indexed points in the POI. As per the petition, the Petitioner has not introduced any new like product or technology in the market that led to such increase.

- iv. The Petitioner continues to focus on export markets, while it could have taken steps to increase its market presence in India. The Petitioner cannot take the plea that it is disposing its inventories in the export market because the subject product is made to order.
- v. The domestic industry's price shows continuous increase whereas the demand for the product showed substantial decline.
- vi. In the absence of information about imports from the subject countries, it needs to be seen as a mere argument which is untenable and of no relevance in an SSR investigation.
- vii. It is an unsubstantiated claim that future demand in India would all be taken away by exporters from the subject countries. At the same time, the Applicant has not provided any information about future demand for the subject goods in other countries.
- viii. Imports of the subject product have reduced over the injury period in line with reduction in the overall demand in India. Further, it can be seen that imports from the subject countries also fell in relation to production. Petitioner has cleverly relied on Ovum Reports to show inflated level of imports in this case. Further, the Petitioner itself admits that dumping margin is lower than the antidumping duty in force. Therefore, such heavy anti-dumping duties are not warranted to be continued in this case. Such low volume of imports cannot influence the production and sales of the domestic industry and, therefore, cannot be the reason for any material injury to the domestic industry.
- ix. The Petitioner has failed to provide any data on price undercutting. Therefore, Petitioner's conclusion with respect to price underselling has to be rejected. Further, the Petitioner is wrong in concluding that there is price underselling in the present case because the Petitioner has wrongly determined landed price. Landed price has to be determined based on a proper analysis of import statistics as well as based on the data provided by the interested parties.
- x. Alleged dumped imports of the subject product have been wrongly computed by the domestic industry. For a proper analysis, the Designated Authority should procure DGCI&S import statistics for the subject product. The import volumes cannot increase during the injury analysis period in light of very heavy anti-dumping duties, which are to tune of 266% ad valorem rate in this case.
- xi. With regard to changes in the patterns of consumption of the subject goods, the DI has gone on to claim that the consumption pattern has changed in favour of PUC. However, at the same time, it has admitted that the demand for the product under consideration has declined. Such contrary statements made by the DI only verifies the fact that the DI has been freely concocting facts as to its convenience and requirement. Even it has claimed that data pertaining to export performance has been provided by it separately. However, no such data has been found in the said submissions.
- xii. The outsourcing of manufacturing activity by the DI to the job workers has led to its price escalation, and it is wrong to take the DI price as a benchmark for domestic price. There is no evidence to even substantiate that there was efficient utilization of raw materials, utilities, production capacities, etc. for the manufacture of the subject products by such job workers. For this, firstly the premises of such job workers have to be investigated and the production mechanisms, financial documentation, etc. have to be analyzed at a micro level. DI has no evidence to substantiate the efficient utilization of resources on its part and on the part of its job workers, it has also conveniently tried to claim that capacity and capacity utilization may be considered irrelevant parameter in the present case.
- xiii. The demand for PUC has recorded significant decline. This shows that there is no causal link between alleged dumped imports and any continued injury to the applicant and the continued injury being caused is on account of other factors such as decline in demand for PUC
- xiv. In the absence of basic import data from all sources pertaining to the Applicant, information on production and sufficient causal link, the right to a fair proceeding for an interested party is simply deprived, as it is unable to state its opinions effectively before the Designated Authority.
- xv. The claim of the petitioner regarding excess capacity in China is unsubstantiated argument when it is necessary to demonstrate not only the existence of excess capacity but how such excess capacities would be diverted to India in the event of revocation of duties.
- xvi. Any attempt of evasion of duties is required to be strictly dealt with under the relevant provisions of the law but the same is not any argument to suggest that the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
- xvii. The Applicant has not submitted any reliable actual information and data is from unreliable secondary source based on net weighted averages.

- xviii. The petition suggests no nexus between the performance of the domestic industry and imports from the subject countries. The injury information as provided in Proforma IV A suggests that the domestic industry has not suffered any injury on account of continued imports from the subject countries. The imports from subject countries are attracting anti-dumping duties as high as 266% and if the domestic industry has suffered any injury thereafter, such injury is self-inflicted and not on account of any alleged dumping of PUC.
- xix. Even after lapse of years since imposition of anti-dumping duty on PUC, the domestic industry has not taken steps towards capacity building. There are certain high-end equipments included within PUC, which the Applicant does not have the capacity to produce. The Applicant cannot be allowed to take protection by imposition of anti-dumping duty when alleged injury to the Applicant is self-inflicted and is caused on account of the inefficiencies of the Applicant
- xx. The intent of the Applicant is to unfairly curb imports and monopolize domestic market in India.
- xxi. It is not the present level of dumping and injury which is important but the likely dumping and injury, which is more essential in a sunset review investigation. It is the practice of the Designated Authority to conduct post POI examination in a sunset review investigation. The Petitioner has not provided any post POI data to indicate continuance of dumping or injury being caused to it, in order to claim likelihood of recurrence of dumping and injury.
- xxii. The Petitioner has not provided data on capacity and capacity utilisation for the injury period.
- xxiii. Not only has Petitioner been unable to substantiate existence of continued dumping, but it has also failed to substantiate likelihood of recurrence of dumping and injury in future, if anti-dumping duties are revoked.
- xxiv. The Petitioner's profit/loss for the subject product, cash profit and PBIT have significantly improved over the injury period. The Petitioner's losses were least in the POI, even though imports from subject countries in the POI annualised had increased. The Petitioner's situation has been continuously improving over the injury analysis period and this trend is likely to continue in the future. Even after such heavy anti-dumping duties, if Petitioner is still not able to make profits, then it means there is something inherently wrong with the Petitioner.
- xxv. The Petitioner's data indicates consistent increase in depreciation over the injury analysis period. It seems that the Petitioner has invested significantly in new plant or machinery, which has led to high depreciation cost. If that is the case, the Petitioner's profits will naturally show a decline.
- xxvi. ROCE was -280 indexed points in 2011-12, which significantly improved to -66 indexed points in 2012-13. ROCE further improved during the annualised POI when it became -52 indexed points.
- xxvii. Interest cost substantially increased during the annualized POI. Such high interest cost is the reason that the Petitioner has been unable to improve its profitability.
- xxviii. The Petitioner is incorrect in stating that it could not increase its prices and there is price depression and suppression. The Petitioner's prices have drastically increased during the injury analysis period.
- xxix. None of the parameters mentioned above demonstrate that the domestic industry is facing injury. Profits, cash profits, PBIT and return on investment have continuously improved in the injury period. Huawei India, which also strongly claims to be domestic industry, has emphatically admitted during the public hearing that it is making profits in the same market where the Petitioner is claiming to suffer losses. Any injury to the Petitioner is definitely due to other reasons and not due to imports of the subject product.
- xxx. Despite such high protection, the domestic industry is deceptively claiming likelihood of recurrence or continuation of dumping and injury in the present case without any supporting data.
- xxxi. Sub-para (iii) of para (4) of Annexure III to AD Rules requires the Designated Authority to consider the best capacity utilisation over the past three years and period of investigation, while arriving at the non-injurious price. However, Petitioner has not even provided data pertaining to capacity utilisation in the petition. Similarly, sub-para (ix) of Para (4) of Annexure III to AD Rules provides that while examining the reasonableness of interest cost, details of term loans, cash credit limits, short term loans, deposits and other borrowings taken by the company need to be examined in detail.
- xxxii. The Petitioner has failed to acknowledge in Section V (Causal Link) of the petition that developments in technology are a relevant factor due to which demand of the subject product has been reducing over time. Injury due to such a factor cannot be attributed to imports of the subject product.
- xxxiii. Firstly, the Petitioner has made gross errors in computing import volumes in this case. Secondly, without prejudice to the above contention, the import data provided by the Petitioner itself shows decline in imports in the injury analysis period. Thirdly, it is impossible for imports to increase in light of such heavy anti-dumping duties on the subject product.

- xxxiv. Existence of surplus production capacity cannot be taken as posing a clearly foreseen and imminent threat of injury.
- xxxv. There is no information provided in the petition with respect to non-injurious price or price underselling analysis. The Petitioner has considered its own price that it offered in various tenders as export price in the petition. As a natural corollary, the Petitioner used its own price to arrive at the landed price of the subject product in India from both China PR and Israel. Petitioner has not determined non-injurious price based on principles enunciated under Annexure III of the AD rules. Such an arbitrary approach cannot be accepted.
- xxxvi. When the Petitioner has not even provided any information with regard to price undercutting, how can it claim price undercutting in the present case? Petitioner's claim in this regard has to be rejected outright. The Petitioner's data itself demonstrates that there is no price pressure on it from alleged dumped imports due to which it has been forced to sell at sub-optimal prices.
- xxxvii. In determining the non-injurious price for domestic industry, the AD Rules provide for a reasonable rate of return to be included. It would be quite unjustified on the part of the domestic industry to claim an exorbitant rate of return and the Designated Authority to allow such return as it may result in unduly high non-injurious price and thus colour the entire injury analysis.
- xxxviii. The imports by the subject countries in the period of investigation are the lowest in the last ten years. Further, the imports have seen a decline of 50% in the injury period itself. Therefore, an analysis of the import volume proves that there is clearly no indication of likelihood whatsoever.
- xxxix. India is no longer as large a market as it was. As the demand in India in the period of investigation has declined by 60% from 2010-11, India presently does not have the demand to attract any potential exports.
- xl. The volume of imports from Huawei China being at a minimal level during the POI, the question of recurrence of dumping does not arise.
- xli. The DI has not been able to establish continuance of any "supposed injury" and therefore this question necessarily has to be reviewed, during the present sunset review proceedings. Therefore, the question of determination of injury to the domestic industry is still open during the sunset review.
- xl.ii. The fact of continued dumping is baseless. During the period of investigation for the sunset review, Huawei India has made only five imports from Huawei China and even these imports have been restricted only to the products which have not been manufactured by the DI and the same were meant to meet the pending obligations under the erstwhile agreements.
- xl.iii. Huawei India undertakes the said 'substantial transformation' for the goods manufactured by it in India, and such production even constitutes a 'major proportion' of the domestic production. Therefore, it offers a healthy competition to the alleged DI against which, the alleged DI has not been able to sustain itself. Accordingly, this so called injury is due to the stiff competition offered by Huawei India on account of the domestic production of the PUC by it.
- xliv. The DI's sale and profits fell sharply immediately after imposition of ADD while results should have been just the opposite. The DI's exports also dropped / did not improve which as such were not impacted by dumping. Thus drop in sale of the DI products cannot be attributed to alleged dumping since the DI was recording higher sale in the no ADD period.
- xl. v. Breach of Causality: The Authority must establish a causal link between the injury suffered and the subject imports. It is submitted that there is a severe breach in causality in the present investigation, which arises primarily out of the plummeting demand in the Indian market and the poor investment choices of the Petitioner.
- xl. vi. Inefficiencies of the Petitioner: It is submitted that another reason that the Petitioner has suffered injury is its own operational inefficiency and poor managerial decisions. A glaring example of this is the fix asset investments made by the company in 2010-11 and 2011-12. While demand for the product under consideration was plummeting, the Petitioner was making heavy investments in fixed assets for the product under consideration. It is not surprising that in a poorly performing market, the Petitioner ended up suffering a loss after making such heavy investments. Thereafter, the profitability of the Petitioner has only improved except for the skew suffered from 2010-11 to 2011-12 which was evidently on account of the above. Therefore, it is submitted that there is no correlation between the imported Product under Consideration and the injury faced by the Petitioners. Evidently, there are non attributable factors such as the Petitioner's inefficacy and the decline in demand which have caused an injury to the Petitioner.
- xl. vii. Absence of causal link between alleged dumping and injury caused to domestic industry: - The demand for PUC has recorded significant decline. This shows that there is no causal link between alleged dumped imports and any continued injury to the Applicant and the continued injury being caused is on account of other factors such as decline in demand for PUC. The Applicant wrongly concludes that demand for the subject product is likely to

increase in India in view of tenders which are likely to come up. The truth is that SDH technology will phase out soon and will be replaced by DWDM, OTN and PTN technology. These are much better technologies that provide higher network bandwidth and also provide network access at high speeds to larger distances. In fact, network suppliers are already shifting to these technologies and have demanding the same in their tenders. The Applicant cannot expect its production for the subject product to increase as SDH technology is slowly being phased out by all users.

- xlvi. Given that development in technology has resulted in multiple products / functions being available in one single unit which hitherto were available only as independent products, likewise development in technology has resulted in SDH, OTN and DWDM being available together in one box, which earlier were available as separate products only. Given this important development, levy of anti-dumping duty should be restricted to only those goods which are SDH as a whole and not where SDH is part of one box having multiple technologies.
- xlix. Apart from the competition faced by the domestic producers, one another factor to be considered for the decline in demand of the product of the alleged DI is the development in technology. The injury margin should be calculated PCN wise so as to depict the clear picture in the context of the price behavior of the exporter in their domestic and export market.
 - 1. The Authority is requested to grant fresh opportunity to present the views orally due to the reason that the petitioner has filed the petition for the POI consisting of April 2013 - March 2014, but the POI has been extended by the Authority vide notification dated 06.12.2014 by three months
 - li. The Petitioner has provided contradictorily information regarding imports from the subject countries in different parts / section of their petition. The Petitioner has claimed that the selling price has declined even more than the decline in the cost resulting in price depression. However, on the contrary the information provided in the petition shows that the average selling price of the so-called domestic industry has increased consistently and significantly from 100 in the base year to 152 in the POI. Therefore, it is amply clear that there is no price effect on the so-called domestic industry on account of imports from the subject countries.
 - lii. The Government companies are floating tenders. However, the DI is not participating for the products under PUC which may be based on the fact that the DI either does not have the capacity to supply or the technology to support. The DI should be directed to explain their failure in participating in the tenders for domestic supply of the products under the PUC to the Government companies. Furthermore, the alleged DI shall be directed to provide details with respect to the participation and success rate in such tender during the tenure of the said levy.
 - liii. The DI also alleged during personal hearing that overseas suppliers are granting long credit periods to Indian customers to push sale of their goods. On perusal of Balance Sheets of DI for different years available on the website of Ministry of Corporate Affairs, it appears that DI is also granting similar credit to their customers and their outstanding was as high as 50% of their sales. Also average 14-15% of sales was made with credit period of more than 180 days.
 - liv. The DI has alleged that its products are suffering price suppression/depression on account of the low prices of the imported products. Further, it is alleged that the DI has lost tenders on account of such lower pricing of imported products. In this regard, it is submitted that the alleged DI has nowhere provided any evidence to substantiate its claim that the imported goods have lower pricing. It is clear that the DI is not engaged in R&D with respect to the PUC in as much as it has admitted that there is not much scope for R&D left therein. Therefore, it is submitted that if the DI's R&D activities are not undertaken with respect to SDH transmission equipment, but some other products (i.e., products not covered within the scope of PUC such as OTN/DWDM), then the cost of such R&D ought to be regarded as irrelevant to the present review/investigation and thereby, kept out of the computation undertaken for the determination of injury margin for the alleged dumping in the present case. Accordingly, it is requested that the DI be directed to provide details of the nature of R&D undertaken by it and with respect to what products such R&D has been undertaken.

Submissions made by the Domestic Industry

- 65. The following are the submissions made by the domestic industry with regard to injury and causal link:
 - a. Dumped imports from subject countries have remained significant despite anti-dumping duty. The deployment of imported SDH equipment by various consumers in general and deployment of Huawei equipment by various consumers in particular establish that the domestic industry has suffered significant injury despite existing anti dumping duties.
 - b. The subject imports have increased in relation to total imports and consumption in India despite anti-dumping duty.
 - c. The subject imports are undercutting and underselling the prices of domestic industry to a significant extent. The price undercutting is despite low prices already kept by the domestic industry.

- d. The imports are preventing the price increases that would have occurred in the absence of dumped imports. The imports are causing both price suppression and depression. Resultantly the domestic industry is faced with negative profits, cash profits, PBIT and return on investment. The market share of the domestic industry had declined whereas that of the imports from subject countries has increased.
- e. As regards the argument that petitioner has not provided data on capacity and capacity utilisation for the injury period, the petitioner refer and rely on the original final findings wherein the issue has been settled
- f. The sales with the domestic industry declined in 2011-12 but increased thereafter. It is submitted that since the domestic industry kept its prices matching to the import prices, the sales volumes and consequently production improved over the period. However the volume of sales is far lower that what the company has achieved in the past or in the base year of the injury period
- g. The profits earned by the petitioner from production and sale of the product under consideration in the domestic market declined over the injury period. So significant has been decline in the profits over the years that the petitioner has suffered financial losses since 2011-12. Consequently, return on investments and cash flow also deteriorated. This is a situation when anti-dumping duty is in existence. Cessation of anti-dumping duty and non enhancement of current duty would lead to much worse situation of the domestic industry. The domestic industry is unable of increase its profitability due to the fact that the importers are importing the product claiming it as non SDH and the evading the duty. Therefore, the remedial effect of anti-dumping duty is undermined.
- h. Despite the fact that the petitioner is India's first optical networking product company which is innovating and creating significant intellectual property, and anti dumping duty is in place, the market share of domestic industry has not increased. The same has, in fact, declined due to continued dumping of the product under consideration in India.
- i. Whereas the petitioner had expected to increase its market share by introduction of new products to expand its range, the market share of the petitioner has declined over the years because of presence of dumped imports in the market
- j. The wages have declined significantly during the POI as compared to 2011-12.
- k. In a technology product, the R&D needs to be done in every 6 months unlike other products. The products need to be upgraded with the increased demand of the customers. R&D is not required only for a new product but to upgrade the new products as well to meet the requirement of the market.
- l. The parties are wrongly interpreting the data to suit their purpose. The depreciation has increased only mildly.
- m. The opposing interested parties failed to note that the petitioner is faced with negative return on investment which in itself is sufficient to establish the injury suffered by the domestic industry.
- n. Interest cost to the domestic industry has reduced from 100 points in the base year to 71 points in period of investigation. The interest cost has declined over the period.
- o. The petitioner has significant export activities. Its profits in combined operations in domestic and exports continue to be positive. However, export profits are at present financing the domestic losses. It may be appreciated that no company can survive in the long run on such basis. Dumping has created very adverse situation for the domestic industry.
- p. The legal requirement is either establishment of price undercutting or price suppression or price depression. Price undercutting is not a mandatory condition to establish price effect. The petitioner offered some price and yet lost the order establishes that the prices offered by the foreign producers were lower. However, since exporters and producers have responded to the present investigation, the price undercutting can be determined PCN wise at this stage
- q. The petitioner never disputed increase in selling price during the period of investigation. However, the cost of sale has increased but domestic industry is unable to increase its price in proportion to increase in cost or to the level of cost.
- r. The domestic industry is suffering financial losses since 2011-12. The opposing interested parties have put forth their arguments without any factual basis. As regards the claim of Huawei India, the company has nowhere in their submissions stated that they are earning profits. Nor the interested parties have provided any evidence to establish that Huawei India is a producer of the product under consideration or it is earning profits.

- s. There is no legal requirement to provide information of price underselling and injury margin. However, the petitioner has provided information to the best of its ability. Now that the exporters have responded, the injury margin would be determined on the basis of the information filed by them
- t. The petitioner also claims that the Authority should determined Non Injurious Price on the basis of the return on investment as per the company norms and not 22% arbitrarily. Annexure III provides guidelines to determine Non Injurious Price. However it also has to be seen from case to case basis. Final findings of the Authority in the original case is referred and relied upon
- u. The Petitioner submits that development in technology means a new technology which replaces the previous one. For example CDR to pen drives. However, the upgradation of technology is the natural phenomena and every technological product needs to be upgraded from time to time to meet the demand of the customers. An SDH equipment (i) converts voice and data into digital signals, (ii) bundle them into packets (iii) transmits the same from one place to other place and (iv) decodes and segregates the same into voice and data for delivering to customer. With the higher usage of voice and data, there was a need for enhancing/upgrading the capacity of the SDH equipment. Further the SDH equipment needs to be upgraded from time to time in order to meet the requirement of the customers and to make the product more efficient. This upgradation process requires lots of R&D. Thus, the product under consideration is being constantly upgraded to higher versions, which may be sold by different names. The Designated Authority should clarify that the scope of the product under consideration is "SDH transmission equipment" in any of its form and includes all upgraded versions of the product under consideration.
- v. The petitioners submit that the dumping and consequent injury to the domestic industry is considered for the period pre-determined at the stage of initiation. Any consequent development is of no relevance. The proposition of the opposing interested parties will skew the sanctity of the period of investigation and its relevance.
- w. Despite high protection, the domestic industry is faced with continued dumping and is suffering injury. The imports are entering the Indian market in huge volumes and the importers are resorting to all sorts of methods to avoid payment of anti-dumping duty and bringing the product into India. DRI investigations have already proved the same. In the event of cessation of anti-dumping duty, these importers will have open access to dumped imports to the detriment of domestic industry.
- x. The anti-dumping duty is not against imports per se. The anti-dumping duty is against unfair imports. The petitioner on the basis of positive evidence established that there is continued dumping causing injury to the domestic industry which itself is sufficient to prove likelihood of dumping and injury in the event of cessation of anti-dumping duty.
- y. Decline in demand for the product under consideration is because of the following factors:
 - i. Significant drop in procurement by the Govt. owned/controlled entities due to 2G spectrum scandal
 - ii. MTNL and BSNL are struggling financially
 - iii. Hyper competition resulting in unprofitable tariff levels
 - iv. Reclassification or misclassification- DRI investigations have revealed how imports of product under consideration are being declared as non SDH and have been misclassified. This has further led to understated demand.
- z. The Petitioner in any case is suffering due to decline in demand and the imports have intensified its injury. It is submitted that dumping need not be the only or primary cause of injury
 - aa. If India is no longer a large market to attract potential exports, then why at all the exporters have objection to extension of duty. Evasion of anti-dumping duty proves the desperation of the importers to bring in the dumped product in the Indian market. It shows clear likelihood of continuation of dumping and consequent injury to the domestic industry
 - bb. The statement of the interested party that imposition of duty as high as 266% has the capability to greatly change the trend of demand and supply in the market itself proves that the imports have been curbed due to imposition of duty and with the cessation of anti-dumping duty imports from China would increase.

Examination by the Authority

66. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties. However, the specific submissions made by the interested parties, and considered relevant, are addressed by the Authority herein below;

A. Volume Effect

Assessment of import volumes

67. The Authority had called for the imports data pertaining to the PUC from the DGCI&S. which was made available to the Authority by the DGCI&S. The Authority as per its past practice in a large number of investigations has adopted the import volumes as reported by the DGCI&S. Accordingly, the assessment of import volumes is seen as under.

	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI (Annualised)	POI (April, 2013-June, 2014)
Imports						
Subject Countries						
-China PR	Nos	18	4,847	5,206	1907	2,384
-Israel	Nos	37,954	20,100	5,180	9,583	11,979
Subject Countries as a whole	Nos	37,972	24,947	10,386	11,490	14,363
Other Countries	Nos	1,441	1,127	1,077	2,483	3,104
Total Imports	Nos	39,413	26,074	11,463	13,973	17,467

68. It is seen that the imports of the subject goods from China have increased from the base year till 2012-13 and thereafter decreased in the POI. From Israel, though the imports declined from 2010-11 till 2012-13 but in the POI the imports increased over the previous year.

Assessment of demand

69. The Authority has determined the demand or the apparent consumption of the subject goods in the country as the sum of the domestic sales of the domestic producers and the imports from all sources. The demand so assessed can be seen in following table.

Demand	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI (Annualised)	POI
Sales of Domestic Industry (in domestic market)	Nos	20,069	6,263	5,970	6,454	8,067
Sales of Others (in domestic market)	Nos	7,379	3,407	2,093	2,138	2,673
Imports from Subject Countries						
-China PR	Nos	18	4,847	5,206	1907	2,384
-Israel	Nos	37,954	20,100	5,180	9,583	11,979
Imports from Subject Countries as a whole	Nos	37,972	24,947	10,386	11,490	14,363
Imports from Other Countries	Nos	1,441	1,127	1,077	2,483	3,104
Total Demand/Consumption	Nos	66,861	35,744	19,526	22,565	28,206
Sales of Domestic Industry in Total Demand	%	30	18	31	29	29
Sales of Others in Total Demand	%	11	9	10	8	8
Imports from Subject Countries in Total Demand						
-China	%	0	14	27	9	9
-Israel	%	57	57	27	43	43
Imports from Subject Countries as a whole in Total Demand	%	57	71	54	52	52
Imports from Other Countries in Total Demand	%	2	3	6	11	11
Total Demand/Consumption	%	100	100	100	100	100

70. It is seen that the total demand of the subject goods has decreased substantially from the base year till 2012-13 and increased thereafter. The sales of the domestic industry have shown declined throughout the injury period in comparison to the base year. Further, the total imports of the subject goods from the subject countries in the total demand has shortly increased during the injury period as compared to the base year.

Import volumes and market share

71. With regard to the volume of the dumped imports, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Annexure-II (ii) of the anti-dumping rules provides as under: -

“While examining the volume of dumped imports, the said authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India”

72. The market share of the dumped imports from the subject countries is given in following table.

	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI (Annualised)	POI (April, 2013-June, 2014)
Imports						
Subject Countries						
-China PR	Nos.	18	4,847	5,206	1907	2,384
-Israel	Nos.	37,954	20,100	5,180	9,583	11,979
Subject Countries as a whole	Nos.	37,972	24,947	10,386	11,490	14,363
Other Countries	Nos.	1,441	1,127	1,077	2,483	3,104
Total Imports	Nos.	39,413	26,074	11,463	13,973	17,467
Total Demand/Consumption	Nos.	66,861	35,744	19,526	22,565	28,206
Total Production	Nos.	28,178	9,769	9,669	11,773	14,716
Market Share in Imports:						
Subject Countries-						
-China	%	0.05	18.59	45.42	13.65	13.65
-Israel	%	96.30	77.09	45.19	68.58	68.58
Subject Countries as a whole	%	96.35	95.68	90.60	82.23	82.23
Other Countries	%	3.65	4.32	9.40	17.77	17.77
Subject Countries Imports in relation to:						
Total Imports	%	96.35	95.68	90.60	82.23	82.23
Demand	%	56.79	70.23	53.70	51.81	51.81
Production	%	135	255	107	98	98

73. It is seen that the market share of the imports of the subject goods from the subject countries in relation to total imports of the subject goods has declined throughout the injury period but still remains significant. Further, the market share of the imports of the subject goods from the subject countries in relation to total demand of the subject goods in India has declined over the injury period. Also, whereas the imports from the subject countries in percentage terms have remained significant, the production percentage of the Indian production has declined.

B. Price Effect

74. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority examined whether there has been a significant price undercutting and underselling by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

Price Undercutting

75. For the purpose of determining the price undercutting in respect of the subject countries, the Authority has determined the landed value for the subject countries for the Period of Investigation on the basis of the response filed by the cooperative exporters from the subject countries. This was necessitated because in the DGCI&S data for the injury period, PCN to PCN mapping/matching was not possible as the DGCI&S import data does

not give complete information to construct the PCNs. Further, each consumer procures SDH equipment meeting its specific requirement. SDH equipment used by a consumer at one station might differ from SDH equipment used at other stations in terms of associated physical and optical properties. Therefore, the PCN to PCN matching/mapping of the subject goods of the domestic industry vis-à-vis the exported subject goods of the cooperative exporters was done for the POI as these parties had provided the PCN wise details. A comparison of the Net Sales Realisation (NSR) of the domestic industry with the landed values of so determined for the cooperative exporters from the subject countries for the POI shows that the price undercutting margin is significant in respect of China PR and negative in respect of Israel.

SN	Particulars	Unit	POI (April, 2013-June, 2014)
A	China PR		
	Landed Value	Rs./No	***
	Net Sales Realisation	Rs./No	***
	Price Undercutting	Rs./No	***
	Price Undercutting	%	***
	Price Undercutting Range	%	35 to 50
B	Israel		
	Landed Value	Rs./No.	***
	Net Sales Realisation	Rs./No.	***
	Price Undercutting	Rs./No.	***
	Price Undercutting	%	***
	Price Undercutting Range	%	(-) 180 to 195
C	Subject Countries		
	Price Undercutting	Rs./No.	***
	Price Undercutting	%	***
	Price Undercutting Range	%	(-) 35 to 50

Price Underselling

76. For the purpose of determining the price underselling in respect of the subject countries, the Authority has determined the landed value for the subject countries on the basis of the response filed by the cooperative exporters for comparing it with the corresponding Non-Injurious Price of the domestic industry. This was necessitated because in the DGCI&S data for the injury period, PCN to PCN mapping/matching was not possible as the DGCI&S import data does not give complete information to construct the PCNs. Further, each consumer procures SDH equipment meeting its specific requirement. SDH equipment used by a consumer at one station might differ from SDH equipment used at other stations in terms of associated physical and optical properties. However, this PCN to PCN matching/mapping of the subject goods of the domestic industry vis-à-vis the exported subject goods of the cooperative exporters was done for the POI as the domestic industry and the cooperative exporters had provided the PCN wise details. Further, the products exported by different cooperative exporter are different in features in the sense that some have exported only equipments and some have exported equipments as well cards or only cards, and the domestic industry has used only the equipments. Therefore, for most of the PCNs, mapping/matching of PCNs of the domestic industry with the PCNs of the cooperative exporter has been done by constructing the cost of these PCNs on the basis of the cost of the parts and components of the domestic industry except where equipment to equipment PCNs matched. As a consequence, the NIP of the domestic industry for each individual cooperative exporter is different. For China PR, weighted average NIP of the cooperative exporters has been taken. A comparison of the Non Injurious Price (NIP) of the domestic industry with the landed values of so determined shows the price underselling margins as under.

Particulars	UOM	China PR	Israel
NIP	Rs./No.	***	***
Landed Price	Rs./No.	***	***
Price Underselling	Rs./No.	***	***

Price Underselling	%	***	***
Price Underselling	% Range	70 to 80	(-) 5 to -10

Price suppression & price depression

77. In order to determine whether the imports of the product under consideration are suppressing or depressing the prices of the product under consideration in the domestic market, the Authority has considered the trends in the cost of sales and the sales revenue for the domestic industry as per the data provided by the domestic industry. The relevant information is given below.

Parameters	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI Annualised
Cost of sales	Rs./No.	***	***	***	***
Trend	Index	100	174	186	196
Selling price	Rs./No.	***	***	***	***
Trend	Index	100	116	161	159

78. It is seen that though the selling price of the domestic industry has increased throughout the injury period, the trend of the cost of sales shows that the cost of sales of the domestic industry has increased much more than the corresponding selling price, resulting in price depression and suppression.

Examination of Economic Parameters relating to Domestic Industry

79. Annexure II to the Antidumping Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise capital investments. Various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

Capacity and capacity utilization:

80. The Petitioner claimed that the core of production in this industry is in the design and development of the product. The actual process of manufacturing and extent thereof can be in house or outsourced depending on requirement. The petitioner claimed that it can meet the entire Indian demand without any addition to plant and machinery, since producers in this industry leverage the capacities of Electronic Manufacturing Services partners, who in turn have enough capacities to meet the next 10 years requirements of India. In other words, capacity and capacity utilization must be seen in terms of intellectual property and ability of the company to deploy qualified personnel to carry out necessary design and development and manage its global supply chain. On this account, the petitioner has sufficient capacity to meet the Indian demand. In view of the same, the petitioner claimed that capacity and capacity utilization may be considered irrelevant parameter in the present case.
81. The Petitioner also claimed and no interested parties disputed that production of the product under consideration is extremely peculiar. Further, the petitioner claimed that capacity to produce is not an appropriate parameter in the fact and circumstances of the present case as the manufacturers decide to outsource part production activity depending on a number of factors. The Authority holds that petitioner's claim on this score is correct.

Production and sales volumes

82. The production and the sales volumes of the domestic industry moved as shown below:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI (Annualised)	POI
Production	Nos.	***	***	***	***	***
Index	<i>Trend</i>	100	32	37	48	48
Domestic Industry Sales	Nos.	***	***	***	***	***
Index	<i>Trend</i>	100	31	30	32	32

83. It is seen that the production trend of the domestic industry shows that the production declined significantly in the year 2011-12 in comparison to the base year but from 2011-12 till the annualised POI, it showed significant increasing trend. The domestic industry's sales trend shows that the domestic sales also declined significantly in the years 2011-12 and further in 2012-13 in comparison to the base year but in the POI, the domestic sales increased.

Factors affecting prices:

84. As stated before, the landed price of imports being offered by foreign producers are significantly below the selling price of the domestic industry. As a result of significant price difference between the imported product price and domestic industry price, consumers have switched over part of their demand to the imported product. Further, the domestic industry has been forced to reduce its prices not only in subsequent supplies to the same customer, but also supplies to other customers in the market as well.
85. The domestic industry claimed that there is dramatic decline in the prices offered by Chinese suppliers. As a result of continued competition from foreign suppliers and loss of business, the domestic industry has been lowering its prices with every successive offer. The imports are, therefore, clearly having significant price depressing effect in the Indian market.

Profit/Loss

86. The profit/loss of the domestic industry was determined in respect of its domestic operations. The verified information showed as follows.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI (A)	POI
Profit/Loss	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Index	<i>Trend</i>	(100	(1161)	(518)	(777)	(777)
Cash Profits	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Index	<i>Trend</i>	100	(116)	23	(22)	(22)
ROI	%	***	***	***	***	***
Index	<i>Trend</i>	100	(484)	(112)	(338)	(338)

87. It would be seen that domestic industry is suffering losses over the injury period. However, losses suffered by the domestic industry have increased during the period of investigation as compared to the base year. The domestic industry is suffering cash losses and negative return on investment during the period of investigation.

Inventories

88. The petitioner claimed that the product under consideration is produced only after taking firm order based on detailed specifications and these goods are not kept in inventories. The Authority holds that inventories are not a parameter reflecting injury to the domestic industry.

Employment, wages and productivity

89. From the information given below, the Authority notes that the employment has declined since 2012-13 and the wage position of the domestic industry has increased mainly due to enhancement of capacities, but productivity in terms of production per day and production per employee show decline.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI (A)	POI
Employment	No.	***	***	***	***	***
Trend	<i>Index</i>	100	101	91	79	79
Productivity	Nos/Day	***	***	***	***	***
Trend	<i>Index</i>	100	31	34	48	48
Wages	Rs. Lakh	***	***	***	***	***
Trend	<i>Index</i>	100	126	103	101	101
Wages	Rs./MT	***	***	***	***	***
Trend	<i>Index</i>	100	399	274	209	209

Ability to raise funds

90. The petitioner claimed that investments in plant and machinery are not a critical factor in the present case. In fact, funds requirements in this industry are more on account of working capital than in fixed assets. Ability of this industry to raise funds may, therefore, seriously be affected with the present level of profitability of the domestic industry.

Assessment on Injury

91. Having regard to the information made available by various interested parties and the investigation conducted, the Authority notes that the subject imports in have remained significant in absolute terms and in relation to production & consumption in India. There is significant decline in the import price over the injury period. The imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry in the market. The imports are also depressing the prices of the product under consideration in the domestic market. The performance of the domestic industry deteriorated in terms of profits, return on investment, cash flow and growth despite the anti-dumping duty in existence during the period under investigation. The deterioration in the performance of the domestic industry during the injury period is quite significant.

Causal link and Analysis of Other Factors

92. Having examined the existence of material injury and volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic market in terms of its price undercutting, price underselling and price suppression and depression effects, the Authority has also examined whether other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Anti Dumping could have contributed to injury to the domestic industry. Therefore, the following parameters have been examined:
- i. Imports from third countries: - Imports from the countries not under investigation are either insignificant or at prices higher than the import prices from the subject countries and, therefore, do not affect the prices in the domestic industry.
 - ii. Contraction in Demand: - The demand for the subject goods decreased up to 2012-13 in comparison to the base year but showed increasing trend thereafter. Therefore, possible contraction in demand cannot be attributed to the injury to the domestic industry.
 - iii. Pattern of consumption: - No significant change in the pattern of consumption has been noted.
 - iv. Conditions of competition: - The goods are freely importable. The applicant is the major producer of the subject goods. Therefore, the domestic competition could not be attributed to the injury to the domestic industry. No other evidence of conditions of competition or trade restrictive practices has been brought to the knowledge of the Authority.
 - v. Developments in technology: - It is noted that there were no significant changes in the technology relating to SDH items covered under the PUC which could have caused injury to the domestic industry.
 - vi. Export performance of the domestic industry: - There is no evidence on record to show that exports of the Domestic Industry have any impact on its performance considered hereinabove.
 - vii. Productivity: - The productivity of the domestic industry has improved in terms of the total output. Therefore, this cannot be attributed to the injury to the domestic industry.
93. The non-attribution analysis as above shows that no other factor other than the dumped imports from China PR have affected the domestic industry.

Factors establishing causal link

94. The analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows that the performance of the domestic industry has deteriorated due to dumped imports from the subject countries. Therefore, the causal link between dumped imports and the injury to the domestic industry is established on the following grounds:
- a. The dumped import prices and consequently the landed price of imports from the subject countries steeply declined, resulting in significant price undercutting. As a direct consequence, the domestic industry was forced to reduce the prices.
 - b. Reduction in the selling prices by the domestic industry adversely affected the profits, cash flow and return on investments of the DI.
 - c. Even though the domestic industry responded to decline in import prices, significant positive price undercutting resulted in increase in the market share of imports from the subject countries. As a direct consequence, market share of the domestic industry declined.

- d. In spite of increase in demand and reduction in selling prices by the domestic industry, the market share of the domestic industry declined due to significant reduction in landed price of imports. This retarded the growth of the domestic industry.
- e. The significantly low prices being offered by the foreign producers have prevented the domestic industry from increasing its production and sales to the level it could have in the absence of dumping.
95. The Authority, therefore, concludes that the domestic industry suffered material injury and the injury have been caused by the dumped imports from the subject countries.

Magnitude of Injury and Injury Margin

96. The non-injurious price determined by the Authority has been compared with the landed value of the exports for determination of injury margin. The comparison has been done by determining the non injurious price for the model imported in India. Separate comparison has been done and injury margin determined for each model imported. Thereafter, the weighted average injury margin has been determined considering the associated import volumes. The injury margins have been worked out as follows.

Injury Margin Table

Country	Producer/Exporter	NIP (Rs per PCN)	Landed Value (Rs per PCN)	Injury Margin (Rs per PCN)	Injury Margin % (Rs per PCN)	Injury Margin Range % (Rs per PCN)
China PR	M/s ZTE Corporation Ltd	***	***	***	***	45-55
	M/s Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd.	***	***	***	***	50-60
	M/s Huawei Technologies Co. Ltd.	***	***	***	***	35-45
	M/s Hangzhou ECI Telecommunication Co. Ltd.	***	***	***	***	75-85
	All other producers/exporters	***	***	***	***	90-100
Israel	M/s ECI Telecom Ltd.	***	***	***	***	(-)5 to (-)10
	All other producers/exporters	***	***	***	***	215-225

H. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

H1. Submissions by the Domestic Industry

97. The domestic industry submitted as under in support of its claim of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury:
- Significant dumping margin during the POI establishes that the dumping is likely to continue and intensify in the event of cessation of present anti dumping duty.
 - The imports from the subject countries are showing the increasing trend even in the presence of anti dumping duty, thereby showing that the imports would increase in the event of withdrawal of anti dumping duty.
 - The producers in the subject countries maintain huge capacities to produce the product under consideration. In case of revocation of anti dumping duty, the volume of imports is bound to increase further.
 - The landed price of imports is undercutting the prices of the domestic industry without anti dumping duty. Therefore, cessation of anti dumping duty is likely to cause significant adverse volume and price effect on the domestic industry.
 - The price at which Huawei China has been exporting the PUC to third countries are far higher than the prices at which Huawei China is exporting the PUC to India. In fact, the third countries prices of Huawei China clearly establish discriminatory prices being adopted by Huawei China in exporting the PUC to India.

- vi. The Indian market for the product under consideration is highly price sensitive. The consumers decide their source, with the price being the foremost consideration. In fact, all orders are placed on the basis of price comparison. Such being the case, availability of such low priced imports from subject country in the market would definitely cause an adverse impact over the Domestic Industry.
- vii. The subject goods of major producers are not allowed to sell the product in major countries like US, UK and Australia. India being a huge market and the closure of such markets for the Chinese producers, the dumped imports are likely to enter the Indian market in the event of cessation of anti dumping duty.
- viii. The demand of Indian market is likely to increase in view of upcoming tenders. This fact coupled with the continued dumping and material of Chinese producers being banned by major countries like US, Australia and UK, in all probability the dumped imports are likely to enter the Indian market in the event of cessation of anti dumping duty.
- ix. DRI is conducting investigations against imports of product under consideration. If such practices of duty evasions are prevailing when anti-dumping duty in force, there is a strong likelihood that in the event of cessation of anti-dumping duty, the dumped imports from subject countries would enter the Indian market at significant volumes. The factors relevant to likelihood of dumping are relevant to the likelihood of injury as well in the present case and the same are relied upon.
- x. The producers from the subject countries have significant capacity which establishes that in the event of revocation of duties, the exports to India will intensify.
- xi. Both dumping margin and injury margin in the current POI are positive and significant. The price undercutting is positive too.
- xii. The import prices are materially below selling price of the domestic industry. The consumers would therefore switch to imported product in the event of cessation of anti-dumping duty which will lead to significant increase in imports of the product.
- xiii. The domestic industry is already suffering price depression due to dumped import prices which are even below cost of sales of the domestic industry. In case of revocation of anti-dumping duty, the domestic industry shall have to reduce their selling price further to compete with dumped imports, driving it even below the cost of sales, leading to severe price injury.
- xiv. The importers during the period of anti-dumping duty have been importing the product claiming it to be non SDH to evade anti-dumping duty. The same importers are likely to bring in the dumped imports in huge volumes in the event of cessation of anti-dumping duty.
- xv. Surplus capacities have been considered as one of the parameters to prove likelihood of injury. However, continued dumping and injury to the domestic industry itself is sufficient to prove likelihood of continuation of dumping and injury.
- xvi. Minimum level of imports do not prove that there would not be recurrence of dumped imports. Huawei is attracting 266% of anti-dumping duty. The low volume of imports prove the effect of anti-dumping duty and in the event of cessation of anti-dumping duty, the imports are likely to increase. The Authority in the past has extended same anti-dumping duty when there were low volumes or even zero imports from the subject countries. The petitioner requests the Authority to adopt the same approach.
- xvii. The Petitioner has provided relevant evidence of sales restrictions on Huawei products in other countries. These documents are even available in public domain. The company by denying such facts raises serious doubts on its credibility and arguments put forth.
- xviii. There is no legal requirement to provide information on future demand. The petitioner is required to establish that in the event of cessation of anti-dumping duty, there would be likelihood of dumping and injury.
- xix. Evasion of anti-dumping duty proves the desperation of the importers to bring in the dumped product in the Indian market. It shows clear likelihood of continuation of dumping and consequent injury to the domestic industry.

H2. Submissions by the opposing interested parties

98. The opposing interested parties have made the following submissions with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury:

- i. Volume of imports between original period and subsequent periods: The Petitioner alleged that the volume of imports reported in previous cases as well as in the current period would show that volume of imports in case of subject countries have “remained quite significant” despite imposition of duty. It is submitted that the submissions of the Petitioner are contradicted by the facts placed on record by them, which indicate that the imports by the subject countries in the period of investigation are the

lowest in the last ten years. Further, the imports have seen a decline of 50% in the injury period itself. Therefore, an analysis of the import volume proves that there is clearly no indication of likelihood whatsoever.

- ii. Freely disposable present and potential capacities with foreign producers: It is submitted that nothing in the petition seems to indicate any evidence placed on record to substantiate the extent of excess capacities existing in the subject countries. Given that the claim of the Petitioner remains unsubstantiated by evidence, no further response is required to be provided until a cogent analysis corroborated by evidence is placed on record.
- iii. Price attractiveness of the Indian Market: The Petitioner has claimed that if anti-dumping duties are allowed to expire, the imports from the subject countries are likely to undercut prices of the domestic industry. It is unclear on what basis the Petitioner has made this claim as there appears to be no actual analysis or evidence provided in the petition. Yet again, the Petitioner has forwarded empty claims without a shred of evidence to corroborate them. Further, there is no claim in the petition that undercutting will be as a result of dumped prices from the subject countries. Merely claiming potential price undercutting cannot be the reason for continuation of duties ad infinitum.
- iv. Vulnerability of Domestic Industry in terms of price sensitivity of the product and the Indian market: The Petitioner again bases its claim on hypothetical price undercutting. As averred above, the Petitioner's estimations hinge on a highly speculative claim and need to be disregarded in light of the complete absence of any evidence.
- v. Market share held by the subject countries in the Indian market: The fact that the market share of the subject countries is significant does not in any manner indicate that cessation of duties will lead to dumping or consequent injury.
- vi. Sales restrictions in other countries: It is the claim of the Petitioner that major producers in the subject countries are not allowed to sell the product in major countries like US, UK and Australia. Therefore, since India is a "huge market", the "dumped" imports are likely to enter the Indian market if duties are allowed to expire. However, the Petitioner has provided no actual evidence that exports of the product under consideration from China or Israel have in fact declined to these major markets.
- vii. Future increase in demand in India: The Petitioner goes on to claim that this falling demand is likely to increase in the future. This claim is based on certain impending tenders by Network of Spectrum and BSNL – tenders for which no evidence or substantiation has been provided yet again. In any event, it is submitted that a likelihood of injury cannot be proved on the basis of a future increase in demand. The injury cannot be deemed to exist solely on the analysis of the increase in demand. The increase in demand has to be observed in the connection with other injury parameters such as the demand of the Petitioner's products. Therefore, due to the absence of a correlation between the increase in demand and the other injury parameters, this averment should be rejected.
- viii. A number of investigations by the Directorate of Revenue Intelligence: The Petitioner has claimed that the DRI is conducting investigations against imports of the product under consideration. The Petitioner then goes on to admit that it has no information about the details of such an investigation. However, despite admittedly having no information regarding this investigation, the Petitioner believes that these investigations are an indication of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury. Assuming without conceding that some producers are under investigation for duty evasion, there is still no correlation of that with the cessation of duty and likelihood implications thereof. The Petitioner's averments, therefore, ought to be disregarded out rightly.
- ix. The Petitioner has insisted that even if one of the above conditions is satisfied, the duties cannot be allowed to expire. However, as established above, not even one of the above conditions is corroborated with evidence, i.e., duly substantiated. Therefore, the petition should be rejected due to the abovementioned reasons.
- x. Application does not contain information to satisfy the condition for continuation of existing duties as set out in Rule 23. The Applicant has determined substantial dumping margin in the Petition on some hypothetical basis. But the fact of the matter is that as provided by the Applicant itself, the export price is based on Applicant's price and not actual 'export price' which is untenable under the AD Act and the Rules.
- xi. The claim of the Applicant that imports even after imposition of duties remained significant is not based on any reliable information. The imports claimed by the Applicant are based on some hypothetical basis which has no evidentiary value. Thus, the Applicant failed to establish any likelihood aspect under this heading also.

- xii. As per the Applicant, the subject goods are produced against orders and they have even requested to treat capacity not as an appropriate parameter. Having made that argument considering their own capacity, how can the Applicant presume that the foreign producers have got huge excess capacity?
- xiii. The Applicant has made tall claims on price attractiveness without providing any factual information about actual price of imported PUC from subject goods.
- xiv. The petition does not contain any information to enable the Designated Authority to decide that the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The information as seen in the Application clearly shows that the expiry of duty is not likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
- xv. The claim of the Applicant that imports even after imposition of duties remained significant is not based on any reliable information. The imports claimed by the Applicant are based on some hypothetical basis which has no evidentiary value. Thus, the Applicant failed to establish any likelihood aspect under this heading.

H3. Examination by the Authority

- 99. The present investigation is a sunset review of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods from China PR and Israel. Under the Rules, the Authority is required to determine whether there is likelihood of dumping and injury to the domestic industry if the existing duties are removed and, therefore, continued imposition of antidumping duty is warranted or not. This also requires examination whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating the injurious dumping.
- 100. The Authority notes that as far as Huawei China, ZTE Corporation Ltd, China and Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd., China are concerned, there is no need to examine the post POI data as well as to do the likelihood analysis because continuous dumping and injury have been established in the POI of the present investigation in respect of these companies. As far as HETC, China is concerned, the re-examination of their data has shown that there is negligible (less than ***) dumping in the POI and in this behalf, the Authority has, therefore, examined the post POI exports to India as well as third countries and found that the same were un-dumped. Therefore, there is no likelihood of dumping. As far as ECI Telecom, Israel is concerned, it is seen that the exports of the PUC to India in the POI and to India as well as third countries in the post-POI are not at dumped prices and thus there is no likelihood of dumped imports from ECI Telecom, Israel if the duty is revoked. Still, the Authority has carried out the likelihood analysis. Regarding the claim of the Domestic Industry with respect to freely disposable present and potential capacities with foreign producers, no tangible evidence has been provided by the domestic industry, which has itself claimed that since the manufacturing of the assemblies is outsourced, capacity does not have much relevance meaning. Regarding the claim of the Domestic Industry with respect to price attractiveness of the Indian market, vulnerability of Domestic Industry in terms of price sensitivity of the product, sales restrictions in other countries impacting demand in India, market share held by the subject countries in the Indian market and the future increase in demand in India, it is seen that the demand for SDH technology is in fact in decline because new technologies are being preferred making it improbable that future demand will increase. Thus there is not any merit in the domestic industry's these claims. Regarding the claim of the Domestic Industry with respect to a number of investigations by the Directorate of Revenue Intelligence, it is seen that the present investigation is based on its independent facts and merits.

I. POST DISCLOSURE STATEMENT COMMENTS

(A) Post Disclosure comments of the opposing interested parties

- 101. The Authority notes that post Disclosure Statement submissions made by the opposing interested parties are repetitive in nature and have already been dealt with in the Disclosure Statement. The opposite interested parties have, in brief, filed the following post Disclosure Statement submissions:
 - i). The present sunset review is illegal as there is no legally valid anti-dumping duty in existence. During the original investigation, several interested parties had appealed the final findings to the Hon'ble CESTAT. The Hon'ble CESTAT disposed off the appeals by remanding the matter to the Designated Authority. By remanding the matter, the Hon'ble CESTAT had principally quashed the final findings issued vide Notification No. 14/2/2009-DGAD dated 19 October, 2010 and the Customs Notification No. 125/2010 dated 16 December, 2010. The Hon'ble CESTAT directed the Designated Authority to reconsider the issues raised by interested parties. Pursuant to this, the Designated Authority granted a post-decisional hearing to parties and issued new final findings vide Notification No. 14/2/2009-DGAD dated 10 February, 2012. However, the Ministry of Finance did not issue any customs notification pursuant to the new final findings. It is no solace to argue that the previous customs notification will continue because the Designated Authority reconfirmed the previous findings in the new final findings, as that customs notification had already been quashed by the Hon'ble CESTAT. Since there was no customs notification pursuant to the new final findings, all sets of proceedings thereafter including

collection of anti-dumping duty till date and the present sunset review are illegal. It would be prudent for the Designated Authority to terminate the present sunset review immediately.

- ii). The sunset review should have been completed within 12 months from the date of initiation. The present sunset review is illegal as the Designated Authority had failed to conclude the same within 12 months as provided in Rule 23(2) of the AD Rules. The Designated Authority has no jurisdiction to extend the time period for a sunset review as that power has not been granted to the Designated Authority in the Customs Tariff Act, 1975 and the AD Rules. For violation of Rule 23(2) of the AD Rules, the present review is illegal and should be terminated forthwith.
- iii). The time given to comment on the disclosure statement was inadequate as respondents were only provided five working days to examine the lengthy disclosure statement and file the comments. This has seriously prejudiced Respondents in defending their interests effectively.
- iv). It is reiterated that the customs department is collecting anti-dumping duties even on components / parts / spares imported on a standalone basis despite the fact that these have been specifically kept outside the purview of Product under Consideration by the Authority. Interested parties have to suffer undue hardship by paying anti-dumping duties even on those products that are outside the scope of this investigation. Therefore, it is requested to clarify the product scope in the form of a separate note in the duty table mentioning that "components / parts imported on a standalone basis including Printed Circuit Boards are outside the scope of PUC and, therefore, not subject to levy of Anti-dumping Duty". A "printed" circuit board consists of insulated board with proper conductors laminated on it. Conductors may be formed by photo chemical fetching process or by deposition. A "printed" circuit board does not contain any external material which is loaded or affixed in the slots/places/positions earmarked in the "printed" circuit board. Such Printed Circuit Board is neither an SDH equipment nor a part/component thereof.
- v). The Designated Authority has observed that STM-256 shall continue to be part of the product scope. Respondents submit that admittedly STM-256 could not be imported into India during the POI as technical approvals/permissions to deploy the same are not in place in the country. When permissions to deploy STM-256 is not even in place in India, no user will express requirement for the same and as a result, STM-256 would naturally not be exported to India nor could be supplied by the domestic industry to Indian users. Therefore, it is requested that the aforesaid observation be modified and the Designated Authority may exclude STM-256 from the product scope.
- vi). Add Drop Multiplexers (ADM) (For SDH Application only), Multiple Add Drop Multiplexers (MADM) (For SDH Application only) and Digital Cross Connect (DXC) (For SDH Application only) are covered in the PUC. As is evident, the definition does not say that these products are SDH equipments. The definition says that such equipments are included in the product under consideration only if designed for SDH applications, i.e., though such goods are not SDH equipments but may be designed to be used only with SDH equipment. If fact, these goods are equipments used between an SDH equipment and other network/board band equipments. These equipments are not used to transmit voice or data in the optical fibre as the SDH Equipment and should be kept out of the PUC.
- vii). It is an admitted position that Tejas does not manufacture broadband or cellular equipments. However, such equipments are subjected to anti-dumping duty, if certain populated boards (having technology of SDH) are used in manufacturing such equipments. There are no manufacturers of such equipments in India.
- viii). Imposition of anti-dumping duty on Multiple Products is illegal. The Designated Authority in its determination for imposition of anti-dumping duty has included many articles, which is illegal. The Authority under Rule 4 (b) has to identify the "article liable for anti-dumping duty", whereas in the present case the Designated Authority wrongly identified the articles subject to antidumping duty.
- ix). Respondents submit that during the original investigation, PTN was included in the product scope in a very arbitrary manner. While PTN was excluded from the product scope in the Final Findings notified vide Notification No. 14/2/2009-DGAD dated 19 October, 2010, it was arbitrarily made part of the product scope when a corrigendum was issued to above final findings vide Notification No. 14/2/2009-DGAD dated 22 October, 2010. The interested parties were not even given an opportunity to comment on this change of product scope during the original investigation. At least in the present review, the Designated Authority should examine on merits whether PTN should be made part of the product scope. It is to be noted that SDH and PTN are completely different technologies serving different needs. PTN or Packet Transmission Network is used to deliver Ethernet services. Though PTN may provide both PDH and SDH services (dual-functionality), it is to be noted that the original investigation and the sunset review is limited only to SDH transmission equipment/SDH transmission technology and not dual or multi-functional equipment. Therefore, PTN cannot be a part of the product scope as it is a dual-functional equipment.

- x). The present investigation being an SSR does not impose any duty on the Authority to follow an erroneous determination of PUC in the past. There are cases in India and elsewhere wherein the Authority reduced the scope of PUC in the SSR. Thus, decision of PUC in the original investigation is not an open and shut case for the Authority not to be further examined in the SSR. In the present case, there is case on merit for exclusion of certain items from PUC like PTN which the Authority may reconsider.
- xi). Normal Value for the cooperating exporters from China should be calculated based on the actual prices prevailing in China. In the instant case HETC, China has fully cooperated in the investigations and has also been granted the market economy treatment (MET). Therefore, considering the overriding provisions of Section 9A (1) (c) of the Customs Tariff Act, 1975, it would be more appropriate to consider the costs and price data of HETC for the purpose of the determination of the normal value for the exporters from China as the same have been found acceptable by the Authority as a true reflection of market economy driven costs and prices. The disclosure statement is completely silent as to why the prices of the Chinese company, which has been granted MET, are not acceptable for the purpose of determining the normal value for other producers from China.
- xii). No valid or legitimate grounds exist for not using ECI's information for determination of Normal Value for ZTE Corporation Ltd., M/s Huawei Technologies Co., Ltd. and M/s Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd. The sole ground for not adopting the information of ECI for the purpose of computing the normal value for these companies is the apparent refusal of ECI to share its PCNs. This ground is completely non-existent on account of the reasons that BOQ for these companies are to be designed based on their own PCNs and not on the basis of the PCNs of ECI. Therefore, PCNs of ECI are of no consequence. Further, once the BOQ for the PCNs is decided for the individual exporter, the Authority has to merely take into account the prices of the individual parts and components as reported by ECI. There is no compromise with regard to the claim of confidentiality by ECI as neither the PCNs nor the prices of individual parts and components are required to be disclosed to other parties. There is absolutely no reason as to why the Authority cannot take the price / cost of components of ECI, Israel to work out the normal value for these companies instead of taking the exaggerated prices / costs of the Domestic Industry.
- xiii). The Hon'ble Supreme Court in *Shenyang Matsushita S. Battery Co. Ltd. v. Exide Industries Ltd. and others*, (2005) 3 SCC 39 has observed with affirmation that the Designated Authority can resort to the last alternative only when the first two methods have been exhausted. It is submitted that the Designated Authority already has information on prices or constructed value in a market economy third country i.e. Israel in this case as ECI Israel has fully cooperated in this investigation and has provided its data to the Designated Authority. The Designated Authority also has information on ECI Israel's prices for exports to other countries. In addition to this, since the Designated Authority has awarded market economy treatment to Hangzhou ECI, China PR, the Designated Authority could have easily adopted the prices or cost of production data of Hangzhou ECI. It is incorrect to state that PCN comparison would not have been possible if ECI Israel's or Hangzhou ECI's data would have been considered. It is to be noted that both ECI Israel and Hangzhou ECI have exported full equipment to India. Further, even the domestic industry has supplied full equipment in India. If the Designated Authority could select cost of various parts of the equipment from the costing data of the domestic industry for PCN comparison, the same method could have been adopted for ECI Israel and HETC, China, so as both companies must have supplied their costing data to the Designated Authority based on which their normal value had been calculated. The Designated Authority should have at least adopted the normal value of HETC, China. It is submitted that if commercially accepted prices from cooperating exporters from China PR are available, then the same may be adopted for other exporters who have not been granted market economy status.
- xiv). The Designated Authority has denied market economy treatment to ASB on the mere ground that there is state shareholding in the company. The Designated Authority has failed to consider the submissions made by the Appellant during the course of investigation. ASB submits that mere state shareholding in a company cannot itself be a ground not to grant market economy status to exporter. The Designated Authority has denied market economy treatment to Huawei China also without valid reasons and inspite providing all the relevant documents during the verification.
- xv). The comparison of PCNs for the products exported by the exporters with that of the domestic industry is very critical in this case as quantum of anti-dumping duty is based on this analysis. It is submitted that ASB had provided detailed observations on why all the PCNs of the domestic industry were not matching with any PCN of ASB. The primary reasons for this were that i) ASB had exported only cards while the domestic industry had supplied full SDH transmission equipment during the POI, and ii) the domestic industry's PCNs were of higher configuration as almost all PCNs were supporting more than one transmission technology, i.e. SDH + OTN, etc. due to which costs of these PCNs was higher in comparison to ASB's PCNs which are single-functionality (SDH only) having substantially lower cost of production. In spite of these critical differences, the Authority has rejected ASB's comments on 10 PCNs and applied its own prudence and wisdom to construct cost of such PCNs based on the cost of domestic industry. Respondents submit that due to such an approach, ASB is afraid that PCN comparison is no longer fair and transparent as claimed by the Designated Authority because the

Designated Authority has now applied its own discretion for PCN comparison which seems arbitrary. It is submitted that due to this approach, the dumping and injury margin calculated for ASB seems incorrect and these should be recalculated in light of ASB's comments on all the PCNs.

- xvi). ASB's exports are not at dumped/injurious prices. This fact is well established from ASB's transaction-wise export data as well as ASB's prices in all the tenders which it has lost to the domestic industry. ASB had quoted significantly high prices in these tenders whereas the domestic industry had quoted significantly low prices. ASB's prices were higher even after excluding anti-dumping duty in the prices. This clearly establishes that ASB has never dumped its goods during the POI and during the injury analysis period and shall continue this in the future. Therefore, there is no likelihood of dumping and injury to the domestic industry from ASB's exports of the subject goods.
- xvii). Many substantial arguments made by Huawei concerning various contentious issues in the investigation such as erroneous constitution of PUC, lack of merit in domestic industry and standing claims, allegation of dumping and likelihood and recurrence of the same, alleged continued injury to the domestic industry, methodologies of determination of dumping margin and injury margin etc. before the Authority with undeniable evidences and supporting documents still stand unexamined with the required seriousness which those submissions warranted.
- xviii). The proposed determination of Dumping Margins for Huawei is highly flawed as a result of an improper methodology of determination of normal value proposed by the Authority. While reiterating the arguments that the denial of MET to Huawei is unjustified as provided in their comments on verification report which is once again reiterated here, it is even more unjustified that the Authority adopted an improper method to determine normal value in case of Huawei by ignoring the best options available with it. Having denied MET, unfortunately, the Authority straightaway considered the last option in the chronology of options provided in the Rules, that is, price actually paid or payable in India duly adjusted to include reasonable profit. There are no justifiable reason which has prevented the Authority from considering the initial options in the chronology though information on such basis was at the free disposal of the Authority, and it is still available. The proposal of the Authority to opt for the last option in the chronology of options in para 7 of annexure I of AD rules is not only inappropriate qua the position of Huawei, but the approach is also inconsistent with past decision of the Authority itself. The Office of Designated Authority being a quasi judicial body what is equally important is adherence to its past practices which has same effect of a legal provision.
- xix). Huawei's submission is that it is the prerogative of the Authority to use best available information and in the present case the Authority did not exercise its prerogatives and determined NV in case of Huawei based on cost of production of Indian producer which is highly distorted and too far away from the reality. The cost of production of DI has no nexus to the normal value of subject goods produced by Huawei and using such basis has caused exorbitant and unrealistic dumping margins in case of exports of Huawei. The Authority could have preserved confidentiality of information provided by the producer from Israel without any difficulty and still have used the same in case of Huawei. Thus, the dumping margin allegedly found on Huawei is not the result of any real situation of dumping practiced by the company, but the outcome of an erroneous, improper and flawed methodology of normal value determination adopted by the Authority. The cost of the petitioner is unrealistically high due to self inflicted reasons best known to them and Huawei should not be at the receiving end of such unjustified higher costs which is reflected in the exorbitant dumping margin proposed to be determined for Huawei.
- xx). Any positive dumping margin proposed to be determined in case of Huawei is merely the outcome of a wrong normal value and determination of dumping margin in a fair and appropriate manner would show no dumping in case of exports by Huawei. The methodology proposed by the petitioner and proposed to be adopted by the Authority suggests that the petitioner found consideration of Indian cost as the basis of normal value is the only way to slap anti dumping duties on exporters from China PR and there would not be any dumping margin based on any other proper basis as enshrined in para 7 of Annexure I of the rules. It is thus requested to the Authority is that the Authority should not succumb to the foul cry of petitioner for continued imposition of anti dumping. Thus, neither there is any case of continued dumping and injury nor likelihood of dumping and injury.
- xxi). An important issue which has been raised by Huawei since the beginning of the present investigation is that the petitioner has resorted to excessive confidentiality and even the disclosure statement barely discloses anything. Huawei requests the Authority to make fair disclosures about the PCN wise cost of production of petitioner used for the purpose of Normal value. There is no justification of non disclosure of this information to Huawei as the entire allegation of dumping on Huawei is based on the cost of production (COP) of petitioner. When the COP of petitioner has got a huge adverse impact on Huawei, there is no justification for not disclosing PCN wise cost details or a meaningful range at least is highly unjustified.
- xxii). The BOQ designed for ZTE's PCN includes many components, which are either not, warranted at all or excess quantities of the required components have been incorporated / integrated in the BOQ designed for ZTE's PCN. It appears that this has been done at the instance of the Domestic Industry and it is for this reason that ZTE has

been requesting for complete transparency and disclosure of the comments received from the Domestic Industry. Further, it is submitted that the BOQ, which ZTE has received from the Authority along with the disclosure statement, includes many components that were not integrated in the original BOQ. Accordingly, the Authority is requested to provide the comments of the domestic industry on the amendment suggested by ZTE on the BOQ designed for ZTE, which the Authority may have considered while finalizing the BOQ for ZTE. ZTE also requests the Authority to consider its comments to amend the BOQ for ZTE.

- xxiii). A contentious issue concerning SDH since original investigation is that Tejas Networks Ltd cannot be called as a 'domestic industry' within the meaning of AD rules by no stretch of imagination and the issues continues in this SSR investigation also. Tejas is nothing but a company engaged in some assembly of subject goods after importing the parts and consideration of Tejas as the domestic industry under Rule 2 (b) is untenable. They do not qualify to constitute the domestic industry. In the alternative, Huawei India should be considered in the ambit of domestic industry. Imports by Huawei India or its relation with the exporter is not a reason to preclude their argument completely. The Authority in the past had considered companies who have imported in the scope of Domestic Industry as per the discretions available with it. It is not either a case that the behaviour of Huawei India is that of a trader. Huawei India is clearly a producer who can be considered as the Domestic Industry.
- xxiv). The Designated Authority is willing to consider an intellectual property holder who does not manufacture in India as domestic industry, while on the other hand, is not considering Huawei India as domestic industry though it possesses intellectual property in India as well as manufactures the subject goods in India. This shows that the Designated Authority has applied different and arbitrary standards to examine domestic industry status of Tejas Networks Limited and Huawei India. It is submitted that if Tejas Networks Limited is considered as domestic industry, then even Huawei India should be considered as domestic industry as facts and circumstances of both the companies appear to be same. Further, while providing information on production in India, the Designated Authority has not provided information on other producers of the subject goods in India.
- xxv). Huawei India should have been considered Domestic Industry. It has remained undisputed that Huawei India is engaged in the domestic production of the PUC during the POI and, therefore, it should have been considered as the Domestic Industry also and its claim merely because of the reasons that it is related to the Huawei China and imported the PUC during the POI should not have been rejected. In fact import made by Huawei India during the POI were negligible which were meant to meet the requirement of pending contractual obligations at that point of time.
- xxvi). ASB submits that in the present case, negative dumping margin was calculated for ECI, Israel. Despite this fact, the Designated Authority has failed to exclude un-dumped imports of ECI Israel from the total volume of dumped imports in the injury analysis. Such a lapse has seriously distorted the injury analysis in the present case.
- xxvii). The Respondents submit that an analysis of injury parameters reveal that the domestic industry is not suffering any injury and there is no causal link between alleged dumping and injury. It is to be noted that in a sunset review, the legal threshold is to examine whether dumping and injury are likely to continue or recur if anti-dumping duty is revoked. It is apparent that demand for the subject goods has been sharply declining in India during the injury analysis period. Imports of the subject goods have also declined in a similar fashion. It is expected that demand for the subject goods will continue to decline as SDH transmission technology is on the verge of getting outdated. Users are graduating to advanced technologies such as DWDM and OTN. It is submitted that the domestic industry's real challenge is the shift in user preference to better technologies and not imports of the subject goods from the subject countries.
- xxviii). While the domestic industry is showing losses and decline in return on investment, it should be appreciated that SDH transmission technology is on the verge of phasing out. Therefore, the domestic industry should not expect high profits and returns in this segment as users are shifting their preference to advanced technologies. This is the major challenge for the domestic industry and not imports of the subject goods.
- xxix). Another reason for injury to the domestic industry is the aggressive pricing policy adopted by the domestic industry to win tenders. The prices of the domestic industry are so low that almost all bids during the injury analysis period have been won by the domestic industry. As per the information available with Respondents, the prices quoted by the domestic industry were way lower than the prices quoted by exporters.
- xxx). The domestic industry has not suffered any injury on account of continued imports from subject countries. The imports from the subject countries are attracting anti dumping duties as high as 266% and if the domestic industry has suffered any injury thereafter, then it proves beyond any doubt that the reason for injury to the domestic industry is something else and anti dumping duties has no purpose to serve.
- xxxi). Export orientation is also the cause of the injury, if any, in the domestic market. The export of the Petitioner has increased significantly from 100 in the base year to 554 in the POI.

- xxxii). ZTE submits that the Authority is requested to make the adjustments in the price of the components of the domestic industry which the Authority proposes to consider for the normal value determination on account of the facts that the domestic industry is not the manufacturer or producer of the part and components of the product concerned and has imported the same from other countries. Adjustments like Port Charges (Indian Port), Overseas Transportation (Port of Origin to India) and Inland Transportation (Factory of the exporter of the part / component to the port of Origin), Overseas Marine Insurance (Port of Origin to India), Port Charges (port of Origin), Inland Transportation (Indian Port to the factory of the domestic industry), Standard profit of the Job Worker / exporter of the part / component should be adjusted.
- xxxiii). The Designated Authority has not provided actual production and domestic sales figures for the domestic industry. These are critical volume parameters that should have been disclosed in the disclosure statement. The Authority is requested to provide the absolute numbers of production, capacity, domestic sales and exports of the domestic industry considering the consistent practice of the Authority.
- xxxiv). No valid or legitimate grounds exist for not resorting to the likelihood analysis. It is submitted that the reason provided in the disclosure statement for not doing the likelihood analysis for Huawei China, ZTE Corporation Ltd, China and Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd., China is that continuous dumping and injury have been established during the POI. In this context, attention of the Authority is invited to the fact that the reason provided in the disclosure statement for not resorting to the likelihood analysis is neither enunciated anywhere in the law nor in line with the consistent practice of the Authority. Further, it is submitted that the Authority has resorted to the likelihood analysis in plethora of cases despite the fact that continuous dumping and injury have been established during the POI. In view thereof, it is requested Authority to do the likelihood analysis in the present investigation also.
- xxxv). Huawei disputes the proposed conclusions on likelihood aspect. Without prejudice to the fact that causal link examination is more important in the present case considering the fact that there is an unusual kind of demand decline concerning the product, certain observations that there is continued dumping and injury and likelihood is obvious is an unfounded argument. It is submitted that there is neither any current dumping and injury nor any likelihood of dumping and injury in the present case. The entire case brought up by the petitioner is on manufactured facts and they are not even qualified to be true producer of the subject goods. The petitioner is attempting to ensure the continuance of duties as an ornament which is impermissible as per the essence of AD Agreement and there is no justification to the claim that there is likelihood of dumping and injury in the event of expiry of duty.
- xxxvi). The Price Undercutting is calculated only for the POI against the consistent practice of the Authority to calculate the same for the entire injury period, i.e., for the POI and the preceding 3 years. The Authority has followed the said approach in plethora of cases. In view thereof, the Authority is requested to calculate the price undercutting for the entire injury period.
- xxxvii). It is submitted that the landed value has not been considered in the price suppression and price depression analysis done in the disclosure statement in gross violation of the consistent practice of the Authority. As a consistent practice of the Authority, the landed value is to be considered while doing the price suppression and price depression analysis. The Authority has followed the said approach in plethora of cases Accordingly, the Authority is requested to also consider the landed value in the price suppression and price depression analysis.
- xxxviii). Till the stage of public hearing, Ovum Reports had been relied upon by the domestic industry for import volume and value, and information on market share. It is noted that DGCI&S data has been relied upon in this investigation for the first time in the disclosure statement. If the Designated Authority had decided to rely upon DGCI&S data in this investigation, there was an obligation on the Designated Authority to inform all the interested parties about this and provide the DGCI&S data to all interested parties. At least, the Designated Authority should have provided DGCI&S data to interested parties along with the disclosure statement so that interested parties were in a position to examine the data and offer their comments. Reliance on DGCI&S data completely changes the injury parameters, and the domestic industry should have been directed to file updated injury information, which has not happened in this case.
- xxxix). The petition filed by the domestic industry requesting initiation of the sunset review was not duly substantiated in terms in Rule 23(1B) of the AD Rules. Further, Respondents had strongly objected to the domestic industry's reliance on Ovum Reports for import volume and value of the subject goods. The Designated Authority seems to have brushed aside Respondents' contentions by observing that it has considered DGCI&S data for import volume and injury analysis. It is submitted that merely because the Designated Authority has relied upon DGCI&S data does not cure the defects in the petition filed by the domestic industry.
- xl). The domestic industry has claimed significantly high imports of the subject goods from the subject countries in the application as well in their written submissions *vis-à-vis* the import data considered by the Authority in the disclosure statement. The domestic industry has provided significantly higher imports volume to claim dumping, injury and causal link and justifying initiation of the investigation. Accordingly, it is requested to the

Authority to terminate the investigation at the earliest as a contrary approach will encourage the domestic producers to use the fabricated or misleading import data to get the investigation initiated.

- xli). HETC, China submits that the Designated Authority has rightly determined that HETC, China, on account of being wholly foreign owned and controlled, is operating under Market Economy Conditions since its costs are comparable to that of Israel. Further, the Designated Authority rightly has determined individual margins for HETC and ECI. However, the companies submit that they deny the finding of the Designated Authority with regard to the margin for HETC. The data placed on record, which was also verified in the onsite verification, clearly reflects a negative dumping margin. The exporters, therefore, request the Designated Authority to take the same into consideration.
- xl ii). As regards the various allegations regarding incomplete data being filed by ECI and HETC, the exporters submit that they have placed their complete sales data on record. Further, the exporters had also made available their detailed books and records during the time of verification and demonstrated to the Designated Authority's satisfaction that all exports to India were reported accurately. All elements of the exporters' data including volume, pricing, PCNs, cost and margins have well substantiated to the Designated Authority's satisfaction. Therefore, any allegations made against the veracity of the exporters' data may be disregarded.
- xl iii). HETC, China submits that as regards China, it is critical to note that due to competition factors, the landed price of the product exported from HETC cannot be priced substantially lower than the domestic industry's product. Therefore, HETC objects to the high injury margin calculated for HETC when in fact the goods have been sold at comparable prices in the domestic market. HETC requests the Designated Authority to reconsider its injury margin calculations.
- xl iv). It is submitted that the purpose of a sunset review is to examine whether continuation of anti-dumping duty is warranted in light of the likelihood of dumping and injury due to imports of the product under consideration. As per the provisions in the Act, the Central Government may extend the anti-dumping duty for a further period of five years if it is found that cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The provisions envisage that the same anti-dumping duty is to be continued that had been levied in the original investigation. It is submitted that in view of the above provisions, in the event the Designated Authority decides to extend anti-dumping duty, it is requested that the quantum of anti-dumping duty should not increase the duty that was imposed during the original investigation. The Designated Authority may consider continuing the same rate of duty which was levied pursuant to the original investigation.
- xl v). Further, the Designated Authority may note that several interested parties had challenged the original investigation and the customs notification pursuant to it before the Hon'ble CESTAT. It is expected that the Hon'ble CESTAT will issue its final order disposing the appeals in the next two to three weeks. In light of this, the Designated Authority is requested to issue its final findings in the present review only after the Hon'ble CESTAT's final order disposing the appeals is issued so that a proper determination is made in this case.

(B) Post Disclosure Comments of the Domestic Industry

102. The Authority notes that most of the post Disclosure Statement submissions made by the domestic industry are repetitive in nature and have already been dealt within the Disclosure Statement. Following are, in brief, the post Disclosure Statement submissions made by the domestic industry:

- i. The imports are entering the Indian market at dumped prices. The dumping margin is not only above de minimis but also substantial. Both dumping margin and injury margin in the current POI are positive and significant.
- ii. Imports were significantly undercutting the prices of the domestic industry. Further, the imports were suppressing and depressing the domestic prices.
- iii. The price depression and suppression effect of dumped imports has resulted in significant erosion in profitability of the domestic industry. In fact, profits declined to such an extent that the domestic industry started suffering financial losses and negative return on capital employed.
- iv. The domestic industry is already suffering price depression due to dumped import prices which are even below cost of sales of the domestic industry. In case of revocation of anti-dumping duty, the domestic industry shall have to reduce their selling price further to compete with dumped imports, driving it even below the cost of sales; leading to severe price injury.
- v. The producers from subject country have significant capacity which establishes that in the event of revocation of duties, exports to India will intensify.
- vi. The petitioner submits that in the past Findings the Authority has distinguished between Printed Circuit Board (PCB) and Populated Circuit board by stating that PCB are populated as per the design developed by the manufacturer and thereafter, apart from loading of software, there is only a need to arrange them in a shelf and adjust them to a circuit. Further the Authority has stated that PCB is within the scope of product under

consideration. The only situation where PCBs are beyond the scope of the product under consideration is when such PCB are not meant for production of SDH equipment. Further, it is submitted that PCB is a part of product under consideration due to the reasons that it is a propriety of the manufacturer and it has no other use apart from production of SDH equipment

- vii. It is noted that Authority has treated Huawei India as an ineligible domestic industry. However, the petitioner had contended that Huawei India does not constitute a domestic producer. In fact, the Designated Authority had recorded an elaborate finding in the original investigations on (a) meaning of production and (b) how Huawei, VMCL and Prithvi did not constitute a domestic producer. In fact, Huawei India is admittedly bringing its components and assembling the same in India and selling the product.
- viii. Regarding the dumping margin in the case of ECI, the disclosure statement states that the normal value has been based on cost of production of the producer and a "reasonable profit" has been added thereon. Petitioner submits that the rule prescribes addition of reasonable profit on the basis of actual profits earned by the company. Thus, the Authority is requested to add profit on the basis of actual profit earned by the company in accordance with the rules. The petitioner also requests the authority to determine dumping margin in respect of the third country exports and hold thereafter whether there is no likelihood of dumping and injury.
- ix. The questionnaire responses filed by Huawei China and Huawei India clearly show that the questionnaire responses filed by these parties in any case are grossly insufficient to grant them individual dumping margin. Huawei India itself claimed before the Authority prior to initiation that its share in Indian demand is significantly high. At the same time, the questionnaire response filed either by Huawei China or by Huawei India does not show this kind of sale having been made by them. If such significant Indian demand is being met by Huawei India, it follows that Huawei has sold quite significant volume of SDH equipment in the Indian market. The response filed by them does not show this kind of sales having been made by Huawei. It is, thus, evident that significant information has been suppressed by Huawei China and Huawei India while responding to the Authority.
- x. It is a clear case that Huawei India has attempted to bring in SDH Transmission Equipment in the name of components and avoid anti-dumping duties. The SDH equipment so procured by the consumers and DRI action/decision thereon clearly establish that what has been imported into India is within the scope of the product under consideration. In any case, the petitioner requests the Authority to clarify how the Authority has treated imports of the product where DRI and other authorities in the country have considered that these de-facto amounts to import of the product under consideration. If other authorities in the country have treated these imports as imports of the product under consideration, the Authority cannot treat the same differently. The Authority refers to the recent final findings in case of Melamine, wherein the Authority sought information from DRI. The same approach could have been taken in the present case owing to large number of show cause notices issued by DRI and penalties imposed. In view of this, the petitioner requests the Authority to reject the questionnaire response on the grounds that the party has not provided sufficient information on imports of the product under consideration into India.
- xi. With respect to the "SDH PCN Mapping of DI vs Huawei China", in their submission, Huawei China has indicated that it has exported only three SDH equipment and nine cards/PCBAs to India in the period of investigation. Huawei has further stated that these three equipment PCNs are a close match to three equipment PCNs sold by domestic industry in the POI period and this has been accepted by the Authority. In this regard, Tejas makes the submissions that (a) the three equipment PCNs sold by domestic industry are not identical to those exported by Huawei China and differ from them in terms of usage, capacity and interface ports. This has also been accepted by both Huawei China and DI in the presence of the Authority. It is noted that in every case of a mismatch between exporter PCN and domestic industry PCN, the Authority has always compared with domestic industry's normatted cost of production using the actual weighted average price of the domestic industry's bill of parts and components constituting the PCN. However, in the case of Huawei China's three equipment PCNs, this methodology has not been followed and instead the Authority has considered the nearest matching PCN supplied by Huawei China. The methodology is thus inconsistent between the methodology applied for other exporters and methodology applied for Huawei as disclosed in the disclosure statement; (b) although domestic industry's detailed Bill of Material (BOM) for each PCN has been shared with every exporter for the purpose of fine-tuning and notional adjustments to the actual weighted average price of domestic industry's cost of production for each importer PCN, similar level of part/component detail for exporter PCNs has not been shared with the domestic industry. This has severely prejudiced the interests of the domestic industry and (c) all normatted cost constructions done by domestic industry for the exporter PCNs have been based on very limited configuration information supplied by the importers without any backup or other substantiation. As a result, the final normal values constructed appear biased against the domestic industry.

- xii. All normatted cost constructions done by domestic industry for the exporters' PCNs have been based on very limited configuration information supplied by the importers without any backup or other substantiation. As a result, the final normal values constructed appear biased against the domestic industry
- xiii. The cost of production of the domestic industry should not be normated at all within the meaning of Annexure-III [para 4(iii)] and actual cost of production should be considered for determination of Non Injurious Price.
- xiv. The determination of non-injurious price is inappropriate and is against the object and intent of the dumping law, as interpreted by the Hon'ble Supreme Court in Reliance Industries vs. DA.
- xv. There is no inefficient utilization of production facilities. Since Annexure-III provides for segregating injury due to inefficient utilization, the Designated Authority shall not reduce the NIP by presuming inefficient utilization.
- xvi. Utmost care is required to be taken while determining whether or not lower capacity utilization during the POI is due to inefficient utilization of production capacities.
- xvii. Determination of NIP at ex-factory level does not mean that while comparing NIP and Landed price of imports, NIP should be ex-factory and landed price should be at port. This interpretation and practice of the authority is against the Rules and principles of equity and natural justice.
- xviii. Even under CAS-3 commission is classified under selling overheads. Hence, commission shall be included while calculating the NIP. In case the foreign producer has paid commission, the same is considered part of landed price whereas commission paid by the domestic industry is to be excluded under the rules.
- xix. Transportation cost from the factory to warehouse must be included while calculating the NIP. Warehouse is nothing but extended factory gate of the company. All expenses till transfer of ownership should be taken into consideration while determination of NIP.
- xx. Rule 4 (vii) is contrary to Rule 4 (vi). Since Rule 4 (vi) is completely in line with CAS -3, bad debts shall not be treated as non-cost item and should be allowed while determination of NIP.
- xxi. For the purpose of return on capital employed, fixed assets must be included at gross value basis and not on net basis. Rather, DA must consider the replacement value of fixed assets which have depreciated substantially at original cost/replacement cost.
- xxii. The Designated Authority must add excise duty to the Domestic Industry's NIP and countervailing duty on imports for determining injury margin. If excise duty is not added to the non injurious price and countervailing duties is not added to the landed price of imports, the injury margin is proportionately understated.
- xxiii. The selling price and non injurious price of the domestic industry should be compared with the landed price of imports only after adding the transportation costs. The comparison of NIP of the Domestic Industry without including the associated freight with the landed price of imports will not constitute a fair comparison and would lead to gross under estimation of the injury suffered by the industry.
- xxiv. The injury margin is understated to the proportionate extent, if the sales tax paid by the Domestic Industry is not added to the NIP as imports are attracting special additional duty.
- xxv. Sales tax, excise duty, discounts, commission are payable at ex-factory level and, therefore, the fact that injury margin is being determined at ex-factory level does not imply that the sales tax and excise duty cannot be added.
- xxvi. Fibcom India Ltd, one of the domestic producers of the product under consideration in India, is surprised to read the methodology for determining the Anti-Dumping duty, especially the applicability of the proposed duty rate 35% to 45% on Huawei against the existing rate of 266% and also drastically reduction in duty %age on all other producers/exporters in China PR from 266% to 90% -100% only.
- xxvii. Fibcom is also surprised on the acceptance of the Data of Huawei, China, i.e., their export claim of three equipments and nine cards/PCB/As as against the fact known to DRI who found them involved in heavy duty evasion for SDH Products and imposed penalty on Vodafone, Idea, Tata Teleservices. Infact Tata Teleservices has accepted duty evasion which shows that SDH was supplied by Huawei. All these exports have not been declared to DGAD. This is a gross misrepresentation of facts by Huawei.
- xxviii. Fibcom further reiterate that Fibcom is one of the domestic producers of the product under consideration in India. Fibcom has suffered significant injury because of continued dumping of the product in the country despite existing anti- dumping duty. While the present injury to domestic industry is because of circumvention of anti-dumping, and further reduction in anti-dumping duty will adversely impact the domestic companies.
- xxix. The high cost of funds for Indian domestic companies is the key concern to compete with the foreign vendors as the cheaper funds are to these companies. Also longer payment terms are acceptable to these vendors even up-to one year.

- xxx. In the light of the contentions raised, information provided and submissions advanced, the Authority may be pleased to extend the existing ADD in its existing form, manner and quantum.
- xxxi. The domestic industry submits that anti dumping duty may be imposed as percentage of the CIF value of imports of the subject goods from the subject country (ad valorem form of duty) as the product under consideration includes a number of product types where the associated costs and prices of different product types vary depending upon configurations.

(C) Examination by the Authority

103. The Authority notes that most of the post disclosure statement submissions made by the domestic industry and the opposing interested parties are repetitive in nature and have already been dealt with in the Disclosure Statement and again have been addressed in this Final Findings Notification under the appropriate headings. Nonetheless, the Authority has addressed these issues to the extent considered relevant as under:
 - i). Regarding the claim of some co-operative exporters from China that since there was no customs notification pursuant to the new final findings, all sets of proceedings thereafter including collection of anti-dumping duty till date and the present sunset review are illegal, as there is no legally valid anti-dumping duty in existence and thus it would be prudent for the Designated Authority to terminate the present sunset review immediately, the Authority notes that in the remand findings dated 10th February, 2012, the Authority has held that the final findings earlier notified by the Authority did not require any modification and further that no part of the Final Findings Notification dated 19th October, 2010 was required to be modified as a result of the post decisional hearing conducted by the Authority. It may be appreciated that the Hon'ble CESTAT in its remand order has clearly directed the Authority that *".....Any modifications made in the final findings would be considered by giving effect to the same by the Government by carrying out the necessary amendments to the impugned notifications imposing anti-dumping duty....."*.
 - ii). Regarding the claim of some of the co-operative exporters from China that the present sunset review is illegal as the Designated Authority had failed to conclude the same within 12 months as provided in Rule 23(2) of the AD Rules, it is to be noticed that the Hon'ble High Court of Delhi in W.P.(C) 2310/2015 has already passed its judgement on 06.01.2016 holding that the Central Government has the power to grant an extension of 6 months for concluding a review.
 - iii). Regarding the claim that the time given to comment on the disclosure statement was inadequate, the Authority notes that the time of nine days given was sufficient and all interested parties have submitted elaborate comments on the Disclosure Statement.
 - iv). Regarding the claim of some of the co-operative exporters from China that the interested parties have to suffer undue hardship by paying anti-dumping duties even on those products that are outside the scope of this investigation and, therefore, a separate note mentioning that "components / parts imported on a standalone basis including Printed Circuit Boards are outside the scope of PUC, the Authority notes that under the Product Under Consideration heading, it has already dealt with this issue.
 - v). Regarding the claim of the opposing interested parties to exclude STM-256, Add Drop Multiplexers (ADM) (For SDH Application only), Multiple Add Drop Multiplexers (MADM) (For SDH Application only), Digital Cross Connect (DXC) (For SDH Application only), the Authority notes that it has covered these products with SDH application only and not for non-SDH applications. Further, as far as broadband or cellular equipments are concerned, the Authority has put a Note 3 in the PUC that *"When SDH is imported as a part of eventual broadband / cellular equipment, the AD Duty shall be payable only on the SDH portion of the imports. Similarly, when eventual Broadband / Cellular equipment is imported as a part of the SDH equipment, the AD Duty shall be payable only on the SDH portion of the imports"*.
 - vi). Regarding the claim of the opposing interested parties that the imposition of anti-dumping duty on multiple products is illegal, the Authority notes that the PUC covers only SDH products having similar nature and application and not on the multiple products.
 - vii). The Authority notes that in their post Disclosure Statement, the opposing interested parties have contested the decision of the Authority regarding removal of PTN from the "exclusion list" in the Note 4 of the Duty Table in the Final Findings Notification No. 14/2/2009-DGAD dated 19th October, 2010, read with Corrigendum No 14/2/2009 dated 22nd October, 2010 and further read with Final Findings Notification No 14/2/2009 dated 10th February, 2012. In this behalf, the Authority notes that according to the Association of United Telecom Services Providers of India (COAI), New Delhi, they have got technical advice from the Telecom Engineering Centre (TEC), Department of Telecommunications, New Delhi that in the technical opinion of TEC SDH and PTN (using IP-MPLS/MPLS-TP etc, technologies) are different. On the other hand, the Domestic Industry has given its technical inputs claiming that the SDH equipment evolved over years to cater to the bursty and high capacity

data/ broadband traffic which in turn were marketed by many in industry as a new class of equipment called PTN and hence PTN should also be classified as an SDH class of equipment. The Authority is of the view that the present investigation being the sunset review investigation, the Authority has thus kept the scope of the PUC same as in the original investigation and accordingly, retained the Note 4 in the Duty Table as it was in the Final Findings Notification No. 14/2/2009-DGAD dated 19th October, 2010 read with Corrigendum No 14/2/2009 dated 22nd October, 2010 and further read with Final Findings Notification No 14/2/2009 dated 10th February, 2012.

- viii). Regarding the claim of the opposing interested parties that the Normal Value for the cooperating exporters from China should be calculated based on the data of HETC, China which has fully cooperated in the review investigation and has also been granted the market economy treatment and further that no valid or legitimate grounds exist for not using ECI's information for determination of Normal Value for ZTE Corporation Ltd., Huawei Technologies Co., Ltd. and Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd, solely on the ground that the information of ECI for the purpose of computing the normal value for these companies is the apparent refusal of ECI to share its PCNs, the Authority notes that it has elaborately dealt with these claims of the opposing interested parties and for the valid reasons as explained above in detail, the Authority could not consider Israel as a surrogate country for determining the constructed normal value of these non-market economy Chinese countries in this investigation. No new tangible facts or evidence have been brought before the Authority.
- ix). Regarding the claim of ASB that the Designated Authority has denied market economy treatment to ASB on the mere ground that there is state shareholding in the company, the Authority notes that not only state shareholding is significant, but also significant percentage of nominees on the Board of Directors represent the State, out of which, a government nominee is also the Chairman of the Board of Directors. Thus state interference cannot be ruled out. Therefore, the Authority reiterates that ASB cannot be granted market economy treatment status.
- x). As far as the claims of Huawei China that their MET claims has been wrongly rejected, the Authority notes that during the verification, the company could not provide evidence backed with documents about the complete details/sources of raw material suppliers and the sources of capital invested by its promoters. Therefore, the company was informed that since these basic documents/information which are crucial for examining the market economy treatment status have not been made available, there was no justification in going ahead with the verification of the data pertaining to the domestic sales and its related cost of production. The market economy status to M/s Huawei Technologies Co., Ltd., China PR was, therefore, not granted.
- xi). As far as the claims of the cooperative exporters that because of the faulty PCN to PCN comparison methodology adopted by the Designated Authority, the dumping and injury margins, as the case may be, so calculated seems incorrect and these should be recalculated in light of these exporters' comments on all the PCNs, and further claim that the BOQ designed for these exporters' PCNs include many components, which are either not warranted at all or excess quantities of the required components have been incorporated / integrated, the Authority draws their attention again to the facts that to construct the normal values for the purpose of calculating the dumping margin for these non-market economy Chinese companies as also to determine the injury margin for these Chinese companies as well as ECI, Israel and HETC, China, efforts were made to match the PCNs of the domestic industry with those of these companies. The Authority notes that in their post Disclosure Statement comments regarding the PCN to PCN matching/mapping done by the Authority, both the cooperative exporters and the domestic industry have contested that in the case of some of the PCNs, the mapping/matching adopted by the Authority is not acceptable to them. In this regard what the Authority has noted is that the exporters have not objected to the mapping of the Authority where the mapping was acceptable to them but the domestic industry has objected to. Likewise the domestic industry has not objected to the mapping of the Authority where the mapping was acceptable to them but the exporters have objected to. The Authority notes that the reason for this is that the SDH equipments/cards etc. have different capacity, redundancy or non-redundancy, different cross connect capacity, number of interfaces used, optical reach etc. etc. In this regard, the Authority notes that in the beginning the Authority had shared only the 15 digit PCNs (like E43B0400K0CAA0S) of the exporters with the domestic industry and vice versa for PCN to PCN matching. The domestic industry had prepared its BOQ based on the 15 digit PCN only. However, later on for more clarity, transparency and objectivity, as also because PCN to PCN matching was found to be difficult because of variations in the equipments/cards exported with those of the domestic industry's equipments, the Authority organised one-to-one meetings between the domestic industry and the exporters along with detailed description of the equipments/cards covered by the PCNs, i.e., what's its capacity, whether it is a redundant or non-redundant equipment, what's its cross connect capacity, how many interfaces are used in the said equipment, what is the optical reach of the equipment etc. Thereafter, the domestic industry again constructed its BOQ for various equipments/cards/PCBAs exported by these exporters based on the features. That is the reason the BOQ prepared by the domestic industry based solely on the 15 digit PCN was amended by the domestic industry later on based on the complete description of the product/PCN which explained its nature/type

etc., by either adding some new parts/components, interfaces, or removing some. The Authority, thereafter, instead of accepting the BOQ of the domestic industry, arranged more one-to-one meetings to arrive at a consensus because not only the exact matching/mapping was not found to be possible in many of the PCNs because of the variations, complexities and end-use of the equipments/cards, but also because no party was fully agreeing to the mapping of the other. The Authority, therefore, had to use its own wisdom and prudence based on the discussions with the technical experts of the domestic industry and the exporters to arrive at the closest possible mapping. What is to be appreciated is that in the case of Alcatel, for example, matching/mapping done by the Authority for many of the PCNs has been accepted by Alcatel. Likewise Huawei China and ZTE have also accepted some matching/mapping and contested some. The Authority notes that as different cards/equipments exported have variations in capacity, end-use etc, vis-a-vis the equipments of the domestic industry, there is bound to be some conflict in what the exporters expect the BOQ of the domestic industry to be and what the domestic industry expects the Authority should adopt the BOQ. That exactly is the reason that in the post Disclosure Statement comments, the domestic industry as also the exporters have not accepted the matching/mapping adopted by the Authority fully. However, the Authority, based on the post Disclosure Statement comments of the domestic industry and the exporters, has re-examined the mapping/matching of the PCNs where there is conflict and finds that the mapping/matching adopted by the Authority is in order as the same was based on the discussions with the technical experts of the exporters and the domestic industry and its own prudence arrived at on the basis of generally acceptable technical features or its alternates of those equipments/cards prevalent in the industry, and thus no change in mapping/matching is warranted.

- xii). Regarding the claim of the opposing interested parties that they had strongly objected to the domestic industry's reliance on Ovum Reports for import volume and value of the subject goods and thus the petition filed by the domestic industry was defecting, the Authority notes that the Authority has relied upon the DGCI&S import data for capturing the volume of imports from the subject countries and not the Ovum report and thus there is no merit in the claim of the opposing interested parties.
- xiii). Regarding the claim of the opposing interested parties that negative dumping margin was calculated for ECI, Israel and despite this fact, the Designated Authority has failed to exclude un-dumped imports of ECI, Israel from the total volume of dumped imports in the injury analysis, the Authority notes that what it has done is correct because the Authority, as per its practice, has captured the entire import volume from Israel to assess the total demand to assess injury. The claim of the opposing interested parties is, therefore, without merit.
- xiv). Regarding the claim of the opposing interested parties that an analysis of injury parameters reveal that the domestic industry is not suffering any injury and there is no causal link between alleged dumping and injury, the Authority notes that the detailed examination during the course of the investigation has shown that the imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry in the market. The imports are also depressing the prices of the product under consideration in the domestic market. The performance of the domestic industry has deteriorated in terms of profits, return on investment, cash flow and growth despite the anti-dumping duty in existence during the period under investigation.
- xv). Regarding the claim of the opposing interested parties and the domestic industry regarding excessive claim of confidentiality, the Authority notes that the information which are confidential in nature and provided by the interested parties on confidential basis have been treated so wherever warranted after due examination of the confidentiality claims as per the general practice followed by the Authority. Therefore, the concerns of the interested parties have been adequately addressed.
- xvi). Regarding the claim of the opposing interested parties that the transaction-wise DGCI&S data has not been provided by the Authority to the responding exporters which jeopardizes the injury analysis of the domestic industry, the Authority re-iterates that as far as capturing the import volume is concerned, the consolidated figures as provided by DGCI&S for the tariff codes for SDH equipments and parts of SDH equipments have been used. It is further explained that as far as Price Undercutting and Under Selling are concerned, the Authority has determined the landed value for the subject countries on the basis of the response filed by the cooperative exporters from the subject countries and that this was necessitated because in the DGCI&S data for the injury period, PCN to PCN mapping/matching was not possible as the DGCI&S import data does not give complete information to construct the PCNs whereas the cooperative exporters and the domestic industry have given PCN wise details for the POI and thus PCN to PCN mapping/matching was done for these exporters and the domestic industry. Regarding the claim that the landed value has not been considered in the price suppression and price depression analysis in gross violation of the consistent practice of the Authority, the Authority finds no merit in the claim as for price suppression/depression, the cost of sales is compared with the selling price.
- xvii). Regarding the claim of the opposing interested parties that in the event the Designated Authority decides to extend anti-dumping duty, the quantum of anti-dumping duty should not increase the duty that was imposed

during the original investigation, the Authority notes that the sunset review is an independent investigation and if the data for the POI of the review investigation so warrants, the Authority can amend the duty, as the Authority has done in several review investigations in the past. Further, the Hon'ble CESTAT has not passed any interim or final order as yet on the pending appeals.

- xviii). As far as the claim of the domestic industry that the producers from subject countries have significant capacity which establishes that in the event of revocation of duties, exports to India will intensify, the Authority has already determined that Huawei China, HETC China, Alcatel and ZTE are dumping the PUC and has thus recommended imposition of the duties on them. In any case, the domestic industry has not provided any tangible and substantial evidence regarding their claim of excessive capacity of the co-operating exporters.
- xix). As far as the claim of the opposing interested parties that the Designated Authority is willing to consider an intellectual property holder who does not manufacture in India as domestic industry, while on the other hand, is not considering Huawei India as domestic industry though it possesses intellectual property in India as well as manufactures the subject goods in India, the Authority notes that various arguments have been made by the interested parties questioning Tejas Networks Ltd's standing as eligible domestic industry with major proportion in the total Indian production. However, only after detailed examination of the production analysis of the Applicant, as also of substantial transformation carried out by it during the process of producing the PUC, the Authority has held that Tejas Networks Ltd accounts for a major proportion of the total domestic production of the subject goods during the POI and constitutes domestic industry within the meaning of the Rule 2 (b) and satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Anti- dumping Rules.
- xx). Regarding the claim of Huawei India that it should be treated as the eligible domestic industry, the Authority notes that every investigation is based on its own facts and merits and, therefore, reference to any other decision in the past investigations does not have any bearing on the case under investigation. The Authority thus reiterates that since Huawei India is a fully owned group company of Huawei China and has also imported the PUC in the POI of the present sunset review investigation and filed the importers questionnaire response, there is no merit in the claim of Huawei India for considering it as the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Anti Dumping Rules for the purpose of the present sunset review investigation.
- xxi). Regarding the request to do the likelihood analysis by determine the dumping margin in respect of the third country exports and hold thereafter whether there is no likelihood of dumping and injury, the Authority has analysed the data of ECI Israel for third country exports and found out the exporter has not exported to third countries at dumped prices. As far as cooperative exporters from China are concerned, the Authority in a large number of investigations has also taken the view that if there is dumping and injury in the POI, there may not be any need to do the likelihood analysis as the duty will be imposed on the basis of the margins in the POI.
- xxii). As regards the claim of the domestic industry regarding injury to it because of the dumped imports, the Authority, on the basis of the information made available by various interested parties and the domestic industry, notes that there is no doubt that though the demand has declined yet the subject imports have remained significant in absolute terms and in relation to production & consumption in India. The imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry in the market. The imports are also depressing the prices of the product under consideration in the domestic market. The performance of the domestic industry has deteriorated in terms of profits, return on investment, cash flow and growth despite the anti-dumping duty in existence during the period under investigation. The deterioration in the performance of the domestic industry during the injury period is quite significant.
- xxiii). Regarding the claim of the domestic industry that the Authority has distinguished between Printed Circuit Board (PCB) and Populated Circuit board by stating that PCB are populated as per the design developed by the manufacturer and thereafter, apart from loading of software, there is only a need to arrange them in a shelf and adjust them to a circuit and further that the PCB is a part of product under consideration due to the reasons that it is a propriety of the manufacturer and it has no other use apart from production of SDH equipment, the Authority has already concluded that Populated Circuit Board/Assemblies; (for SDH use) are very much part of the PUC. However, the Authority has also determined that Printed Circuit Boards are of the nature of parts and components, and thus if Printed Circuit Boards are imported on stand-alone basis, they remain outside the scope of the PUC.
- xxiv). Regarding the claim of the domestic industry that the Authority has determined the dumping margin in the case of ECI Israel based on the cost of production of the producer and has added a "reasonable profit" thereon whereas the Authority should have added profit on the basis of actual profit earned by the company in accordance with the rules, the Authority notes that it has followed the normal practice as the domestic sales of ECI Israel, a market economy exporter, are less than five percent of the exports sales to India.

- xxv). Regarding the various submissions of the domestic industry relating to the NIP determination and various ex-factory expenses and taxes, including the submission that for determining NIP, the cost of production of the domestic industry should not have been normated, the Authority holds that NIP of the domestic industry has been calculated based on Annexure-III of the AD Rules which is a consistent practice of the Authority. All non-allowable expenses have not been taken into consideration and the Annexure-III clearly lays down the expenses which shall not to be considered while assessing non-injurious price. As far as the Hon'ble S.C. judgement in the Reliance Industries matter relied upon by the domestic industry is concerned, the Authority notes that the Annexure-III has been included in the AD Rules after the said judgement and thus become applicable, and being consistently followed by the Authority. As far as the submission of the domestic industry regarding inclusion of commission is concerned, the Authority notes that although the same may be an allowable expense under CAS-3, Annexure-III does not allow the same to be included in the calculation of the NIP.
- xxvi). As regards the issue of equivalent units or adoption of actual production figures without normation for determination of costs, as raised by the DI at the very advanced stage of investigation, the Authority notes that the contention suggested by DI is not supported by any technical reasoning (in terms of the time required for production etc). Further, the products manufactured are technology products, which have limited life, irrespective of number of units actually produced or sold.
- xxvii). The authority also notes that the DI does not have any installed capacity of its own. The PUCs are manufactured by outsourcing to the Electronic Contract Manufacturers on job contract basis. In fact, DI has claimed that it is in position to execute the orders received without having any installed capacity of their own and capacity is not a constraint due to use of EMS. Therefore, the procedure as prescribed under para 4(iii) of Annexure-III to Anti Dumping Rules regarding Principles for determination of Non-Injurious Price has been followed. This methodology has been consistently applied in many other similar investigations. The relevant extract of the rules is as under:
- “The best utilisation of production capacities, over the past three years period and period of investigation, and at period of investigation rates may be considered to nullify injury, if any, caused to the domestic industry by inefficient utilization of production capacities.”
- xxviii). Regarding the claim of the domestic industry that the questionnaire responses filed by Huawei China and Huawei India clearly show that the questionnaire responses filed by these parties are grossly insufficient to grant them individual dumping margin as in the responses significant information has been suppressed, the Authority notes that export data filed by Huawei China was duly verified by the Authority and thereafter only, the individual dumping margin has been calculated for them. Huawei India has not been considered to be qualifying as domestic industry within the meaning of the AD Rules.
- xxix). Regarding the claim of the domestic industry that Huawei India has attempted to bring in SDH Transmission Equipment in the name of components and avoid anti dumping duties and that the SDH equipment so procured by the consumers and DRI action/decision thereon clearly establish that what has been imported into India is within the scope of the product under consideration and further that owing to large number of show cause notices issued by DRI and penalties imposed, the Authority ought to have sought information from the DRI, the Authority notes that the export data filed by Huawei China was duly verified by the Authority and thereafter only the individual dumping margin has been calculated for them. Therefore, the Authority has dealt with this issue on its own merits as per the Anti Dumping Rules. The Authority is also of the opinion that the DRI proceedings, in any case, are the proceedings which are independent of anti dumping proceedings and thus, if the DRI finds that some exporters/importers are misusing the law, the DRI will take necessary action against them as per their procedure in such cases in accordance with law.
- xxx). Regarding the claim of Fibcom India Ltd questioning the methodology adopted for the proposed duty rates for Huawei against the existing rate and also drastic reduction in duty %age on all other producers/exporters in China PR, the Authority notes that the present review investigation is an independent investigation wherein the dumping margins and the injury margins have been calculated based on the verified data for the POI, after following a transparent and elaborate methodology of PCN to PCN mapping/matching, and thus previous margins have no relevance.
- xxxi). Regarding the claim of the domestic industry to recommend anti dumping duty as percentage of the CIF value of imports of the subject goods from the subject countries (ad valorem form of duty), the Authority notes that it has recommended duties as percentage of the CIF value of imports.

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

104. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product

in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the end user. The end user could still maintain two or even more sources of supply.

105. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not affect the availability of the product to the consumers.

K. CONCLUSION

106. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in this final finding and on the basis of the above analysis of the state of continuation of dumping and consequent injury and likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury, the Authority concludes that:

i). As far as Huawei China, ZTE Corporation Ltd, China, Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd., China are concerned, there is continued dumping of the subject goods from these companies in the period of investigation. Dumped imports are causing injury to the domestic industry in the period of investigation.

ii) As far as HETC, China is concerned, the re-examination of their data has shown that there is negligible (less than ***) dumping in the POI and in this behalf, the Authority has, therefore, examined the post POI exports to India as well as third countries and found that the same were un-dumped. Therefore, there is no likelihood of dumping. As far as ECI Telecom, Israel is concerned, it is seen that the exports of the PUC to India in the POI and to India as well as third countries in the post-POI are not at dumped prices and thus there is no likelihood of dumped imports from ECI Telecom, Israel if the duty is revoked.

L. RECOMMENDATIONS

107. Having concluded as above, the Authority is of the view that the antidumping measure is required to be recommended to offset dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries and its consequential injury to the domestic industry.
108. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, antidumping duty as indicated in the duty table below, which shall be as a percentage of CIF value of imports, is recommended to be imposed from the date of notification, to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of subject goods originating in or exported from the subject countries.

Duty Table

Sl. No.	Heading/ Subheading	Description of goods	Country of Origin	Country of Exports	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit
1.	851762 & 851770	***Synchronous Digital Hierarchy transmission equipment” as per notes below	China PR	China PR	M/s ZTE Corporation Ltd.	M/s ZTE Corporation Ltd.	48.42	% of CIF Value of Imports
2.	Do	Do	China PR	China PR	M/s Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd.	M/s Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd.	54.09	Do
3.	Do	Do	China PR	China PR	M/s Huawei Technologies Co., Ltd.	i). M/s Huawei Technologies Co., Ltd., China PR Or ii) Huawei Tech Investment	37.73	Do

Sl. No.	Heading/ Subheading	Description of goods	Country of Origin	Country of Exports	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit
						Co., Ltd., Hong Kong Or iii) Huawei International Pte Ltd., Singapore		
4.	Do	Do	China PR	China PR	Hangzhou ECI Telecommunication Co. Ltd.	M/s ECI Telecom Ltd., Israel	NIL	Do
5.	Do	Do	China PR	China PR	Any other than Sl. No. 1,2,3 and 4 above	Any	86.59	Do
6.	Do	Do	China PR	Any other than China PR	Any	Any	86.59	Do
7.	Do	Do	Any	China PR	Any	Any	86.59	Do
8.	Do	Do	Israel	Israel	M/s ECI Telecom Ltd.	M/s ECI Telecom Ltd.	NIL	Do
9.	Do	Do	Israel	Israel	Any other than Sl. No 8 above	Any	9.42	Do
10.	Do	Do	Israel	Any other than China PR and Israel	Any	Any	9.42	Do
11.	Do	Do	Any other than China PR	Israel	Any	Any	9.42	Do

****Note 1.** The product under consideration will include "Synchronous Digital Hierarchy transmission equipment, viz., STM-1, STM-4, STM-16, STM-64, STM-256, in assembled, CKD, SKD form, its assemblies and sub-assemblies or fitted with eventual broadband / cellular equipment. Product under consideration will also include Add Drop Multiplexers (ADM) (For SDH Application only), Multiple Add Drop Multiplexers (MADM) (For SDH Application only), and Digital Cross Connect (DXC) (For SDH Application only), Populated Circuit Boards (For SDH Application Only) and parts / components imported as a part of equipment, so long they are imported along with the equipment or its assemblies / subassemblies. The Product under consideration will also include Software meant for SDH, which is an integral part of these equipments, which may be bought either as a part of the equipment or separately. However components/ parts imported on a standalone basis are outside the purview of Product under Consideration.

****Note 2.** SDH Equipment essentially transmits signals through the medium of Optical Fibre. There may be SDH equipment meant for transmission through electrical Copper Medium or Microwave Radio Medium. The SDH Equipment transmitting the data through optical fibre alone shall be subject to levy of antidumping duty.

****Note 3.** When SDH is imported as a part of eventual broadband / cellular equipment, the AD Duty shall be payable only on the SDH portion of the imports. Similarly, when eventual Broadband / Cellular equipment is imported as a part of the SDH equipment, the AD Duty shall be payable only on the SDH portion of the imports.

****Note 4.** PDH, CWDM, DWDM, Microwave systems, GPON, DSLAM, MSAN, BITS, Routers, PDSN, SGSN, MGW, BTS, BSC, MSC, ONT, HLR, HSS and MRP being non-SDH in any of its form are outside the scope of PUC and, therefore, not subject to levy of AD Duty.

****Note 5.** Microwave Radio Terminals which could have an STM-1 interface to the SDH transmission equipment and act as a physical media to enable the connectivity between the radio and the SDH equipment are outside the purview of payment of AD Duty.

109. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.
110. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

A. K.BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority